हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, 25 मार्च, 2015 को अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

25.03/1100/2015.जेके/एजी/1

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री रविन्द्र सिंह जी आप क्या कहना चाहते हैं?
श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विभिन्न समाचार-पत्रों में छपा हुआ है। पिछले कल माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता हैं, उनके ऊपर एक केस IPC की धारा 120-B और 420 के अन्तर्गत है।

अध्यक्षः अभी मैं एलाऊ नहीं करूंगा क्योंकि अभी प्रश्नकाल का समय है और प्रश्न काल के बाद आपको समय दे दिया जाएगा। ---(व्यवधान) ----Raviji, no matter can be raised during the Question Hour. मैं कह रहा हूं कि प्रश्नकाल के बाद आपको टाईम दूंगा और उसके बाद आप बोलें। This is not the time to raise this question. अखबारों में तो बहुत कुछ लिखा होता है। (Interruption) No, no. Not to be recorded. इस बारे में बात करने का यह उचित समय नहीं है। Let the Question Hour finish. This issue is not to be taken now. We are not to discuss anything during the Question Hour. (Interruption) This is not the appropriate time to raise this issue. Let the Question Hour finish. No, no, please.

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, धूमल साहब के प्रति मैंने कोई अपशब्द नहीं कहे और न ही मैंने राज्यपाल महोदय के बारे में कहा। मैं तो उनका सम्मान करता हूं। मेरे से यह पूछा गया कि राज्यपाल महोदय ने कुछ आदेश दिये हैं और मैंने कहा कि जो राज्यपाल महोदय ने आदेश दिए हैं उसके बारे में हमने सारी कार्रवाई की है और यह जो आदेश है उसके बाद प्राप्त हुए हैं The matter can be raised in the court of law. This was I said. That's all. ---(व्यवधान) ----

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री रविन्द्र सिंह जी, अखबारों में तो बहुत कुछ छपता है।
मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अगर इससे ज्यादा किसी अखबार में लिखा है तो उस पर मैं मानहानि का दावा करूंगा।

25.03/1100/2015.जेके/एजी/2

अध्यक्षः आज के लिए जो माननीय सदस्य सर्वश्री ईश्वर दास धीमान, महेन्द्र सिंह, सतपाल सिंह सत्ती, नरेन्द्र ठाकुर एवं श्री रणधीर शर्मा के प्रश्न निर्धारित हैं, उनका विषय एक ही है इसलिए माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अपने-अपने अनुपूरक प्रश्न स्पैसिफिक और संक्षेप में पूछें जिससे प्रश्नकाल का समय अनावश्यक चर्चा में व्यतीत न हो।

अब प्रश्न संख्याः 779 श्री ईश्वर दास धीमान।

25.03/1100/2015.जेके/एजी/3

प्रश्न संख्याः779

श्री ईश्वर दास धीमानः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने जो उत्तर दिया है उसका ज़वाब चौथे-पांचवें सैशन में आ रहा है। यह 1.1.2013 से ले करके 30.11.2013 तक है। केवल 11 महीने का है। 11 महीने में जो ट्रांसफर हुई उनकी संख्या 29,622 है।

श्री एस.एस.द्वारा जारी------

25.03.2015/1105/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 779 क्रमागत

श्री ईश्वर दास धीमान क्रमागतः

3837प्रशासनिक आधार पर और 8884 जन-प्रतिनिधियों के अर्धशासकीय पत्रों (DOs) पर ट्रांसफर्ज़ हुईं। मुझे यह बात समझ नहीं आई कि 3837 प्रशासनिक तौर पर ट्रांसफर हुए 8884 ,अर्धशासकीय पत्रों पर हुए, ये 16901 बनते हैं। 29622 में से इनको घटा करके 16900 ट्रांसफरें किस आधार पर हुईं? क्या वे विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए की गईं? किसी को सज़ा देने के लिए की गईं? जो आपने प्रशासनिक तौर पर ट्रांसफरें कीं क्या उनकी इंक्वायरी करवाई गई? जो 16900 ट्रांसफरें हैं पहले इसका ब्योरा दीजिए कि ये किस आधार पर हुईं? इसका कोई-न-कोई आधार तो होगा। जो प्रशासनिक तौर पर ट्रांसफर्ज़ हुईं क्या वे इंक्वायरी और

प्रोसिज़र एडॉप्ट करने के बाद हुईं या वे वैसी ही की जा रही हैं? इसके साथ ही 930 लोग न्यायालय में गए। आप हैरान होंगे कि 806 को रद्द किया गया। ये अनुचित ट्रांसफर क्यों करते हैं? ये कब बंद होंगी?

अध्यक्षः धीमान साहब, आप सप्लीमेंटरी कीजिए। आप टैक्स्ट मत पढ़िये।
श्री ईश्वर दास धीमानः लोग कोर्ट में गए, सबको राहत मिली। इसका मतलब यह है कि ये ट्रांसफर सारी गलत हुई थीं और न्यायालय जो फैसला दिया, उसका भी ये जवाब दें कि वे किस आधार पर ट्रांसफर्ज़ की गईं? क्या आगे यह सिलसिला चलता रहेगा या बंद भी होगा?

मुख्य मंत्रीः मैं आपके वक्त की भी ट्रांसफर्ज़ बताऊंगा। मेरे पास पूरी लिस्ट है। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा विस्तृत ब्योरा अपने प्रश्न के उत्तर में दे चुका हूं। इन्होंने 1 जनवरी, 2013 से 30 नवम्बर, 2013 तक ट्रांसफर्ज़ के बारे में पूछा है। उसमें कुल ट्रांसफर 29622 हुई हैं। जिसमें क्लास-I के 2451, क्लास-II के 586, क्लास-III के 23382 और क्लास-IV के 3203 हैं। इनमें से एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राऊंड पर 3837 और बाकी 413 ऑन रिक्वैस्ट हुए हैं। पब्लिक रिक्वैस्ट 1239 है। जिसमें 1239 में से rest were general transfers on request.

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री महेन्द्र सिंह। सेम क्वैश्चन है। धीमान साहब एक मिनट बैठिए। --(व्यवधान)--

25.03.2015/1105/SS-AG/2

श्री ईश्वर दास धीमानः अध्यक्ष महोदय, एक रोज़ की 100 ट्रांसफर्ज़ बनती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सारे साल में कितनी ट्रांसफर्ज़ होती होंगी और ये केवल 11 महीने की हैं। आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सारा साल कितनी ट्रांसफर्ज़ होती हैं। क्या सरकार को सिर्फ ट्रांसफर करने का ही काम रह गया?

अध्यक्षः आप सप्लीमेंटरी पूछिये ताकि ये उसका जवाब दें। Please ask the supplementary.

श्री ईश्वर दास धीमानः यह तो प्रतिशोध की भावना से किया गया है। यह ठीक नहीं है। क्या यह सिलसिला बंद होगा? मई में ट्रांसफर पर बैन लगा था।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये एक साल की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इसी सदन के अंदर श्री कौल सिंह ठाकुर ने दिनांक 11.12.2008 को प्रश्न संख्याः 179 मुख्य मंत्री से प्रश्न पूछा था। वह भी ट्रांसफर के बारे में था। ..

जारी श्रीमती के0एस0

/1110/25.03.2015केएस/जेटी/1

प्रश्न संख्याः 779 जारी--मुख्य मंत्री जारी--
मुख्य मंत्री से प्रश्न पूछा था और यह जनवरी, 2008 से 15 अगस्त 2008 तक यह आठ महीने का ब्यौरा था। उस वक्त के मुख्य मंत्री ने इसका उत्तर दिया था। पहली जनवरी, 2008 से 15 अगस्त, 2008 तक प्रदेश में सभी विभागों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कितने तबादले हुए, पूर्ण विवरण सभा पटल पर रखें, यह प्रश्न था और इसके जवाब में उन्होंने कहा कि 27 444,तबादले 8 महीने में हुए और इसका श्रेणीवार ब्यौरा निम्न हैः-श्रेणी-I 2549, श्रेणी-II ,383 श्रेणी- III ,21547 श्रेणी iv - 2965 कुल 27,444 और यह 8 महीने का है और यह आपके समय का जवाब है।

Speaker: I club all the Postponed Questions so that Hon. Members make one supplementary each. Replies to all these questions will be the same. So, I think, if you make combined supplementaries at one place, it will save the time.

प्रश्न संख्याः 1178,1408 तथा 1484

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो है यह श्री महेन्द्र सिंह और श्री सतपाल सिंह सत्ती जी के द्वारा इसी विषय यानि कर्मचारियों के स्थानान्तरण के ऊपर दूसरा प्रश्न संख्या- 1178 है तो क व ख सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, क्या आपने उपरोक्त सभी प्रश्न क्लब कर दिए हैं या अलग-अलग पूछने हैं?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, ये क्लब कर दिए हैं।

/1110/25.03.2015केएस/जेटी/2

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना यहां पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उपलब्ध करवाई है चार प्रश्नों की, ये चार प्रश्न हैं। मुझे लगता है कि ये चारों ही पोस्टपोंड क्वैश्चन हैं। प्रश्न संख्या-779, 1178,1408 तथा 1484 । इसमें धीमान जी ने जो प्रश्न किया था उसके जवाब में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बताया है कि 1 जनवरी,2013 से लेकर 30 नवम्बर, 2013 तक 29,622 स्थानांतरण इस प्रदेश में हुए। दूसरा प्रश्न जो यहां पर श्री सतपाल सिंह सत्ती जी और महेन्द्र सिंह जी का है, 1 दिसम्बर, 2013 से लेकर जुलाई, 2014 तक 10,142 स्थानान्तरण हुए और नरेन्द्र ठाकुर जी ने सुजानपुर विधान सभा क्षेत्र के बारे में पूछा है तो चुनाव के बाद वहां पर 210 स्थानान्तरण हुए डेढ़ महीने में और 16 जुलाई, 2014 से 31 अक्तूबर, 2014 तक, जिसका जो प्रश्न पूछा नहीं गया था माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे थे, उसमें इन्होंने 6327 स्थानांतरण बताए। यहां पर अभी तक ये पोस्टपोंड क्वैश्चन है। उसके बाद यानि की अक्तूबर, 2014 से लेकर अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने में कर्मचारियों के ऊपर क्या कहर बरपा वह फाईल तो अभी बंद है । इसमें कुल मिलाकर आप देखेंगें।

मुख्य मंत्रीः रवि जी, यह आप किस पीरियड को रैफर कर रहे हैं ,यह किस क्वैश्चन में है?

/1110/25.03.2015केएस/जेटी/3

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय ने चार प्रश्न क्लब कर दिए हैं। पहले चारों प्रश्न कर्मचारियों के स्थानांतरण के ही है। क्लब करके इनका एक प्रश्न बना दिया है।

अध्यक्षः ये प्रश्न अब 1 जनवरी, 2013 से 31 अक्तूबर, 2014 तक क्लब कर दिए हैं।

श्री रविन्द्र सिंहः ये सारे प्रश्न क्लब कर दिए हैं। इसमें डेढ़ साल में आपने 46301 स्थानांतरण किए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

25.3.2015/1115/jt/av/1

प्रश्न संख्या : 779 1408 ,1178 ,और 1484 -------जारी

इस डेढ़ साल में आपने अक्तूबर, 2014 तक 46301 स्थानांतरण किए। प्रदेश में उसके बाद 6 महीने की पोजिशन क्या है? आपने यहां पर जो प्रतिबंध लगा रखा है, आप को ही ऑथोरिटी है और केवल आप ही कंडोन करके या दूसरी तरह से स्थानांतरण कर सकते हैं। अभी तक उसकी स्थिति क्या है? क्या वह फाइल अभी गर्भ में है; उसका क्या परिणाम आयेगा, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने ऐसे कितने स्थानांतरण जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या अन्य, जिसकी सूची मैंने पीछे यहां पर सत्यापित करके ले की थी। मुझे लगता है कि वह आपके पास पहुंच गई होगी? आपने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उस सारी स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने स्थानांतरण हुए जो ऐसे आलतू, फालतू और कालतू लोगों के द्वारा करवाये गये? कृपया उनकी सूचना भी दी जाए। ये जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं ये सभी कालतू लोगों की श्रेणी में आते हैं। इनका काम कोई नहीं है। उल्टे प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को खराब करते हैं और साथ में डी.ओ. देते हैं, इसके अलावा इनका कुछ काम नहीं है। उनका केवलमात्र एक काम डी.ओ. देना है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस 6 महीने के अंतराल में इन लोगों के द्वारा कितने स्थानांतरण करवाये गये?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने चारों प्रश्न क्लब कर दिए। मैंने हरेक प्रश्न के अंदर पूरा-पूरा ब्यौरा दे रखा है। अब माननीय सदस्य किस पीरियड की बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है मगर हमने इनके बारे में ब्यौरा दे रखा है। मैं आपको एक बात और बता दूं। हाई कोर्ट ने कहा था कि एम.एल.एज. या अन्य किसी भी जन प्रतिनिधि को ट्रांसफर के बारे में कहने का हक नहीं है। But that decision was reversed by the Hon'ble Supreme Court. और जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार सभी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बदली पर जनहित में विचार किया जायेगा। हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय की जजमैंट दिनांक

25.3.2015/1115/jt/av/2

,22.11.2013सी.डब्ल्यू.पी., न0.6145/22013 द्वारा स्थानांतरण नीति की उस क्लॉज को निरस्त कर दिया गया है। साथ में, हाई कोर्ट ने यह कहा था कि न कोई एम.एल.एज., न कोई पंचायत के लोग, न ही कोई जन प्रतिनिधि ट्रांसफर के बारे में सिफारिश कर सकता है। That has been upturned by the Hon'ble Supreme Court. उन्होंने कहा है कि अब ग्राम पंचायत के लोग, पंचायत समिति के लोग, जिला परिषद के लोग और दूसरे सभी जन प्रतिनिधि अपनी सिफारिश दे सकते हैं।
अध्यक्ष : आपको सूचना मिल गई है।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो यहां कहा कि चुने हुए जन प्रतिनिधि जिसमें विधायक या पंचायती राज संस्थाओं के सभी; जो भी इन्होंने यहां पर बताये हैं। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने यहां पर एक सूचना ले की थी। आपने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। जिसमें आपके उस समय के एक एन.जी.ओ. लीडर ने एक ही नोट पर 43 स्थानांतरण कर दिए। एक और आपकी पता नहीं क्या वह एसोसिएशन फॉर समथिंग, समथिंग; क्या था उसमें? उसके नोट पर 70 स्थानांतरण कर दिए। मैंने वह सूची भी यहां पर ले की थी। आपने जो यहां प र वर्गीकरण किया है कि ये, ये और ये बंद कर दिए तो क्या ऐसे लोगों को आपने छूट दे रखी है कि वे नोट लेकर आए और आप उन सबको अप्रूव करके सारी-की-सारी ट्रांसफर कर देंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह कोई नई बात नहीं है, ऐसी परम्परा रही है। अगर कोई ट्रेड यूनियन्ज है या इम्पलॉइज एसोसिएशन्ज हैं, they have a right to represent about their members and if any merit is found in that, the Government does accede to their request.

25.3.2015/1115/jt/av/3

प्रश्न संख्या : 1408
श्री नरेन्द्र ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 1408 के संदर्भ में दिए गए उत्तर के अनुसार पिछले 6 महीने के अंतराल में मेरे सुजानपुर निर्वाचन क्षेत्र में 210

स्थानांतरण किए गए। मेरे ख्याल में इतने ही और शेष बचे हैं; तो मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि उन्हें भी बदल दें। मेरी सूचना के मुताबिक ये जो ट्रांसफर्ज की जा रही है यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपदा नियंत्रण बोर्ड का एक वाइस चेयरमैन बनाया है उसके कहने के मुताबिक की गई हैं और----------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

25.03.2015/1120/negi/ag/1

प्रश्न संख्याः 1178 ...(1408).. जारी..

श्री नरेन्द्र ठाकुर जारी..

उसके कहने के मुताबिक की गई है और यह वही व्यक्ति है जो वुडविला होटल में कॉल गर्ल्ज़ का धन्धा करने वाले केस का इनक्वायरी फेस कर चुका है । मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जो आप ट्रांसफर्ज़ कर रहे हैं उनका आधार क्या है ? क्या यह मेरी इन्फोर्मेशन सही है, मैं इसका जवाब आपसे जानना चाहूंगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था प्रश्न संख्या 1 408 जिसको और प्रश्नों के साथ क्लब कर दिया गया है । इसका मैंने विस्तृत जवाब अलग से दिया हुआ है । मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो ट्रांसफर्ज़ हैं ये जन-प्रतिनिधियों जिसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं , जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वे भी शामिल हैं और आपके (भाजपा) लोग भी शामिल हैं उनके आधार पर किया गया है और इसमें ज्यादा प्रशासनिक आधार पर किया गया है ।

समाप्त

25.03.2015/1120/negi/ag/2

प्रश्न संख्याः 1728.

श्री रविन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा यहां पर जो सूचना रखी है उसमें इन्होंने कहा है कि 26.9.2014 को माननीय उच्च न्यायालय में केस दायर किया गया था Titled Ramesh Sharma V/s State of

H.P. & others. CWP No. 4499/2012 titled Mehar Singh & others V/s State of H.P. & others and CWP No. 5076/2012 titled Sonali Purewal V/s State of H.P. and others. इसका निपटारा करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने यहां पर पशु बलि के ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया था। उसके बाद माननीय Sh. Maheshwar Singh & others V/s State of H.P. & others ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है । इसमें प्रदेश सरकार को भी प्रतिवादी बनाया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मण्डी में शिवरात्रि का पर्व और कुल्लू में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का जो दशहरा पर्व होता है ,उस दौरान वहां पर काफी संख्या में लोगों का हजूम रहता है और हम सभी लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी है। मुख्य मंत्री महोदय वहां गए थे । वहां पर जो विभिन्न स्थानों से देवता आते हैं उन देवताओं ने भी इसके ऊपर एतराज़ किया था। वहां पर मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि हम पशु बलि की मन्जूरी के लिए नहीं लाएंगे आध्यादेश, आपने यह कहा था। लेकिन अभी जो आपने जवाब दिया है इसमें आपने कहा है। आपको कांगड़ा के सांसद, श्रीमान शांता कुमार जी ने कहा कि आपको माननीय हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। एक तो इसमें हमारी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, साथ में हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है उसपर आगे श्री महेश्वर सिंह जी ने अपील कर रखी है तो आप इसके ऊपर क्या रिएक्ट करना चाहते है? मुख्य मंत्री महोदय इसमें आपका क्या जवाब है, प्रदेश सरकार क्या करना चाहती है? प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि इसमें आपका क्या वर्शन है ?

25.03.2015/1120/negi/ag/3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहली बात जो माननीय सदस्य ने कही कि मैंने कोई ब्यान दिया है, वह बिल्कुल गलत है, मैंने कोई ब्यान नही दिया है। और न ही मैंने यह कहा कि सरकार इस कानून के खिलाफ कोई अध्यादेश लाएगी । ऐसी बात भी मैंने कहीं नही की है। किस अखबार में क्या छपता है वो मैं नहीं जानता मगर मेरी ओर से ऐसा कोई ब्यान नही दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, तथ्य इस प्रकार से है -:जुलाई, 2012 में CWP No. 5076/2012 सोनाली पुरेवाल बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार उच्च-न्यायालय में... श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

25/1125/03.2015.यूके/एजी/1

प्रश्न संख्या- 1728--जारी---

मुख्य मंत्री--जारी---

उच्च न्यायालय में दायर की गयी है । 28-9-2014 के आदेश द्वारा याचिका स्वीकृत की गयी और समस्त हिमाचल प्रदेश में पशु बलि पर प्रतिबन्ध लगाया गया, पशु ही नहीं बल्कि पक्षियों की बलि पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया । 26-9-2014 के उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध श्री महेश्वर सिंह आदि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, भारत में याचिका दायर की गयी । सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई 8-10-2014 को हुई । अपील को दायर करने की अनुमति दी गयी । कोई भी अंतरिम राहत नहीं दी गयी । आगामी तिथि नहीं दी गयी है । सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहले से ही न्यायाधीन है । हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ-साथ विभाग मुख्य सचिव सहित इस मामले में प्रतिभागी हैं । SLP की सुनवाई के दौरान सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट एवं प्रस्तुत किया जायेगा ।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्य मंत्री महोदय देव परम्परा से और देव संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इन परम्पराओं से भलिभांति परिचित हैं और जो याचिका की यहां बात कही गयी जो रिट-पेटिशन की गयी, एक बात तो स्पष्ट है कि कानून बनाना विधायिका का काम है । उसकी परिधि में रहते हुए निर्णय देना वह अदालत का काम है । लेकिन मैं इस बात पर नहीं जाता । यदि सत्यता है कि इस पेटिशन को डिस्पोज़ ऑफ करती दफा उन्होंने रोक लगायी और

25/1125/03.2015.यूके/एजी/2

वह भी कहां पर? सार्वजनिक स्थलों पर कोई बलि नहीं दी जायेगी ,इस प्रकार की रोक लगी । क्योंकि यह डबल बैंच का निर्णय था, इसलिए यहां उसकी अपील नहीं हो सकती थी, रिव्यू पेटिशन नहीं हो सकती थी । इसलिए न केवल मैं, बल्कि जो कारदार संघ का अध्यक्ष है, अध्यक्ष के रूप में पूरे कारदार संघ ने भी वहां पर याचिका दायर की है । इसमें सरकार को भी पार्टी बनाया गया है, विभाग को भी

पार्टी बनाया गया है । तो मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो सरकार को पार्टी बनाया गया है अभी तक भी सरकार की ओर से उत्तर नहीं आया है, जैसे ही उत्तर आयेगा, इसका निर्णय होगा और यह जो पशु बलि की प्रथा है, आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि न केवल हमारे धर्म में बल्कि यह अन्य धर्मों में भी है और इस निर्णयानुसार केवल और केवल हमारी संस्कृति पर रोक लगी है । इसलिए हम अदालत में गए हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कब तक सरकार इसका उत्तर देगी? क्योंकि जब पार्टी बनाया है, तो जब उत्तर आयेगा तभी इसकी डेट लगेगी । तो मैं यह आपके माध्यम से जानना चाहूंगा ?

Chief Minister: Mr. Speaker, Sir, the matter is sub-judice in the Hon'ble Supreme Court of India. The position of the State Government will be explained and made clear in the Supreme Court. But I must say, Sir, that there are two thoughts. There are two ways of thinking on it. There are one people who say it should be no time to compromise. It is also proved

25/1125/03.2015.यूके/एजी/3

not only in hills, not only among section of Hindus but in other communities also animal sacrifice is done. For example, Bakarid which is celebrated throughout the world the sheep or goats, they are sacrificed in the ceremonies. So, there cannot be order only prohibiting one section and allow the other section.

श्री महेश्वर सिंहः सर, मेरा उत्तर नहीं आया । जो वहां पर हिमाचल सरकार को पार्टी बनाया गया है कब तक उनका उत्तर आ जायेगा?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हम जल्दी सरकार की ओर से उत्तर पेश कर देंगे ।

अध्यक्षः रवि जी, अब काफी हो गया ।

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, जैसे मैने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री को कि उनके बयान अखबारों में लगते हैं । लेकिन ये बोलते हैं कि मैने यह नहीं कहा, अखबारे क्या बोलती हैं, क्या छापती हैं मुझे इसका कुछ पता नहीं है । आप ही वहां पर दशहरे के पर्व पर गए थे । आपने वहां पर कहा है ।

एस0एल0एस 0द्वारा जारी-----

25.03.2015/1130/sls-jt-1

प्रश्न संख्या : 1728... जारी

श्री रविन्द्र सिंह...जारी

आपने वहां पर कहा - 'पशु बलि की मंजूरी के लिए नहीं लाएंगे अध्यादेश'। साथ में यह भी कहा था कि 'रघुनाथ मंदिर को न्यास बनाने पर होगा विचार'। इसी के विरोध में, जो आपका सुबह का नाश्ता था, विरोध के कारण महेश्वर सिंह जी उस नाश्ते में भी नहीं आए थे। उसके बाद माननीय महेश्वर सिंह जी का बयान आया - 'बयानबाजी के बजाये अध्यादेश लाएं'। यह आपको कहा है। आपके बयान कंट्राडिक्टरी हैं। मुख्य मंत्री महोदय, अख़बारों की न्यूज की जैसे मैंने सुबह भी बात उठाई, आपने कहा कि मैं उनके ऊपर डिफेमेशन केस फाइल करूंगा। अख़बारों में आपके बयान छपते हैं और बाद में आप कहते हैं कि ---(व्यवधान)---

मुख्य मंत्री : आप किसके बारे में कह रहे हैं?

श्री रविन्द्र सिंह : आपने जो यह कहा कि 'पशु बलि के बारे में नहीं लाएंगे अध्यादेश' और महेश्वर सिंह जी कह रहे हैं कि 'बयानबाजी के बजाये अध्यादेश लाएं' ,उसके बारे में कह रहा हूं। फिर आपने कहा कि 'रघुनाथ मंदिर को न्यास बनाने पर होगा विचार'।

मुख्य मंत्री : मैंने बताया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है and the Supreme Court has asked the State to state its point of view. We will respond to it. और हम मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे। We will respond to the orders of the Hon'ble Supreme Court.

श्री रविन्द्र सिंह : आपने रघुनाथ मंदिर के लिए न्यास बनाने की बात की है।

मुख्य मंत्री : पशु बलि से रघुनाथ मंदिर का क्या ताल्लुक है? जहां तक न्यास बनाने की बात है, it is under consideration of the Government.

25.03.2015/1130/sls-jt-2

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने भोज का बहिष्कार करने की बात कही, माननीय मुख्य मंत्री जी मंदिर में पधारे थे और वहां इन्होंने अपने श्रद्धा-सुमन भी चढ़ाए। उस समय मैं इनके साथ था। उस दिन वहां यज्ञ था और मैं एक समय ही खाना खा रहा था। यह सही है कि मैं कर्ण जी के निवास स्थान तक इनके साथ गया। आप भी यह जानते हैं कि जब हम उठान करते हैं तो

बार-बार खाना नहीं खाते। इसलिए मैं खा नहीं सकता था। अख़बार क्या लिखती है, वह कोई धर्म सत्य नहीं है। यह मैं अपना स्पष्टीहकरण दे रहा हूं।

Speaker: I think, let us not decide the case. Let the Supreme Court decide the case. माननीय धूमल जी ,आप कुछ बोलना चाहते हैं?

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न के 'ग' भाग में जो उत्तर दिया गया है, वह यह है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। 'क' और 'ख' भाग का आपने उत्तर दिया है लेकिन 'ग' में कह रहे हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मैंने पहली बार विधान सभा या पार्लियामैंट में ऐसा देखा कि किसी क्वैश्चन के तीन पाट्र्स हों; दो पाट्र्स का उत्तर आ जाए लेकिन तीसरे में कहा जाए कि सूचना एकत्रित की जा रही है। यह क्या बात है? पूरे प्रश्न का इकट्ठा जवाब आना चाहिए था।---(व्यवधान)---

मुख्य मंत्री : आप किस प्रश्न की बात कर रहे हैं?

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : आप इसी प्रश्न का 'ग' भाग पढ़िए जिसमें आपने यह लिखा है।

Speaker: They want to collect the relevant papers for the Supreme Court case.

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : नहीं अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के तीन भाग हैं। एक में पूछा गया कि कब तक ये सुप्रीम कोर्ट में अपना रिप्लाई फाईल करेंगे ताकि निर्णय जल्दी हो? ---(व्यवधान)---

25.03.2015/1130/sls-jt-3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 'ग' भाग का उत्तर फील्ड से क्लैक्ट किया जा रहा है , इसलिए यह लिखा है।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के सभी पाट्र्स का उत्तर, वह चाहे दो हों या चार हों, सारा एकत्रित करने के बाद ही दिया जाना चाहिए था। It cannot be replied. जो प्रश्न का भाग अनुत्तरित रह गया, क्या अब आगे वह दोबारा लगेगा?

अध्यक्ष : एक पार्ट का रिप्लाई आ भी सकता है और अन्य पाट्र्स का रिप्लाई दे भी सकते हैं। लेकिन जब पूरे प्रश्न का पूर्ण उत्तर आ जाएगा, तब यह पूरे प्रश्न का जवाब देंगे।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : फिर आप इसके लिए समय निश्चित कीजिए।

प्रश्न समाप्त

25.03.2015/1130/sls-jt-4
प्रश्न संख्या 1729 :

श्री सतपाल सिंह सत्ती : सर, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, मेरा सिम्पल प्रश्न था कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को कितनी बसें मिली हैं। मंत्री महोदय ने अनेकों बार दावे किए हैं कि इतनी बसें आई हैं। वह खुद इन्होंने

चलाई भी हैं और प्रतिदिन कहीं-न-कहीं से विधायक, संबंधित मंत्रीगण या वहां के अन्य जो कार्यकर्ता हैं ..
जारी ..गर्ग जी

25/03/2015/1135/RG/JT/1

प्रश्न सं.1729—क्रमागत

श्री सतपाल सिंह सत्ती------**क्रमागत**
विधायक, संबंधित मंत्रीगण या वहां के इनके जो कार्यकर्ता हैं वे बसों को हरी झण्डी दे रहे हैं ,लेकिन एक छोटी सी सूचना थी जो इसमें नहीं आई है। इसके साथ-साथ मैंने यह भी पूछा था कि जिन रूट परमिट पर बसें चलाई गई हैं जहां-जहां ये बसें हैं क्या वे बसें रोड टैक्स दे रही हैं जो हिमाचल प्रदेश में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत बसें आई हैं जो हमने चलाई हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सारी सूचना इसी सत्र में दे देंगे?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो अभी प्रो. साहब कह रहे थे, तो 'क' भाग की सूचना तो अभी मेरे पास है ,अगर अलग से चाहिए या यहां इनको सूचना चाहिए, तो मैं उपलब्ध करवा दूंगा।' क' भाग की सूचना देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है।' क', 'ख' और 'ग' की तीनों की, जो प्रश्न का तीसरा भाग है ,उसकी सूचना एकत्रित की जाएगी और उसमें समय लगेगा। यह सूचना 5-10 दिन में एकत्र नहीं की जा सकती है। जैसे ही सूचना उपलब्ध होगी, आपको दे देंगे। We don't want to hide anything.

प्रश्न समाप्त
2/-
25/03/2015/1135/RG/JT/2
प्रश्न सं. 1730

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है वह बहुत विस्तृत है। इसमें मैंने वैकेन्सीज पूछी थीं, तो बहुत सारी वैकेन्सीज़ आयुर्वेदिक विभाग में हैं। लेकिन यदि हम सिर्फ ए.एम.ओज़. और फार्मासिस्ट्ज की वैकेन्सीज ही लें, तो लगभग 278 पोस्ट्ज ए.एम.ओज. की खाली हैं और इसमें से भी 50 चम्बा, 50 मण्डी 46 ,शिमला और 30 कुल्लू में खाली हैं। यानि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके सारे डॉक्टर्ज की पोस्ट्ज खाली पड़ी हुई हैं। चम्बा में 103 में से 50 पद डॉक्टर्ज के खाली हैं और इसी तरह से यदि हम फार्मासिस्ट्ज की पोस्ट देखें ,तो 507पद आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट्ज के खाली पड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि हमारे पास ट्रेंड आयुर्वेदिक डॉक्टर्ज और ट्रेंड आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट्ज भी हैं। इन पोस्ट्ज को भरने के लिए क्या उन ट्रेंड लोगों की नियुक्ति की जाएगी?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ महीने पहले ही हमने लगभग 100-150 आयुर्वेदिक डॉक्टर्ज भर्ती किए थे। मैं कहना चाहूंगा कि filling up posts is a continuous process. समय-समय पर हम भर्तियां करते हैं और जो खाली जगह हैं उनको भरने का प्रयास किया जाता है और प्रयास किया जाएगा।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रही हूं कि जो वैकेन्सीज़ हैं वे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा हैं। यदि आप ऊना में देखें, तो एक ही डॉक्टर की पोस्ट खाली है ,लाहौल-स्पिति में तो चार पद डॉक्टर्ज के खाली हैं, हमीरपुर में दो पद खाली हैं ,लेकिन चम्बा, शिमला और मण्डी जिले में 278 में से 150पद सिर्फ तीन जिलों में खाली हैं। तो क्या अब जो आप भर्ती करेंगे ,उन्हें स्पेसिफिक इन जिलों में ही भेजेंगे so that they don't adjust themselves round about Kangra, Hamirpur and Una and go to the backward areas also?

Chief Minister: Hon. Member has raised a very important point because हम जितनी भी भर्तियां करते हैं वे सब आसान जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं , उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं ,डेलीगेशन्ज लाते हैं, political प्रैशर डालते हैं , लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो भी भर्तियां होंगी, पहले उन्हें वहां भेजा जाएगा जहां रिक्त स्थान हैं।

प्रश्न समाप्त

3/-

25/03/2015/1135/RG/JT/3

प्रश्न सं. 1731

अध्यक्ष : श्री महेन्द्र सिंह अनुपस्थिति।

4/-

25/03/2015/1135/RG/JT/4

प्रश्न सं. 1732

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस निजी भूमि का लैण्ड ऐक्वीजीशन का प्रौसेस शुरू हो गया है और दूसरा यह कि क्या इस सेब सीजन में ऑक्शन यार्ड इस भूमि पर लगाया जाएगा?

एम.एस. द्वारा मंत्री महोदय शुरू

25/03/2015/1140/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 1732क्रमागत---

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैसे इसकी प्रक्रिया पहले भी शुरू हुई थी। क्योंकि यह निजी भूमि है तो कुछ लोगों ने उस समय भूमि देने के लिए इन्कार कर दिया था। अब सभी लोग भूमि देने के लिए मान गए हैं और 70 हजार रूपया बिस्वा के हिसाब से उस भूमि को खरीदने का फैसला हुआ है। डी0सी0 शिमला ने विभाग को दिनांक 26 फरवरी, 2015 को सूचना दे दी है और विभाग ने मार्किटिंग बोर्ड को 10 मार्च, 2015 को सूचना दे दी है। अब इस मण्डी का कार्य शुरू किया जाएगा।

प्रश्न समाप्त/

25/03/2015/1140/MS/AG/2

प्रश्न संख्याः 1733

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर मुझे मिला है उससे ऐसा लगता है कि विधायक प्राथमिकता की सड़कों की डी0पी0आर0 बनाने में विभाग द्वारा कोई सकारात्मक कोशिशें नहीं की जा रही हैं। पिछले दो सालों में केवलमात्र तीन डी0पी0आर्ज0 बन करके तैयार हुई हैं। अभी नौ डी0पी0आर्ज0 कई वर्षों से लम्बित पड़ी हैं। यह सुस्ती क्यों है और किस स्तर पर है ,यह मैं जानना चाहता हूं? जिन नौ सड़कों की डी0पी0आर्ज0 अभी भी लम्बित हैं, वे कब तक तैयार हो जाएंगी? मैं मुख्य मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जो लम्बित डी0पी0आर्ज0 हैं उनकी किस स्तर पर मॉनिटरिंग की जाती है?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो डी0पी0आर्ज 0Pending in Sarkaghat Division - year 2008-09 ,वे हैं, -1 चरीघाट-कसमैला-त्रिफालघाट रोड-फॉरैस्ट लैण्ड इन्वोल्वड। -2आबला गलू और सवेली रोड-फॉरैस्ट लैण्ड इन्वोल्वड; एफ0आर0ए0 अवेटिड। They are of 2008-09. Year 2009-10 - लोअर भामला, मलवाणा, हरलाण, खलौट रोड- फॉरैस्ट लैण्ड इन्वोल्वड। 4-मटयारा समैला रोड-FCA submitted for approval.5- Year 2011-12; बदाई-सरोआ-टीकरी नाडगी रोड-प्राइवेट लैण्ड। 6-धटोली- कठियार रोड including bridge - forest violation (FRA awaited). Year 2012-13 - 7. बग्गी खलाण टिकरी, जमन गलू वाया सरोहल रोड including bridge - private land. 8-संगरोह-बाहडू-बटयाहडी-फतेहपुर रोड-Land not available. Year 2013-14 - Metaling & Tarring on Patrighat Cehra Chandesh road - Manuscript for Rs. 416.74 lacs prepared under scrutiny. Total MLA priority works - 32; sanctioned - 20; sanctioned amount - Rs. 4239.55 lacs; balance DPRs - 12; forest involved - 2; private land involved - 4; sanctioned under other programme - 2; and DPRs under preparation - 4. I have given you a detailed reply with regard to the roads in your constituency.

श्री इन्द्र सिंह श्री जे0के द्वारा------

25.03/1145/2015.जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 1733 --जारी-------

श्री इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, एफ.सी.ए. की वजह से दो रोड़ की डी.पी.आर. लम्बित पड़ी है, वह कब तक तैयार हो जाएगी? चार रोड़ की वन विभाग की वजह से डी.पी.आर. लम्बित पड़ी है actually on ground there is no forest. यह विभाग की सुस्ती है जिस वजह से काम नहीं हो रहा है। Serial No. 4 - there is no forest involved. Serial No. 5 - No forest involved. सीरियल नम्बर-1 ये सड़क तो काफी समय से तैयार है और काफी समय से इसमें गाड़ियां आती-जाती हैं। उसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। ये सारे मोटरेबल रोड़ज हैं। लेकिन डी.पी.आर. नहीं बन रही है और इसलिए मैटलिंग का काम नहीं हो रहा है। यह विभाग की सुस्ती के सिवाय और कुछ नहीं है। दो सालों में तीन-चार एक्सियन्ज बदल दिये इस कारण से भी काम में कॉन्टिन्युटि नहीं हो पाती है।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय जो सूचना मैंने दी है और विभाग से जो सूचना आई है वह उसके आधार पर है। मैं यह भी कहता हूं कि our department is taking up with the Forest Department. Yet for private land, MLA will have to talk to the farmer concerned.

Concluded

25.03/1145/2015.जेके/एजी/2

प्रश्न संख्याः 1734

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि नव-निमार्णित सब्जी मण्डी मल्सान की अद्यतन स्थिति क्या है?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसका कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न समाप्त।

25.03/1145/2015.जेके/एजी/3

प्रश्न संख्याः 1735

श्री कर्ण सिंहः अध्यक्ष महोदय,मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस समय बंजार में अग्निकाण्ड हुआ मुख्य मंत्री जी भी वहां मौके पर पधारे थे। वहां पर सारी की सारी समस्याओं को देखते हुए इन्होंने तुरन्त बंजार क्षेत्र के लिए अग्निशमन सेंक्शन किया। लेकिन जो यहां पर लिखित उत्तर आया है इसमें कहा गया है कि वहां पर जो ब्लॉक है और बोर्ड के एक नहीं बल्कि चारों ब्लॉक खाली पड़े हैं। They are lying waste. पहला ब्लॉक चिन्हित् किया गया है for the fire station. मुख्य मंत्री जी के आदेशानुसार वहां पर टीम गई जो वहां पर कमियां पाई गई हैं वे सारी की सारी पूरी कर दी गई हैं। अब वहां पर केवलमात्र स्टाफ की आवश्यकता है। वहां पर तीन गाड़ियां लगनी है और एक गाड़ी का प्रबन्ध हो चुका है। बाकी जो ब्लॉक है वह तो बाद की बात है उनमें चाहे आई.पी.एच. का ऑफिस आएगा लेकिन वह तब खुलेगा जब बोर्ड के लिए आएगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक है, उसमें जो कमियां थी वे पूरी हो गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वहां पर जल्द से जल्द स्टाफ भेजा जाए ताकि यह कार्य शुरू हो सके।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का मैं विस्तृत उत्तर दे चुका हूं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

25.03.2015/1150/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 1735 क्रमागत

मुख्य मंत्री क्रमागतः

<u>मगर फिर भी हमारा प्रयास होगा कि जल्दी-से-जल्दी आपका जो फायर फाइटिंग स्टेशन है, यूनिट है जोकि सरकार द्वारा स्वीकृत है उसको वहां पर चालू किया जाए।</u>

प्रश्न समाप्त

25.03.2015/1150/SS-AG/2
प्रश्न संख्याः 1736

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रदेश में राशन का वितरण करने वाले कुल कितने डिपो होल्डर्ज़ हैं? ज़िलावार उनकी जानकारी दें और इन डिपो होल्डर्ज़ को किस अनुपात में राशन की सप्लाई की जाती है? उपभोक्ताओं को ठीक समय पर सुविधा प्राप्त हो उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और इन डिपो होल्डर्ज़ को कितने प्रतिशत कमीशन पर काम दिया जाता है? उपभोक्ताओं को कोई समस्या न आए, जो इंस्पैक्टरी राज का ज़ोर चल पड़ा है इन सबसे निज़ात दिलाने के लिए क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि इन डिपो होल्डर्ज़ को जो वर्तमान में कमीशन दी जाती है क्या वह पर्याप्त है या उसको बढ़ाने पर भी आप विचार कर सकते हैं?
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने काफी डिटेल्ड जानकारी दी है और जानकारी में एक-एक चीज़ खुले से बताई है। जो इन्होंने कहा है कि ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 राशनकार्डों का जिलावार ब्योरा क्या है, मैं इनको बताना चाहता हूं कि जिला बिलासपुर में ए0पी0एल0 के 55769, बी0पी0एल0 के 1 ,8169चम्बा में 63,230 हैं --(व्यवधान)—

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः मैंने डिपो होल्डर्ज़ के बारे में पूछा है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः वे तकरीबन साढ़े 4 हजार के करीब हैं। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सूचना चाहिए तो मैं वह भी दे दूंगा। तकरीबन साढ़े 4 हजार के करीब हैं। जो आपने दूसरी बात कही, एन0एफ0एस0ए0 आने के डिपो होल्डर्ज़ की कमीशन कम हुई है। सरकार ने फैसला लिया था और माननीय वीरभद्र सिंह जी के इनीशियेटिव पर उनकी कमीशन बढ़ाने का फैसला हुआ था और जल्दी ही इसके बारे में सूचना जारी की जायेगी।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहा था कि अभी तक आप डिपो होल्डर्ज़ को किस अनुपात में राशन देते हैं और यह भी बताएं कि वर्तमान में उनको क्या कमीशन दे रहे हैं और इंस्पैक्टरी राज व बाकी

कामकाज से निज़ात दिलाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? यह जानकारी भी दें।

25.03.2015/1150/SS-AG/3

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें डिपुओं में सामान सामान्य रूप से जाए इसके लिए हमने गाड़ियों के निर्धारित रूट किये हैं। समय निर्धारित किये हैं। पहले उसकी अनाऊंसमैंट की जाती है। पहले उसका चार्टर बनाया हुआ है।

दूसरी बात जो आपने इंस्पैक्टरी राज की कही, हमने हर डिपो पर कम्प्लेंट नम्बर बोर्ड पर लगाए हुए हैं ताकि पारदर्शिता से काम चले। अगर वहां पर किसी को कम्प्लेंट हो, डिपो धारक सहित, तो वह डायरेक्ट कम्प्लेंट रूम में कम्प्लेंट कर सकता है। उसकी कम्प्लेंट पर हम लोग तुरन्त ऐक्शन लेते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि 4800 डिपो हैं और हमने अभी मापदंड भी चेंज किये हैं। और डिपो खोलने की रिक्वैस्ट आ रही है इसलिए मैं कह रहा था कि अपडेट करना पड़ता है। रोज़ के रोज़ उसकी रिक्वैस्ट आ रही हैं। जहां ज़रूरत होगी वहां डिपो खोले जायेंगे और इसमें हमने रिलैक्सेशन दी है। जो पहले था ,उससे ज्यादा उसको दुरूस्त किया है और ट्रांसपेरेंट काम हो। अगर आपके पास किसी इंस्पैक्टर की कम्प्लेंट है तो मुझे अलग से बता दें।
जारी श्रीमती के0एस0

/1155/25.03.2015केएस/जेटी/1
प्रश्न संख्या 1737

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसमें बड़े विस्तार से जिन मंदिरों को निर्माण हेतु पैसा दिया जा रहा है, भाषा एवं संस्कृति विभाग, जिलाधीश या सरकार द्वारा उसकी सारी विस्तृत जानकारी है लेकिन मैंने उन मंदिरों के बारे में भी पूछा था जिनके रख-रखाव के लिए भी पैसा दिया जाता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि मण्डी का

प्रधान देवता राज माधव मंदिर को राजाओं के समय से लेकर पूजा-अर्चना के लिए एक भत्ता दिया जाता था और स्वर्गीय राजा जोगिन्दर सेन के समय में इस मंदिर को और कुछ अन्य मंदिरों को छः या सात हजार रुपये के बीच में राशि दी जाती थी, उसका वितरण होता था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उसके बाद आज भी जो यह दायित्व है वह भाषा एवं संस्कृति विभाग निभा रहा है तो अगर अभी सूचना नहीं है बाद में दे दीजिएगा कि यह जो राज माधव का मंदिर था उसमें कोई रीवाईज़ किया गया या जो राजाओं के समय में दिया जाता था, वही पैसा दिया जाता है? वहां पर स्थिति यह है कि सात दिन में पुजारी एक दिन पूजा करता है। वह कहता है कि मैं लो-पेड हूं मैं रोज़ पूजा नहीं कर सकता और स्नान इत्यादि भी मंदिर में नहीं होते। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या मुख्य मंत्री जी इस सूचना को देंगें?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मैंने इस प्रश्न के उत्तर में दी है उसमें इस मंदिर का जिक्र नहीं है। आपने जो सवाल उठाया है, इस मंदिर के बारे में मैं जानकारी प्राप्त करूंगा और इस बात को सुनिश्चित किया

/1155/25.03.2015केएस/जेटी/2

जाएगा कि वहां पर रोज़ विधि-विधान के मुताबिक पूजा-अर्चना होती रहे।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जिन देवी-देवताओं की भूमि टैंडैंसी एक्ट के अंतर्गत चली गई, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने वहां जो इस प्रकार के मंदिर है मुआफीदार देवताओं के उनके लिए एक रिवोल्विंग फंड का सृजन किया है जिसमें पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस रिवोल्विंग फंड के लिए प्रदेश या जिला स्तर पर कोई समिति बनाई जाए और आयकर विभाग से यह प्रार्थना की जाए कि जो दानी सज्जन उसके लिए पैसा देंगें, उनको आयकर विभाग की ओर से दान दिए गए पैसे पर टैक्स में छूट मिल जाएगी तो इस पैसे में वृद्धि हो सकती है और जिस उद्देश्य से आपने यह रिवोल्विंग फंड किया है ताकि जिन मंदिरों में सिक्योरिटी के लिए सी.सी.टी.वी. कैमराज़ इत्यादि लगाने हो या सुरक्षा की दृष्टि से कुछ करना हो तो

उसमें काम आए तो उस धन में निश्चित तौर पर वृद्धि हो सकती है । तो क्या इस पर विचार करेंगें?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण विषय यहां पर उठाया है। बहुत से मंदिरों की अपनी जागीरें-जमीनें थीं परन्तु भूमि सुधार कानून के अंतर्गत वह मुजारों को चली गई और उसमें जो मुजारे थे वे इन मंदिरों में सेवा करते थे। कोई पुजारी था, कोई पानी लाता था कोई कुछ और काम करता था। उसकी एवज़ में मंदिर की जमीन उनको मिलती थी। भूमि सुधार कानून के अंतर्गत वे लोग जो जमीन के मालिक हो गए उनका नाता मंदिर से टूट गया। कुछ श्रद्धालु हैं जो अभी भी काम

/1155/25.03.2015केएस/जेटी/2

करते हैं मगर अधिकांश कहते हैं कि हम तो जमीन के मालिक बन गए हैं अब हम उसकी एवज़ में मंदिर की सेवा क्यों करे? इसी को ध्यान में रखते हुए कि उनको सरकार की ओर से एन.ओ.सी. मिले, उनका वहां पर धूपबत्ती पूजा-पाठ का नियमित रूप से प्रबन्ध किया जा सके, हमने अपने पिछले कार्यकाल में उसके लिए 10 करोड़ रुपये का एक कोष बनाया था जिसके मुताबिक काम हुआ मगर उसके बाद सरकार बदल गई और वह काम धरा का धरा रह गया, एक मंदिर को भी उसके अंतर्गत कोई राहत नहीं मिली। अब जब दोबारा से हमारी सरकार आई है हमने इसके लिए 5 करोड़ रुपये से यह निधि दोबारा बनाई है। यह मामला चल रहा है । इस वक्त तक 14 केसिज़ आए हैं जिनके ऊपर विचार किया जाएगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

25.3.2015/1200/ag/av/1

मुख्य मंत्री : जारी

अभी तक 14केसिज आए हैं जिनके ऊपर विचार किया जायेगा और फिर फैसला होगा। हम चाहेंगे कि जिनके पास आज मंदिर है, सब कुछ है; मगर आय नहीं है जिसके कारण वे मंदिर में पूजापाठ और दूसरे रख-रखाव के कार्य पूरे नहीं कर पाते। वे जल्दी-से-जल्दी सरकार को लिखकर दें ताकि छानबीन करके उनको भी इस स्कीम में शामिल किया जा सके।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आयकर विभाग से छूट के बारे में प्रश्न पूछा था।

मुख्य मंत्री : वह अलग बात है। You are exempted from income tax, जो इनकम का सर्टिफिकेट देते हैं। जो सरकार से पैसा मिलता है उस पर कोई आयकर नहीं लगता।

(प्रश्नकाल समाप्त)

25.3.2015/1200/ag/av/2

<u>कागजात सभा पटल पर</u>

अध्यक्ष : अब माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री, तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 35 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक लेखा तथा तुलन-पत्र (Balance Sheet), वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 35 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक लेखा तथा तुलन-पत्र (Balance Sheet), वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

25.3.2015/1200/ag/av/3

अध्यक्ष : अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री कुछ दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिलिखत दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

(i) कम्पनी अधिनियम, 195 6की धारा 619(4) के अन्तर्गत ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14; और

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 ।

25.3.2015/1200/ag/av/4

अध्यक्ष : अब माननीय उद्योग मन्त्री कुछ दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

उद्योग मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

(i) हिमाचल प्रदेश **खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड** अधिनियम, 1966 की धारा 27(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2010-1 1 (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) कम्पनी अधिनियम, **195 6की धारा 619(4)** के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-14; और

(iii) कम्पनी अधिनियम, 195 6की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14।

25.3.2015/1200/ag/av/5

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2014-15), समिति का 12वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सकारात्मक गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2014-15), समिति का 12वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सकारात्मक गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

25.3.2015/1200/ag/av/6

अध्यक्ष : अब श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सदस्य, कल्याण समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के कुछ प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति (वर्ष 2014-15) के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः -

(i) समिति का **15वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए संचालित योजनाओं सम्बन्धी गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **16वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति समुदायों के शिक्षा व सामाजिक

सुधार कार्यों में लगे गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता अनुदान योजना की संवीक्षा पर आधारित है तथा **जनजातीय विकास विभाग** से सम्बन्धित है।

अगली समिति का प्रतिवेदन श्री बी.जे.द्वारा जारी

25.03.2015/1205/negi/ag/1

अध्यक्षः अब श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2014-15), समिति का 15वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री राकेश कालियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2014-15), समिति का 15वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति (वर्ष 2014-15) , समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री महेश्वर सिंह :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

(i) समिति का **13वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के द्वितीय मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **14वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 31वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग** से सम्बन्धित है ।

25.03.2015/1205/negi/ag/2

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्षः अब नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, अब श्री रवि ठाकुर जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

Sh. Ravi Thakur: Hon'ble Speaker, Sir, this is to draw your kind attention to helicopter flights which are plying to Lahaul & Spiti this year also like every year for emergencies and patients. I would like to draw attention of the Hon'ble Chief Minister that schedule for helipads announced and fixed a day earlier is changed or does not happen many times due to which the patients of Barring Helipad were brought from 36 kms to and fro on steep mountain terrain by villagers on stature and had to return back twice late in the evening causing problem to the patients and villagers. This has also happened earlier in other times and at other helipads. Also the schedule once given and cancelled is changed next day causing problem as some time the flights are diverted to other areas. Henceforth, the flights cancelled should be repeated next day. It is also requested that the schedule of Lahaul be not kept the day it is plying to Pangi, Ajog etc. as it takes lot of time for chopper to return which causes cancellation of flights to Lahaul as children, old people, and patients reach the helipad walking long distances in heavy snow. Life being the most precious not only to

humans but also to all sentient being priority of airlift be given to patients to avoid any casualty due to the back up.

25.03.2015/1205/negi/ag/3

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जिला लाहौल-स्पिति के अन्तर्गत बारिंग हैलीपैड से हाल ही में उड़ानें रद्द होने के कारण गम्भीर रूप से बीमार तीन मरीजों को ईलाज़ के लिए न ले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

Contd. By AG/Uk...

25032015/1210/UK- AG/1

Chief Minister: Hon'ble Speaker, Sir, the Government of Himachal Pradesh has hired the services of MI-172 helicopter of M/s Pawan Hans Helicopters Limited w.e.f. 01.01.2013 for a term of five years for the use of the State Government including VIP duty, emergency evacuations/relief operations etc.

The winter helicopter services are provided to snowbound tribal areas of Lahaul & Spiti District; Pangi Sub Division of Chamba District; Kinnaur District; and Dodrakwar area of Shimla District as per the requirements and recommendations of the Tribal Development Department and subject to the availability of State helicopter. Such flights generally start from the last week of December when Rohtang Pass is closed and continue till the opening of Pass for vehicular traffic.

During this winter Tribal Flights were started w.e.f. 18.12. 2014 and upto 21.03.2015, 49 sorties to 14 helipads of Lahaul & Spiti District were carried whereby 1360 passengers including 36 patients were evacuated.

The State leased helicopter from M/s Pawan Hans Helicopters Limited was performing the tribal flights till 13.03.2015 where after the same was grounded for long haul service. For emergency evacuation from tribal areas IAF helicopter was requisitioned by the Government thereafter, which carried out sorties on 19.03.2015 and 30.03.2015 to some of the helipads in tribal areas. However, on 21.03.2015 a technical snag developed in IAF helicopter because of which it was withdrawn by the Government of India. Since the State leased helicopter was also out of service, the General Administration Department could not provide any helicopter service. However, viewing the urgency of the matter the department placed a demand on 21.03.2015 requesting Government of India to give a suitable substitute. However, the Government of India has not so far provided any helicopter. General Administration Department is constantly in touch with Government of India on this particular issue.

25032015/1210/UK- AG/2

With regard to sorties to Barring Helipad, on 10.01.2015, 09.02.2015 and 10.03.2015 flights were carried out and 63 passengers including three patients were airlifted.

As per requirement from Tribal Development Department, sortie to Barring Helipad were scheduled on 19.03.2015 and 20.03.2015 through IAF helicopter to evacuate patients/stranded people, but the same could not be matured on technical grounds. Since then the General Administration Department is vigorously pursuing the matter with Government of India to provide a helicopter to evacuate patients and other stranded people.

Mr. Speaker, Sir, I would also like to say that this helicopter service is not a regular tribal schedule service. It is only meant to evacuate

people. It is not a regular service like the airlines to a helipad in a routine. It is only during winter and on other times also whenever there is emergency, it is used in other parts of Himachal also other than tribal area also. Therefore, Government is doing best. I don't want that this matter should not be politicized I would like to tell the Hon'ble Member. Government is as much concerned as anybody to see that the rescue work is taken in time and we have our own helicopter which is grounded for some repairs and they are asked that this repair should be done urgently and helicopter should be sent back so that it can be pressed into service and also in the absence of that, we also asked air force to send a helicopter. It worked for some time and it also developed snag which was withdrawn. We again asked Indian Air Force to send another helicopter. So, we are doing our best and nobody should feel that Government is not concerned about it. Even for State purposes also, nobody has used this helicopter for the last two months. I can say that. This is not a matter of publicity or trying to gain sympathy of the people. People know that this Government is committed to the welfare of tribal's and has not only done

25032015/1210/UK- AG/3

a lot for the development of the area, but has stood by the area at time of crisis. I am sorry if some inconvenience has been caused, but I only have one helicopter which is down and tried to get another helicopter which also got a technical problem and we have asked the Air Force to send another helicopter. As soon it comes, it will be sent to the area which Hon'ble Member desires. Thank you very much, Sir.

Continued by AG in English ....

25.03.2015/1215/sls-ag-1

Speaker: Shri Ravi Thakur, if any clarification is required.

Shri Ravi Thakur: Hon'ble Speaker, Sir, I thank the Hon'ble Chief Mihister for all the efforts being made for the helicopter services for Lahaul & Spiti. The only thing which I want to repeat and would like to bring to the notice of the Chief Minister is that Lahaul is the only area, which is cut off for six months like other places where choppers are plied are cut off for eight-ten-twelve-fifteen days. So, our total flights are cut out. We are not trying to politicize. Maybe other people are trying to politicize and they are giving it to the newspaper and other things. It is a real matter of agony and pain. If you really see the plight of the people there it is an open jail during winter for six months. It is not mandatory for the people to stay there only all the time. I have been repeatedly requesting the Hon'ble Chief Minister time and again, but I fully agree with what the Hon'ble Chief Minister has said and would request him to still keep his blessings and his hand on Lahaul for this matter. Thank you.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इस हैलिकौप्टर सर्विस की सर्दियों में जितनी भी फ्लाईट्स हुई हैं, उनमें से, सारे ट्राईबल एरिया को देखते हुए, 99% फ्लाईट्स सिर्फ़ लाहौल के लिए हुई हैं। इतनी चम्बा के लिए नहीं हुई हैं, पांगी के लिए नहीं हुई हैं और भरमौर के लिए भी नहीं हुई हैं।
समाप्त

25.03.2015/1215/sls-ag-2

अध्यक्ष : अब श्री महेश्वर सिंह जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।
श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व की आपकी अनुमति से मैं नियम-62 के अंतर्गत यहां अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करूं, मैं कुछ तथ्य आपके माध्यम से बागवानी मंत्री महोदया के ध्यान में लाना चाहता हूं।

इसमें कोई दोराय नहीं है कि महोदया न केवल एक प्रोग्रैसिव फार्मर है, बल्कि ऐसे परिवार से संबंध रखती है जिनके पुर्वजों के फलस्वरूप हिमाचल में सेव उत्पादन शुरू हुआ। इसलिए बागवानों की समस्याओं से भली-भांति परिचित है।

महोदय, स्प्रे सीजन फरबरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होकर पूरे मार्च मास में चलता है और स्प्रे ऑयल प्रमुख रूप से हिमाचल में तीन कंपनियां बनाती हैं। एक इंडियन ऑयल है, इसके अतिरिक्त दो कंपनियां और हैं जो इस तेल को तैयार करती हैं। कुल्लू फल उत्पादक संघ एक बहुत जागरूक संघ है। वह इस बात की चिंता करता है कि बागवानों को अच्छी और बढ़िया किसम का इनसैक्टिसाईड, पैस्टिसाईड और ट्री स्प्रे ऑयल उपलब्ध हो। जो पैस्टिसाईड बोर्ड है, अनिवार्य था कि यह कंपनीज उसमें रजिस्टर होतीं। लेकिन वह समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाईं और समाचार-पत्रों में छपा कि इस वर्ष ये कंपनियां तेल का वितरण नहीं करेंगी क्योंकि तेल का उत्पादन नहीं कर पाई हैं। क्योंकि ये समय रहते रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाईं तो फल उत्पादक संघ ने विभाग के ध्यान में यह बात लाई कि इसका अविलंब प्रबंध किया जाए नहीं तो कहीं-न-कहीं से घटिया स्तर का तेल लेना पड़ेगा।

जारी... श्री गर्ग जी

25/03/2015/1220/RG/JT/1

श्री महेश्वर सिंह------क्रमागत

लेकिन उतने में इतनी देर हो चुकी थी कि इन कम्पनियों ने तेल नहीं बनाया। फिर बीच में एक 'मैक्स' कम्पनी आई और तेल की जितनी भी कमी थी उसकी पूर्ति उन्होंने कर दी और आनन-फानन में फल उत्पादकों को उनसे तेल खरीदना पड़ा। अब उसका परिणाम क्या रहेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस चीज की चिन्ता विभाग को समय रहते करनी चाहिए थी। जब यह मैन्डेट्री था कि केन्द्रीय बोर्ड में पंजीकरण करवाना चाहिए था ,तो इस बात की चिन्ता करनी चाहिए थी कि समय रहते इसका पंजीकरण किया जाता और यह समस्या उत्पन्न नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि जहां यह कमी रही है ,उसकी ओर मंत्री महोदया का ध्यान जाएगा और उनके विरूद्ध कार्रवाई करेंगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलती न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी अनुमति से टैक्स्ट पढ़ता हूं कि 'Certifief Tree Spray Oil के मार्केट में उपलब्ध न होने के फलस्वरूप किसानों और बागवानों को हो रही कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।'

अध्यक्ष : माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री इसका उत्तर देंगी।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय श्री महेश्वर सिंह जी ने जो बात कही ,मैं समझती हूं कि इनको बागवानों की बहुत चिन्ता है। आपको ही नहीं वरन् सारे प्रदेश में बागवानों को भी इस बात की चिन्ता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक द्वारा मामले की जो वस्तुस्थिति बताई गई है, वह सही है इसमें कोई शक की बात नहीं है। वर्ष 2014 से Central Insecticide Board under the Insecticide Act, 1968 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप फल पौधों में लगने वाले कीटों व बीमारियों की रोकथाम हेतु मात्र उन्हीं कीटनाशकों की सिफारिश की जा सकती है जोकि Central Insecticide Board के पास पंजीकृत हैं। कीटनाशाकों को Central Insecticide Board के पास पंजीकृत करवाने का दायित्व इनको बनाने वाली फर्मों/कम्पनियों का होता है। लेकिन जैसा माननीय विधायक महोदय जानते हैं और इनको इस मामले की सभी कुछ जानकारी है ,लेकिन मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहती हूं। जहां तक Tree Spray Oil का प्रश्न है इसकी सिफारिश वर्ष 2013 तक सेब में लगने वाले कीटों की रोकथाम हेतु उद्यान विभाग व बागवानी एवं वानिकी

25/03/2015/1220/RG/JT/2

विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन द्वारा संयुक्त रूप से की जाती रही है परन्तु वर्ष 2014 से Tree Spray Oil की सिफारिश करना संभव नहीं है। बहुत कोशिश की जा रही है और इस बारे में बहुत बातचीत भी हुई, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं और इसके लिए कोई तरीका निकालेंगे ,लेकिन मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि क्योंकि इसे बनाने वाली किसी भी फर्म/कम्पनी ने Central Insecticide Board के पास पंजीकरण नहीं करवाया है। Tree Spray Oil बनाने वाली फर्मे/कम्पनियां भारत सरकार के उपक्रम हैं। केवल हम लोग नहीं कर सकते, यह उनके द्वारा किया जाता है। इस पर प्रदेश सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। हम लोग तो प्रैशर डाल रहे हैं, लेकिन वे नहीं मान रहे हैं और मैं समझती हूं कि विभाग द्वारा Tree Spray Oil बनाने वाली कम्पनियों को इस उत्पाद को Insecticide Act, 1968 के अन्तर्गत Central Insecticide Board के पास पंजीकृत करवाने हेतु समय-समय पर अनुरोध किया है ,उनसे बार-बार कहा है फिर भी नहीं हुआ। इस विषय पर उद्यान विभाग द्वारा बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय को भी विकल्प देने के लिए कहा गया है

कि आप भी कोई तरीका निकालें। हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही किसी कम्पनी का Tree Spray Oil पंजीकृत हो जाता है ,तो उसकी सिफारिश विभाग द्वारा संबंधित कीट की रोकथाम हेतु कर दी जाएगी। हमें भी इस बात की चिन्ता है कि यह बागवानों के लिए बहुत जरूरी चीज है चाहे वह छोटा या बड़ा बागवान हो, यह सभी के लिए जरूरी है। आप तो इस बात को जानते हैं। लेकिन इस विषय पर प्रदेश सरकार द्वारा उचित प्रयास किए जा रहे हैं। शायद आपके साथ इस विषय पर मेरी बातचीत भी हुई थी ,लेकिन आपने शायद उस समय अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया कि हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी
25/03/2015/1225/MS/JT/1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जारी----------

इस विषय पर प्रदेश सरकार द्वारा उचित प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि यह मामला केन्द्रीय पैट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय से उठाया गया है। हमने केन्द्रीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र जी को इस बारे में पत्र भी भेजा है कि हमारे बागवानों के बारे में कुछ किया जाए। उन्होंने उस पत्र पर कोई खास गौर नहीं किया है। The department of Horticulture has been regularly pursuing this matter with the Hon. Union Minister. ऑयल कम्पनीज ने जो सेंट्रल इन्सैक्टिसाइड बोर्ड हैं ,लास्ट दो साल हो गए हैं and the matter has already been taken up with the Union Petroleum Minister. Let us not worry about that part. We have done our best and will still do our best. But the only thing is कि हम लोग जो बागवान हैं ,हमारे पास अभी भी स्प्रे ऑयल आ रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि वे फंस जाएंगे। वे स्प्रे ऑयल ला रहे हैं और दे रहे हैं। स्प्रे ऑयल लग रहा है। सभी बागवान लगा रहे हैं। आप चिन्ता मत कीजिए। आप मत घबराइए कि अब क्या होगा। अगर केन्द्रीय मंत्री इस बारे में कुछ नहीं कर सकते तो हम इसके लिए कोई तरीका निकाल रहे हैं ताकि सबका काम हो। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि जो हमारी यह बात हुई है उसको लेकर केन्द्रीय पैट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री के पास हम फिर भी जाएंगे। फिर भी यदि वे कुछ नहीं करेंगे तो हम आपको कह रहे हैं कि इसके लिए कोई और तरीका/फॉर्मूला निकालेंगे। हम चाहे

बाहर से इस तरीके/फॉर्मूला को मंगवाकर लाएंगे। मैं आपको बता दूं कि बागवान अभी भी स्प्रे ऑयल कर रहे हैं। इसलिए चिन्ता मत कीजिए। धन्यवाद।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बड़ा ही विस्तृत उत्तर दिया है और उसके लिए मैं इनके प्रति आपके माध्यम से आभार भी व्यक्त करता हूं। लेकिन एक चिन्ता का विषय है कि जो यह इंडियन ऑयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम और भारत पैट्रोलियम है, ये तीनों रिप्यूटिड कम्पनीज हैं। इनको भी तो आय का यह स्त्रोत है। कौन सा कारण है कि ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं और इस कारण को जानने की चेष्टा क्या विभाग ने की ताकि उस स्थिति में उनकी मदद हो ? जैसा आपने विकल्प के बारे में कहा तो निश्चित रूप से विकल्प तो ढूंढना ही चाहिए लेकिन जो

25/03/2015/1225/MS/JT/2

आप कह रहे हैं कि चिन्ता मत कीजिए, इधर-उधर से तेल आ रहा है उसकी गुणवत्ता की क्या गारंटी है? कहीं लेने के देने न पड़ जाए। अभी तो सही किया जो भी किया लेकिन भविष्य में ऐसा न हो क्योंकि इन्सैक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का भी तो इसी बोर्ड से लाइसैंस लाएंगे। अगर इस प्रकार से दुकानें खोलकर लोग घटिया सामान बेचना शुरू करेंगे तो उसको कैसे रोका जाएगा?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं दुबारा यह कह रही हूं कि कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्रचार हम सब जगह नहीं कर सकते और न करना चाहिए। जो आज की स्थिति है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूं कि किसी तरीके से लोगों को बचाने के लिए स्प्रे ऑयल आ रहा है, जा रहा है और इस्तेमाल हो रहा है। हम सबका नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि फिर उसमें कई दिक्कतें आती हैं। मैं आपको इतना विश्वस दिलाती हूं कि इस वर्ष तो कम से कम स्प्रे ऑयल इस्तेमाल में रहेगा। हमारे बागवानों को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए आप शांति रखिए और इसके लिए हम कोई न कोई इंतजाम करेंगे ,वह भी पक्के तौर से। वैसे अभी भी हो रहा है। जो ऑयल कम्पनीज हैं वे भी चाह रही हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करे, न करे या कर रहे हैं। इसके बारे में सब सोच रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ प्रैशर केन्द्रीय मंत्री के ऊपर भी डालना पड़ेगा। ट्री स्प्रे ऑयल तो स्मॉल पार्ट है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते है कि शुरू से ही हमारे बागवान जानते हैं कि उस ऑयल को कैसे मिक्स

करना है। उस ऑयल को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में आप तब जानेंगे यदि आप हमारे बागीचों में आए ,तब आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम इस स्प्रे ऑयल को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका इंट्रस्ट हमें देखना है। यह हमारे बागवानों के लिए बहुत जरूरी है। बाकी मैंने ईमानदारी से आपको सच्ची बात कह दी है। हम सब बातों का प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि प्रचार करना हमारे लिए सही नहीं होगा।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष जी, जो ये रिप्यूटिड कम्पनीज हैं इनको भी तो यह आय का स्त्रोत है। क्या इन कारणों को जानने की विभाग ने चेष्टा की है कि कौन सा कारण है कि ये रजिस्ट्रेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं?

25/03/2015/1225/MS/JT/3

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः मैंने सबसे पहले यही कहा कि उन्होंने कुछ प्वाइंट्स के बारे में कहा है कि ये चीज हम नहीं लगाने देंगे।

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

25.03/1230/2015.जेके/जेटी/1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः-----**जारी**----
कि ये चीज़ हम नहीं लगाने देंगे। जब उन्होंने कह दिया कि इस सिस्टम को नहीं करने देंगे, जिस तरह से वे चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि बागवान और जो कम्पनीज़ वाले हैं उन चीजों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि किस चीज को हम अवाईड करेंगे और अगर अवाईड नहीं होता है तो उसको हम चलाएंगे। अभी भी आप अगर देखेंगे सब बागवान स्प्रे करने लगे हैं। कोई घबराहट नहीं है। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, उसको हम करेंगे। हमारी सरकार इस बात को ध्यान से देखेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम खुद भी बागवान है इसलिए हमें भी अपनी हिम्मत का पता है कि कैसे हम औरों को बचाएं और खुद भी बचें। धन्यवाद।

25.03/1230/2015.जेके/जेटी/2

अध्यक्षः अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लॉयमैंट गारंटी एक्ट के बारे में वक्त्वय देंगे।

Rural Development and Panchayati Raj Minister: Hon'ble Speaker, Sir, I would like to inform this august House that a meeting of the Empowered Committee under the chairmanship of Secretary (RD) to the Government of India was held on 20.3.2015 at New Delhi to approve the Mahatma Gandhi NREGA labour budget of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2015-16. The proposal of labour budget was put forth strongly by the Department and all queries raised by the Ministry were addressed. Thereafter, the presentation on the labour budget was made by the Department. After going through the presentation made by the Department of Rural Development, the Ministry of Rural Development, Government of India approved the labour budget of generation of 251.81 lakh person days for 2015-16 in respect of Himachal Pradesh. The monetary value of labour budget comes to Rs. 692.33 crore, out of which Rs. 627.02 crore wil be the Central share. This amount is on the prevailing wage rate of Rs. 154/- for non -tribal areas and Rs. 192/- for tribal areas. However, the State will get more money after the hike in wages which will come into effect from 1.4.2015. Besides this, the Government of India has also agreed to provide additional funds to liquidate the approximate liabilities of Rs. 90 crore likely to be created during current financial year. Thus, the State Government will get approximately Rs. 717.02 crore from Government of India during the year 2015-16 at the current wage rate.

25.03/1230/2015.जेके/जेटी/3

During the year 2013-14, labour budget amounting to Rs. 671.69 crore was approved by Government of India out of which Rs. 551.48 crore

was the Central share (after adjusting opening balance as on 1.4.2013) against which Rs. 477.97 crore were released by Government of India.

For the current financial hear i.e. 2014-15, labour budget amounting to Rs. 761.71 crore was approved by Government of India out of which Rs. 670.71 crore was the Central share which was further reduced to Rs. 355.43 crore and this entire amount has been received from Government of India.

Thus, there is an increase of 76 per cent in the labour budget for 2015-16 in comparison to the 2014-15.

Since the planning exercise has been done at the Gram Panchayat level for the preparation of labour budget, this time the Government of India has made the Gram Panchayat-wise and month-wise agreed labour budget available on the nregasoft. This labour budget will be printed from the nregasoft and handed over to the Pradhan of the concerned Gram Panchayat so that each Gram Panchayat could know the agreed labour budget for 2015-16.

Thank you, Sir.

(Concluded)

Contd...ss..

25.03.2015/1235/SS-JT/1

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों पर चर्चा

अध्यक्षः अब बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2015-16 पर सामान्य चर्चा आरम्भ होगी। माननीय सदन की सूचना के लिए मैं बता सकता हूं कि माननीय सदस्यों की जो सूची मेरे पास आई है उसमें 25 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि आप समय-सीमा के अंदर रहें और दस-दस मिनट में अपनी बात रखें। जैसा आप चाहेंगे वक्त को मैनेज किया जा सकता है। फिर भी आप संक्षेप में बोलें। रैपीटिशन न

हो तो अच्छा रहेगा। एक सदस्य जो बात बोल चुका है दूसरा वही बात न करे। रिपीट न करें। अब मैं ठाकुर रविन्द्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वे बजट पर बोलें।

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा, जिनके पास प्रदेश का वित्त विभाग भी है 18 ,मार्च, 2015 को इस माननीय सदन में वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान प्रस्तुत किये गए। जैसा कि इससे पहले बड़ी चर्चा थी कि 18 मार्च, 18 तारीख और 18वां बजट है। पता नहीं, क्या नया कुछ करने वाले हैं। फिर भी मैं माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने बतौर वित्त मंत्री अपना 18वां बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया। बाकी सदस्य चाहे पक्ष या विपक्ष के हों वे लगातार इस पर बोले। पिछले कल तक मेरा इस पर बोलने का मन नहीं था। लेकिन पिछले कल ही अपने दल की ओर से मुझे आदेश हुआ कि आपको इस पर बोलना है। इसलिए मैंने पिछले कल से इस बजट को देखना शुरू किया। इस सारे बजट भाषण में छोटे-बड़े 193पैराज़ हैं और कुल मिलाकर 79 पृष्ठ हैं। मुख्य मंत्री महोदय ने उन्हीं पुरानी योजनाओं को तोड़-मरोड़कर पेश करके प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है। इससे पहले कि मैं इस बजट पर आऊं, अभी हाल ही में जो आपने आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2014-15 का दिया है ,मैं उस पर बोलना चाहता हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने लगातार केन्द्र सरकार की आलोचना की कि हमारा योजना आयोग का आकार कम कर दिया। ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। यह मिलेगा नहीं। यह 90:10 की रेशो काट दी। ऐसा कोई दस्तावेज़ आपके पास नहीं है। अगर होता तो मुख्य मंत्री महोदय को इस माननीय सदन में प्रस्तुत करना चाहिए था। सभापटल पर रखना चाहिए था। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। लेकिन आपने ही जब यह आर्थिक सर्वेक्षण इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया तो पहले ही पेज़ पर खुद माना है कि अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हुई है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर जो पहला पैरा पहले पेज़ का है उसमें आपने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2014-15 में

25.03.2015/1235/SS-JT/2

पुनर्जीवित हुई है। जबकि पिछले वर्षों में आंतरिक संरचनाओं एवं बाहरी तथ्यों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में ठहराव महसूस किया गया था। ये आर्थिक ठहराव खास कर औद्योगिक क्षेत्र पर प्रभावित रहा। यद्यपि इन वर्षों में मुद्रास्पिति कम हुई परन्तु फिर भी एक सहनीय सीमा से ऊपर नहीं गया। ये आपने खुद माना है कि केन्द्र में जो वर्तमान सरकार आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विराजमान है, एक

नई सोच के साथ एक नये स्वरूप में पूरे देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। पुराने ढर्रे को बदलते हुए एक नीति आयोग बनाने का फैसला किया, जिसके माननीय मुख्य मंत्री महोदय सदस्य हैं। आप मीटिंग्ज़ में गए भी हैं। आपने वहां पर देखा भी होगा और जांचा भी होगा कि सोच बदलने की आवश्यकता है।
जारी श्रीमती के0एस0

/1240/25.03.2015केएस/एजी1/

श्री रविन्द्र सिंह जारी--
कि सोच बदलने की आवश्यकता है। मा0 प्रधानमंत्री जी लगातार कई वर्षों तक गुजरात राज्य के मुख्य मंत्री के पद पर रहे और उन्होंने जो वस्तुस्थिति खुद मुख्य मंत्री के तौर पर देखी व झेली, जो राज्यों को वहां पर कष्ट होता है, वहां पर उनकी बातें सुनी नहीं जाती, उसी को ध्यान में रखते हुए जब उनके पास इस देश की बागडोर आई तो इन्होंने एक नया आयोग बनाने का निर्णय लिया और उसको नीति आयोग का नाम दिया। मुख्य मंत्री महोदय, नीति आयोग के तहत आपको भी बड़ा दिल करना चाहिए था । आपने 18वां बजट पेश किया। आपके मैं दस्तावेज़ देख रहा था कई वर्षों से, आप इसमें इस बार नई नीति ले कर आते। आपकी केन्द्र के साथ, वित्त मंत्री जी के साथ, प्रधान मंत्री जी के साथ लगातार मीटिंग हो रही थी । आपको चाहिए था कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, प्रदेश के हर क्षेत्र की जानकारी आपको है और जो भी मुख्य मंत्री रहते हैं उनको होती है ।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री होने के नाते मैं नीति आयोग का स्वयं भी सदस्य हूं। इस पर चर्चा हुई है मगर एक स्पैसिफिक चर्चा नहीं हुई है। हमने अपना पक्ष नीति आयोग के सामने नहीं प्रधान मंत्री जी के सामने मौखिक और लिखित रूप में विस्तार में रखा है। मुझे उम्मीद है कि वे उस पर गौर करेंगें और एक अच्छा निर्णय उसमें निकलेगा।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि मुख्य मंत्री जी ने बाद में इसका जवाब देना है। हमारे समय की सीमा बांधे या तो अध्यक्ष महोदय हमारा समय बीच में नोट करते रहें ।

/1240/25.03.2015केएस/एजी2/

अध्यक्ष महोदय, हमने अच्छे सुझाव देने हैं। अच्छे सुझाव सभी अधिकारी भी नोट करें और कृपया मुख्य मंत्री जी आप भी उन पर ध्यान दें तो मैं जो कह रहा था कि नीति आयोग जो बना उसी नीति को, जैसे मैंने कहा कि हर क्षेत्र की आपको जानकारी है, परन्तु जब आप प्लानिंग की मीटिंग करते हैं, हर वर्ष होती है। पूर्व में हमारे समय में भी होती रही है। उसमें योजना आयोग था जब यह संस्था ही बदल दी गई तो आप भी उसी संस्था के अनुसार प्रदेश के विकास के लिए एक नई सोच पैदा करते हालांकि आपने बीच में किया थोड़ा सा लेकिन आप हर क्षेत्र के लिए जो नीति, जैसे केन्द्र ने राज्य के ऊपर छोड़ दिया कि आप अपनी नीति अपने तौर पर बनाकर लाओ अपनी योजना बनाकर लाओ, हमने आपको पैसा देना है, आप उन योजनाओं को जैसे अपने प्रदेश में लागू करना चाहते हैं, उसी ढंग से लागू करिए। उसी ढंग से प्रदेश में आप भी सभी माननीय विधायकों के क्षेत्रों में उस विधायक के ऊपर छोड़ देते कि नीति आयोग ने यह फैसला किया है और इतना पैसा आपके विधान सभा क्षेत्र को दे दिया और जो आपने एक प्लान साईज़ यहां पर बनाया, उसी ढंग से काम होता तो सभी माननीय विधायकों को काम करने में आसानी होती क्योंकि अपने-अपने क्षेत्र की तकलीफों, वहां के विकास, वहां की योजनाओं का कुछ सामाजिक जो आपने काम करने हैं उनको छोड़कर विकास के कार्य, चाहे लोक निर्माण का विभाग है, आई.पी.एच. है या रूरल डिपार्टमैंट है, ऐसे जो विभाग है जो मूल रूप से जनता के विकास के काम में अग्रणी

/1240/25.03.2015केएस/एजी3/

रहते हैं, उनको आपने एक पैकेज़ के तौर पर अगर विधान सभा क्षेत्रों को दिया होता तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर प्रदेश में एक अच्छा वातावरण तैयार होता लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।

यहां पर जो आपने बातें कही हैं कि आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप आपने 22,800 करोड़ रु0 का यहां पर रखा है। जबकि योजना का आपका प्रारूप जो है वह वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए रहेगा आपने कुल घाटा जो 2015में रहने वाला है वह 1200.41 करोड़ बताया है। इसकी जिम्मेवारी आप देंगें तो किसको देंगें? माननीय

मुख्य मंत्री जी, आपने इस प्रदेश में पहला बजट 1984-85 में पेश किया था। मैं लगातार प्रयास में रहता हूं कि आपको यह हर साल याद करवाता रहूं, मैं तथ्य यहां पर ले कर आया है। आपने जो उस समय यहां पर बजट पेश किया था आपने उस समय कहा था जो हमारा 9वां वित्तायोग यहां पर आया था, यहां पर कई माननीय सदस्य नए हैं, कइयों को यह जानकारी नहीं होगी, उस समय प्रदेश के आर्थिक स्थिति हमारी क्या है, कोई सही आंकड़े वहां पर पेश नहीं कर पाए। यह सारा रिकॉर्ड इस माननीय विधान सभा में मौजूद है। आपने कहा था कि 1988-89 के संशोधित अनुमानों में बजट सम्बन्धी 15.37 करोड़ रु0 के घाटे के मुकाबले में 10 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया गया है। और आपने यह कहा कि

श्रीमती अ0व0 द्वारा--

25.3.2015/1245/jt/av/1

श्री रविन्द्र सिंह : जारी--------

और आपने यह कहा कि प्रारम्भिक घाटे 10 करोड़ से आरम्भ होगा और आगे आपने इस प्रकार अंत घाटा 1.21 ; प्रत्येक को शामिल करते हुए कुल 10 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया। उसके बाद श्री शांता कुमार जी मुख्य मंत्री बने। उन्होंने यहां 11 मई, 1990 में बजट पेश किया और यहां पर महालेखाकार की रिपोर्ट पढ़ी गई। उन्होंने उस समय यहां पर कहा था कि मैं माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मैं बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति की विरासत का जो जिक्र किया है जिसका जिक्र अंतरिम बजट पेश करते समय भी किया गया था, वह किसी राजनीतिक वैमनस्य की भावना से प्रेरित होकर नहीं किया गया अपितु इस विश्वास के साथ किया गया है क्योंकि जनता को विश्वास में रखने के लिए यह आवश्यक है। तथ्य चाहे कितने भी कड़वे क्यों न हो उनको जनता से छुपाया नहीं जाना चाहिए। उन पर पर्दा डालने के झूठे सब्ज-बाग नहीं दिखाए जाने चाहिए। वर्ष 1988-89 में महालेखाकार द्वारा स्थापित आंकड़े यह पुष्टि करते हैं कि उस समय जो घाटा था वह 10 करोड़ रुपये नहीं था बल्कि अंतिम घाटा 112.92 करोड़ रुपये था। जिनको आपके द्वारा इन कागजातों में/ आर्थिकी में छिपाया गया। उसके बाद वर्ष 1990-91 का घाटा आगे पहुंचकर 289.79 करोड़ रुपये हो गया। परंतु आगे चलते-चलते; उसके लिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मगर बीच में आपकी सरकार दोबारा से बनी। आगे जब आपकी सरकार बनी तो आपने चरणबद्ध तरीके से बजट पेश किया और फिर सारे-का-सारा दोष

पिछली सरकार के सिर मढ़ दिया। आपने यह कहा कि तत्कालीन मुख्य मंत्री ने उन्नति व विकास की सही नीतियां अपनाने की बजाय राज्य में वित्तीय स्थिति के बारे में भयपूर्ण वातावरण पैदा कर दिया। राज्य की अधिकांश जनता को इस बात की चिन्ता/भय सताने लगा कि प्रदेश का विकास अब असम्भव है। मैं इस माननीय सदन में पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि हमारी वित्तीय स्थिति बिगड़ने का कारण 9वें वित्तायोग; आपने खुद माना है। आपने माना है कि 9वें वित्तायोग द्वारा हमारी प्राप्तियां और व्यय का गलत आकलन करना रहा है। यह आपने अपने 17 मार्च, 1994 को दिए गए भाषण में माना है। मगर आपने

25.3.2015/1245/jt/av/2

सारे-का-सारा यह कहा कि इसके लिए पिछली सरकार ही दोषी थी, आपने इसमें कहा है। मगर मूल रूप से इस प्रदेश में आर्थिक संकट उस समय पैदा हुआ यानि कर्ज लेने की रिवायत उस समय पैदा हुई जब आप बतौर प्रदेश के मुख्य मंत्री यहां पर आए। उससे पहले प्रदेश न तो कभी आर्थिक संकट में था और न ही यहां कर्ज लेने की रिवायत थी। वर्ष 1983 के बाद जब प्रदेश जाल में फंसा तो उसके बाद इस प्रदेश की सारी-की-सारी आर्थिक स्थिति बिगड़नी शुरु हुई। मुख्य मंत्री जी, चाहिए तो यह था कि आप इससे आगे चलने से पहले नई नीतियां और नई दिशा लेकर आते। मगर आपने लगातार प्रयास किया कि सत्ता का सुख भोगो, काम हो या न हो। विकास हो या न हो। जैसे-तैसे सरकार बनती रहे, चलती रहे और काम चलते रहे। उसके उपरांत जब माननीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी यहां मुख्य मंत्री बने तो 3 जुलाई, 1998 को इनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। यहां पर प्रदेश को नई दिशा, नई दृष्टि और नई सोच देने वाला बजट प्रस्तुत किया गया। जो उस समय प्रदेश की 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1996-97 के मूल्यों पर आधारित था। उस समय 5700 करोड़ रुपये का निवेश स्वीकृत किया गया था। उस साल आपका योजना आकार 1008 करोड़ रुपये का था। उसकी तुलना में वर्ष 1998-99 में जो सरकार बनी और माननीय मुख्य मंत्री श्री धूमल जी अपना बजट पेश कर रहे थे तो इस आकार को बढ़ाकर 1425 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया। हमने 43 प्रतिशत के ऊपर लगभग 1600 करोड़ रुपये एक साल का प्रस्तावित किया। हमने उस समय बहुत बड़ी छलांग लगाई थी और उसके बाद हमने कोशिश की है। मेरे पास यहां आपका ही डाक्युमैंट है। यहां पर कब-कब और कितना-कितना कर्ज लिया गया तथा किस के समय में

लिया गया, मुख्य मंत्री जी, मैं यह भी आपके समक्ष रखना चाहूंगा। वर्ष 2002-03में जब हम सरकार छोड़ कर गये थे तो उस समय इस प्रदेश में ऋण 13209.47 करोड़ रुपये था। आपके द्वारा अगले पांच वर्ष में यानि वर्ष 2003 से लेकर 2007-08 तक 8032.37 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया। मुझे लगता है कि शायद उसकी जो गारंटियां देते हैं इसके बीच में है या नहीं है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हो सकता है कि होंगी भी या नहीं भी होंगी।---

श्री बी.जे.द्वारा जारी

25.03.2015/1250/negi/ag/1

श्री रविन्द्र सिंह ..जारी...

लेकिन इतना आपने लिया। जब हमारी सरकार बनी, वर्ष 2007-08 से लेकर 2012-13 तक यानि दिसम्बर, 2012 तक हमने कुल 5292.23 करोड़ रूपये ऋण लिया। जैसे ही आपकी सरकार आई, उसके बाद आज की स्थिति क्या है? आज प्रदेश 35 हजार करोड़ रूपये के ऋण के नीचे दब चुका है। आपकी सरकार को ढ़ाई साल हुए और मुझे लगता है कि साढ़े 8 हजार करोड़ रूपये से ऊपर का ऋण आप अभी तक ले चुके हैं। यहां पर भाई रणधीर ने कहा कि आप तनख्वाह देने के लिए क्या-क्या हथकंडे अपना रहे हैं। आपने डी.सीज़ को कह दिया, ब्लॉक्स को कह दिया और उन्होंने सारे के सारे पैसे वापिस किए। ये तथ्यों सहित सभी ने कहा है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय आपने ऐसी स्थिति यहां पर बनायी है। इसलिए आपका जो यह बजट है, मैं नहीं मानता कि यह इस प्रदेश को किसी भी दिशा में आगे ले करके जाएगा। जैसे मैंने कहा कि हमारे पूर्व मुख्य मंत्री प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक नई योजना, एक नई सोच पैदा करने की कोशिश की थी । ऐसा हम भी चाहते थे आपसे कि आप भी ऐसा करते। इन्होंने यहां पर 2020 की परिकल्पना की थी। 9 मार्च, 1999 को यहां पर जो बजट भाषण दिया गया था उसमें इन्होंने इस मान्य सदन में कहा था कि कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद हमारी गठबन्धन सरकार अवरूद्धों को समाप्त करने की दिशा में प्रयासशील है। प्रदेश को आत्म निर्भर बनाने में ग्रामीण कृषि अर्थ-व्यवस्था में छोटे-छोटे किसानों के आय स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने वर्ष 2020 तक प्रदेश के विकास की परिकल्पना की है जिसके अन्तर्गत आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं में निम्न विषयों की पूर्ति के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएंगे। कार्यक्रम क्या होंगे, वो

इसमें लिखे हैं। वर्ष 2020 तक हिमाचल प्रदेश आर्थिक दृष्टि से देश के सर्वोत्तम विकसित 5 प्रदेशों में एक हो। वर्ष 2020 तक 15 हजार मैगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की स्थापना । फल उत्पादन 4 लाख टन से बढ़ा कर 12.5 लाख टन करना। सब्जी उत्पादन 4 लाख टन से बढ़ा कर 10 लाख टन करना । सिंचाई की एक लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षमता स्थापित करना। 5 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर

25.03.2015/1250/negi/ag/2

वनीकरण करना। सभी संभव गांवों को सड़कों के साथ जोड़ना । पर्यटन में स्वदेशी पर्यटकों की संख्या 38 लाख से बढ़ा कर 80 लाख करना और विदेशी पर्यटकों की संख्या 60 हजार से बढ़ा कर 5 लाख करना। ऐसे वांछित अद्योसंरचना, नई सोच पैदा करने की कोशिश की है। अब मैं एक-एक के ऊपर आऊंगा। आप देखें, हिमाचल प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से देश के सर्वोत्तम विकसित 5 राज्यों में आगे ले जाना। आप देखेंगे,आपका जो यह भाषण है, इस सारे के सारे भाषण में जो सारी योजनाएं हैं, आप एक-एक योजना को पढ़ लें । मातृ शक्ति योजना को आपने नाम दिया महिला शक्ति योजना।

अध्यक्षः रवि जी समय हो गया है।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो 10 परसेन्ट भी नही हुआ है । अभी तो शुरूआत हुई है। मैं तो सुझाव दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए पॉलीहाऊस का निर्माण करना । पंडित दीन दयाल किसान-बागवान समृद्धि योजना । मैं शॉर्ट में चर्चा करूंगा और डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसके साथ, हमने वायदा किया था कि पर्यटकों की संख्या हम निश्चित तौर पर बढ़ा कर 5 लाख करेंगे। हमें इस बात की खुशी है कि वर्ष 2010-11 में विदेशी पर्यटक हमने 5 लाख पूरे किये और वर्ष 2012-13 में 4 लाख 84 हजार विदेशी पर्यटक यहां पर आए। जो हमने डॉकुमैन्ट तैयार किया था, मुझे याद है कि मेरे एक भाई बिजली बोर्ड में चीफ इंजीनियर रहे थे, वह सिविल साइड से थे। उनको पुर्तगाल का दौरा करने का मौका मिला। पुर्तगाल का आपको पता होगा। पुर्तगाल या कोई और छोटा सा देश होगा वहां पर 12 महीने बर्फ रहती है। 1952 में उस देश को पहली बार आजादी मिली । उस समय जो सरकार बनी उसने एक नीति बनाई कि हम क्या काम कर सकते हैं।

क्योंकि वहां पर फसल कोई होती नही है और पैदावार कुछ नही है । हम अपने देश में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं? उन्होंने वहां पर विद्युत पैदा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया। बाद में सरकारें बदलती रही ।

25.03.2015/1250/negi/ag/3

क्योंकि सरकारों का समय था और वे एक बार, दो बार , तीन बार बदलती रही लेकिन उस कमेटी को बदला नहीं। कमेटी बदली नहीं चाहे लगातार कोई सरकार आती रही। जो उस सरकार ने नीति बनाई थी, जो योजना पहली सरकार ने बनाई थी, बाद की सरकारें उस योजना को आगे अमली-जामा पहनाते रहे । आज पूरे पश्चिमी देशों को वो जो छोटा सा देश है...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

25/1255/03.2015.यूके/जेटी/1

श्री रविन्द्र सिंह--जारी---
आज वह छोटा सा देश पूरे पश्चिमी देशों को बिजली सर्व करने में सबसे अग्रणी देश बन कर आगे आया है । ऐसी योजना होनी चाहिए । यह नहीं कि धूमल जी ने कोई योजना बनाई तो उसको बन्द कर दो, स्कूलों और कॉलेजों को बन्द कर दो, ये ऐसे कर दो, ये वैसे कर दो । मुख्य मंत्री जी, यह अच्छी बातें नहीं है । खमली का मेरा प्लस टू का स्कूल बन्द कर दिया।

मुख्य मंत्रीः हमने कहा है, एक कॉलेज इनका है, वह कॉलेज जिस जगह पर है वह सारे इलाके को सर्व नहीं कर सकता, इसलिए हमें यह करना पड़ा । बाकी सारे कॉलेज बहाल हो गए हैं ।

श्री रविन्द्र सिंहः सर, इसकी नोटिफिकेशन है । आप ऐसे मत बोला करो । मुख्य मंत्री महोदय, मेरा यह कहना है कि हमारे खोले हुए जो कॉलेज और संस्थान है, उनका बन्द करना यह अच्छी बात नहीं है, आपके लिए । जैसे मैने पयर्टन

मुख्य मंत्री : सारे कॉलेज खोल दिए हैं except one. That college in my humble view, I can give you facts, does not serve the entire population.

श्री रविन्द्र सिंहः सर, उसमें बड़ा दिल करके एक लाईन लिखनी है, वह करना था, मुख्य मंत्री जी, बड़ा दिल करते हुए एक खोल देना था आपने। पूर्व की सरकार ने

मुख्य मंत्रीः आपने देखा कि जब इलैक्शन नज़दीक आ गए हैं तो कॉलेज खोल दिया, किसी स्कूल के कमरे में, कोई डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक आफिसर के

25/1255/03.2015.यूके/जेटी/2

कमरे में और एक प्रिंसीपल बैठा दिया ,एक चपरासी बैठा दिया और उस पर कॉलेज का फट्टा लगा दिया । यह कोई बात है? (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंहः चलो मुख्य मंत्री महोदय, आपको इतना तैश नहीं खाना चाहिए। आप हमारी बातें सुनने की क्षमता रखिए। हम तथ्य आपके सामने पेश कर रहे हैं।

मुख्य मंत्री : मैं नहीं चाहता कि आप जैसे अच्छे और सुलझे हुए व्यक्ति के मुख से कोई गलत बात निकले।

श्री रविन्द्र सिंहः सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पयर्टक को बढ़ावा देने के लिए क्यों कि जो बिन्दु यहां पर बजट में दिखाए गए हैं, मैं किताबों में नहीं जाऊंगा क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, बार-बार कह रहे हैं। इसमे बिन्दु पयर्टन को बढ़ावा देने के लिए, आपने इसमें लिखा नहीं है। आपने विद्युत लगायी है और 3-4 विभागो को लेकर पयर्टन के ऊपर कुछ नहीं लिखा है कि पयर्टन से प्रदेश को कितनी इनकम होती है, वह इसमें दर्शाया नहीं गया है। किसी भी डाक्युमेंट में नहीं है। लेकिन पयर्टन की यहां पर बड़ी संभावना है। हम पीछे कमेटी के साथ टूर पर गए थे। मुख्य मंत्री महोदय, यह एक नोट करने वाली बात है। मेरे साथ करणेश जंग जी, के0 एल0 ठाकुर जी, और सुरेश भारद्वाज जी, जय राम ठाकुर जी, हम लोग गए। हमने राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्यों को दौरा किया था। वहां पर देखने को

मिला । एक तो राजस्थान में यदि आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर अपने कल्चर का अपनी संस्कृति को अभी तक लाईव

25/1255/03.2015.यूके/जेटी/3

रखा हुआ है । एक स्थान पर गए, उनका अपना एक चौखी ढाणी है, जय राम जी को पता है, इनकी ससुराल वहां पर है । वहां पर हर चीज़ पयर्टन की मिलेगी । राजस्थान में पयर्टन को बढ़ावा देने के लिए क्या चीज़ है, उसमें पूरे प्राईवेट सैक्टर में, मैं यह नहीं कहता कि सरकार करे । आपको इसको बढ़ावा देना चाहिए । मैं अभी पिछले शनिवार को अपने पालमपुर में गया था ,माननीय अध्यक्ष महोदय के चुनाव क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर हमारे एक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक छोटा सा होटल बनाया है । वहां मैं भी पहली बार गया । उस होटल को बनाए हुए लगभग 8-9 साल हो गए हैं । वह देखने लायक है । उसने उसमे हर जिले का नाम लिख कर दे रखा है। जैसे ऊना का दे रखा है, एक साईड में कांगड़ा का बना रखा है और एक जगह शिमला का बना रखा है । उसने उनके चार अलग-अलग कोरीडोर बनाए हुए हैं । उसमें अपना कल्चर कि ऊना वाले लोग कैसे रहते हैं, उसमें उन्होंने पूरा स्लेट डाल कर, या टीन डाल कर और कांगड़ा का कैसा रहन-सहन है, उसी ढंग से जैसे होता है, सीढ़ी अन्दर से लगाई हुई है, वैसे ही अन्दर जाते हैं, उसी ढंग से उसको बनाया है । ऐसे पयर्टन को बढ़ावा देने के लिए ताकि बाहर के लोग यहां आएं और वे सब-कुछ भूल कर इस प्रदेश में आ कर खो जाएं । तो इस तरह से वहां पर विजिट करने की आवश्यकता है । उसने उस होटल का नाम हिमाचल हैरीटेज रखा हुआ है । उसी तरह से एक चोखी ढाणी है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अधिकारियों को दौरा करने लिए भेजे । वाल्दी जी, हमारे प्रधान सचिव,

25/1255/03.2015.यूके/जेटी/4

ACS भी वहीं के हैं, इनको भी मालूम है कि वहां पर क्या चीज़ है । वहां पर यह देखने की आवश्यकताहै । आप अपने अधिकारियों को वहां पर भेजिए और उसी ढंग से हम यहां पयर्टन को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको यहां पर भी करना चाहिए ।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, यहां पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास पौंग डैम बहुत बड़ा है या हमारा भांखड़ा डैम है, पंडोह डैम है। हमारा चम्बा का बैरास्यूल के प्रोजेक्ट में डैम बने हुए हैं । हमने वहां कोशिश की थी कि वहां गांव का नाम मैं भूल गया । भलई माता के मंदिर के नीचे जो डैम बना हुआ है, चमेरा-तलेरू में ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

25.03.2015/1300/sls-jt-1

श्री रविन्द्र सिंह ...जारी

वहां पर हमने शुरुआत की है और वहां बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिला हुआ है। इसके लिए सरकार को नई योजना देने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। आज के दिन ऐसा कुछ नहीं है। जल खेलों और साहसी खेलों को बढ़ावा देने के लिए आपने लिखा ज़रूर है लेकिन इसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है।

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के ऊपर सभी ने बात की है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को मेरा एक सुझाव है। जब हमारी सरकार थी, मैं धूमल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमने एक नीति बनाई थी। हमने खेलों का कलेंडर बना दिया था कि सारे साल में खेलें निश्चित समय पर होंगी। प्राथमिक पाठशालाओं की खेलें इस समय पर, मिडल पाठशालाओं की खेलें इस समय पर और उच्च पाठशालाओं की खेले इस समय पर होंगी। ...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : अभी भी वही होता है।

श्री रविन्द्र सिंह : बिल्कुल नहीं है।...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : आपको जब मालूम नहीं है तो बोलते क्यों हो? अभी भी खेलें वैसे ही हो रही हैं।

श्री रविन्द्र सिंह : अगर होती हैं तो अच्छी बात है।

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय जो वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 28 फरबरी तक होते रहे; 2 मार्च को ...(व्यवधान)... मैं प्रश्नों की लिस्ट मंगवाऊं, जिसमें सारा जवाब आ जाएगा? आप (श्री जगजीवन पाल जी को) बीच में टोकाटाकी बंद कर दो। मैंने आपका नाम नहीं लिया है, आप बैठिए। इसका मतलब कि बात पिंच हुई और आपने किया होगा।

मुख्य मंत्री महोदय, यह वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह लोहड़ी यानी 13 जनवरी के बाद कंपलीट बंद कर दिए थे। लोहड़ी यानी जनवरी 13 के बाद कोई भी

25.03.2015/1300/sls-jt-2

कार्यक्रम स्कूलों में न हो ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, हमने ऐसा कार्यक्रम लागू किया। उसको फिर से दोहराने वाली बात है।

यह जो शिक्षकों की कमी है ,मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कहना चाहता। लेकिन निश्चित तौर पर आपकी सूचना में लाना चाहूंगा कि आज प्रदेश की क्या स्थिति हो गई है। प्रश्न के माध्यम से भी सूचना आई लेकिन यू-डाईस की जो रिपोर्ट है ,उसके अनुसार एक शिक्षक के सहारे प्रदेश में कुल 1117 स्कूल हैं। उनमें से प्राथमिक स्कूल 943 हैं। ...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : यह तो केवल रिपीट करने वाली बात है।

श्री रविन्द्र सिंह : बाकियों ने प्राथमिक पाठशालाओं की बात की है, उससे आगे की बात नहीं की है।

माध्यमिक पाठशालाएं ऐसी 172हैं। उच्च पाठशालाओं में दो ऐसी हैं जहां केवल मात्र एक अध्यापक है। जो स्कूल दो शिक्षकों वाले हैं ,...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : क्या आप यह कह रहे हैं कि मिडल और उच्च पाठशालाओं में केवल एक ही टीचर है?

श्री रविन्द्र सिंह : मिडल के 172ऐसे स्कूल हैं जहां केवल एक अध्यापक है।

Chief Minister: I challenge that. ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिडल स्कूल में एक अध्यापक हो ही नहीं सकता। ...(व्यवधान)... यह रिपोर्ट किसी ने शिमला में बैठकर लिखी होगी। ऐसा नहीं हो सकता।

श्री रविन्द्र सिंह : आप इसकी जांच कर लें। ...(व्यवधान)... मुख्य मंत्री जी, आगे सुनिए।

इसी तरह से जहां केवल मात्र 2-2 शिक्षक हैं ऐसे 6786 स्कूल हैं। इनमें से प्राथमिक पाठशालाएं 6570, मिडल पाठशालाएं 208 और 8 उच्च पाठशालाएं हैं।

25.03.2015/1300/sls-jt-3

इसके अतिरिक्त 3 शिक्षकों वाले स्कूलों में प्राथमिक पाठशालाएं 1211, मिडल 496, उच्च पाठशालाएं 37 और जमा दो के भी ऐसे 2 स्कूल हैं। यह एक रिपोर्ट पर आधारित सूचना है, जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूं।

मुख्य मंत्री : यह रिपोर्ट किसकी है?

श्री रविन्द्र सिंह : यह यू-डाईस की रिपोर्ट है। इसमें आपका जवाब भी है। ...(व्यवधान)... यह सरकार का जवाब है। असैंबली क्वैश्चन में, अध्यक्ष महोदय, आपने सही जवाब दिया है। ...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : यह रिपोर्ट मेरे नोटिस में नहीं है। अगर ऐसी रिपोर्ट किसी ने बनाई है तो उस आदमी ने घर में बैठकर किसी से पूछकर यह रिपोर्ट बनाई है। ...(व्यवधान)... Yes, there are many primary schools which have one teacher. I agree with that. मगर मिडल स्कूल में एक अध्यापक है, इससे बड़ी गप्प कोई और हो ही नहीं सकती।

श्री रविन्द्र सिंह : हम भी यही कह रहे हैं कि गप्प कोई हो नहीं सकती। पर मुख्य मंत्री जी, गप्पें सारी ऐसी ही हैं। अगर इस भाषण को पढ़ो तो गप्पों के सिवाये क्या है? आपने अपने भाषण में तो शे'रो-सायरी की है। गालिब का एक शे'र है कि 'ताउम्र गालिब .. ...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : गालिब ने यह कहा है कि जब बोलना है तो सच बोलें और नकली कागज़ देखकर न पढ़ें, यह गालिब जी ने कहा है।

जारी... श्री गर्ग जी

25/03/2015/1305/RG/JT/1

मुख्य मंत्री के पश्चात-----क्रमागत

गालिब का शेर हैः

ताउम्र गालिब चेहरा को देखता रहा,
धूल चेहरे पर थी,
और आईना साफ करता रहा।

और यह सरकार भी कर रही है, यह अब तक केवल धूल साफ कर रही है। यहां पर सुजानपुर की रैली के बारे में एक बात बहुत कही जा रही थी । पक्ष के वक्ताओं ने कहा, लेकिन चारो-की-चारों लोक सभा की सीटें हमारी रहीं ,हम चारों सीटें जीते। आप सारे-के-सारे हमीरपुर में बैठे रहे कि इस बार तो हमीरपुर को हरवाना है बाकी कुछ मिले या न मिले। वहां आप अनुराग ठाकुर जी को हराने के लिए बैठे रहे।

मुख्य मंत्री : उसकी वजह से यह नहीं है, यह आपकी वजह से नहीं हुआ है, यह तो मोदी जी का करिश्मा था, यह आपका करिश्मा नहीं था।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम भी तो वही बात कर रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं?

मुख्य मंत्री : ठीक बात है । I acknowledge the fact, but don't take its credit to yourself. मैं मोदी जी का बहुत सम्मान करता हूं, मैंने मोदी जी को कभी कुछ

नहीं कहा। मैंने उनकी कभी भी आलोचना नहीं की और मैंने उनके लिए कभी एक भी अपशब्द नहीं कहा।

श्री रविन्द्र सिंह : मुख्य मंत्री जी, मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं---(व्यवधान)---आप (श्री जगजीवन पाल, मुख्य संसदीय सचिव) बैठो, जब देखो आप बार-बार उठकर खड़े हो जाते हो। आपके मन की पीड़ा को मैं समझ सकता हूं।

Chief Minister: What you are going to say, I know it.

श्री रविन्द्र सिंह : नहीं, आप जो कह रहे हैं, मैं बोलूंगा नहीं, आप समझ गए हैं , लेकिन आपका सारा परिवार और आप हमीरपुर में बैठे रहे और पीछे सारे प्रदेश में क्या हो गया, यह आप भली-भांति जानते हैं।

मुख्य मंत्री : हम कई अर्से से राजनीति में हैं ,हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, हम पार्टी के लिए काम करेंगे। क्या हमें आपसे कोई लाइसैंस या सर्टिफिकेट या कोई पास पोर्ट लेना है? हम वहां जाएंगे, आप भी जा सकते हैं।

श्री रविन्द्र सिंह : यदि आप कहेंगे, तो इसमें मुझे क्या ऐतराज है, मैं लिखकर सर्टिफिकेट दे दूंगा कि आप चारों सीटें हार गए। हिमाचल प्रदेश की 68 विधान सभा

25/03/2015/1305/RG/JT/2

सीटों में से 60 विधान सभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। यहां तक की आपके विधान सभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली।

मुख्य मंत्री : अगले चुनाव में देखेंगे कि क्या होगा?

श्री रविन्द्र सिंह : चाहिए तो यह था कि यदि आपमें थोड़ी सी भी राजनीतिक सूझबूझ होती, तो आपको तुरन्त त्याग-पत्र देकर हिमाचल में फिर से चुनाव कराने चाहिए थे। फिर मैं आपको मानता कि आप यहां के नेता हैं। 68 में से 60 सीटों पर हमारी लीड

है। उस रैली के बारे में आप बार-बार कह रहे हैं ,इसको बार-बार कहने की आवश्यकता नहीं है।

Speaker : Please wind up now.

मुख्य मंत्री : आप अतीत के बारे में क्या कहते हैं, आप भविष्य के बारे में बोलें।

श्री रविन्द्र सिंह : मुख्य मंत्री महोदय, हमारा भविष्य बहुत उज्जल है। यह कांग्रेसमुक्त भारत अभियान शुरू है और ऐसे साफ कर देंगे कि नामोनिशान मिट जाएगा।----(व्यवधान)----

मुख्य मंत्री : जैसे दिल्ली शहर भाजपामुक्त हो गया है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सवा एक बजे तक समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष : नहीं-नहीं, अब आप समाप्त करिए।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, ---(व्यवधान)—

मुख्य मंत्री : इनको मैं बाद में जवाब दूंगा।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से यह बहुत खुश हो रहे हैं। अभी सन्ता-बन्ता के ऊपर एक चुटकला बहुत प्रसिद्ध हुआ है। सन्ता को फोन आता है कि मैं 'आप' पार्टी के कार्यालय से बोल रहा हूं। सन्ता कहता है कि हां जी, बोलिए,' आप' पार्टी वाला कहता है कि आप हमारा दस क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर बुक कर लो। सन्ता-बन्ता दोनों मित्र बहुत खुश हुए और कहते हैं कि आपको बधाई हो, आपने तो सारा दिल्ली साफ कर दिया। उसने फोन रखा तभी फोन की घण्टी फिर बज गई। उसने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, तो फोन पर जवाब मिला कि मैं कांग्रेस पार्टी के

25/03/2015/1305/RG/JT/3

कार्यालय से बोल रहा हूं। हमारे लिए भी दस क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर बुक कर लो। उसने कहा कि आपने तो कमाल कर दिया। उसने पूछा कि आप लड्डुओं के ऑर्डर क्यों बुक करवा रहे हैं आपकी तो सारी पार्टी हार गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो केवल तीन सीटों पर सीमित हो गई। इसलिए हम भी खुश हैं और लड्डुओं के ऑर्डर दे रहे हैं--------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

25/03/2015/1310/ms/Jt/1

श्री रविन्द्र सिंह जारी---------

यह आपका हाल है। लेकिन वहां क्या हुआ मुख्य मंत्री महोदय, सारे देश की पार्टियां एक तरफ और भाजपा एक तरफ। हमारा 35 परसेंट का वोट बैंक इंटैक्ट रहा। (व्यवधान) यह जो लड्डू का ऑर्डर दिया, यह कांग्रेस वालों का इसीलिए गया कि आपके 70 उम्मीदवारों में से 63 और 64 की जमानत जब्त हो गई थी। इसलिए आपने वहां पर लड्डुओं का ऑर्डर दिया।

अध्यक्ष जी, पिछले कल आपदा प्रबंधन पर यहां प्रश्न लगा था कि उसके तहत कितनी राहत दी गई। मुझे इस बात का दुःख है। मैंने सारी वह लिस्ट पढ़ी। यहां उपाध्यक्ष महोदय भी बैठे हैं। मेरा निवेदन है कि आप भी इसे पढ़ लें। इसके तहत जो मुख्य मंत्री जी ,राहत दी है, मैं किन्नौर की लिस्ट की बात कर रहा हूं प्रदेश में क्या हुआ, वह आप जान सकते हैं। इसमें लिखा है कि सैंक्शन्ड अमाउंट 20 हजार किसी को इण्डीविजुअल राहत दीः amount delivered Rs. 1000/- and pending Rs. 19,000/-. ऐसा तो आपने काम किया है। यह आपका पिछले कल का जवाब है। किन्नौर में पैसे की डिस्ट्रिब्यूशन नहीं हुई है। मैं किन्नौर की बात कर रहा हूं। यह जो राहत मैन्युअल के तहत राहत दी जाती है, उसकी रिपोर्ट यहां पूरी की पूरी ले (lay) हुई है। उसका जवाब है कि यह पूरे प्रदेश की स्थिति है। प्रदेश में ऐसे हालात पैदा हुए हैं। जो राहत डिलीवर कर दी है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन साथ में,

अध्यक्षः उपाध्यक्ष जी कुछ बोलना चाहते हैं।

उपाध्यक्षः अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद। मेरे चुनाव क्षेत्र के बारे में रवि जी ने कुछ रैफ्रेंस किया है। शायद रवि जी को किन्नौर जाने का मौका नहीं मिला होगा या वहां क्या-क्या काम हुए, उस बारे में इनको जानकारी नहीं होगी। केवलमात्र एक सनसनी क्रिएट करने के लिए इन्होंने यह बात की है। मैं इस माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिला किन्नौर में वर्ष 2013 में एक प्राकृतिक आपदा उत्तराखण्ड के साथ-साथ आई थी और वहां बहुत ही नुकसान हुआ था। जो उस समय में राहत के काम किन्नौर के अन्दर हुए शायद ही हिन्दुस्तान के किसी भी जिले में हुए होंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बड़ा आभारी हूं कि धन

25/03/2015/1310/ms/Jt/2

के अलावा जो भी वहां पर चाहे हेलिकॉपटर की बात थी, बिजली या पानी की बात थी, उसको बहाल किया गया तथा खुलकर इन्होंने वहां पर धन दिया। हमने स्वयं भी कई महीने वहां काम किया। जो आप कह रहे हैं कि पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ ,मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान में खड़ी फसल के नुकसान का पैसा किन्नौर के लोगों को मिला है और 18 करोड़ रूपये अभी तक किन्नौर के किसानों और बागवानों को दिया गया है। यह एक बहुत बड़ी राहत प्रदेश के लोगों को मिली और अभी भी उस राशि में से 5 करोड़ रूपया हमारे पास पड़ा हुआ है। जिनके अभी कोई केस रह गए हैं उनको हम फिर दे रहे हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, मैं समाप्त कर रहा हूं। जो समय लगा वह व्यवधान का है। मैं अध्यक्ष जी वही समय लूंगा। मैंने तो केवल एक सूचना दी है अगर उपाध्यक्ष जी को अच्छी नहीं लगी तो इनकी मर्जी है। कल का जो इस बारे में उत्तर आया है, यह उसको पढ़ लें। मैंने तो इतना ही निवेदन किया है। बाकी प्रदेश में ऐसी ही स्थिति है।

इसी तरह से भूमि अधिग्रहण बिल के ऊपर जो भारत सरकार में पेश हुआ , उस पर यहां बड़ी चर्चा की है। लेकिन इस प्रदेश का हाल क्या है? भाखड़ा बांध कब

बना? आज जब उस बारे में आपकी मीटिंग होती है तो आप कहते हैं कि भाजपा इसके लिए दोषी है। पौंग बांध बना तो कब बना? जब इस बारे में भी मीटिंग करते हैं तो हमें तो बुलाते ही नहीं है। पौंग बांध का मैं भी मैम्बर हूं और माननीय नीरज जी भी हैं। ऐसे ही कई अन्य सदस्य भी होंगे लेकिन मीटिंग में हमें नहीं बुलाया जाता। पौंग बांध और भाखड़ा बांध के विस्थापितों को मुआवजा अभी तक भी नहीं मिला है। एक प्रोजैक्ट 1961 में बन गया है और 72-1971में दूसरा बन गया है। उन लोगों की स्थिति क्या है मुख्य मंत्री जी आपको चलकर देखना चाहिए। मेरा निवेदन है, मैं इस पर लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा। लेकिन पौंग बांध विस्थापितों के जो आपने पूरे प्रदेश में इन्क्रोचमैंट के केसिज लगाए हैं, आप वहां गए भी थे और आपने वहां कहा भी था। तो उस समय 1971में उन पौंग बांध विस्थापितों को कहा कि जहां आपका दिल करे वहां बस जाओ। उस समय एफ0सी0ए0 लागू नहीं था। वे बेचारे वहां बस गए। जब एफ0सी0ए0 लागू हो गया तो उनकी एक दीवार वन विभाग की बन गई और तीन दीवारें उनकी अपनी हैं। उनको आए दिन नोटिस आ जाते हैं।

25/03/2015/1310/ms/Jt/3

हमारी सरकार के समय उनको रोका गया था। मेरा निवेदन है कि ये दो तरह की इन्क्रोचमैंट्स हैं। एक हमारे आपके जैसे हैं जब समय मिला इन्क्रोचमैंट कर ली और एक वे प्रोजैक्ट वाले हैं जिन्होंने इस देश की प्रगति के लिए अपनी जमीनें दे दीं। ये दोनों अलग-अलग विषय हैं। इन दोनों को बाइफरकेट करना होगा।

जारी श्री जे0के0 द्वारा---------

25.03/1315/2015.जेके/जेटी/1

श्री रविन्द्र सिंहः-------जारी---------

- बाइफरकेट करना होगा। मेरा निवेदन रहेगा आप तिब्बत वालों को भी रैगुलराईज करें। इन हमारे किसानों ने तो अपनी जमीनें तक वहां पर दे दी है। वहां पर 21-22 हजार परिवार आज के दिन भी प्रभावित है। राजस्थान में जाओ तो जनवरी के महीने में आपके मंत्री महोदय ने वहां पर जाना था लेकिन वे अभी तक गए नहीं, मेरा निवेदन मुख्य मंत्री जी आपसे यह है कि आपने उस मीटिंग में कहा था कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा तो जाएंगें

ऐसा आपने लिखा है। लेकिन उस मीटिंग में हमें नहीं बुलाया गया। न मुझे बुलाया गया, न विक्रम सिंह ठाकुर को बुलाया गया और न ही नीरज भारती जी को बुलाया गया। पठानियां जी का तो इसमें बयान लगा था, इन्होंने कहा था कि यह झगड़ा भाजपा का पैदा किया हुआ है और विस्थापितों को 23 बसों में भरकर राजस्थान छोड़ आए थे। यह आपका बयान लगा हुआ था। यह सारी स्थिति कब किसने पैदा की है, यह देखने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि एक बात अंत में कहते हुए मैं अपना भाषण फिर समाप्त करूंगा। मुख्य मंत्री महोदय, कानून-व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। आपने अपने भाषण में इस बारे में सीमित सा कहा है। शिमला के बारे में यहां पर धूमल जी ने बात रखी। अन्य अपने क्षेत्रों के बारे में यहां पर बात रखी। मैं फिर उन आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा। लेकिन उस गवर्नर एड्रैस के बाद की चर्चा और आज की चर्चा के मध्य जो प्रदेश की स्थिति बनी है, आप चाहें तो मैं पूरी पढ़ कर सुनाता हूं लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर इन पुलिस वालों को जो आपने केवलमात्र चालान करने के लिए खड़े किए हुए हैं या पैसा इकट्ठा करने के लिए खड़े किये हैं, यह स्थिति प्रदेश की ठीक नहीं है। उनको कहो कि यह गलत स्थिति पैदा हुई है। कोई समय था जब पुलिस वाला वर्दी पहन कर जाता था तो सारा इलाका कांप जाता था। वैसे तो इतना डर पैदा नहीं करना

25.03/1315/2015.जेके/जेटी/2

चाहिए। लेकिन समय बदला उसके अनुसार आज कानून-व्यवस्था का हाल, ड्रग्ज माफिया,खनन माफिया, वन माफिया का क्या हाल है? मैं यहां पर वन माफिया के ऊपर बात नहीं करुंगा। मेरा निवेदन है ,आप बार-बार कहते हैं लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई है। मैं यहां पर डॉक्यूमैंट लाया था लेकिन समय की कमी है इसलिए मैं वन माफिया के ऊपर नहीं बोलूंगा। मुख्य मंत्री महोदय मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इन सारी चीजों को रोकने की आवश्यकता आपके दिल में है। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इन सभी तथ्यों को इस डॉक्यूमैंट में जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना बजट भाषण यहां पर 18 मार्च को पढ़ा है, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जो आपने विधायक निधि 50 लाख से 70 लाख की है,

उसको 1 करोड़ करने का मेरा अनुरोध है। दूसरा आपने जो राइडर लगा रहा है उस राइडर को खत्म करें। साथ में ऐच्छिक निधि जिसके बारे में सभी पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे हैं , उसको भी आप बढ़ाएं और जो लाभार्थी होंगे उनको हम भी कुछ धन देने की राहत दे सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया। इस बजट भाषण में हमारे क्षेत्र के लिए मैंने डॉक्यूमैंट देखें विशेष कुछ भी नहीं है। आपने जो घोषणाएं वहां पर की यदि उनको भी बजट में डाल देते तो भी मैं आपका धन्यवाद करता। आप वहां पर घोषणा करके आए हैं लेकिन उनको आपने बजट में नहीं डाला है। इस बारे में मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि उनको भी इस बजट में डालिए। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक स्थगित की जाती है।

25.03.2015/1415/SS-AG/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत माननीय उपाध्यक्ष, श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 2:15 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)

उपाध्यक्षः अब चर्चा में श्री बलबीर सिंह वर्मा जी भाग लेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 18 मार्च, 2015 को हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय जननायक, लाखों दिलों की धड़कन वाले माननीय मुख्य मंत्री, राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो इस माननीय सदन में वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान प्रस्तुत किये हैं और अपने कार्यकाल का 18वां बजट पेश किया है वह एक इतिहास बन गया है। जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्य मंत्री बने और 18वीं बार आपने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया।
जारी श्रीमती के0एस0

25.03.2015/1420/केएस/एजी/1

श्री बलवीर सिंह वर्मा जारी---
यह हिमाचल के इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। आपका जो राजनीतिक अनुभव है, इस हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ही नहीं देश के इतिहास में आपके मुकाबले या आपने जितने इलैक्शन्ज़ जीते, आप देश की पार्लियामैंट में पांच बार जीतकर गए और प्रदेश में 8 बार विधान सभा में जीतकर आए। हिन्दुस्तान के इतिहास में तीन बार सैंटर में मंत्री बने और छः बार हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री बने, इस तरह का इतिहास इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में किसी का नहीं होगा। मुख्य मंत्री जी की लोकप्रियता बहुत लोगों को अखरती है। आपसे लोकप्रिय, अनुभवी, कर्मठ, जुझारू, कठिन परिश्रमी, ईमानदार, जनता के प्रति वफादार, वचनबद्ध और समयनिष्ठ आपके मुकाबले कोई भी नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015-16 का बजट 28239 करोड़ का होगा जो कि पहले वर्ष की अपेक्षा 4726 करोड़ ज्यादा है। आप सर्वकल्याण और समग्र विकास के उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे हैं। छोटे कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाया गया। 37 लाख लोगों को राजीव गांधी अन्न योजना के दायरे में लाया गया है। प्रदेश में बस अड्डों के निर्माण के लिए भी बजट का प्रावधान रखा गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम में नए 510 नई बसें खरीदी है और 800 और नई बसें JNNURM के अंतर्गत खरीदी जा रही है इससे दूर दराज के क्षेत्रों में बस की सुविधा उपलब्ध होगी क्योंकि वहां पर लोगों को 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। दूर-दराज के क्षेत्रों में बस की सुविधा से हमारे डवैल्पमैंट के कार्यों में भी तेजी आएगी। प्रदेश में 719 नए

25.03.2015/1420/केएस/एजी/2

विद्यालय खोले। मुख्य मंत्री महोदय, आप गरीबों के दिलों को समझते हैं, किसानों के दिलों और दूर-दराज के क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को समझते हैं। आपने जो स्कूल खोले हैं, यह जनता के हित में बहुत बड़ा कार्य हुआ है। इस प्रदेश में चाहे दूर-दराज के क्षेत्र के कोई भी लोग हैं, सभी को पढ़ने का अधिकार है। चाहे उस स्कूल में 5 या 10 ही बच्चे हों परन्तु वे सभी आपके प्रदेश के बच्चे हैं और उनको भी पूर्ण शिक्षा

का अधिकार है। आपने जो यह योजना चलाई है कि जहां भी बच्चे होंगें, वहां स्कूल खोला जाएगा, यह जनता के हित में बहुत बड़ा निर्णय है और गरीब तथा दूर-दराज के क्षेत्र की जनता इसका बहुत स्वागत कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 719 नए विद्यालय खोले या स्तरोन्नत किए गए। दो वर्षों की अवधि में ही 14 नए डिग्री कॉलेज खोले गए। एप्पल रीजुविनेशन प्रोजैक्ट के दिशा-निर्देशों का सरलीकरण कर बागवानों के हित में बनाया गया । डॉ0 वाई.एस. परमार किसान स्वरोज़गार योजना आरम्भ की जिसमें किसानों को पॉली हाऊस स्थापित करने के लिए 85 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। पूर्व भाजपा सरकार द्वारा हटाए गए पी.टी.ए. अध्यापकों को बहाल भी किया और उनके अनुदान में वृद्धि भी की। पैरा अध्यापकों की सेवाओं को नियमित किया ओर पी.टी.ए. अध्यापकों की सेवाओं का सरकारी अनुबन्ध में परिवर्तित किया। हिमाचल प्रदेश के जो दूर-दराज क्षेत्र के स्कूल थे, जहां अध्यापकों की कमी थी, वह कमी दूर हो गई और साथ ही साथ वहां के बच्चे शिक्षा सही तरीके से ले सकेंगें।

25.03.2015/1420/केएस/एजी/3

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो गौ-वंश संवर्द्धन बोर्ड बनाएंगें यह बहुत ही उचित निर्णय है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

25.3.2015/1425/ag/av/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा --जारी

गो-वंश संवर्द्धन बोर्ड बनायेंगे, यह एक बहुत ही उच्च निर्णय है। इस संसार में सभी जीवों को रहने का अधिकार है। इसमें चाहे पशु-पक्षी है या इनसान है। हमारे पशु बड़ी बेरहमी से घूमते हैं। उनके लिए न तो पानी की और न ही चारे की व्यवस्था होती है। उनके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो गो-वंश संवर्द्धन बोर्ड बनाया है इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इस तरह की यह पहली योजना बनी होगी। उत्तम चारा उत्पादन योजना आरम्भ करने के लिए भी प्रस्ताव रखा है। सरकार पंचायतों को 109 करोड़ रुपये जारी करेगी। 14वें वित्तायोग की संस्तुतियों के अनुरूप भी पंचायतों को 195 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि के रूप

में जारी होंगे। इससे पंचायतों के प्रतिनिधि भी पंचायतों में विकास के कार्य करवा सकेंगे। आपदा राहत के तहत इस बार बजट में 236 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। प्रदेश में कोई भी आपदा आए तो इसके अंतर्गत एकदम राहत कार्य शुरु हो सकते हैं। अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ आए तो उसके लिए भी आपने बजट में 183 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। शिमला में सर्कुलर रोड/ कार्ट रोड को चौड़ा करने के लिए जो आपने बजट में राशि का प्रावधान किया है यह भी काबिलेतारीफ है। प्रदेश के सभी लोगों को इससे सुविधा मिलेगी तथा आय दिन जाम के कारण हो रही दिक्कतें भी हमेशा के लिए खत्म हो जायेगी।

महिलाओं को स्व-रोजगार के लिए वित्तीय सहायता 2500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी है। पहली से 12वीं कक्षा तक 'बेटी है अनमोल योजना' के तहत छात्रवृत्ति में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सामाजिक सुरक्षा पैंशन, अपंग, विधवाओं के लिए पैंशन 5 50रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति माह कर दी गई है। प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आपने जो सभी पुलिस चौकियों को अधीनस्थ पुलिस थानों के रूप में नियमित करने हेतु जो प्रावधान रखा है, यह प्रशंसनीय है। गृह आरक्षियों का मानदेय 260 रुपये से बढ़ाकर 280 रुपये प्रति दिन कर दिया जायेगा।

25.3.2015/1425/ag/av/2

दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 170 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये की गई है जो कि बहुत ही उचित निर्णय है। अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 1700 रुपये किया गया। 21 मार्च, 2015 को 5 साल का सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मी नियमित होंगे, यह भी आपका बहुत ही उचित निर्णय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों, ऑटो-रिक्शा तथा टैक्सि चालकों में 4.48लाख लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे; यह भी एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। खेल सुविधा के विकास के लिए सभी गेमों के खिलाड़ियों को भी बहुत ज्यादा खुशी होगी क्योंकि आपने उनके लिए भी बजट में 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आई.जी.एम.सी. में सुपरस्पैशिलिटी होस्पिटल निर्मित करने हेतु आपने बजट में जो 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, यह भी काबिलेतारीफ है।

7750 आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के उपरांत गांव में तैनात किया जायेगा। चिकित्सकों के 200 तथा पैरा मैडिकल कर्मियों के 500 पद भरे जायेंगे। दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा को ज्यादा सुदृढ़ करने का निर्णय लेना भी काफी प्रशंसनीय है। सभी जिला अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए वार्ड खोलने का निर्णय भी एक उचित कदम है। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बाजार भाव से कम मूल्य पर तीन-तीन एल.ई.डी. बल्ब उपलब्ध करवाये जायेंगे तथा उपभोक्ताओं से बल्ब की कीमत बिजली के बिलों के माध्यम से वसूल की जायेगी। लोक निर्माण----------

श्री नेगी द्वारा जारी

25.03.2015/1430/negi/ag/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा.. जारी...

लोक निर्माण विभाग में कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए क्वालिटी मॉनिटर्ज़ नियुक्त होंगे, यह बहुत बड़ा निर्णय है और जनता के हित का निर्णय है। सड़कों में जहां दुर्घटना का डर है उन स्थानों पर स्टील क्रैश बैरियर स्थापित करने के लिए आपने 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, यह भी जनता के हित में एक बहुत बड़ा निर्णय है। आपने प्रदेश में 10 नई आई.टी.आई. खोलने का प्रावधान किया है और प्रत्येक आई.टी.आई. में 400 छात्रों की प्रवेश क्षमता होगी। आपने कौशल विकास भत्ता के लिए 100 करोड़ रूपये का बजट रखा है, यह भी काबिले तारीफ है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग तथा लोग निर्माण विभाग में जितनी भी योजनाएं हैं उनको समय पर पूरा करने के लिए ठेका प्रबन्धन सूचना व्यवस्था आरम्भ की है, जो कि बहुत जरूरी था, इससे कार्य में पारदर्शिता प्रगति होगी और समय पर कार्य पूर्ण होंगे। सरकारी विभागों में हल्फनामें के स्थान पर सादे कागज़ पर प्रार्थी सेल्फ घोषणा कर सकता है, यह भी जनता के हित में बहुत बड़ा फैसला है । विधायकों का श्रेत्रीय विकास निधि जिसकी डिमाण्ड पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के विधायक कर रहे थे, आपने दोनों पक्षों के विधायकों के दिलों की बात सुनी और आपने इस राशि को 50 लाख रूपये से बढ़ा कर 70 लाख रूपये किया, इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही, मैं पक्ष और विपक्ष के विधायकों भी बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जो इंटीरियर इलाके हैं जहां सड़क

व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था कई बार मौसम खराब होने के कारण, बर्फ गिरने के कारण और बरसात के कारण इमिडिएट ग्रस्त हो जाती है उसके लिए एम.एल.ए. फंड में कोई ऐसा प्रावधान किया जाए कि रिपेयर के लिए भी उस पैसे को यूज़ किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने खाद्य उपदान योजना के लिए 210 करोड़ रूपये का बजट रखा है । आपने राजीव गांधी सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के लिए 154 करोड़

25.03.2015/1430/negi/ag/2

रूपये का प्रावधान किया है । किसान भाईयों के लिए यह बहुत ही अच्छी स्कीम है और इससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। आपने 50 परसेन्ट वित्तीय सहायता के साथ 20,000 केंचुआ खाद इकाईयां स्थापित करने की घोषणा की है इससे गरीब लोगों को हेल्प मिलेगी और इससे किसानों को और बागवानों को बहुत फायदा होगा। यह भी काबिले तारीफ है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने किसान एवं खेतीहर मज़दूरों को जीवन बीमा प्रदान करने की दृष्टि से मुख्य मंत्री किसान एवं खेतीहर मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना आरम्भ की है, इससे मजदूरों को काफी फायदा मिलेगा।

किसान व बागवानों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रदेश के सभी खण्डों में शुरू होगी इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। कौशल विकास भत्ता योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं के कौशल में वृद्धि कर उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए कौशल भत्ते के रूप में प्रतिमाह 1000/- रूपये प्रदान किये जा रहे हैं और अक्षम व्यक्तियों को 1500/- रूपये प्रदान किए जा रहे हैं। यह बहुत ही काबिले तारीफ है। सरकारी विद्यालयों में पहली से ले कर 12वीं कक्षा तक के छात्रों को हिमाचल राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में घर से स्कूल और स्कूल से घर तक निशुक्त यात्रा सुविधा जो आपने दी है यह बहुत ही काबिले तारीफ है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपके आर्शीवाद से, आपके सहयोग से, आप मेरे चुनाव क्षेत्र में एक साल पहले आए थे, आपने मेरे चौपाल चुनाव क्षेत्र का उद्धार ही नहीं किया बल्कि विकास की दृष्टि से हम भी हिमाचल प्रदेश के दूसरे कॉंस्टिट्युएंसीज़ के मुकाबले आए हैं। आपने मेरे चुनाव क्षेत्र में 3 हॉस्पिटल दिए। 3 पी.एच.सी. दी। 30 से ऊपर स्कूल दिए। 2 तहसीलें दी और थाने दिए।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

25.03.2015/1435/यूके/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा-- जारी---

थाने दिये । 33 के0वी0 के लिए उसका फाऊंडेशन स्टोर भी रखा है । 66 के0वी0 में कार्य प्रगति पर लाने के लिए आपने दिशा-निर्देश दिए । बस अड्डा नेरवा दिया । जितना कार्य 25-30 सालों में नहीं हुआ उतना कार्य आपने दो साल में मेरी चौपाल कंस्टिचुएंसी में किया । मैं ही नहीं समस्त चौपाल की जनता हमशा आपकी ऋणी रहेगी । माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं थोड़ा सा आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि देहा से चौपाल के बीच का जो हमारा 28 किलोमीटर का स्पैन है, उसमें बर्फ और बरसात के समय बहुत सारे लोग रात को दो-दो दिन तक उसमें फंसे रहते हैं । उसके बीच कोई भी आबादी नहीं है । उसमें फॉरेस्ट या PWD का रैस्ट हाऊस बनना बहुत जरूरी है । अभी हाल ही में हमारी सड़क 4-5 दिन बन्द रही और कुछ लोग तो हमने चौपाल और देहा के बीच मे जो बर्फ में फंसे थे उनको निकाला । कुछ लोग दो-दो दिन तक उसी बर्फ में फंसे रहे। फिर उसके लिए स्पेशल एक टीम बनाई । उन्होंने उन लोगों को निकाला । मैं आपसे विनती करूंगा इसके बीच एक रेस्ट हाऊस का होना बहुत जरूरी है ।

हर बरसात और हर विंटर में हमें पानी और बिजली से सम्बन्धित बहुत सारी समस्याएं आती हैं । मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि जो हमारा 28 किलोमीटर का स्पैन है, बिजली का वह जंगलों के बीच से जाता है । थोड़ा तूफान आए, बर्फ गिरे, बरसात आए तो जैसे ही पेड़ गिरते हैं तो पूरे चौपाल चुनाव क्षेत्र की लाईट बन्द हो जाती है । उसके लिए कोई अन्डरग्राऊंड ऐसी व्यवस्था की जाए या उसके लिए पेड़ों से

25.03.2015/1435/यूके/2

ऊपर टॉवर की व्यवस्था की जाए । उससे हमारे यहां की बिजली की लाईनें नहीं टूटेंगी ।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय से से मैं यह भी आग्रह करूंगा कि हमें चौपाल में एक पॉलीटैक्नीक कॉलेज जरूर मिलना चाहिए । हमारा क्षेत्र दूर-दराज का क्षेत्र है । इसके अतिरिक्त मैं यह भी आग्रह करूंगा कि इंटिरियर में स्नोफॉल बाउंडिड एरिया है, जहां हैवी स्नो फॉल होता है । उस एरिये के लिए बजट में स्पेशल प्रावधान रखा जाए । इलैक्ट्रीसिटी, IPH और PDD में बरसात और बर्फ के समय इन तीनों विभागों से सम्बन्धित बहुत ज्यादा नुकसान होता है । इलेक्ट्रिीसिटी, IPH और PWD में करोड़ों का नुकसान होता है । इमिडिएट इसके लिए कोई ऐसा प्रावधान किया जाए कि जहां इंटिरियर में हैवी बर्फ पड़ती है, उनके लिए अलग से बजट का प्रावधान हो तो एकदम से उसके लिए सहायता उपलब्ध हो सकती है ।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैं यह भी आग्रह करूंगा कि हिमाचल प्रदेश में 68 चुनाव क्षेत्र हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हड क्वार्टर से चुनाव क्षेत्र के लिए रोड जाती है, उनमें मेरी रोड जो चौपाल को जाती है, वह बहुत तंग है । PMGSY और नाबार्ड से जो अन्दर की सड़कें बनी हैं, मैटल हुई हैं और जो गांव के लिए विलेज स्तर की सड़कें बन रही हैं वे चौड़ी हैं । बजट में ऐसा प्रावधान हो कि डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर से कंस्टिचुएंसी हैड-

25.03.2015/1435/यूके/3

क्वार्टर तक सड़क चौड़ी बने । यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी चुनाव क्षेत्र में आता है पहले वह मेन रोड से आता है । उस रोड की स्थिति को देख कर वह पूरी कंस्टिचुएंसी का आंकलन कर देता है कि इस कंस्टिचुएंसी में विकास का कार्य बिल्कुल नहीं हुआ होगा । हमारे क्षेत्र चौपाल में 25 सड़कें PMGSY और नाबार्ड से मैटलिंग, टारिंग और वाईडनिंग के लिए सैंक्शन हुई है । लेकिन जो मेन रोड है उसको न PMGSY में डाल सकते हैं न उसको नाबार्ड में डाल सकते हैं और न ही उसको MLA प्रायोरिटी में डाल सकते हैं । अगर प्रदेश सरकार हैड-क्वार्टर से

कंस्टिचुएंसी तक के लिए स्पेशल बजट रखे तो हमारी मेन रोड सुधर जायेगी। नेरवा खड्ड में चेनेलाइजेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। पूरा नेरवा, जहां करीब-करीब 300 दुकानें और हजारों मकान हैं, वह बिल्कुल खड्ड के साथ है। वहां चेनेलाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। यदि चेनेलाइजेशन होगा तो कभी भगवान न करे ऐसी आपदा आए, बिल्कुल खड्ड के साथ है, इसके लिए भी बजट का प्रावधान जरूर करें। कॉलेज बिल्डिंग नेरवा, हास्पिटल बिल्डिंग नेरवा-कुपवी-चौपाल, मिनी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग चौपाल, कुपवी तहसील बिल्डिंग, पुलिस थाना कुपवी, सब-तहसील बिल्डिंग देहा, ब्लॉक ऑफिस कुपवी में ये सारी व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाए।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

25.03.2015/1440/sls-jt-1

श्री बलबीर सिंह वर्मा...जारी

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं, इसमें प्रदेश के सभी वर्गों के हित सुरक्षित हैं। इसमें किसान, बागवान, बेरोज़गार , कर्मचारी, व्यापारी, अपंग, विधवाओं ,एक्स-सर्विसमैन, नौजवान, विद्यार्थी, महिलाओं, बच्चों और पैंशनरों के लिए बहुत ही हितकारी योजनाएं हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग के उत्थान के लिए यह बजट पेश किया है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

जयहिंद।

उपाध्यक्ष : धन्यवाद। अब श्रीमती सरवीन चौधरी जी चर्चा में हिस्सा लेंगी।

25.03.2015/1440/sls-jt-2

श्रीमती सरवीन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट प्रस्तुति माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में 18 मार्च को की है, मुझे लगता है कि यह बजट प्रस्तुति न होकर जैसे किसी मुशायरे को विधान सभा में पेश किया गया हो। बजट प्रस्तुति करते समय मुख्य मंत्री जी बहुत ही असहाय और असुरक्षित नज़र आए।

मुख्य मंत्री : आप मेरी चिंता कर रही हो ,I am proud of it.

Smt. Sarveen Chaudhary : Sir, please take it positively. Let me speak. Thank you, Sir. हमें कुछ तो अच्छा-अच्छा बताना पड़ेगा।

मुख्य मंत्री जी, आप इस बजट को पेश करते हुए इस सदन में बहुत ही असहाय और असुरक्षित महसूस हुए। मुझे समझ नहीं आई कि आप क्यों बार-बार अपने को परिंदा बनाने की कोशिश करते रहे। आप असुरक्षित इसलिए लग रहे थे कि बजट के चौथे पन्ने में आपने मुशायरे की शुरुआत करी। एक शे'र पढ़ा –

'न जाने अभी कितनी उड़ान बाकी है,
इस परिंदे में अभी जान बाकी है।'

मुख्य मंत्री : यह ठीक बात है, गतल-फ़हमी में न रहना।

श्रीमती सरवीन चौधरी : मेरी समझ में नहीं आया कि यह आप अपनी पार्टी वालों को बता रहे थे या अपनी सरकार को बता रहे थे। ...(व्यवधान)...आप अपनी सरकार को यह कह रहे थे, अपने बैठे हुए पार्टी के लोगों को कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ बाकी है; थोड़ा-सा है बचा हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, यह विडंबना हैं कि मुख्य मंत्री जी को यह कहना पड़ा कि अभी जान बाकी है। इसलिए यह बजट इस प्रदेश के लोगों को दिशाहीन भी लगा, निराशाजनक भी लगा और लोगों की आशाओं के विपरीत भी दिखा। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगी –

'बुलंदी की उड़ान पर हो,
ज़रा सब्र रखो, परिंदे बताते हैं
कि आसमान में ठिकाने नहीं होते।'

25.03.2015/1440/sls-jt-3

ज़मीन पर ही रहना पड़ता है और वास्तविकता को जानना पड़ता है। इसके साथ एक और शे'र कहना चाहूंगी। गालिब का शे'र है –

'परिंदों पर याकीन न करना गालिब,

जब इनके पर निकल आते हैं,
तो ये अपना आशियाना भी भूल जाते हैं।'

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सही कहा कि जब 80% स्कीम्ज भारत सरकार की हैं; जैसे हमारे लीडर ऑफ अपोजीशन प्रो० प्रेम कुमार धूमल जी ने और बिन्दल जी ने भी कहा कि आपने उनके लिए एक शब्द भी धन्यवाद का नहीं रखा।80 % स्कीम्ज के पैसे भारत सरकार के हैं ,आप तो केवल उसके ठेकेदार हैं। पैसा 80% केंद्र सरकार दे रही है, आपने केवल उसकी ठेकेदारी करनी है। यह तो वह बात हो गई कि *'माल मालकां दा, मशहूरी कंपनी दी'।* माल तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का है और आप वाह-वाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपने यहां एक शब्द में भी धन्यवाद नहीं किया। मैं कहना चाहूंगी कि अगर मनरेगा की ही बात ले लें, यह 90-10 की स्कीम है। इसमें 90% केंद्र और 10% प्रदेश सरकार का हिस्सा है। रूरल हैल्थ मिशन का भी ...
जारी ..गर्ग जी

25/03/2015/1445/RG/JT/1

श्रीमती सरवीन चौधरी-----क्रमागत
रूरल हैल्थ मिशन की भी 90:10 रेशो की स्कीम है इसमें भी 90 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार देती है। इसी प्रकार यदि आप शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान की बात करें।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदया, आप एक मिनट के लिए बैठिए, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : On a Point of Order, Sir.उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरे विभाग से संबंधित बात की ,यह जो मनरेगा की 90:10 रेशो की स्कीम बता रही हैं ,तो यह 25:75 रेशो की स्कीम है आप मिसगाइड कर रही हैं। सौ प्रतिशत तो लेबर कंपोनेंट में केन्द्र सरकार से पैसा आता है। आप जो कह रही हैं, तो यह 90:10 रेशो की स्कीम नहीं है।

श्रीमती सरवीन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप इसी तरह से रूरल हैल्थ मिशन की बात लें ,तो इसमें भी 90:10 की रेशो है या इसमें भी कुछ और रेशो है? इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी 90:10 की रेशो है। ये सब 90:10 की रेशो की जो स्कीम हैं इनमें 90 प्रतिशत फण्ड्ज केन्द्र सरकार से आते हैं। यदि आप शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान की बात करें ,तो इसमें 80:20 की रेशो है। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान में बिल्डिंग में और यहां तक की रूसा के अध्यापकों के वेतन भी वहां से हैं और एस.एस.ए. में जो अध्यापक लगे हैं उनका वेतन भी पूरा-का-पूरा केन्द्र सरकार दे रही है। आप चाहें, तो तथ्य निकालकर देख लेना इसमें 80:20 की रेशो है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार यदि आप आर.ई.डी.एफ. में या नाबार्ड में आ जाएं, तो यह भी केन्द्र सरकार की योजना है। केन्द्र सरकार के अन्तर्गत नाबार्ड से योजनओं की फण्डिंग हो रही है। यहां तक की जो विधायक प्राथमिकता के लिए योजना की बैठक होती है उसमें दो-दो स्कीम हम लोग देते हैं। चाहे आप लोक निर्माण विभाग या सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को ले लें। इन सारी स्कीम्ज की नाबार्ड से फण्डिंग होती है। मेरा यह आरोप है कि आर.आई.डी.एफ. में केवल कांग्रेस के विधायकों की डी.पी.आर्ज. बन रही हैं और जो भी स्कीम्ज स्वीकृत हो रही हैं वे उन्हीं की हो रही हैं। हमारे विधायकों का इस ओर कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस प्रकार की लूट सहन नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि पिछले दो सालों में तीन बार प्लानिंग की मीटिंग हो चुकी है जब आपने बजट को पास करना होगा, उस

25/03/2015/1445/RG/JT/2

समय आप सभा पटल पर यह भी सूचना दें कि किस-किस विधायक की प्राथमिकता वाली स्कीम पिछले दो सालों में स्वीकृत हुई हैं। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में एक रूपया भी लोक निर्माण विभाग या सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग का नया नहीं है जो भी योजनाएं हैं वे पिछली सरकार की ही हैं और उनसे ही काम चल रहा है। यह सूचना आप सभा पटल पर रखें और वस्तुस्थिति से सबको अवगत कराएं। इसलिए इतने पृष्ठों का बजट भाषण पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हमें वास्तविकता की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां मनरेगा की बात करना चाहती हूं। मैं कांग्रेस के ऊपर एक आरोप लगाना चाहती हूं कि आपने प्रचार किया कि भारत सरकार इस स्कीम को बन्द कर रही है जो बिल्कुल झूठा प्रचार था या नहीं था? क्या यह स्कीम बन्द हुई? भारत सरकार ने इस स्कीम के तहत केन्द्रीय बजट से 33,699 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह एक बहुत बड़ी रक़म है और अभी जेटली जी का बयान आया कि इसमें अभी 5,000 करोड़ रुपये और जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार इसका बजट कुल मिलाकर 38,699 करोड़ रुपये बना। जब से यह स्कीम शुरू हुई है, आज तक मनरेगा के तहत सबसे अधिक पैसा आया है। इस तरह आपके झूठ का पर्दाफाश हुआ है और मोदी सरकार की दरियादली प्रदेश के लोगों के सामने आई है। आपने शोर मचा दिया कि स्कीम बन्द हो गई, बन्द हो गई। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि मैं गाजे-बाजे के साथ इसका प्रचार करुंगा। उन्होंने गाजे-बाजे के साथ ही नहीं वरन् इसके लिए38 , 699करोड़ रुपये दिया और जब से यह स्कीम चली है, इसमें इस बार सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश को बजट मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने वित्त सचिव का बयान पढ़ा था, एक बयान आया कि प्लान डिसकॉन्टीन्यु हो गया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान समाचार-पत्र में आया कि भारत सरकार ने इस प्लान को डिसकॉन्टीन्यु कर दिया है। ऐसा झूठा प्रचार करके प्रदेश के लोगों को गुमराह किया गया। जो फण्डिंग योजना आयोग या नीति आयोग करता था अब वह फण्डिंग वित्त मंत्रालय कर रहा है। इसलिए वित्त सचिव महोदय या तो सही तथ्य रखें या अपनी स्टेटमेंट को सुधारें और सही तथ्य समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रदेश के लोगों तक जाना चाहिए---जारी

एम.एस. द्वारा जारी

25/03/2015/1450/MS/JT/1

श्रीमती सरवीन चौधरी जारी--------

वरना अपनी स्टेटमैंट को सुधारे और सही तथ्य दुबारा अखबारों के माध्यम से प्रदेश के लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसको करने के लिए वित्त सचिव को कतराना भी नहीं चाहिए क्योंकि जब प्रदेश को इतनी बड़ी रकम मिली है तो उस तरह से जिस तरह से पहले अखबारों में समाचार छपे, यह समाचार दुबारा छपना चाहिए और सुधरकर रिपीट होना चाहिए कि मोदी सरकार ने इतना ज्यादा पैसा हिमाचल को दिया है।

जितना आपके समय में हमें पांच साल में पैसा नहीं मिला, उससे ज्यादा पैसा एक साल में केन्द्र से मिला है।

मुख्य मंत्रीः आप और जो मर्जी बोल लो लेकिन यह कहना कि इतना पैसा मिला जितना पांच साल में नहीं मिला, एक साल में मिल गया। We are grateful for what we got. मगर ऐसा बढ़ा-चढ़ाकर मत बोलिए। यह आपको शोभा नहीं देता।

श्रीमती सरवीन चौधरीः मुख्य मंत्री जी, कृपा करके आप इस बारे में अपने रिप्लाई देते समय बोल लें। हम फैक्ट्स रखकर बोल रहे हैं। मुख्य मंत्री जी, प्रदेश की जनता को दो ही चीजें चाहिए होती हैं। एक कानून-व्यवस्था, जिसको बहाल करने में आप पूरी तरह से फेल हुए हैं और दूसरा विकास। दोनों चीजों में कांग्रेस सरकार बुरी तरह से फेल हुई है और ऊपर से आप सुनना भी नहीं चाहते। आपमें धीरज भी नहीं है। आप छोटी-छोटी बातों पर स्टेटमैंट देने उठ जाते हैं। मैं बहुत लम्बी बात नहीं रखूंगी। आज जिस तरह से शिमला के आसपास सिर कटी लाशें मिल रही हैं, अनक्लेम्ड लाशें मिल रही हैं, ब्लाइंड मर्डर हो रहे हैं, इसकी बहुत लम्बी कहानी है। कभी लाशें मशोबरा में मिल रही हैं, कभी कहीं मिल रही हैं। यहां तक की एक महिला को गाड़ी के नीचे कुचला गया है। महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर यह एक बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न है। आरोपी पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। जेल में भेजे कि नहीं भेजे या उससे पहले उन्होंने जमानत करवा ली। ये सारी कानून-व्यवस्था की लम्बी कहानी है। इस कहानी को हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इस बारे में मेरे साथियों ने यहां पहले ही काफी बोल दिया है। आज क्राइम करने वालों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है। इसलिए आपकी सरकार को कानून-व्यवस्था पर खास ध्यान देना पड़ेगा।

25/03/2015/1450/MS/JT/2

यही नहीं दीप कमल ऑफिस के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ है और राजेश शारदा जी की एम0एल0सी0 तक नहीं बनने दी। नॉर्मल FIR हुई। उसमें जो डिले हुआ, दिखता है। यही नहीं SFI के ऑफिस के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, यह सत्ता का नशा है। इस नशे में आज कांग्रेस के लोग चूर हुए पड़े हैं। इससे हमें बचना चाहिए। इस तरह की छोटी-छोटी हरकतों को सिर्फ सत्ता के माध्यम से पूरा करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए।

पिछले दिनों मुख्य मंत्री जी का एक दौरा कांगड़ा जिला में हुआ। बहुत वाह-वाह लूटी और तालियां बजीं। बहुत अच्छा लगा। फूलों के हार भी पड़े। पूछना चाहती हूं कि किस बात के लिए? जहां भी आप गए ,मेरा इस सदन में दावा है। जिस मंच पर आप गए, जहां पर आपने शिलान्यास/उद्घाटन किया, झूठ का पुलिन्दा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कामों का श्रेय लिया आपने। (व्यवधान) मुख्य मंत्री, अब मैं आपको नहीं बोलने दूंगी।

मुख्य मंत्रीः आप मेरी गाड़ी में बैठीं। मैंने आपको लंच करवाया और फिर आप ऐसी बातें बोल रही हैं?

श्रीमती सरवीन चौधरीः मुख्य मंत्री जी, कृपया मुझे बोल लेने दीजिए। आप अपना एक्सप्लेनेशन बाद में दे देना। बहुत हो गया। मुख्य मंत्री जी मैं आपको स्मरण करवाना चाहती हूं। एम0एल0ए0 प्रायोरिटी हमारा अधिकार है, हमारा हक है। आप जिला कांगड़ा गए। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र से बात शुरू करना चाहती हूं। आपने दो चीजों का उद्घाटन किया ,मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मुख्य मंत्री हैं, इनका अधिकार है। मैंने अपने समय में एक शिलान्यास किया था, मैं पैसे लाई थी। मुख्य मंत्री जी प्रदेश के राजा है, ये उद्घाटन कर लें, मैंने भी तालियां बजा ली, उस में कोई हर्ज नहीं हुआ। लेकिन मुझे तब हैरानी हुई जब इन्होंने दो कूहलों का शिलान्यास किया। राज कूहल और बड़ी कूहल। बाली जी आप सब मंत्री तो कांगड़ा के हैं। आप ज्यादा जानते होंगे। सभी पड़ोसी लोग यहां बैठे हैं। मैं यह पूछना चाहूंगी कि जिस कूहल का तीन-तीन बार टैण्डर हो चुका हो, ठेकेदार काम कर रहे हों, वह बड़ी कूहल लगभग पूरी होने वाली थी, उसका शिलान्यास कर दिया। यही नहीं मेरा यह भी आरोप है और मुझे लगता है कि कभी भी कोई भी पार्टी सत्ता में आए, हमारे

25/03/2015/1450/MS/JT/3

जो हक हैं, हमारा जो प्रिविलेज बनता है, उसका ध्यान रखा जाए। जो स्कीम्ज विधायक प्राथमिकता की हैं, उसका आप शिलान्यास भी करते हैं, उसका उद्घाटन भी करते हैं। संजय रतन शायद पहले विधायक नहीं थे, उनकी प्रायोरिटीज नहीं होंगी।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

25.03.2015/1455/जेके/जेटी/1

श्रीमती सरवीण चौधरीः-----जारी------

सुधीर जी के आप गए, श्री किशोरी लाल जी के आप गए और जगजीवन पाल जी के आप गए। इन विधायकों के नाम पत्थरों में लिखें थे मैंने अखबारों में देखा। मैं केवलमात्र एक महिला एम.एल.ए. थी। कांगड़ा से आपने अपने नाम के साथ यदि आप का बस चलता तो किसी और का नाम लिखा देते लेकिन आप लिखवा नहीं सकते थे। एम.एल.ए को बाईपास आप कर नहीं सकते थे। आपने किसी भी पत्थर के ऊपर हमारा नाम लिखाना वाज़िब नहीं समझा। जबकि वह विधायक की प्राथमिकता थी न कि मुख्य मंत्री की प्राथमिकता थी। सदन के सभी माननीय सदस्यों का सम्मान करना चाहिए, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों। जब हमारी प्रायोरिटी है तो हमारा हक भी बनता है। मुझे लगता है कि सारे सदन को इस बारे में विचार करना होगा। मनमर्जी नहीं चलेगी। उन अधिकारियों को भी पूछा जाए। मैंने उन अधिकारियों को पूछा। उन्होंने कहा कि यह ऑर्डर तो ऊपर से आया। मैंने कहा कि यह कोई आसमान से तो नहीं आया। किस आथौरिटी ने आपको बोला कि मुख्य मंत्री का नाम होना चाहिए और मैडम का इसमें नाम नहीं होना चाहिए? वे क्या बोलेंगे? कभी समय आएगा तो अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। उस पत्थर पर एक नाम क्यों लगाया गया? माना कि मुख्य मंत्री है। माना कि आपकी सरकार है। लेकिन हमारा भी हक है और हम भी अपना प्रिवलेज रख सकते हैं। इसलिए इस चीज को सुधारा जाए। आज शाहपुर के लोग जानते हैं कि आपने कुछ नहीं दिया। यदि कॉलेज दिया तो वह भी रूसा की रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है। वह भी मैंने उस समय सारे एन.ओ.सी. उन पंचायतों की दी थी। फिर रूसा के अन्तर्गत वह आता है। वहां पर लेंड भी अवेलेबल थी, स्टुडैंट्स भी अवेलेबल थे इसलिए आपको वह करना पड़ा। आपका धन्यवाद। आपने इसे अपने श्रीमुख से किया। कौल सिंह जी अभी यहां पर नहीं है आपने अपनी गवर्नर स्पीच में बोला कि इतने हॉस्पिटल कर दिये । विक्रम जी आपने बिल्कुल सही कहा और आपने अपने हॉस्पिटल की पीड़ा यहां पर बताई। मैं यहां पर यह कहना चाहती हूं कि आपने कहा कि 7 सीविल हॉस्पिटल कर दिये। यह सारे का सारा झूठ

25.03.2015/1455/जेके/जेटी/2

का पुलिन्दा है। आप लोग ने भाजपा के समय में किए हुए कामों की नोटिफिकेशन विद्ड्रा कर दी। उसके बाद दे देते हैं और किताबों में बार-बार छपवाते हो। हमारे वहां सिविल हॉस्पिटल की बात की है। सिविल हॉस्पिटल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी की देन से बना था। उसकी मेरे पास फोटोग्राफ भी है। मैंने इस बारे में प्रश्न भी किया था। मेरा वहां पर आज भी स्टोन लगा हुआ है। आपकी सरकार ने उस नोटिफिकेशन को विद्ड्रा किया। आपने हमारी एस.डी.एम. ऑफिस की नोटिफिकेशन को विद्ड्रा किया। हॉस्पिटल की नोटिफिकेशन को विद्ड्रा किया। आपने खोली प्रोजैक्ट-॥ की नोटिफिकेशन शाहपुर से विद्ड़ा किया। अब आप लोग शाहपुर में आकर दोबारा-दोबारा आ कर ड्रामा कर रहे हो। वहां पर दोबारा-दोबारा जा करके वहां पर एनाऊंसमैंट कर रहे हो। आप किस बात की एनाऊंसमैंट कर रहे हो? आपने क्या बयान दिया? केवल वाहवाही और तालियों से काम नहीं चलना चाहिए। हम बहुत प्यार से आपका सम्मान करते रहे। आने वाले समय में केवल राजनीति नहीं होगी, ग्राऊंड पर आ करके आपको काम करना पड़ेगा। इसी तरह से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहूंगी कि आपके समय में डी.पी.आर. तक नहीं बनी। जबकि इस सरकार का यह तीसरा बजट है। आपकी प्लानिंग की भी मीटिंग हो गई है। पहले तो प्लानिंग में हम अपनी डीमाण्ड देते हैं फिर डी.पी.आर. बने या या बने वह भी आपकी इच्छा के ऊपर है। उसके बाद वह डीमाण्ड यदि नाबार्ड में चली गई तो उसमें भी टाईम लगता है। उसके बाद फारैस्ट क्लीयरैंस में भी समय लगता है फिर आपकी सरकार कब काम करेगी? मेरे वहां तो कांग्रेस के ठेकेदार भी कहते हैं कि मैडम बहुत-बहुत धन्यवाद और वे सभी बहुत खुश हैं। आप जब भारतीय जनता पार्टी के समय में मंत्री थे और आपकी जो स्कीम चली उसमें करोड़ों-अरबों रूपया आया। हमारा पेट तो उसी से आज भी चल रहा है लेकिन आगे पता नहीं क्या होगा? यह सत्य है मैं इन बातों को इस

25.03.2015/1455/जेके/जेटी/3

माननीय सदन में कह रही हूं। आप लोग यह भूल जाओ कि आपके समय में कोई नया विकास होने वाला है। मुझे शक इसलिए है कि दो प्लानिंग की मीटिंग हो गई है

और अब एक बची है। अगला तो फिर चुनावी वर्ष होगा। यदि कोई स्कीम की डी.पी.आर. नाबार्ड में चली गई तो वहीं पर फंसी रह जाएगी। आपके अंतिम शेयर की बात में करना चाहूंगी। आपने कहा है कि पन्नों तक ही सीमटा है किताब की बात कहां कर रहे हो। ये पन्ने ही बिखरे रह जाएंगे। एक पन्ना प्लानिंग के पास गया और दूसरा नाबार्ड के पास तीसरा फारैस्ट के पास और यह पन्ने ही बिखरते रहेंगे किताब नहीं बन पाएगी। आप आसमान को झूने की बात कर रहे हो। ग्राऊंड पर तो काम कर लीजिए। कुछ नया तो कर लीजिए। कुछ दे तो दीजिए। कुछ नया तो कर लीजिए। डी.पी.आर. तो बना दीजिए। आप लोगों से कुछ नहीं हो रहा है। केवल किताब पढ़ करके ही आप लोग अपना काम चला रहे हैं। आपने यहां पर दैनिक भोगी कर्मचारियों की बात कही। धूमल जी ने उनकी दिहाड़ी 70 से 150 रूपये की थी। आपने उसमें पिछली बार 20 रूपये बढ़ा करके 170 रूपए किया था। अच्छा होता अब 200 रूपए बढ़ाते, क्योंकि 10 रूपए बढ़ाने से उनके पास एक महीने में 300 रूपया आया वह तो आजकल एक नॉरमल जो क्लर्क है उसकी एक दिन की तन्ख्वाह है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----------

25.03.2015/1500/SS-AG-JT/1

श्रीमती सरवीन चौधरी क्रमागतः

अच्छा होता जो 10 रुपये के हिसाब से आपने बढ़ाया है इसको आप 200 रुपये करते तो और भी बढ़िया रहता।

इसी तरीके से मैं केन्द्र के निर्भय फंड के बारे में चर्चा जरूर करना चाहूंगी। एक हजार करोड़ रुपया दिया है। उसी के साथ-साथ इस बजट में महिला आयोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। कोई बजट का प्रोविजन नहीं किया। महिलाओं का सोशल स्टेटस क्या है, उसका सर्वे कैसे होगा? हमने उसमें कोई प्रोविजन ही नहीं किया। यहां पर निर्भय फंड में केन्द्र ने जो एक हजार करोड़ रुपया दिया है इससे कम्युनिकेशन और बाकी चीज़ों में महिला सुरक्षा की बातें सामने आयेंगी। हमारे यहां पर महिला बटालियन हैं। प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी के समय में 3-3 महिला कॉंस्टेबल हर थाने में देने की बात कही। उससे महिलाओं में कॉंफिडेंस आया। वे अपनी बात को कह सकती थीं। कई बार थानेदार बात नहीं सुनता तो महिलाओं के आगे अपनी रिपोर्ट कर सकती थीं। आपने दो महिला थाने प्रदेश में अभी खोले। इससे पूरी महिला

सुरक्षा नहीं हो सकती। इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। केवल दो महिला थाने खोल देने से बात नहीं बनेगी। जो तीन-तीन महिला कॉंस्टेबल हर थाने में देने की बात है उसको सुदृढ़ करें। उसको निश्चित करें। चाहे इंटीरियर का हमारा पुलिस थाना है या शहर का है सब जगह महिलाएं तैनात हों। सिफारिश से कई जगह 5-5, 6-6 महिलाएं बैठी हैं उसका भी ध्यान रखें। हर थाने में महिला कॉंस्टेबल जरूरी है क्योंकि महिला थाने बनते बहुत समय लगेगा। जिस हिसाब से यहां पर दो-दो महिला थानें बनने की स्पीड चली हुई है।

हमारे सभी लोगों ने बेरोजगारी भत्ते की बात कही है। बाली जी, आप भी इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकेंगे। आपने भी इसके ऊपर कई बार स्टेटमैंटस दीं। सरकार ने कौशल विकास भत्ते की बात की। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि प्राइवेट कम्पनियों द्वारा लूट हो रही है। दुकानें खुल गई हैं और यह कौशल विकास भत्ता भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। अब कौशल विकास भत्ते का दाखिला शुरू है। अगर ऐसे पम्फलैटस आयेंगे कि फलां दुकान के पीछे या आगे खुल गया है। बीच में क्या है? इस तरह के पम्फलैटस हैं। मैं इसे माननीय सदन में रख दूंगी। मैं यह कहना चाहूंगी कि फैशन डिजाइनिंग, कटिंग, टेलरिंग का एक साल का कोर्स, योग्यता आठवीं, दसवीं, इससे ऊपर सर्टिफिकेट सरकारी संस्था से मिलेगी। कमाल है।

25.03.2015/1500/SS-AG-JT/2

छोटी-सी दुकान में ये सब खोल कर बैठ गए और सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? अगर उनका कौशल बढ़ाना है तो आई0टी0आईज़0 के माध्यम से इसको कर दीजिए। वहां पर कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। कोई इस तरह से बाज़ार में बैठे हुए लोग नहीं करेंगे। बैच स्टार्ट विद इन 15 डेज़, इन्होंने इसमें सारा कुछ अपनी मशहूरी के लिए दे रखा है। ऐसा कौशल मत करो जो हिमाचल के युवाओं को बेकार कर दे। उनका समय और पैसा बरबाद करे। कौशल विकास भत्ता कांग्रेस का झूठ का पुलिन्दा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे कुछ नहीं होने वाला। कृपया इन दुकानों को बंद कर दीजिए। ये जो दुकानें खुली हैं, कृपया इनको बंद कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि न तो यह मान्यता प्राप्त होगा और न ही यहां पर सर्टिफिकेट मिलेंगे।

आपने एल0ई0डी0 की बात कही। अच्छा होगा कि आप इस सदन में वायदा करो कि प्रदेश के लोगों को सी0एफ0एल0 की भांति ये मुफ्त मिलेंगे। जिस दिन आप बजट पास करेंगे उस दिन आप यह एनाऊंस करो कि सी0एफ0एल0 की तरह एल0ई0डी0 मुफ्त दिए जायेंगे। हम भी आपका धन्यवाद करेंगे जब आप इसको प्रदेश के लोगों को देंगे। नकल ज़रूर की है। लेकिन अमलीजामा नहीं पहना सके। बिलों में पैसे दे रहे हैं।

पठानिया जी, ऐसा है जिस तरह से बिजली के बिल आ रहे हैं इनको भी चैक करो। पुराने मीटर ठीक चल रहे थे। आपने नये लगा दिए, हम चुप रहे। पुरानों को पता नहीं क्या किया। फेंक दिए या क्या किया। किसको फायदा दिलाया? नये मीटर ज़रूर लग गए। जिस तरह से बिजली के बिल आ रहे हैं हैरानी की बात है। चार-पांच हज़ार रुपये आ रहे हैं। लोग इससे परेशान हैं आप इसको चैक करें। आपकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आप कांगड़ा के मंत्री हैं और प्रदेश के भी मंत्री हैं। जिस तरह से मैंने कांगड़ा में बिल्ज़ को देखा है बहुत हैवी बिल हो गया है। विभाग कहां पर फॉल्टी है? इसको आप चैक करवायेंगे। क्योंकि आप पिछले पांच साल के बिलों को देख लें और नये बिलों को भी देख लें। प्लीज़ आप इसको अच्छे से चैक करें।

अच्छा होता, आज जिस तरह से समाज में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है उस पर कोई ठोस कदम उठाते।
जारी श्रीमती के0एस0

25.03.2015/1505/केएस/एजी/1

श्रीमती सरवीन चौधरी जारी---
यहां किसी विधायक ने बोला था, यह बात सच है क्योंकि हम राजनीतिक प्राणी है, हमें अच्छे में भी जाना पड़ता है और लोगों के बुरे में भी जाना पड़ता है और सबसे ज्यादा बुरा मुझे तब लगता है जब 20 से 25 साल तक के उम्र के बच्चों के मरने की खबर सुनते हैं। जब हम उनके घर जाते हैं, माता-पिता क्या करेंगें, वे तो लीपापोती करेंगे ही लेकिन सबको पता है कि ड्रग्ज़ के कारण उनकी मौत हो रही है। आप इस प्रदेश में एक सर्वे करवाओ कि कितने बच्चे आज के दिन में ड्रग्ज़ से ग्रस्त हैं और कितने मर रहे हैं। इस चीज़ की आप चिंता करते और जिस तरह से केन्द्र सरकार ने

नशे की प्रवृत्ति को कम करने के लिए तम्बाकू और बाकी चीजों पर टैक्स की बात कही है, यहां पर अगर टैक्स नहीं लगता है तो किसी और तरीके से समाज को कैसे सुधार सकते हैं, उसके बारे में बजट कुछ नहीं कह रहा है। हमारे बजट में उसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए कि कितनी दवाइयां ऐसी होंगी, बच्चों को दी जाएंगी जिससे बच्चों के नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके।

आपकी तीन सालों की जो बजट की किताबें हैं, उनको अगर हम चैक करें, जो पीछे नहीं हुआ, वह पीछे की किताब में छूट गया। अगला और नया छाप दिया । यह विश्लेषण तो अभी अगले साल फिर होगा आपके कामों का लेकिन उर्जा के क्षेत्र में जिस तरीके से वर्ष 2013-14,2014-15, 2015-16 में पांच हजार मैगावाट बिजली का उर्जा विभाग ने वायदा किया था और अब तक आपके इस बजट में 956 मैगावाट बिजली बनी है, हम चाहेंगें कि जो भी आप किताब में छापें वह सच्चाई पर आधारित हो, उसको अमलीजामा पहनाया जाए। आप कहते बड़ी-बड़ी बातें हैं और उसका रिज़ल्ट बहुत कम निकलता है। कहां पांच हजार मैगावाट और कहां 956 मैगावाट? इसी तरह से टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो घाटे में चल रही है, मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उसमें भी कोई वाईस चेयरमैन है। कई ऐसी कार्पोरेशन्ज़ हैं। मैं चाहूंगी कि जो घाटे में कॉर्पोरेशन चल रही है, कम से कम उन बेचारों को कोई और कॉर्पोरेशन दे देते। कॉर्पोरेशन ही अगर घाटे में है तो बोर्ड का क्या होल होगा? इसी

25.03.2015/1505/केएस/एजी/2

तरीके से केन्द्र से आपको 350 करोड़ का रेलवे का बजट मिला है। रेलवे में हिमाचल सरकार को कुछ वायदा किया कुछ अंशदान देने की बात की है। हम केन्द्र के भी धन्यवादी है कि हमें रेलवे बजट के रूप में 350 करोंड़ रुपये आए हैं। एक मैं बात कहना चाहूंगी कि आपने करूणामूलक आधार पर जो नौकरियों की बात की, आपने उसमें इन्कम में वृद्धि की है 1.25 से 1.50 रु0 किया है लेकिन अभी तक किसी को नौकरी मिली नहीं है1 आप इसको डेढ सौ से ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं लेकिन इसमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह प्रश्नचिन्ह् है। हम चाहेंगें कि आने वाले समय में आप ये नौकरियां जरूर देना केवल इसी चीज़ से खुश मत कर देना कि हमने इन्कम बढ़ा दी।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्या, कृपया वाइंड-अप करें।

श्रीमती सरवीन चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, लेंटाना के बारे में कहना चाहूंगी। लेंटाना की बात पिछले बजटों में आई लेकिन अब गुल्ल हो गई पता नहीं शायद अब लेंटाना हमारे हिमाचल प्रदेश में खत्म हो गया होगा । आप एक सर्वे करवाओ कि वह खत्म हुआ कि नहीं हुआ। उसके पैसे गए तो कहां गए? पैसों की बड़ी बात है, पैसे स्कीम्ज़ के ऊपर लगते हैं या नहीं, कहां जाते हैं इसके ऊपर भी हमें पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक आपने ब्यास नदी पर सर्वे करवाया है । ब्यास नदी के ऊपर कंसलटैंसी सर्विसिज़ की बात कही । आपने दो बार सर्वे करवाया । क्या कारण था, सर्वे के ऊपर पैसे लगते हैं । सर्वे के आंकड़े वही है लेकिन इस पैसे का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं यह चिन्ता की बात है। आपने बंदरों की नसबंदी के बारे में कहा इसमें करोड़ों रुपयों का जो फर्क आया है इसको भी चैक करें कि यह कार्यकर्ता लूट है कि बंदर लूट है। क्योंकि करोड़ों का डिफरैंस फीगर्ज़ में आया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा---

25.3.2015/1510/ag/av/1

श्रीमती सरवीन चौधरी ----जारी

यह कोई कार्यकर्ता लूट तो नहीं या बंदर लूट है क्योंकि फिगर्ज में करोड़ों रुपये की भिन्नता आई है। मेरा मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन है कि आप इस बारे में पूरी तरह से ऑडिट करवाये। आप यहां पर एक ही चीज के लिए दो-दो, तीन-तीन बार सर्वे करवाते हो। सर्वे वही है, वही आंकड़े हैं मगर कम्पनीज को दो-दो बार पैसे दिए जाते हैं।

मुख्य मंत्री : मैडम, कुछ कटसी की बात भी होती है। इतने सीनियर आपके सामने बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं और आप कौन सी बात कर रही है? (बीच में माननीय वन मंत्री जी द्वारा कुछ बोलने के लिए खड़े होने पर कहा।) आपको कटसी की समझ है? If somebody gets up, you must sit down.

श्रीमती सरवीन चौधरी : माननीय मुख्य मंत्री जी, मुझे उपाध्यक्ष बोलेंगे तभी कटसी दिखा सकती हूं। मुख्य मंत्री जी, मुझे कटसी आती है। मुझे पता है कि कटसी क्या चीज होती है। कटसी वह होती है जिसमें किसी को सम्मान दिया जाए। जिस तरह से आपके वाइस चेयरमैन ने मुझे बोला कि आप सोफे से उठ जाओ; क्या वह कटसी थी? हां, मैं बोलना नहीं चाहती थी। आपके एक सरकारी प्रोग्राम में मुझे कहा गया कि यह कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है, आप यहां से चले जाओ। सरकारी पैसों के ऊपर, सरकारी गाड़ियों पर, सरकारी खाने पर; आपने कह दिया, क्या वह कटसी थी? आप मुझे कटसी बता रहे हो। (---व्यवधान---) पत्रकार जानते हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं कि उसने इस तरह से कहा। (---व्यवधान---)

मुख्य मंत्री : मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। वह पार्टी की रैली थी।। cannot take her to Party rally.

श्रीमती सरवीन चौधरी : मुख्य मंत्री जी, आपने नहीं कहा। मैं आपकी बात मानती हूं और आपका सम्मान करती हूं। मैंने आपको नहीं कहा। आपने नहीं कहा मगर आपके सामने कहा गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच को (---व्यवधान---)

25.3.2015/1510/ag/av/2

उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइए। माननीय वन मंत्री जी, बोलिए। आप क्या बोलना चाहते हैं?

वन मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो अभी फरमाया कि दो बार सर्वे हुआ it is not in the knowledge of the Government. आप पता नहीं कहां की बात कर रही हैं और कहां का सर्वे है? जहां तक आप मंकी सटरलाइजेशन के आंकड़ों की बात कर रही है कि गलत है। उसकी टोटल फिगर 94 हजार है। यह फिगर गलत नहीं है। यह बिल्कुल ठीक फिगर है। इसके अलावा आप जो फरमा रही हैं इसकी छानबीन करवाई जायेगी, then I will let you know.

श्रीमती सरवीन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यह कहना चाहती हूं कि यहां सब कुछ बिकता है, दोस्तों जरा रहना सम्भलकर। (---व्यवधान---) मैं खत्म कर रही हूं। प्लीज, मैं खत्म कर रही हूं।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप एक मिनट बैठिए। बैठिए, आप।

मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर और लोगों ने भी बोलना है। She is speaking for half an hour now. आधा घंटा तो धूमल साहब भी नहीं बोले। माननीय सदस्या धूमल साहब से भी ज्यादा बोलना चाहती है। (---व्यवधान---) नहीं, बिल्कुल नहीं। (---व्यवधान---) She is taking advantage of being a lady.

श्रीमती सरवीन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट लेना चाहूंगी। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि :-

यहां सब कुछ बिकता है दोस्तों, जरा रहना सम्भल के।
बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं, गुब्बारों में भरकर॥
सच्च बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती हर कहानी।
तीनों लोकों में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में पानी॥

25.3.2015/1510/ag/av/3

एक जमाना था हम बावड़ियों का ही पानी पीते थे मगर आज कोई बोतल के पानी के अलावा पानी पीता नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि आप गुब्बारे मत बनों। परिन्दें मत बनो, इनसान बन जाओ इतना ही बहुत है। हवा में मत उड़ो, वास्तविकता में रहो ताकि हम सब मिलकर प्रदेश के विकास की चिन्ता कर सकें।

आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद। मैं इस बजट के पक्ष में नहीं बोल सकती हूं और न ही इसका समर्थन कर सकती हूं।
समाप्त

25.3.2015/1510/ag/av/4

श्री राकेश कालिया : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, प्रदेश के मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने 18 तारीख को जो यहां 18 वीं बार बजट पेश किया है मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह अपने-आप में एक हिस्ट्री है कि मुख्य मंत्री जी 18 वां बजट पेश कर रहे हैं। हिन्दुस्तान में इनका एक अपना इतिहास है। इन परिस्थितियों में जहां केंद्र सरकार ने हमारी कई योजनाओं के ऊपर कटौती लगा दी है चाहे वह 90:10 का अनुपात था या 80:20 का अनुपात था। उनके ऊपर कटौती लगाने के -----

श्री नेगी द्वारा जारी

25.3.2015/1515/negi/jt/1

श्री राकेश कालिया.. जारी..

उनके ऊपर कटौती लगाने के बावजूद मुख्य मंत्री महोदय ने एक बेहतरीन बजट जिसमें सभी वर्गों के हितों की बात कही गई है, चाहे महिलाएं हों, युवा हों, बेरोजगार हों, किसान हों और कर्मचारी हों सभी के हितों की बात मुख्य मंत्री महोदय ने इसमें की है, मैं उसके लिए मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। सबसे पहले मैं मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने 922 करोड़ रूपये जो ऊना जिला में स्वां नदी का चैनेलाइजेशन हो रहा है उसके लिए इतनी बड़ी रकम दे कर आपने हमें अनुगृहित किया है । क्योंकि जो स्वां नदी है उसको Sorrow of Una District कहा जाता था। अगर एक घंटा भी बारिश होती थी तो जैसे थाली में एक मग पानी का डाल दो, उस तरीके से खड्डों से पानी बाहर हा जाता था। हमारी नदी की चैनेलाइजेशन तो हो ही गई लेकिन आप खड्डें भी चैनेलाइजेशन करा रहे हैं। उसके लिए आपने पूरे देश में एक हिस्ट्री बनायी है । जहां आज गंगा-यमुना को चैनेलाइज करने की बातें हो रही है वहां आपने यह ऊना जिला का सपना पूरा करके दिखाया है । उसके लिए ऊना जिला के लोग आपके सदा ऋणी और आभारी रहेगी। मुख्य मंत्री महोदय मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में मेहतपुर-जलेडा-अम्ब रोड था, 5 साल हम लोग मिट्टी खाते रहे लेकिन भाजपा सरकार ने हालांकि पैसा मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी दे करके गए थे और ये 5 साल उस रोड को कम्प्लीट नहीं करवा पाये। जबकि आपने आते ही पहले 6 महीने

में ही इस रोड को पूरा कर दिया और अब वहां एक बेहतरीन सड़क बनी हुई है । इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री महोदय का आभारी हूं। भाजपा के लोगों ने उसके लिए एक नये पैसे का काम नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, ऊना में 66 करोड़ रूपये की लागत से पुल बनाए जा रहे हैं जिसमें से 11 करोड़ रूपये के पुल मेरे क्षेत्र में हैं इसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। मुख्य मंत्री महोदय, इन्होंने पिछले 5 साल गगरेट क्षेत्र के लोगों को बहुत सपने दिखाए कि हम कालेज का पूरी तरह से सरकारीकरण कर

25.3.2015/1515/negi/jt/2

देंगे। लेकिन आपने पिछले साल वहां दौरा किया और घोषणा की और अब उसकी सरकारीकरण की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मुख्य मंत्री महोदय, चिन्तपूर्णी एक धार्मिक स्थल है और वहां पर 45 करोड़ रूपये की लागत से एक मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बन रही है उसके लिए भी आपका धन्यवाद है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जब हम प्लानिंग की मीटिंग में धूमल साहब से बात करते थे कि हमें टयूब-वैल लगाने के लिए पैसा दीजिए लेकिन धूमल साहब एक ही जवाब देते थे कि ऊना जिला के ज़मीन में पानी नहीं है। लेकिन अभी मुख्य मंत्री महोदय ने हमारे क्षेत्र के लिए 20 करोड़ रूपये इरिगेशन के लिए, टयूब-वैल्ज़ लगाने के लिए स्वीकृत किया है और इसमें से 7 करोड़ रूपये मेरे क्षेत्र में खर्च होगा इसके लिए भी हम मुख्य मंत्री महोदय का बहुत आभारी हैं। मुख्य मंत्री महोदय, पिछले दिनों गगरेट क्षेत्र के दौरे पर आए थे और इन्होंने मेरे क्षेत्र में बहुत सारी घोषणाएं की । मेरे क्षेत्र की एक बहुत पुरानी डिमाण्ड थी कि वहां पर एक तहसील होनी चाहिए और मुख्य मंत्री महोदय ने वहां इसकी घोषणा की और मेरे क्षेत्र के लोग उस वजह से बहुत प्रसन्न हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब यहां बलबीर जी गगरेट के विधायक थे तो वह धूमल साहब के पास गए और कहा कि धूमल साहब गगरेट क्षेत्र के लोग तहसील के लिए कहते हैं । धूमल साहब ने कहा , काका तेनु पता है गगरेट से अम्ब कितनी दूर है? बलबीर जी ने कहा -जी 10 किलोमीटर। फिर

तेरी तहसील नहीं बन सकती । मैं यह कहना चाहता हूं कि धूमल साहब ने तो गगरेट और अम्ब की दूरी नापी लेकिन गुगलेड जो आखिरी गांव है वहां से अम्ब की दूरी देखो, कितनी दूरी है और गनुमदवाडा से अम्ब की दूरी कितनी है? इन सब चीज़ों का लेखा-जोखा देखकर ,सब छानबीन करके मुख्य मंत्री महोदय ने देखा कि यहां तहसील बनती है और तब तहसील दे दी है। लेकिन भाजपा के लोग इसमें मात्र

25.3.2015/1515/negi/jt/3

राजनीति करते रहे हैं। अभी रवि जी ने बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें की, यह कह रहे थे कि विधायकों से बात करके फिर योजना बनानी चाहिए। मैं कहता हूं कि जितनी बुद्धिमता इनको विपक्ष में जा करके आती है उतनी सत्ता पक्ष में नही आती। अभी एक मैडम सलाह दे रही थी कि हमारे नाम आपने बोर्डों में लिखवाने थे। आपने हमारे कितने लिखवाये? धूमल साहब आई.पी.एच. की स्कीमों की इनोग्रेशन करने गए थे क्या उस समय आपने मेरा नाम लिखवाया था? मैं देखता रहा हूं कि हमारे श्री सतपाल सिंह सत्ती जी और वीरेन्द्र कंवर जी की स्कीमों का अनुराग ठाकुर जी उद्घाटन करते थे और ये दोनों पीछे खड़े हो करके तालियां बजाते थे। ...(व्यवधान) ...जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। आपने जो किया है वह देखो कि आपने क्या किया है? अगर आपने हमारे नाम लगवाए होंगे तो हम भी आपके नाम जरूर लगवाते । नाम नहीं लिखने की प्रथा आपने डाली है।

मुख्य मंत्री महोदय ने सामाजिक सुरक्षा पैशन वृद्धों तथा विधवाओं के लिए 550 रूपये से बढ़ा कर 600 रूपये किया है। 80 साल से अधिक जो बुजुर्ग हैं उनकी पैंशन 1000 रूपये से बढ़ा कर 1100 रूपये किया है। इसी तरह से विक्लांगों की पैंशन 750 रूपये से 1100 रूपये की है।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी..

25.03.2015/1520/यूके/1

श्री राकेश कालिया-- जारी---

तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का इसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा । दिहाड़ी दारों की दिहाड़ी 170 रुपए से बढ़ा कर 180 रुपए की गयी है । आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों का मानदेय भी बढ़ाया गया है, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा । सिलाई अध्यापकों का मानदेय बढ़ा कर 1600 से 2000 रुपए किया है, अंशकालीन जलवाहकों का 1300 से 1500 रुपए मानदेय किया है । होमगार्ड का मानदेय 260 से 280 रुपए कर दिया गया है, उसके लिए भी मैं बड़ा आभारी हूं । दो वर्षों में सरकार ने लगभग 719 नये विद्यालय खोले हैं, जिनमें 100 प्राथमिक पाठशालाएं हैं, 160 स्कूल प्राईमरी से मिडिल किए गए हैं । मिडिल से हाई 234 स्कूल किए गए हैं । 225 सीनियर सकेंडरी स्कूल खोले गए हैं । इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवादी हूं । आपने मेरे क्षेत्र के अन्दर भी स्कूल खोले हैं, 4 स्कूलों मे साईंस और कॉमर्स की कक्षाएं चालू की हैं उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । एक आई0टी0आई0 भी खोली गयी है उसके लिए भी हम लोग आपके बड़े आभारी हैं । ट्यूबवैल्ज़ के लिए 12 करोड़ रुपए, जो पुराने समय के ट्यूबवैल्ज़ थे और बन्द पड़े थे उनको रिएनर्जाइज़ करने के लिए नयी स्कीम बनाई है, उसके लिए मैडम विद्या जी का और राजा साहिब का धन्यवाद करना चाहता हूं । ऊना जिला में एक IIIT और IIM संस्थान सिरमौर जिले में खोलने जा रहे हैं, यह प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है । केन्द्र सरकार की मदद से एम्ज़ के स्तर का एक हॉस्पिटल बिलासपुर में खोला जा रहा है, उसके लिए भी हम आपके अभारी हैं ।

25.03.2015/1520/यूके/2

विधायक निधि, जो सभी विधायकों ने कहा था कि हमारी विधायक निधि बढ़नी चाहिए तो मुख्य मंत्री महोदय हने मारे MLA के इंस्टिट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए 50 लाख से 70 रुपए विधायक निधि की है । उसके लिए हम आपके आभारी ।

आपने भारतवर्ष में सबसे पहले खाद्य वितरण विभाग के लिए सब्सिडी दी थी क्योंकि उस समय खाद्य उत्पादन बहुत महंगे हो गए थे । जिसका पूरे देश ने

अनुसरण किया था और केन्द्र सरकार ने भी उसके ऊपर सब्सिडी देनी शुरू कर दी । तब से लेकर आज तक आप उस योजना को चला रहे हैं, उसको जारी रखने के लिए आपने 219 करोड़ रुपए और दिये है ।

गौ-वंश के संरक्षण के लिए आपने 10 करोड़ रूपए देने की घोषणा की है । शिमला के कार्ट रोड को चौड़ा करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, 3 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है । शिमला शहर की योजना के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार को 1200 करोड़ रुपए की एक योजना भेजी गयी है । यह भी एक सराहनीय कदम है । हिमाचल प्रदेश में हमेशा चाहे बाढ़ हो, भूकम्प हो ऐसी आपदाएं आती रहती हैं । आपने आपदा प्रबन्धन के लिए 236 करोड़ रुपए का बजट रखा है । जिससे यदि जब भी कोई ऐसी घटना होती है, आए दिन सतलुज में बाढ़ आती रहती है, तो उसके लिए आपने यह एक अच्छा बजट रखा है । इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

25.03.2015/1520/यूके/3

हमारे विधायकों ने मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना की था कि हमारी DPR टाईम से नहीं बनती । उसके लिए आपने आऊटसोर्सिंग की बात की है । ऊना जिला में तटीयकरण का काम और बढ़ाने के लिए संतोखगढ़ पुल से पंजाब सीमा तक आप स्वां नदी का तटीयकरण करवा रहे हैं । उसके साथ ही जो हमारी ब्यास नदी की सारी खड्डे हैं, उनके लिए आपने DPR बनाने के लिए कहा है । तो हमारे क्षेत्र के लोगों को उसका फायदा होगा । लगभग 2 हजार हैक्टेयर जमीन उससे रिक्लेम होगी । जैसे स्वां नदी का चेनेलाइजेशन करवाया है, इसी तरीके से आप कुल्लू जिले में ब्यास नदी का चेनेलाइजेशन करवाने की बात भी आप कर रहे हैं और उसकी DPR बना कर केन्द्र सरकार को भेजी है । ब्यास में भी पानी बहुत ऊपर बहता है, रोड के बिल्कुल साईड में, उससे प्रदेश को फायदा होगा ।

सिंचाई और जन-स्वास्थ्य विभाग के लिए आपने 2013 करोड़ रुपए बजट रखा है, उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं । ऊर्जा संरक्षण के लिए 3-3 LED ब्लब आप दे रहे हैं, जिसके लिए आपने 13.75% से वैट हटाकर 5% किया है ।

इससे लोगों को जो बिजली के बिल ज्यादा आते हैं उससे भी राहत मिलेगी और उससे ऊर्जा संरक्षण भी होगा ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

25.03.2015/1525/sls-jt-1

श्री राकेश कालिया (माननीय मुख्य संसदीय सचिव)...जारी

कांगड़ा जिला के कंदरौड़ी और ऊना जिला के पण्डोगा में नए औद्योगिक क्षेत्र खोल रहे हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री जी का भी आभारी हूं। उसके लिए क्रमशः 112करोड़ रुपये और 107 करोड़ रुपये की राशि आपने स्वीकृत की है। प्रदेश से बाहर और विदेश में नौकरी करने वाले नौजवानों को गाईडैंस की बात आपने कही है और रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से वह गाईडैंस देंगे। सीनियर सेकैंडरी स्कूलों में भी कैरियर गाईडैंस की क्लासिज ली जाएंगी।

एच.आर.टी.सी. ने पहले 510 बसें ली थी अब 800 बसें और ले रहे हैं , उसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। इससे हमारे गांव जिला हैड क्वार्टर और ब्लॉक हैड क्वार्टर से कनैक्ट हो जाएंगे। नाबार्ड की 2381 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ नाबार्ड पार्टनरशिप अवार्ड मिला है जिसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। जो हमारे ढाबा, चाय, हलवाई की दुकानें और चाट की दुकानें हैं, इनको पहले5 . 00लाख रुपये की सीमा तक वैट माफ था, अब यह 8.00 लाख रुपये की सीमा रखी गई है। सरकस, जादुगरी या प्राचीन करतब दिखाने वालों को मनोरंजन टैक्स में छूट दी गई है। जो पांचवीं व आठवीं क्लास के लिए आपने बोर्ड की परीक्षा लेने की बात की है, इससे एजुकेशन सिस्टम सुदृढ़ होगा और हमारी शिक्षा में सुधार आएगा। इसके लिए भी आपका आभारी हूं। मंदिरों के रख-रखाव के लिए भी आपने 5.00 करोड़ रुपये की बात की है। इसी तरह खेल परिसर और छात्रावासों के निर्माण के लिए आपने 35 करोड़ रुपये की राशि रखी है। उससे आप धर्मशाला में एक फुटवाल अकादमी बना रह हैं। यूथ क्लबों को सुदृढ़ करने के लिए आपने 18000 रुपये से 20000 रुपये की राशि देने की बात कही है, जिसके लिए आपका आभारी हूं।

मुख्य मंत्री महोदय, आपने एक बहुत बढ़िया और संतुलित बजट प्रस्तुत किया है लेकिन भाजपा वालों को यह दिखाई नहीं देता क्योंकि उन्होंने ऐसा चश्मा लगाया है कि उन्हें केवल विरोध के लिए विरोध करना है।

25.03.2015/1525/sls-jt-2

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट के समर्थन के लिए बोलने हेतु खड़ा था और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : अब श्री वीरेन्द्र कंवर जी चर्चा में भाग लेंगे।

25.03.2015/1525/sls-jt-3

श्री वीरेन्द्र कंवर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, एक लंबे अनुभव के बाद उन्होंने यह 18वां बजट पेश किया। इस बजट से प्रदेश को बहुत उम्मीदें थीं। क्योंकि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है और केंद्र से जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश को लगातार सहायता मिल रही है ,ऐसा तो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इससे पहले जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती थी और केंद्र में यू.पी.ए. की सरकार होती थी तब माननीय मुख्य मंत्री जी मंत्रिमंडल के साथ बार-बार केंद्र में जाते थे और वहां पर हिमाचल भवन के पास के सारे गुलदस्ते भी खत्म कर दिए, लेकिन न कभी प्रधान मंत्री जी से और न सोनिया गान्धी जी से यह मौका हिमाचल को मिला। नरेन्द्र मोदी जी ने जहां प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग बनाया ,मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष से जो पूर्व वक्ता बोले हैं ,वह अभी तक इस बात को समझ ही नहीं पाए।...(व्यवधान)... मैं समझा रहा हूं कि पिछले पांच वर्षों में केंद्र से जो हिमाचल को पैसा मिलता था ,वह 21238 करोड़ रुपया था, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने ,जो हमारा राजस्व घाटा होता था ,उसको पूरा करने के लिए 40,625 करोड़ रुपये की वृद्धि दी है। अगले पांच वर्षों के लिए यह सारी वृद्धि दी गई। चाहे 90:10 की योजनाएं हैं , चाहे

80:20 की योजनाएं हैं, वह प्रदेश के अंदर अपने अनुसार बना सकते हैं। प्रदेश के अंदर जो योजनाएं बनेंगी, वह प्रदेश के हित में होंगी।
जारी ..गर्ग जी

25/03/2015/1530/RG/JT/1

श्री वीरेन्द्र कंवर-----क्रमागत

जो योजनाएं बनेंगी वे प्रदेश के हित में होंगी। इतनी छूट प्रदेशों को दी गई है, यह छूट फैडरल ढांचे को दी गई है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा सेन्ट्रलाइज करने की रही है चाहे वह राजनीति हो, उसको भी ये सैन्ट्रलाइज रखते हैं या चाहे फैडरल सिस्टम हो। इसमें इनका न कभी कोई योगदान रहा और न ही इनका फैडरल सिस्टम में कोई विश्वास रहा। वर्ष 1947-52 के बाद से हमेशा ही देश-प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें आती रहीं। जब कभी किसी प्रदेश में अगर कोई स्थानीय सरकार आ जाती थी, तो ये उसको गिरा देते थे। शुरू से ही इनकी यह मन्शा फैडरल सिस्टम के प्रति रही है। लेकिन प्रदेशों को ज्यादा मजबूती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पॉलिसीज़ को डिसैन्ट्रलाइज किया है, प्रदेशों को पूरे अधिकार दिए हैं कि वे अपने स्तर पर योजनाएं बनाएं और उन्हें कार्यान्वित करें। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी उपलब्धि कोई और नहीं हो सकती। ये कहते हैं कि किस चीज के लिए हम केन्द्र सरकार का धन्यवाद करें ,हम प्रधानमंत्री जी का किस चीज के लिए धन्यवाद करें? तो प्रधानमंत्री जी इनके धन्यवाद के मुरीद नहीं हैं। उन्होंने तो हिमाचल को पहले वर्ष में ही जहां 40,625 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए दी है वहीं हिमाचल प्रदेश को पहले वर्ष ही आई.आइ.एम. इंस्टीटियुट दिया ,ऑल इण्डिया इंस्टीटियुट ऑफ मैडिकल साइंस का इंस्टीटियुट हिमाचल प्रदेश को दिया ,रेणुका बांध की मंजूरी हिमाचल प्रदेश को दी और लाहौल-स्पिति में सौर ऊर्जा का हब बनाने के लिए, साहसिक खेलों का हब बनाने के लिए पहले वर्ष के बजट में ही प्राथमिकता दी गई है। हम यह नहीं कहते कि आप हमारा धन्यवाद करो। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समय में धूमल जी ने प्रदेश में योजनाएं बनाई थीं।' अटल स्वास्थ्य योजना' के तहत गरीब आदमी के घर-द्वार तक फ्री स्वास्थ्य सेवा पहुंचे , 'अटल विद्युत योजना'' ,अटल वर्दी योजना' ,लेकिन वीरभद्र सिंह जी की सरकार जैसे ही सत्ता में आई ,उसने बदले से, द्वेष की भावना से ,आते ही इन योजनाओं के

नाम बदल दिए। कहते हैं कि आपका क्या योगदान है केन्द्र में तो यू.पी.ए की सरकार है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अब तो यू.पी.ए. की सरकार नहीं है, अब तो केन्द्र में मोदी जी की सरकार है जो आपको 40,625 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दे रही है। अब तो आप 'अटल स्वास्थ्य योजना' में ऐम्बूलैंस का नाम उन्हीं के नाम पर रख दो।

25/03/2015/1530/RG/JT/2

उपाध्यक्ष महोदय, आज उसी तरह से पूरे देश में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार एक टीम इण्डिया की तरह काम कर रही है। वह भेदभाव की भावना से काम नहीं कर रही है। आज माननीय मुख्य मंत्री जी को उनसे सबक ले लेना चाहिए और उनको देखकर आज प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समान विकास करना चाहिए। हम विपक्ष के विधायक तो आहत हैं कि हमारे विधान सभा क्षेत्रों में विकास के काम ठप्प पड़े हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेस के विधायक आहत हैं जो उनके गुट के नहीं हैं उनको भी उसी स्तर पर रखा जा रहा है, जैसे हमें रखते हैं वैसे ही उनको रखते हैं। इसी बात से बहुत से लोग इनकी पार्टी में दुःखी हैं चाहे वह मुख्य संसदीय सचिव हैं वे तो त्याग-पत्र दे चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर पूर्व वक्ता श्रीमती आशा कुमारी जी जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि ये मेरी समिति की सभापति भी हैं। माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री महोदया जो यहां पर कल कह रही थीं कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने कॉरपोरेट बजट प्रस्तुत किया था। इसमें गरीब की भावना नहीं है। अरे, गरीब की चिन्ता तो कांग्रेस के लोग करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस के लोग गरीब की कैसे चिन्ता करते है! मैं इस बात को यहां सदन में कहन चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो इस देश में एक अलग विचारधारा लेकर चली है। यह आर.एस.एस. के रूप में वर्ष 1925 से शुरू हुई है और वर्ष 1952 में भारतीय जनसंघ के रूप में एक विचार यात्रा लगातार इस देश में चलती रही। हम वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में आए----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

25/03/2015/1535/MS/AG/1

श्री वीरेन्द्र कंवर जारी--------

1952में भारतीय जनसंघ के रूप में एक विचार यात्रा लगातार इस देश के अन्दर चलती रही। हम वर्ष 1980में भारतीय जनता पार्टी के रूप में आए और हमने एकात्मक मानववाद की भावना के साथ इस देश और प्रदेश के अन्दर काम किया है। हमारी योजनाओं के अन्दर गरीबी की रेखा में बैठे अंतिम व्यक्ति की चिन्ता हमारी सरकारें करती हैं। भाजपा जनता पार्टी के रूप में पूरे देश के अन्दर, तीन प्रदेशों में आई। हिमाचल प्रदेश के अंदर शांता कुमार जी आए और उसी तरह मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनीं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले 'अन्त्योदय अन्न योजना' इस प्रदेश के अंदर शुरू की। 'विकास में जन सहयोग',' काम भी अपना ग्राम भी अपना' और 'काम के बदले अनाज योजना' हिमाचल प्रदेश में उस समय शांता कुमार जी ने शुरू की थी। उसी तरह से तीनों प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इन योजनाओं के तहत काम करती रहीं। उससे पहले तो कांग्रेस को कभी गरीब के लिए सामाजिक सुरक्षा पैंशन देने की चिन्ता नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की शांता कुमार जी की सरकार ने 50 रूपये की सामाजिक सुरक्षा पैंशन 1970 में शुरू की। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब 1990 में फिर से भाजपा की सरकार आई तो फिर से 'अन्त्योदय योजना' शुरू हुई। जिसके तहत तीन रूपये किलो चावल और दो रूपये किलो गेहूं गरीब आदमी को प्रति परिवार 60 किलो के हिसाब से देते थे। जिसको आज केन्द्र सरकार में सोनिया गांधी जी कहती हैं कि वह तब तक रोटी नहीं खाएंगी, जब तक 'अन्न सुरक्षा योजना' नहीं आएगी। जो 60 किलो गरीब को राशन मिलता था, उसको पहले ही कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश के अंदर घटाकर 40 किलो कर दिया था और अब उसको तीन किलो प्रति व्यक्ति कर दिया। यानी अगर घर के अंदर तीन व्यक्ति हैं तो उनको 15 किलो राशन मिलेगा ,उनको 60 किलो राशन नहीं मिलेगा। उस वक्त फूड सिक्योरिटी कहां गई?

वर्ष 1998 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रो0 धूमल जी के नेतृत्व में प्रदेश में फिर आई। पहले शांता जी ने ही उस सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 50रूपये से 100 रूपये कर दिया था और जब धूमल जी आए तो इन्होंने 100 रूपये से 150 रूपये

25/03/2015/1535/MS/AG/2

किया और फिर 150रूपये से 200 रूपये किया। जब वीरभद्र सिंह जी की सरकार 1993 से लेकर 1998 तक रही तो एक फूटी कौड़ी भी गरीब की पैंशन नहीं बढ़ाई। एक गरीब व्यक्ति की दिहाड़ी जो कांग्रेस के कार्यकाल में 70 रूपये होती थी, उसको 75 रूपये कांग्रेस के कार्यकाल में किया गया। लेकिन धूमल जी ने उस दिहाड़ी को 75 रूपये से बढ़ाकर 150 रूपये किया और कांग्रेस ने उस समय कहा कि हम 200 रूपये कर देंगे, लेकिन कितनी दी? 10 रूपये बढ़ाया। जैसे कल पूर्ववक्ता कह रहे थे कि 10 रूपये में चाय का कप आता है। गरीब की पैंशन सिर्फ 50 रूपये बढ़ाई। जो अंशकालिन जलवाहक हैं, उनके मानदेय में सिर्फ 200 रूपये की बढ़ोत्तरी की। यानी 7 रूपये दिन के बढ़ाए गए। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो मजदूर की दिहाड़ी 75 रूपये से 150 रूपये होती है। 50 रूपये सीधे तौर पर होमगार्ड के बढ़ाए जाते हैं लेकिन ये कितने रूपये होमगार्ड के बढ़ाते हैं? 20 रूपये दिहाड़ी बढ़ाई। यह गरीबों का बजट है? यह गरीबों की चिन्ता करने वाला बजट है? जो गरीबों की चिन्ता करने वाले हैं वे तो कहते हैं कि कारपोरेट का बजट है। मुझे तो हैरानी है कि 10 महीने के अन्दर ही इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश का मान और सम्मान पूरे विश्व के अंदर बढ़ाया है। अगर लंका के अंदर प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वहां पर बौद्ध सभा के चीफ उनको रिसीव करते हैं और उनको लगता है कि महाराजा अशोक के बाद यदि कोई सम्राट इस देश के अंदर आया है तो वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी आए हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों को अपने पड़ोसियों से मिलने का समय नहीं था। श्री नरेन्द्र मोदी 28 वर्षों के बाद भूटान जाते हैं और 28 वर्ष के बाद इस देश का प्रधानमंत्री लंका और नेपाल जाता है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

25.03.2015/1540/जेके/जेटी/1

श्री वीरेन्द्र कंवरः------जारी--------

लंका जाता है, नेपाल जाता है वहां पर सांस्कृतिक भारत की कल्पना आदरणीय दीन दयाल जी ने दी थी। आज वहां सांस्कृतिक भारत के रूप में भारत खड़ा हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश का विशेष ध्यान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी

ने अपने थोड़े से समय में ही रख लिया है। आज इस देश के अन्दर जो विभिन्न योजनाएं आ रही हैं उनको श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के अन्दर लागू कर रहे हैं। आज भारतवर्ष को करोड़ों और खरबों रूपयों का विदेशी निवेश जो भारतवर्ष के अन्दर होना चाहिए था वह भारतवर्ष से बाहर जा करके विदेशी निवेश होता था। उन्होंने इस बात की चिन्ता की कि हम छोटे-छोटे टैंक और मशीनरीज़ क्या तैयार नहीं कर सकते थे? यह कल्पना किसकी है यह नरेन्द्र मोदी जी की है मेक इन इंडिया। जो हजारों, करोड़ों और खरबों रूपया भारतवर्ष से बाहर जा रहा है अगर निवेशकों को चाहिए तो वे भारतवर्ष के अन्दर आए। भारतवर्ष के अन्दर आ करके वे निवेश करें। बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज लगेगी। अगर इण्डस्ट्रीज लगेगी तो इस प्रदेश के नौज़वान बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सारा काम जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और भाजपा की सरकार जब हिमाचल प्रदेश के अन्दर थी तो हमने कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद भी प्रदेश में धूमल जी की सरकार ने काम किए। जहां मज़दूर की मज़दूरी बढ़ाई,गरीब की पेंशन बढ़ाई, अन्त्योदय अन्न योजना लागू की ,अटल स्वास्थ्य योजना हिमाचल प्रदेश में लागू की, बाबा भीमराव अम्बेकर छात्रवृत्ति योजना हिमाचल प्रदेश में लागू की, गरीब अनुसूचति जाति के छात्र को 10हजार रूपए की छात्रवृत्ति दी जाती थी। ठाकुरसेन छात्रवृत्ति योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की थी। कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद भी मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना और गांव के अन्दर एक पॉली हाऊस क्रांति आई। पंडित दीन दयाल योजना के तहत 375 करोड़ रूपए का बजट भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव में गरीब के लिए खर्च किया। मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना शुरू की। इन सारी

25.03.2015/1540/जेके/जेटी/2

योजनाओं के या तो नाम बदल दिए गए या उनका स्थान बदल दिया गया। आज ये जो कांग्रेस के लोग हैं वे मात्र एक गन्दी मानसिकता की वजह से ग्रस्त है। जो यह बजट है उसका हम आज समर्थन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसको राजस्वी मानसिकता के तौर पर देखा जा सकता है। जब हमारी सरकार थी तब हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पर्यटन के लिए शुरूआत धूमल जी ने की थी। ब्रह्मा जी का स्थान ब्रह्मेती जहां पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की है। वह स्थान मेरे और सतपाल सिंह सत्ती जी के क्षेत्र के साथ लगता है ,वहां के लिए आदरणीय धूमल जी ने 50 लाख

रूपए स्नानघाट के लिए दिए थे। माननीय उपाध्यक्ष जी, वहां पर हजारों की संख्या में यात्री आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारी सरकार चली गई लेकिन सिर्फ वहां पर अब थोड़ा सा काम बाकी है। उस काम को पूरा करने के लिए मैंने विभाग को भी लिखा। मैंने पर्यटन सचिव महोदय को भी लिखा और मुख्य मंत्री जी को भी लिखा। लेकिन आज तक 4-5 लाख रूपए तक नहीं दिए गए ताकि उस अधूरे काम को पूरा किया जा सके। उसी तरह से भंगाणा के अन्दर ट्वायलैट ब्लॉक 25 लाख से बना है और वह तैयार हो चुका है लेकिन उसको आज तक चालू नहीं किया गया है। वहां पर पर्यटन के माध्यम से एक बड़ी लाईट लगाई गई थी लेकिन आज वह लाईट भी बन्द पड़ी है। मैंने अपने प्रश्न के माध्यम से पर्यटन के बारे में पूछा था। मेरा प्रश्न 1677 था। वर्ष 2008 से लेकर 2012 तक पर्यटन विभाग द्वारा कितनी धनराशि कुटलैहड़ क्षेत्र के अन्तर्गत खर्च की गई? इसका ज़वाब आया कि जहां ब्रह्मेती के अन्दर वहां पर पर्यटन विकसित करने के लिए पैसा खर्च हुआ।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

25.03.2015/1545/SS-AG/1

श्री वीरेन्द्र कंवर क्रमागतः

लेकिन साथ में कहा गया कि टॉयलैट ब्लॉक्स लठैनी के लिए भी स्वीकृत है। सबूर के लिए स्वीकृत है। लेकिन मेरे क्षेत्र में जो बाद की किस्त आनी थी, वह इस सरकार ने आते ही रोक दी। मेरा यह सरकार पर आरोप है। मैं आज के प्रश्न में पढ़ रहा था कि कहां-कहां पैसा पर्यटन का खर्च हुआ तो मात्र एक रामपुर में ही डेढ़ करोड़ रुपया खर्च हुआ। आज जहां श्री भीमाकाली मंदिर ,पंचवीर देवता और रघुनाथ मंदिर रामपुर के लिए पैसा दे दिया गया लेकिन कुटलैहड़ को पांच लाख की आवश्यकता थी, इन्होंने पांच लाख रुपया नहीं उपलब्ध करवाया। मेरा एक प्रश्न लठैनी मंदली पुल के बारे में था। जब भाखड़ा डैम बना था तो कुटलैहड़ क्षेत्र दो हिस्सों में विभाजित हो गया था। उस समय जब पंजाब और हिमाचल प्रदेश का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था तो उस समय बी0बी0एम0बी0 में शर्त थी कि यह पुल बी0बी0एम0बी0 बनाकर देगी। लेकिन बी0बी0एम0बी0 ने नहीं बनाया। हमारे नेताओं ने भी उस बात को नहीं उठाया। प्रदेश की सरकारें आती और जाती रहीं लेकिन उस विषय पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। माननीय उपाध्यक्ष जी, 1990 के चुनाव आए। हमारे मुख्य मंत्री, श्री

वीरभद्र सिंह जी बड़े लम्बे समय से मुख्य मंत्री हैं। वे वहां पर गए। आज भी वहां पर उनका बोर्ड लगा हुआ है। वहां पर पूजन किया है। वहां पर खड़े हो गए, कहते कि कहां से कहां तक बनना है। कितनी-कितनी साइट है। लेकिन तब भी इनकी सरकार नहीं बनी। लोगों ने रिजैक्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार जब सरकार आई तो मैंने कहा कि कितना बजट उपलब्ध है। उसमें 60 लाख रुपया बजट उपलब्ध था। लेकिन आज जब मैंने प्रश्न का उत्तर मांगा कि कितना बजट उपलब्ध है तो कहा कि 60 लाख रुपया नहीं बल्कि दो लाख रुपया उसका बजट रह गया है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया कि आप इसको कहीं-न-कहीं रख दो। आप चाहे वर्ल्ड बैंक को भेज दो, एशियन डिवैल्पमैंट बैंक को भेज दो। आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसको प्लानिंग में डाल करके सी0आर0एफ0 के तहत डोडरा से लेकर ऊना तक वाया लठैनी मंदली करो। जब उसकी डी0पी0आर0 बनेगी तो हम भी धूमल जी से निवेदन करेंगे कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हम उस पैसे को वहां से लेकर आयेंगे। अगर आपके पास इसके लिए कोई फंड नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है। मैं आज कह रहा हूं कि इसको सी0आर0एफ0 में डालो। कहीं-न-कहीं कुटलैहड़ के लोगों से न्याय करो। अभी पिछले दिनों कुटलैहड़ गए थे तो लोगों ने कहा कि लठैनी

25.03.2015/1545/SS-AG/2

मंदली पुल बनना चाहिए। तो कहा, नहीं, मैं यहां पर जलमार्ग की व्यवस्था कर रहा हूं। कहते हैं कि यहां पर किश्तियां चलाई जायेंगी। मैंने कहा कि किश्तियां तो पहले ही चलती हैं। आज तक किश्तियां ही चलती रहीं। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। अभी राजस्व मंत्री, ठाकुर कौल सिंह जी यहां पर थे। मैं बार-बार इस विषय को उठाता भी हूं कि कुटलैहड़ के लोग डैम ऑस्टीज़ हैं। बहुत सारे लोग उस समय रेवेन्यू डिपार्टमैंट ने जहां उनको पट्टे दिए गए, आज वे वहीं पर बैठे हुए हैं। उनकी आबादियां और घर हैं। उन्होंने खेत बनाए हैं। लेकिन अभी रेवेन्यू डिपार्टमैंट ने उनकी किस्म बदल दी। उन्होंने कहा कि आप यहां नहीं आओ, आप वहां पर हैं और उनके ऊपर नाजायज़ केस बनाए गए हैं। बार-बार उनको तंग किया जाता है। अब कहा है कि तिब्बतियों के भी कब्जे रेगुलराईज़ कर रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां आप तिब्बतियों को रेगुलराईज़ कर रहे हैं तो हिन्दुस्तान के अपने कुटलैहड़ के लोगों का क्या कसूर है? आपने कहा कि 150 मीटर उनको एलाऊ कर देंगे अगर

उनका पोजैशन इल्लीगल होगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप उसको एलाऊ करिये लेकिन उनके ऊपर जो केस बने हैं आप उनको भी वापिस लें। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आज बड़े धड़ल्ले के साथ कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण हो रहा है। मेरा आरोप है कि जितने भी आपके कांग्रेस के नेता हैं वे धड़ल्ले के साथ सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। अगर आप ऊना से लेकर लठैनी तक चलेंगे तो किसी ने 11 मरले खरीदी है और 11 कैनाल के ऊपर होटल बनाकर कब्जा किया हुआ है।
जारी श्रीमती के0एस0

25.3.2015/1550/केएस/एजी/1

श्री वीरेन्द्र कंवर जारी----
कब्जा किया हुआ है। किसी ने 3 कनाल जमीन खरीदी है जो अब 6 कनाल के ऊपर बैठा है और हम बाबा जोगी मंदिर के लिए जाते हैं वहां सरेआम पहाड़ी के ऊपर वृक्ष थे, वहां पर वृक्ष भी काटे गए और उनको काटकर उस भूमि को समतल भी किया जा रहा है लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। मुख्य मंत्री जी कुटलैहड़ जाते हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब ये चुनाव से पहले कुटलैहड़ गए, मैं तीसरी बार का विधायक हूं, 1985 में मैंने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया था मैं तीसरी बार विधायक बन गया लेकिन मुख्य मंत्री जी कुटलैहड़ जाते हैं तो कहते हैं कि विधायक ने महल बना दिया। जैसे महल बनाने का अधिकार इन्हीं का है। हम मकान भी नहीं बना सकते? इन्होंने वहां पर चुनाव से पहले कहा कि 6 करोड़ का मकान बना दिया। चार हजार स्कवेयर फुट का मकान है उसको कहा कि यह 6 करोड़ का है। मैंने उस वक्त मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था, अखबार के माध्यम से कहा कि 6 करोड़ का अगर मेरा मकान है, आप लम्बे समय से मुख्य मंत्री है, मैं आपको पांच करोड़ का दे दूंगा और उसमें से चार करोड़ मुख्य मंत्री राहत कोष में डाल दूंगा। मुझे इस बात का दुख हुआ, मैं सोचता था कि ये बहुत अनुभवी मुख्य मंत्री हैं। जब भी ये कुटलैहड़ आते थे तो हम सबसे पहले इनके मान-सम्मान में बुक्का ले कर आगे खड़े होते थे लेकिन इस बार पता नहीं इनके कान में किसने कह दिया कि इसने जो महलनुमा घर बना दिया इसका निर्माण सी.एण्ड सी. कम्पनी ने किया है । इन्होंने कहा कि अगर विधायक की मैं जांच करवाने लगूं तो इनकी विधायकी खतरे में आ जाएगी। मैं विधान

25.3.2015/1550/केएस/एजी/2

सभा में कह रहा हूं कि आदरणीय वीरभद्र सिंह जी, आजकल सी.एण्डसी. कम्पनी रोहडू और रामपुर में है। आज जो फाईव स्टार होटल वहां पर बन रहा है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह सी.एण्ड सी. कम्पनी बना रही है? आज जो महलों का रैनोवेशन हुआ, क्या वह सी.एण्ड सी. कम्पनी करवा रही है? आप तो 1965 से राजनीति में है और हम तो 1964 में पैदा हुए, कोई न कोई मर्यादा तो होनी चाहिए। मैं तो हैरान हूं इस बात से मैं हफ्ता भर बहुत दुखी रहा। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि जब माननीय वीरभद्र सिंह जी पहली बार मुख्य मंत्री बने थे तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था और मैंने इनका पहला इंटरव्यू पढ़ा था कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ देंगें, उसका उन्मूलन कर देंगें और यह शब्द मुझे आज भी याद है। उस समय वीर प्रताप और पंजाब केसरी होता था। आज क्रप्शन का स्तर कहां है? आज मुख्य मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। आज इनको दिल्ली के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मैं फिर भी इनका मान और सम्मान करता हूं और ऐसी मनगढ़न्त बातें अगर कोई कहें आप उनको धैर्य से सुने और अगर हमने भ्रष्टाचार किया है तो हमारे ऊपर केस बना दें। आज अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो झूठी बातें कह कर आप जनता को कुटलैहड़ के अंदर गुमराह मत करिए। प्रदेश की जनता ने आज आपको सौभाग्य से पांच वर्ष का समय दिया है। आप उसका सदुपयोग करिए। आप विधायकों के पीछे पुलिस लगा रहे हैं? आप हमारे नेता आदरणीय धूमल जी के ऊपर झूठे केस दर्ज कर रहे हैं? 120-बी में डालकर 420 का मुकद्दमा दायर करने की कोशिश कर रहे हैं? आपके महामहिम पूर्व राज्यपाल ने केस वापिस किया कि ऐसी प्रवृत्ति बन्द करें और आज

25.3.2015/1550/केएस/एजी/3

महिमहिम ने फिर केस बन्द किया है। मैं निवेदन करूंगा कि वह केस है क्या, उसको सदन के पटल पर तो रखें।

आज पूरा विश्व वर्ल्ड कप देख रहा है और आप हिमाचल प्रदेश में आई.पी.एल. को बन्द कर रहे हैं? आप खेलों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं? अगर आप केस बनाते जाएंगें उतने ही अनुराग ठाकुर का स्तर बढ़ता जाएगा। आज

बी.सी.सी.आई. के जनरल सैक्रेटरी बन कर उन्होंने इस प्रदेश का मान और सम्मान बढ़ाया है। अगर आज आपने आई.पी.एल. बन्द किया है तो जिन लोगों ने इसकी वजह से ढाबे के लिए, होटल के लिए लोन ले कर कमरे बनाएं, आज उनको कितना नुकसान इससे हो रहा है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

25.3.2015/1555/JT/av/1

श्री वीरेन्द्र कंवर जारी----------
लोन लेकर कमरे बनाये। आज उन लोगों को उसके तहत कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट फ्यूडल मानसिकता से ग्रसित है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 1983 से शुरुआत की थी। अगर आप उस समय से **मित्तव्ययीता** का ध्यान रखते, साधन जनरेट किए होते तो 1993 में आपको कर्ज नहीं लेना पड़ता। कर्ज लेने की शुरुआत किसने की? आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने की। आज कर्ज 34हजार करोड़ रुपये हो गया है। आज प्रदेश में जो बच्चा पैदा होगा उसके ऊपर भी कर्ज है। आपने पिछले दो वर्षों के अंदर 8 हजार करोड़ रुपये कर्ज ले लिया। जैसे परसों आदरणीय रणधीर जी कह रहे थे कि आगे हिमाचल प्रदेश (---व्यवधान---)

Deputy Speaker: Hon. Member, please wind up. आपने इस बारे में पहले भी कह दिया है। Now you are repeating the same thing.

श्री वीरेन्द्र कंवर : कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी जो कदमताल करते रहें; कभी एक कदम आगे और एक कदम पीछे। ये यहां ऐसा बजट प्रस्तुत करते रहें जिसके कारण आज हिमाचल प्रदेश कंगाली की ओर है। सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। एम.पी.लैड, विधायक निधि; मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में पता कर रहा था। वहां से एक करोड़ रुपये की राशि वापिस मंगवा ली गई। ऊना की लगभग ढाई करोड़ रुपये की राशि वापिस मंगवा ली गई। शायद ही कभी ऐसी वित्तीय स्थिति इस प्रदेश की रही होगी। माननीय मुख्य मंत्री जी, जब भी आप जाएं। आप जब इनस्टिच्यूशन्ज खोलते हैं क्योंकि इनस्टिच्यूशन खोलना आपका अधिकार है। मगर मेरा इसमें यह सुझाव रहेगा कि

आप आंखें बंद करके हर चीज सैंक्शन मत कर दो जैसे थत्तू राम कहे, नत्थू राम कहे वैसे ही आप कह दें कि तू भी स्कूल ले जा, तू भी स्कूल ले जा। (---व्यवधान---)

Deputy Speaker: Please wind up now.

25.3.2015/1555/JT/av/2

श्री वीरेन्द्र कंवर : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं यह कहता हूं कि आप इनस्टिच्यूट खोलिए, बहुत सारे खोलिए लेकिन उसका एक सर्वेक्षण जरूर करवायें कि बच्चे कहां-कहां पर हैं। जहां बच्चे हैं वहां पर आप इनस्टिच्यूशन जरूर खोलिए, हम उसके लिए आपका मान-सम्मान करेंगे। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा।

Deputy Speaker: Please wind up now; otherwise I am going to call the next speaker Shri Maheshwar Singhji.

श्री वीरेन्द्र कंवर : उपाध्यक्ष जी, एक मिनट, खत्म कर रहा हूं। मोदी जी ने बहुत पैसा दिया है। आप विधायक निधि को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दो। एच्छिक निधि जो आपने 2लाख रुपये शुरु की है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करुंगा। आप इसको भी बढ़ाकर कम-से-कम 5 लाख रुपये करें। मैं आपका बहुत धन्यवादी रहूंगा।

मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता। मैं इसका भरपूर विरोध करता हूं, धन्यवाद।
समाप्त

25.3.2015/1555/JT/av/3

श्री महेश्वर सिंह : उपाध्यक्ष जी, दिनांक 18 मार्च, 2015 को इस माननीय सदन में परम् सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय जिनके पास वित्त विभाग भी है ,ने वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं। मैं इसके संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, इस वित्तीय वर्ष में टोटल अनुमान 4800 करोड़ रुपये के हैं जो कि गत वर्ष की तुलना में 400 करोड़ रुपये अधिक है। इसके लिए सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय बधाई के पात्र है। इस 4800 करोड़ में से 1209 करोड़ रुपये जनजातीय क्षेत्र उप योजना का है। इसी प्रकार जो अनुसूचित जाति की उप योजना है उसके लिए भी है तो कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपये की वृद्धि है। बावजूद इसके कि योजना आयोग की तरफ से जो भरपाई होती थी उसका आज नीति आयोग बनने के बाद ऐसी शंका जताई जा रही है कि इसकी भरपाई इस बार नहीं हो पायेगी। जिसका सीधा अर्थ यह होगा कि 3 हजार करोड़ रुपये की कमी आयेगी-----
श्री नेगी द्वारा जारी

25.03.2015/1600/negi/jt/1

श्री महेश्वर सिंह .. जारी...

जिसका सीधा अर्थ होगा कि 3000 करोड़ की कमी आएगी । मुझे विश्वास है कि जो इधर (विपक्ष) बैठे हैं वे प्रधान मंत्री जी से निवेदन करेंगे क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि अगर सी.आर.एफ. में योजना डाली जाए तो हम वहां से पैसा लाएंगे। तो आप कृपा करके कम से कम ये 3000 करोड़ रूपये वहां ज़ोर लगा करके लाएंगे तो हम भी प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे। ....(व्यवधान) ...जो मेरे साथ बीती है अगर वह आप सुनेंगे तो आप भी दुःखी हो जाएंगे, अन्दर से यह आप भी जानते हैं। आपको किस हालत में छोड़ना पड़ा, मैं बोलूंगा ज़रा रूको। अगर आपको अकल आती तो यह रेंडेपा न पड़ता, हम आप ही के साथ होते। ...(व्यवधान) ..चलिए, मैं अपना समय आपके लिए बर्बाद नही करूंगा।

Deputy Speaker: Please be quiet.

श्री महेश्वर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में हर क्षेत्र का ,हर समुदाय का ध्यान रखा गया है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हम जो भी कार्य करें जिसने मां की कोख से जन्म लिया होता है वह सर्वगुण नही होता है और उसमें सुधार की गुन्जाइश रहती है। अच्छा होता, जब हम आलोचना करें तो साथ में सुधार की भी बात करें और सुझाव भी दें तो ज्यादा अच्छा लगता है। जिन्होंने दी उनका धन्यवाद। लेकिन कुछ को मैं सुन रहा था कि आधे घंटे के भाषण में एक भी शब्द प्रशंसा का नही निकला। यह सत्यता है कि जो विधायक निधि योजना है उसके लिए प्लानिंग

की बैठक में हम सबने आग्रह किया और उसको स्वीकारते हुए इसमें 20लाख की वृद्धि हुई, कम से कम उसके लिए तो एक शब्द धन्यवाद का कह दो। मैं उस आधे घंटे की भाषण जिसने दिया उसकी बात कह रहा हूं इसको आप अपनी ओर क्यों ले जा रहे हैं?

महोदय, इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई जिसका वर्णन पैरा 33 से लेकर पैरा 50 तक किया गया है और जो अन्य इसके पैराज़ हैं

25.03.2015/1600/negi/jt/2

उसमें भी कहीं न कहीं किसानों का उल्लेख है। इस बार कृषि विभाग के लिए 450 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रावधान है और हार्टिकल्चर के लिए 268 करोड़ रूपये का अलग प्रावधान है। यहां मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि एक नई योजना शुरू की गई है और माइक्रो इरिगेशन के लिए 154 करोड़ रूप्ये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरक्त 113 करोड़ सबसिडि के लिए है, जो निजी क्षेत्र में किसान स्पिंक्लर लगाएंगे या लिफ्ट इरिगेशन का काम करेंगे। यहां हमारे पावर मिनिस्टर बैठे हुए हैं मैं उनके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जब से आपने इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रखी, मैं मानता हूं कि उनका दायित्व है कि हर बार उनकी आय में कैसे वृद्धि हो, उसकी चिन्ता करना। लेकिन आज जितनी सबसिडि दे रही है सरकार उसकी कसर वह एक ही साल में निकाल देता है। वह उतनी वृद्धि बिजली टैरिफ की कर देते हैं और बिजली की खपत पर वह टैरिफ नही, वह अनुमान लगाते है कि इतनी पावर हॉर्स की मोटर इतनी तो कम से कम चलनी चाहिए इसलिए इतना सरचार्ज तो आपको देना ही होगा। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप हस्तक्षेप करें और उनसे बात करें। उनके कारण आज जो हमारे स्थानीय निकाय हैं वे बैंक-करप्ट हो गई हैं, घाटे में चल रही हैं। क्योंकि उन्होंने जो बिजली आपके स्ट्रीट लाईट्स में खर्च होती है पहले तो उसको कॉमर्शियल रेट लगाया फिर जब आग्रह किया गया तो थोड़ा कम लगा दिया। लेकिन आज जितनी उनपर रिकवरी पड़ी उसका कारण केवल और केवल यह रेगुलेटरी कमीशन है । इसलिए इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, जहां तक मिडियम इरिगेशन की बात है। विभाग ने अच्छा काम किया है और अच्छी योजनाएं तैयार की हैं। जैसे कुल्लू में...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

25.03.2015//यूके/16051.

श्री महेश्वर सिंह---जारी--

जैसा कुल्लू में भी यहां ,गोविन्द सिंह जीअभी बैठे हैं। उनके भी ध्यान में है कि प्रीणी , नाले से लेकर बिजली महादेव मंदिर तक एक फ्लो इरिगेशन का सर्वेक्षण हुआ है और वह सारा प्राक्कलन तैयार करके मीडियम फ्लो इरिगेशन के अन्तर्गत सरकार 3041 को भेजा गया है। जिसका कमांड एरिया और इरिगेशन एरिया.हैक्टेयर है। 40 354 ये.करोड़ रुपए की योजना है। अगर ऐसी प्रमुख योजनाओं को केन्द्रीय 70 सरकार से आग्रह करके वित्तीय प्रावधान किया जाए। तो वह एक या गांव समूह का आपके प्रीणी से ले कर कायस्थ तक और फिर बिजली ,नहीं बल्कि लैफ्ट बैंक पूरा महादेव वाला भाग जिसको खराब क्षेत्र कहते हैंऔर शावरी क्षेत्र तक कवर करेगा। , कि किस जमीन ,इस साल एक बात की चिंता की गयी है कि सॉयल हैल्थ काड़्ज़ को किस प्रकार के उर्वरक की जरूरत है और वह एक लाख लोगों को देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मोबाईल लैब तीन और खरीदी जायेगी। ताकिजगहजगह - सॉयल टैस्टिंग हो सके। निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र और बागवानी क्षेत्र में जो हमारे अपने यहां उस उत्पादन में वृद्धि कर पाएंगे। यह -काम करने वाले लोग हैं वह अपने योग्य कदम है।-उनका एक स्वागत

50 केंचुआ खाद के लिए भी% अनुदान देने की बात कही गयी है। मार्किटिंग बोर्ड को सुदृढ़ करने के लिए करोड़ रुपए की बात कही गयी है। लेकिन मैं आपके 10 माध्यम से मुख्य मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि इसके अतिरिक्त जो किसानों और बागवानों से वह करोड़ों में हर मार्किटिंग ,मार्किटिंग फीस आती है जिले की यहां पर जमा है और

25.03.2015/2/यूके/1605

कुछ लागों की इस पर गिद्धदृष्टि पड़ गयी है । वे चाहते हैं कि इस पैसे को सड़क - निर्माण में खर्च कर दिया जाए । पिछला अनुभव अच्छा नहीं रहा। पहले भी मार्किटिंग न ग्रेड देखा ,बोर्ड ने सड़कों का निर्माण किया है और न तो उसका कोई सर्वे हुआ गया । मुझे लगता है कि जय राम जी के क्षेत्र में भी मार्किटिंग बोर्ड की सड़कें होंगी । रामपुर क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र में भी बनी हैं । जहांतहां पैसा खर्च किया और स्थिति - लाख रूपए के यूटिलाईजेशन 70 ऐसी है कि इस शिमला जिला में आज भी सर्टिफिकेट मार्किटिंग बोर्ड में नहीं पहुंचे हैं । अर्थात् वह धन बेकार में व्यर्थ में गया । अच्छा होगा कि ऐसी योजना की बजायमुझे विश्वास है ,कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं , कि ये अवश्य ध्यान देंगे कि क्यों नहीं आप मार्किटिंग बोर्ड यार्ड में जहां जमीने उपलब्ध हैं वहां पर कोल्ड स्टोरेज बना दीजिए । अगर कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे तो किसानों के काम आएंगे और ऐसी सड़कें बनाएंगे जिसका ग्रेड ही नही हैजहां सारे , गांव को इकट्ठा हो कर गाड़ी आगे जायेगी तो पीछे से पकड़नी पड़ती है और अगर ऊपर ले जानी होगी तो आगे से घसीटनी पड़ती है । तो व्यर्थ में इन सड़कों पर पैसे को खर्च मत करिए । अगर आवश्यक है सड़क वालों को देना तो फिर विभाग को दे दीजिए । पर अगर ठेकेदारी प्रथा चलेगी तो यहां नुकसान होगा ।

पॉलीनेशन में इनका एक ,यहां पर बागवानी मंत्री जी बैठी हैं ,मधु मक्खी 40 अहम रोल रहता है और केन्द्रीय सरकार इस पर% सब्सिडी देती है । सरकार ने स्वागत योग्य निर्णय लिया है कि 30% उसके अतिरिक्त हिमाचल सरकार सब्सिडी देगी । इसका स्वागत करना चाहिए जो ,

25.03.2015/3/यूके/1605

बागवान बैठे हैं चाहे उधर हैं क्योंकि हमारे हित की बात है ये । ,चाहे वे इधर हैं ,

इसके अतिरिक्त मच्छली उत्पादन एक ऐसा क्षेत्र है ।

एस----द्वारा जारी 0एस0एल0

25.03.2015/1610/sls-jt-1
श्री महेश्वर सिंह...जारी

विशेषकर ट्राऊट उत्पादन जो कि किसानों के लिए आय का स्त्रोत बन सकता है और रोज़गार का भी स्त्रोत बन सकता है। इसको कृषि उद्योग घोषित करने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि बंगाल में और आसाम में यह एग्रीकल्चर मंत्रालय के अंतर्गत आता है न कि एनिमल हसबैंडरी के। पशुपालन के साथ मछली उत्पादन का कोई संबंध नहीं है ,यह कृषि के अंतर्गत आना चाहिए। दक्षिणी भारत में मछली उत्पादन को कृषि उद्योग घोषित किया गया है, बंगाल में भी किया गया है तो हिमाचल में क्यों नहीं? कृषि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। इससे आपका एक विभाग और बढ़ जाएगा। यह आपके पास होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ग्रामीण विकास की बात है, मंत्री महोदय अब चले गए, पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण के लिए 109 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उसके अतिरिक्त यह जो 14वें वित्तायोग की सिफारिशें हैं उनके अंतर्गत 195 करोड़ रुपया पंचायतों को दिया जाएगा। अर्थात पंचायत आज एक महत्वपूर्ण इकाई है। इनका विस्तारीकरण आवश्यक है। कोई भी योजना हो, अगर वैटरिनरी डिसपैंसरी भी आएगी तो पंचायत में, कोई पैसा आएगा तो पंचायत में। यह पैसा सभी पंचायतों को बराबर दिया जाएगा, चाहे वह छोटी पंचायत हो या बड़ी पंचायत हो। वहां पापुलेशन को नहीं देखा जाएगा। केवल केंद्रीय स्थान देख कर दे देंगे। एक तरफ तो मंत्री जी ने इस बात को स्वीकारा कि reorganization of Panchayats, Zila Parishad wards or Block Smiti ward, यह सब करेंगे। जो पंचायत विधान मंडलों में दो क्षेत्रों में बंटी है, उसको भी रिआर्गेनाईज करेंगे। मैंने यहां एक प्रश्न में जानना चाहा था कि मंत्री जी, जब आप रिआर्गेनाईज करोगे और ऐसी पंचायतों को इकट्ठा करोगे तो हो सकता है कि दूसरे क्षेत्र में केवल दो वार्ड रह जाएं औार एक में तीन आ जाएं तो क्या वहां पर अलग से पंचायत बनेंगी? इसका उत्तर केवल और केवल एक है कि जब तक आप पंचायतों की रिआर्गेनाईजेशन नहीं करेंगे तो यह संभव ही नहीं हो पाएगा और इसका कोई अर्थ नहीं होगा। बड़े-बड़े ब्लॉक बने हैं। मैंने

25.03.2015/1610/sls-jt-2

कुल्लू की बात की थी कि यह प्रदेश में सबसे बड़ा ब्लॉक 70पंचायतों वाला कोई अगर है तो वह कुल्लू है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि इन सबकी बाऊंडरी आप विधान सभा क्षेत्र के साथ कोटर्मिनस कर देंगे, ...(व्यवधान)... 70 हैं। आपकी (श्री

केoएलo ठाकुर जी से) पापुलेशन कितनी है और क्षेत्रफल कितना है? आपका एरिया हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वह पहाड़ों का बच्चा है। ...(व्यवधान)... (श्री रिखी राम कौंडल जी से) मैं तारीफ़ ही नहीं कर रहा हूं बल्कि सुझाव भी दे रहा हूं। आप औरों के असंसदीय शब्द कटवाते हैं लेकिन स्वयं 100 बार झूठ बोलते हैं। आपको यह ज्ञान ही नहीं है कि झूठ शब्द अनपार्लियामैंटरी है। ऊपर से आसन ने भी कोई निर्देश नहीं दिए कि इस शब्द को बाहर निकालो। अनपार्लियामैंटरी शब्द खुद बोलते हैं और जो हम कहते हैं उसको कटवाते हैं।

महोदय, मैं फिर आपके माध्यम से मंत्री जी से निवदेन करना चाहूंगा कि पहले तो उन्होंने जो ऑर्डर निकाला कि नई पंचायतें नहीं बनाएंगे और बाद में कैबिनेट की मोहर भी लगवा दी; मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि प्रजातांत्रिक अधिकार से लोगों को वंचित मत करिए। यहां पूर्व पंचायत मंत्री बैठे हैं जो इस बात के गवाह हैं। पीछे भी नई पंचायतें नहीं बन पाई क्योंकि इलैक्शन कमीशन और सैनसस डिपार्टमैंट ने रोक लगाई थी। अब यह 10 वर्ष का बैकलॉग है। अभी आप नहीं करेंगे तो यह काम और 5 साल आगे चला जाएगा। इसलिए अगर आपको सचमुच पंचायतों के प्रति मान-सम्मान है तो यह समय है कि कैबिनेट अपने निर्णय को रिवियु करे और 1994 के एक्ट के अंतर्गत जहां-जहां...

जारी..श्री गर्ग जी

25/03/2015/1615/RG/AG/1

श्री महेश्वर सिंह-----क्रमागत

और 1994 के ऐक्ट के अन्तर्गत जहां-जहां पंचायत बन सकती है वह बननी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट में राजस्व विभाग की चर्चा पैरा-78 से लेकर पैरा-82 तक की गई है। उसमें बहुत सी बातें रिकॉर्ड के सुधारीकरण की व अन्य बातें भी कही गई हैं। लेकिन इसके अन्तर्गत 300करोड़ रुपये का प्रावधान है। मैं इसमें एक सुझाव देना चाहूंगा। यहां राजस्व मंत्री महोदय बैठे हैं। एक तरफ आपने तिब्बत के शरणार्थियों के नाजायज़ कब्जों को नियमित करने की बात कही है मैं उसका विरोध नहीं करता क्योंकि वे शरणार्थी हैं ,लेकिन उनके बारे में क्यों नहीं सोचते जो पुश्तैनी लोग जंगलों में बसे हैं। उस समय 1980 का ऐक्ट तो नहीं था। उससे पूर्व से उनके कब्जे हैं। आप उन पुश्तैनी कब्जों को उठा तो नहीं पाएंगे। क्योंकि राजनैतिक

व्यवस्था में यह संभव नहीं है। यहां श्री नन्द लाल जी, माननीय मुख्य संसदीय सचिव बैठे हैं। मैं इनके क्षेत्र से भली-भांति परिचित हूं। इनके यहां पूरा-का-पूरा बाजार जंगलों में बसा हुआ है। क्या उनको उठा पाएंगे? तो क्यों नहीं इनको भी गुण-दोष के आधार पर नियमित करने का विचार करें ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। इसके अतिरिक्त एक रैवेन्यु मैनुअल की बात है ,तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन करुंगा कि इसमें मूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। स्थिति ही कुछ ऐसी है। आपने कुछ सुधार किया है मैं इसके लिए आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। लेकिन आज भी स्थिति क्या है किसी की जान चली जाए ,तो तुरन्त ऐक्स-ग्रेशिया ग्रांट दे दी जाती है ,मकान सौ प्रतिशत क्षतिग्रस्त हो जाए या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाए ,तो उसके लिए भी कुछ-न-कुछ मिल जाएगा ,लेकिन इस हिमपात या अधिक वर्षा के कारण जहां सारे प्रदेश में क्षति हुई है और विशेष रूप से कुल्लू जिला, आपका द्रंग क्षेत्र और चच्योट क्षेत्र सिराज क्षेत्र प्रभावित हुआ है। लोगों के घर बच गए, लेकिन घर के नीचे की सारी जगह स्लाइड कर गई और यदि समय रहते उसकी सुरक्षा दीवार नहीं लगेगी ,तो अगली बार घर ही चला जाएगा। तो क्या करेंगे? क्योंकि आपके पास राजस्व मैनुअल में देने के लिए कुछ नहीं है। हजारों की संख्या में लोगों ने आवेदन-पत्र पटवारी की रिपोर्ट लेकर जिलाधीश के कार्यालय में दिए हैं और इन्तजार कर रहे हैं कि हमको कब रिलीफ मिलेगा। अब मैनुअल में तो कोई इसके लिए प्रावधान है नहीं। तो क्या वह इन्तजार करेगा कि उसका घर कब गिर जाए या वह खुद ही गिरा दे। अब मैं पैसे की बात कहने जा रहा हूं और मेरा एक सुझाव है कि जो विकास कार्य में जनसहयोग योजना है, तो जो इस प्रकार के मामले

25/03/2015/1615/RG/AG/2

हैं आप सर्वे करिए और रिपोर्ट मंगाइए ,उसमें जो पब्लिक शेयर है वह प्रभावित व्यक्ति दे देगा और ऐस्टीमेट के अनुसार शेष पैसा आप उसको दीजिए ताकि वहां उसका घर प्रोटैक्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त जो अति निर्धन है ,उसका पब्लिक शेयर विभाग तैयार करे ,विभाग व्यवस्था करे ताकि उसका घर बच सके। जैसा आपका यह मैनुअल है, मण्डी में एक कहावत है कि 'ज्यो-दियों नहीं, तीन मूलए तलुए।' अर्थात जीते जी तो तीन नहीं देना, अगर मर गया, तो तेरह दे देंगे। इसलिए इस प्रथा को बंद करिए और इन लोगों के बारे में सोचिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सिंचाई विभाग का संबंध है ,पैरा-86 के अन्तर्गत जो बिजली के चार्जिज हैं जो आपको लिफ्ट इरीगेशन स्कीम, वाटर सप्लाई स्कीम

या दूसरी योजनाओं में देने पड़ते हैं उसमें तीन सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शायद यह बिलों के भुगतान के लिए है संभवतः। लेकिन मेरा एक और सुझाव है कि हमेशा देखा गया है कि जो बिल जाते हैं और जो बिल सर्टिफाई करता है वह ऐक्सीयन करेगा और फिर अप्रूवल के लिए ऊपर मुख्यालय में भेजता है। जितने में वह अप्रूव होकर नीचे भुगतान में आता है उतने में लेट फीस लग जाती है , सर चार्ज लग जाता है और कभी-कभी डिसकनैक्शन भी हो जाता है। इसका आप सरलीकरण क्यों नहीं करते?----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

25/03/2015/1620/MS/AG/1

श्री महेश्वर सिंह जारी--------

इसका आप सरलीकरण क्यों नहीं करते कि जैसे बिल उपलब्ध होता है ,XEN उसको सर्टिफाई करके तुरन्त ऊपर भेज दे और एप्रूवल के उपरान्त ,अब तो सबकुछ Online है तो हैडक्वार्टर से ही पेमैंट क्यों नहीं हो जाती? इसको ऊपर नीचे भेजने में क्यों अतिरिक्त पैसा आप बिजली विभाग को देते हैं? आपकी करोड़ों की बचत एक साल के अंदर हो जाएगी। मुझे लगता है कि यहां ऊर्जा मंत्री भी बैठे हैं और ये भी बैठे हैं। अगर आपस में चर्चा करेंगे तो पैसे की बचत हो जाएगी और पैसे को किसी अच्छे काम में लगा दीजिएगा।

उपाध्यक्ष जी, मैंने एक फ्लो इरीगेशन स्कीम की बात की थी। यह प्रीणी नाला से जहां से अलाइन दुहांगन प्रोजैक्ट है, वहां अलाइन नाला है। वहां से लेकर बिजली महादेव तक यह अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है इसलिए इसके ऊपर अगर आपकी कृपा दृष्टि हो, विभाग को अगर आप आदेश दे और इसको स्वीकृति के बाद सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम में डालें तो निश्चित रूप से इसका लाभ होगा।

यहां फ्लड प्रोटैक्शन की बात कही है कि उसकी चैनेलाइजेशन के लिए भी पैसा रखा है। यह एक ऐसी स्कीम है जो ब्यास नदी के पल्चान से लेकर, मनाली क्षेत्र से आउट तक का 74 किलोमीटर का सर्वेक्षण हुआ है। जिसमें पार्वती और बाकी ट्रिब्यूटरीज और ब्यास नदी के चैनेलाइजेशन का फर्स्ट फेज का प्राक्कलन 1155.15 करोड़ रूपये का तैयार हो चुका है और जो स्टैग की मीटिंग होती है उसमें इसकी

एप्रूवल हो चुकी है। दिनांक12 /7/ 2014को यह एप्रूव हो चुका है और सरकार की कृपा से बजट में पिछले साल एक करोड़ रूपये का वित्तीय प्रावधान (टोकन प्रोविजन) है। इसको कृपया प्राथमिकता दे ताकि इसका कार्य आने वाले वर्ष में शुरू हो सके। यह स्कीम बहुत ही सार्थक सिद्ध होगी।

जहां तक लोक निर्माण विभाग का संबंध है। उपाध्यक्ष जी, अगर सबसे ज्यादा शिकायत माननीय सदस्यों ने की और जिस बात पर प्लानिंग की मीटिंग में चिंता व्यक्त की, वह सब-स्टैंडर्ड काम होने के बारे में की। विशेषकर मैटलिंग और टारिंग की शिकायतें कीं। आज ऐसा है कि मैटलिंग/टारिंग की और छः महीने में उखड़ गई। (व्यवधान) आप लोग ठीक कह रहे हैं, छः दिन में भी उखड़ी हैं। मैं आप ही की बात

25/03/2015/1620/MS/AG/2

का समर्थन कर रहा हूं। आप लोगों को ऐसा सुझाव यहां देना चाहिए था। मेरा यह कहना है कि जब पहले मैटलिंग/टारिंग होती थी। हम उन दिनों में स्कूल जाते थे तो देखते थे कि सबसे पहले ऐसी सड़कों में खड़ौंजा लगता था और उस खड़ौंजे के ऊपर कोटिंग होती थी। फिर उसको रेस्ट देते थे। फिर उसमें रोड़ी डाली जाती थी और रोड़ी के बीच में मिट्टी डाली जाती थी। फिर रोलर चलता था और उसको बैठने और सैटल होने दिया जाता था। बाद में खूंटियां लेकर उस मिट्टी को खुरचा जाता था। फिर कम्प्रैशर की हवा लगाकर साफ किया जाता था। दो-तीन महीने के बाद टारिंग होती थी। आज एक नई स्कीम आ गई है कि पहले ट्रक में पत्थर, दूसरे ट्रक में रोड़ी, तीसरे में तारकोल में मिली हुई बजरी और वह भी दूर से लाते हैं, वहां गर्म नहीं करते। वहां आते-आते वह बजरी ठण्डी भी हो जाती है और कुछ ही दिनों में पूरी की पूरी सड़क मैटल्ड हो जाती है और बहुत अच्छी सड़क बनाने के लिए रेत में तारकोल लेकर मिलाया जाता है। अगर पहले दिन ऐसी सड़क पर जाओगे तो पेट का पानी तक नहीं हिलता और जब महीने के बाद जाते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। ये कैसी सड़कें हैं? इसलिए इस ओर ध्यान देना होगा। गलती विभाग करता है लेकिन बदनामी सरकार की होती है। इसलिए इस बात की ओर ध्यान देना होगा।

उपाध्यक्षः कृपया समाप्त कीजिए।

श्री महेश्वर सिंहः उपाध्यक्ष जी, मैंने तो अभी कम ही समय लिया है लेकिन फिर भी यदि आपका आदेश है तो 2-4 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। (व्यवधान) हम सरकार की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि विभाग की बात कर रहे हैं। सरकार उसका नोट ले। इसमें सुधार होना चाहिए। सबने कहा है कि उसमें पहले खड़ौंजा लगता था।

उपाध्यक्ष जी, मैं अब फोर लेन की बात करूंगा। मैंने योजना की बैठक में भी कहा था। आपको याद होगा। पिछले वित्तीय वर्ष में मांगों पर चर्चा के दौरान,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

25.03.2015/1625/जेके/जेटी/1
श्री महेश्वर सिंहः-------जारी-----

आपको याद होगा पिछले वित्तीय बजट पर चर्चा में और मांग पर चर्चा करते हुए भी कहा था कि पंडोह तक आप नेशनल हाई वे फोर लेन ले जाईए हमें कष्ट नहीं है। उसके सामने चच्योट का क्षेत्र है उसको कुकलाह बोलते है वहां पर पूरी सड़क है और बड़ा पुल है और वहां से जाकर फिर लारजी में सड़क मिल जाएगी। यदि इधर से आप फोर लेन बनाएंगे तो द्रंग क्षेत्र का इलाका सारा सड़क में आ जाएगा। क्योंकि वह सारा स्लेट की खानों का एरिया है और स्लाइडिंग का एरिया है। और फिर वह टनल सबसे बड़ी समस्या है जो उधर रहने वालों के लिए एक मौत का कुंआ है, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। फिर अगर लारजी जाते हैं तो जिया तक सड़क है। वहां पर लैफ्ट बैंक आ जाता है। क्यों न इसको दोनो तरफ डबल लेन किया जाए? वह व्यवहारिक भी होगा और लोग भी नहीं उजड़ेंगे। अगर यह बजौरा की तरफ से आगे भी राईट या लैफ्ट बैंक पर भी ले जाए तो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वहां पर केन्द्र है, जमीन है ,पालमपुर यूनिवर्सिटी का जहां पर केन्द्र है। उस केन्द्र में 80 बीघे जमीन लग जाएगी और समाप्त हो जाएगा। जहां के लिए आप एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी को बनाने की प्रोपोज़ल सोच रहे हैं। इस प्रकार से जमीन का उजड़ना जनहित में नहीं है। मैंने इसके बारे में प्रश्न किया था। उस उत्तर को भी मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। उसमें कहा गया है कि जो तो पंडोह की बात है मैंने कहा था कि जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इण्डिया हाई वे की है क्या उनसे

25.03.2015/1625/जेके/जेटी/2

चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा जी हाँ । यह मुख्य मंत्री जी का ज़वाब है। लेकिन जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग पंडोह और थलौट के बीच में है उसके लिए कहा है कि यह सलाइडिंग एरिया है इसमें वन वे ही रहेगा। लेकिन साथ में एक बात और कही है कि एक टनल बनाई जाएगी और वह सीधी नगवाँई निकलेगी। एक टनल को तो हम पहले ही भुगत रहे है। यह दूसरा टनल ट्रेफिक का और जाएगा तो फिर इलाका सनौर जहां पहले भी सिंचाई की योजना सूख गई। धूमल जी के समय में डुगलीचला जो कि लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बनी थी सलाऊट से आज उससे लोगों का गुजारा चला हुआ है। अगर फिर आप उस ज्वालापुर क्षेत्र के नीचे से टनल बनाएंगे तो उससे सारे के सारे गांव प्रभावित होंगे। जो आपका कुल्लू में खराल क्षेत्र है वह सारा स्लाइडिंग एरिया है। उसमें लोकल चूना है जिसको हम ककरू बोलते हैं। वह सारे का सारा इस वर्षा में भी स्लाईड करता है। इतने बड़े-बड़े पत्थर उस नेशनल हाई वे के बाई पास की सड़क में आए हैं कि जितना बड़ा मकान होता है । अगर इसको ज्यादा छेड़ोगे तो बिजली महादेव में रहने वाली सारी की सारी आबादी नीचे सड़क में आ जाएगी। इसलिए मेरा नम्र निवेदन रहेगा और इसमें कहा गया है कि नगवाँई के बाद कुल्लू में टू लेन दोनों तरफ जाएगी। नगवाँई से जाएगी या कुल्लू से जाएगी।

Dy. Speaker: Please wind up now. आपका आधा घंटा पूरा हो गया।

25.03.2015/1625/जेके/जेटी/3

श्री महेश्वर सिंहः उपाध्यक्ष जी, मेरा सुझाव रहेगा कि इस पर सरकार पुनर्विचार करे। टू लेन बनेगी और रोड़ साइड ढाबे और रोड़ साइड जो वर्कशॉप हैं, उनको यह सुनिश्चित कर दिया जाए कि अलग से उनको जगह मिले। धर्मपुर के पास भी एक ज्ञानी का ढाबा है आधा वह सड़क में चलता है। अगर यहां पर पार्किंग न हो तो ट्रेफिक जैम तो होगा ही होगा। आप फोर लेन करें या दस लेन करें। आपने बोलने का अवसर दिया और सदन ने भी बड़े ध्यानपूर्वक सुना। मैं आपके माध्यम से सदन का भी धन्यवाद करता हूं और सभी का धन्यवाद करता हूं । आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

25.03.2015/1625/जेके/जेटी/4

उपाध्यक्षः अब श्री विक्रम सिंह ठाकुर चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विक्रम सिंह ठाकुरः आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, 18 मार्च, 2015 को जो बजट आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट निराशाजनक बजट है। मज़दूर विरोधी बजट है, दीशाहीन है और किसान विरोधी है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

25.03.2015/1630/SS-AG/1
श्री बिक्रम सिंह क्रमागतः

मेरे पास इसका क्रिटीसिज्म करने के लिए शब्द कम हैं। मेरे भाई चले गए, उन्होंने बड़ा अच्छा गुणगान किया। उन्होंने कोई शब्द नहीं छोड़ा और मुख्य मंत्री जी का ईश्वर के साथ कम्पैरीजन कर दिया। यहां पर कांग्रेसी मित्रों ने बात रखी और केन्द्र सरकार के बारे में बोला भी गया। आपके पास कोई शब्द नहीं हैं कि केन्द्र सरकार क्या कर रही है। जिसके सहारे हिमाचल प्रदेश की सरकार के विकास के काम चलेंगे उसके बारे में आपके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं हैं। जिस दिन मुख्य मंत्री जी ने बोला, उसके बाद मैं सचिवालय में गया। तो मैंने कहा कि क्या यहीं पर प्रॉब्लम है या इनके कमरों में भी प्रॉब्लम है। तो केवल मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में प्रधान मंत्री जी की फोटो लगी है और परिवहन मंत्री जी के कमरे में किसी की भी नहीं लगी। बाकी मंत्रियों के सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी की फोटो लगी है। अच्छी बात है, लगनी चाहिए। लेकिन आप केन्द्र में गुलदस्ते लेकर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा-से-ज्यादा मदद मिले और अपने कमरे में अपने देश के प्रधान मंत्री की फोटो लगाने में भी आपको शर्म आती है। डर इनका सच्चा है। अभी मुख्य मंत्री जी हैं नहीं, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो सदन में आ जाएं। इनको डर सच्चा है। आज आदरणीय मुख्य मंत्री जी की भाषा में कितना अंतर है। कहते हैं कि मैंने कभी मोदी जी के बारे में ऐसा नहीं बोला। बड़ी जल्दी बदल जाते हैं।

जिस समय अखबार की कोई बात आती है, आदरणीय रवि जी ने बोला कि आपने अखबार में ऐसा बोला। इन्होंने खड़े होकर बोल दिया कि मैंने तो बोला ही नहीं। अब आप लोगों ने झूठ बोलने में पी0एच0डी0 कर ली है तो हम भी क्या करें। थोड़ी बहुत शर्म तो होनी चाहिए कि इन विषयों के ऊपर मैंने बोला है तो बोला है। मैंने कहा कि जहां एक भी बच्चा नहीं होगा तो मैं वहां स्कूल खोलूंगा। आप बोलिये कि हां मैंने बोला है। जहां दो बच्चे होंगे, वहां मैं स्कूल खोलूंगा, फिर उस बात को घूमाते हैं कि बच्चों के ऊपर हम रेशनलाइजेशन की बात करेंगे। मोदी जी के विषय के ऊपर इनके बयान बदलते गए। लोक सभा के इलैक्शन से पहले जिस समय टिकटें मिलीं तो उस समय क्या बोला। कोई 50 बार आदरणीय मुख्य मंत्री जी का बयान है कि ये तीन बार जीते हैं और मैं पांच बार जीता हूं। देखा, पांच बार वालों की सफाई कैसे हुई। महेश्वर सिंह जी चले गए। इन्होंने उस समय क्या कहा? इन्होंने कहा कि रामस्वरूप जी की अंतिम इच्छा पूरी हो गई है कि उनको एम0पी0 का टिकट मिला। आप सब की बोलती बंद हो गई। सारी-की-सारी सीटें आप लोग हार गए। हिमाचल प्रदेश के

25.03.2015/1630/SS-AG/2

लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के हक में मैनडेट दिया। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए उस समय की बात और इस समय की बात में बड़ा अंतर देते हैं। मुझे कई बार थोड़ी हैरानी होती है। मेरे काफी मित्र यहां बैठे हैं, बड़े प्रेमी हैं। चम्चागिरी की भी एक सीमा होनी चाहिए। आप इतनी ज्यादा चम्चागिरी करते हैं कि हद है कि मैंने करना क्या है। मैं समझता भी हूं कि आप चम्चागिरी क्यों करते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि 12 मंत्री के पद हैं। 11 बन गए हैं और एक बनना है। आपको आज खुले मन से सदन के अंदर बता देता हूं कि ये 11 मंत्री ही रहेंगे। 12नहीं होंगे क्योंकि मुख्य मंत्री जी को बताया है कि अगर 12 हो गये तो वह सीट खाली हो जायेगी। इसलिए वह पांच साल तक नहीं बनेंगे। इसलिए इस वहम में मत रहिये और जो सच्चाई है उसको बोलिये। अगर विकास हुआ है तो विकास की बात करें। अगर विकास नहीं हुआ है तो विकास की बात मत करें। यहां पर खड़े हो कर बोल रहे हैं कि मैंने कोई कॉलेज बंद नहीं किया। आदरणीय रवि जी ने कहा कि आपने इनका कॉलेज बंद किया है तो फिर बोला - हां मैंने बंद किया है क्योंकि वह कॉलेज बनता नहीं है। बड़े दुख से मुझे इस सदन में बताना पड़ रह है। मैंने आर0टी0आई0 में सूचना ली। ये जो प्रिंसीपल की वहां पर डयूटी लगी थी जिन्होंने वहां पर जाकर सर्वे किया। उन्होंने

10.11.2003 को रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में लिखा कि जिस समय वे वहां पर सर्वे करने गए तो उनकी 400 से ज्यादा लोगों के साथ मीटिंग हुई।

जारी श्रीमती के0एस0

25.03.2015/1635/केएस/एजी/1

श्री बिक्रम सिंह जारी----

और उसके दो-तीन मेन कंटैंट्स मैं जरूर पढ़ूंगा - "The land available for the purpose is about 104 kanals. The area of the 40 kanals in the forefront is partially khad which needs to be selectively channelized." कोटलाबेड़ जहां पर पूर्व मुख्य मंत्री श्री धूमल जी ने कॉलेज खोला था - "Kotlaber is 42 km, 41 km, 45 km from Government Post Graduate College, Dhalyara, Amb and Berri. The Government land available for the purpose is in the possession of concerned Gram Panchayat and is allotable pool. NOC from the panchayat is attached herewith." इसके साथ-साथ उन्होंने और भी ऐसे प्वाईंट्स दिए हैं जिससे उन्होंने बाद में यह निष्कर्ष निकाला है कि वहां पर कॉलेज जरूरी है। सर्वे हो रहा है, प्रिंसिपल और बाकी जो लोग वहां पर गए हैं, वे इसकी रिपोर्ट दे रहे हैं कि वहां पर कॉलेज होना चाहिए और आप कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि वहां पर कॉलेज की जरूरत नहीं है। फिर सात कॉलेज कैंसिल हुए और उसमें हाई कोर्ट के अंदर एफेडेविट दिया कि ये कॉलेज इसलिए कैंसिल किए जा रहे हैं क्योंकि यहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्टूडैंट्स नहीं है। एफेडेविट दे दिया, महीने के बाद मुख्य मंत्री जी का प्रवास शुरू हो गया। एक कॉलेज खोला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कॉलेज खोल दिया और उनकी वस्तुस्थिति आज क्या है? गवर्नमैंट कॉलेज कुमारसैन, बीच में जो पहले वाले भी हैं उनकी स्ट्रैंथ बता रहा हूं, कुमारसैन- 75, गवर्नमैंट कॉलेज क्यारकोठी- 38, गवर्नमैंट कॉलेज धर्मपुर-20, गवर्नमैंट कॉलेज ननखड़ी-16, गवर्नमैंट कॉलेज दिग्गल-32 और एक गवर्नमैंट कॉलेज, वह बन्द नहीं हुआ, नया खुला है नगरोटा सूरियां उसकी संख्या 117 है और हाई कोर्ट के अंदर जो एफेडेविट दिया है उसमें यह बोला गया है कि कोई भी कॉलेज 25 किलोमीटर के अंदर तब नया खुलेगा जब उसके साथ लगते कॉलेज की स्ट्रैंथ तीन हजार से ज्यादा होगी। मुझे इन बातों का कोई दुख नहीं है कि आप जहां जा रहे हैं,

25.03.2015/1635/केएस/एजी/2

वहां आप कॉलेज खोल रहे हैं, तहसील खोल रहे हैं, एस.डी.एम. के ऑफिस खोल रहे हैं, अच्छी बात है लेकिन जहां पर लोगों के लिए जरूरत है वहां काम करिए। मुख्य मंत्री जी अभी बैठे नहीं है, मैंने इनसे पूछना था, मुझे तो ये कहते हैं कि यह बड़ा अच्छा लड़का है, नौटी ब्वाय है तो मेरे साथ की पंचायत के साथ में विप्लव ठाकुर जी का घर है कहीं उनके चक्कर में तो मैं नहीं रगड़ा जा रहा हूं? वे अभी यहां पर नहीं बैठे हैं लेकिन मेरे मित्र उस तरफ जो बैठे हैं वे उनसे इस विषय पर जरूर बात करेंगें। कहा जा रहा है कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ऐजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया हो रहा है। यहां पर मेरे कई मित्र कह रहे हैं कि आप पिछले बजटों की बात क्यों करते हैं आप प्रैज़ेंट बजट की बात कीजिए। एक बात ध्यान में रखें कि केवल मूर्खों के टोले में मूल्यांकन नहीं होता, समझदारों के टोलों में मूल्यांकन होता है। आपने पीछे क्या किया, आपकी क्या पॉलिसी थी, आपका क्या प्रोग्राम था उसके बारे में पता होना चाहिए। पिछली बार आपने कोई ए स्कीम चला दी, अगली बार बी चला दी और उससे अगली बार सी स्कीम चला दी। ए की क्या स्थिति है, बी की क्या स्थिति है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। शिक्षा के विषय में कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं । मैं तो बोलता हूं, यहां कांगड़ा के मेरे विधायक मित्र बैठे हैं जो बेइन्साफी कांगड़ा के साथ हुई है उसके बारे में हमें चिन्तन करना चाहिए। सैंट्रल युनिवर्सिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज सैंट्रल युनिवर्सिटी के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है? कभी कहा जाता है इसको देहरा में खोलेंगें। नई सरकार आ गई कहते हैं कि

25.03.2015/1635/केएस/एजी/3

धर्मशाला में खोलेंगें। कुछ तथ्यों के साथ यह वीरभद्र सिंह जी की चिट्ठी है जो इन्होंने मुख्य मंत्री बनने के बाद श्रीमती जयन्ती नटराजन, ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फोरैस्ट एण्ड एन्वायरन्मैंट, गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को भेजी है। यह चिट्ठी बड़ी लम्बी है क्योंकि समय की यहां सीमा है लेकिन दो-तीन चीजें इसमें जरूर बताऊंगा। इसमें डेट है 28.01.2013 और इसमें लिखा हैः-

अंग्रेजी अ0व0 की बारी में--

25.3.2015/1640/JT/av/1

श्री बिक्रम सिंह जारी-

"The matter is pending with the Ministry of Environment and Forest since November, 2011 regarding diversion of 385.223 hectare. Out of that, 62.54 hectare at Dharamsala and 370.97 hectare at Dehra." यह मैं नहीं लिख रहा हूं, यह वीरभद्र जी लिख रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा - "The fact that I am writing this letter to you within two weeks of my assuming the office is testimony to the importance that I accord to this prestigious project and I would like to urge you to look into the matter personally and give FCA clearance for the proposal at the earliest." यह वे लिख रहे हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद क्या हो गया? इनके सलाहकार मेरे मित्र है। किसी ने सलाह दे दी कि यहां सब कुछ हो रहा है आप धर्मशाला में करो। (---व्यवधान---) संजय रतन अच्छा है, इसकी बात बाद में करेंगे। यह धर्मशाला में खुलनी चाहिए। धर्मशाला के बारे में कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है? उन्होंने कहा कि वहां जमीन नहीं है। अर्थ क्वैक प्रोन एरिया है। वहां बिल्डिंग नहीं बन सकती। वह कमेटी वाइस चानसलर के पास गई और उस कमेटी ने ये सारी-की-सारी बातें वहां रखी हैं। उसके बाद नई प्रपोजल दे दी कि 80 प्रतिशत धर्मशाला में हो और 20 प्रतिशत देहरा में हो। यह बड़ा अजीब सा विषय है। अभी एक अखबार में आ गया कि 'केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए धर्मशाला में नहीं निकली नई जमीन।' देहरा वाले भी मूर्ख बन रहे हैं और धर्मशाला वाले भी मूर्ख बन रहे हैं। देहरा के अंदर खैर के पेड़ है और खैर का पेड़ कैश क्रॉप में आता है जो कि दस साल के बाद कटता ही है जबकि धर्मशाला में ग्रीन ट्रीज हैं। उन पेड़ों को धर्मशाला की ग्रीनरी बचाने के लिए वर्षों से प्रोटैक्ट किया हुआ है। देहरा में पानी की कोई समस्या नहीं है। उसको ऐक्सपेंड किया जा सकता है। धर्मशाला के अंदर तो सारी-की-सारी समस्याएं हैं। लेकिन, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं जिद्दी हूं। मैं जो बोलता हूं, वही करता हूं। यह केवल ऐसा विषय नहीं है कि सिर्फ सैंट्रल युनिवर्सिटी की बात है। आप कहीं भी देख लो, इन्होंने हर जगह जिद्द की है। आप आदरणीय धूमल जी के विषय में देख लो, हमारे भाई अनुराग ठाकुर के विषय में देख लो। जहां-

जहां ऐसा किया है वहां-वहां या तो जो राज्यपाल महोदय से टिप्पणियां मिली हैं उनसे सिद्ध हो जाता है कि आप जो कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। कोर्ट से जितने फैसले आए हैं वहां पर कहीं भी इस प्रकार का नजर नहीं आता कि जो आप कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं। मगर यह ठीक है, क्योंकि मैंने तो यह करना ही है। अभी यहां पर भाई सुधीर जी नहीं है। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि धर्मशाला में जमीन नहीं मिली और देहरा में ये खोलना नहीं चाहते तो फिर कांगड़ा में ये क्या करना चाहते हैं? यह कांगड़ा के साथ भेदभाव है या नहीं? (---व्यवधान---) संजय रतन जी, आप नहीं बोलेंगे। आपको यह अभी तक समझ नहीं आया है। बड़ी क्लीयर बात है, जब सैंट्रल युनिवर्सिटी की आंधी चलेगी तो हम कोई नहीं बचेंगे। अभी मुख्य मंत्री जी ने खड़े हो कर बोला था कि मोदी जी की लहर थी। उस समय अपने स्टेज से सौ बार बोला होगा कि मोदी नाम की तो कोई लहर है ही नहीं। मेरी लहर है, मेरे काम से ही सब कुछ होता है। उस लहर के कारण संजय रतन जी, आपको भी 14000 वोट का नुकसान हुआ। (---व्यवधान---) आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आपके काम की प्रशंसा करता हूं। आपने कोई दफ्तर ऐसा नहीं छोड़ा है जो वहां नहीं खोला। मैं यह कहना चाहता हूं कि बाद में कोई दफ्तर नहीं देखेगा। जिस समय देहरा में सैंट्रल युनिवर्सिटी के विरोध की लहर चलेगी आप भी उड़ जायेंगे। आप मेरे मित्र है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप डब्बलिंग मत कीजिए। हमें-आपको ओपन बोलना पड़ेगा कि इसका मेज़र पोर्शन धर्मशाला के अंदर नहीं बल्कि देहरा के अंदर खुलना चाहिए। हम धर्मशाला के विरोधी नहीं है। धर्मशाला जिला कांगड़ा का एक पार्ट है मगर वहां पर स्थान नहीं है। वहां पर बिल्डिंग नहीं बन सकती। आपको इस बारे में ओपनली बोलना चाहिए। आपको यह बोलना चाहिए कि सैंट्रल युनिवर्सिटी का मैन हक देहरा के लिए बनता है। (---व्यवधान---) एम.एल.ए. बनने के बाद ही तो बीमारी पड़ी है। एम.एल.ए. बनने से पहले तो आप बड़े अच्छे थे। उस समय तो आप राजनीति की कोई बात नहीं करते थे। अब आपको राजनीति की बात करनी आ गई है, भाई। लेकिन मैं आपको मित्रता के नाते यह बता रहा हूं।(---व्यवधान---)इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं----------श्री नेगी द्वारा जारी

25.03.2015/1645/negi/jt/1

श्री बिक्रम सिंह.. जारी...

तो इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि इन चीज़ों के ऊपर चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और चाहे हम कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जब सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी की बात आएगी और किसी अनपढ़ आदमी के आगे अगर आप केस प्लीड करेंगे तो उसका जवाब यही होगा कि सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी देहरा के अन्दर खुलनी चाहिए । सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में इन-इन कारणों से नहीं खुलनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी भी मुख्य मंत्री महोदय इसके बारे में सोचें और विचार करें और सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पर पूरे कांगड़ा को मूर्ख बनाने का जो काम चलाया हुआ है उसको आप बन्द करें। ...(व्यवधान) ...आपको (श्री जी.एस.बाली) देहरा से कोई प्रॉब्लम है? आपके कांगड़ा में बहुत कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे एरिया में नही है तो वहां होनी चाहिए। हमने तो सभी वर्गों का बहुत ख्याल रखा। हमारे कई भाईयों ने यहां पर इसका बड़ा गुणगान किया। भाई किशोरी लाल जी यहां बैठे हैं और भी हमारे बड़े भाई हैं। मैं खास करके उन भाईयों की बात कर रहा हूं जो आरक्षित सीटों से जीत करके आए हैं । आप काहे का धन्यवाद कर रहे हैं? क्या पी.टी.ए. के अन्दर रोस्टर लगा? पैट के अन्दर रोस्टर लगा? सचिवों के अन्दर रोस्टर लगा? एस.एम.सी. के अन्दर रोस्टर लगा? आप सब लोग अपनी कम्युनिटी के विरोधी हैं। आपको यहां पर यह प्लीड करना चाहिए था कि बजट तो बड़ा अच्छा है लेकिन हमारे वर्ग के साथ अनदेखी हुई है। मैं तो सामान्य वर्ग से हूं, मुझे उनका केस प्लीड करना चाहिए। लेकिन आप जिस वर्ग से हैं उनका केस प्लीड नहीं कर पाये। एस.सी. को उसमें रिज़र्वेशन नहीं है, ओ.बी.सी. को रिज़र्वेशन नहीं है, आई.आर.डी.पी. को रिज़र्वेशन नहीं है और एस.टी. को रिज़र्वेशन नहीं है। इसलिए आप इस प्रकार से गुणगान करेंगे तो आपके विधान सभा क्षेत्र वाले समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। यहां की सारी की सारी रिपोर्टिंग भी जाती है। अगर आप कांग्रेस के विधायक हैं तो कोई न कोई बी.जे.पी. वाला लगा होगा चुगली करने। अगर हम बी.जे.पी. वाले यहां गलत बोलेंगे तो कांग्रेस वाला लगा होगा चुगली करने। यहां पर ठीक बात बोलो। अगर सही बात बोलेंगे तो उसका नतीज़ा भी सही

25.03.2015/1645/negi/jt/2

आएगा। यहां पर यह बोला गया कि दिहाड़ी 150 रूपये से बढ़ा कर 170रूपये की थी और हमने दिहाड़ी 170 रूपये से बढ़ा कर 180 की है। यहां पर अलग-अलग क्वैश्चन लग रहे हैं और पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे लोग हैं जो आपने फालतू दफ्तरों में बिठाए हुए हैं? कितने ऐसे लोग हैं जिनको एक्सटैंशन दी हुई है? वहां पर आपका करोड़ों रूपये खर्च आ रहा है। लेकिन जिस समय दिहाड़ीदार की बात आती है तो उसको 10 रूपये दिए जाते हैं। यहां पर जब पे-कमीशन की बात आती है तो आप कहते हैं कि पंजाब के आधार पर होना चाहिए। आपको पता है कि पंजाब में दिहाड़ी कितनी है? पंजाब में दिहाड़ी 256 रूपये है और हरियाणा में दिहाड़ी 223 रूपये है और आपकी दिहाडी सबसे कम 180 रूपये है। कहते हैं कि यह गरीब का बजट है और हमने गरीबों को बहुत सहुलियत दे दी। आपने वृद्ध तथा विधवाओं की सामाजिक पैंशन 550 रूपये से बढ़ा कर 600 रूपये कर दी और बहुत बड़ा काम कर दिया। गरीबों का बजट तो तब माना जाता जिस समय मजदूर की दिहाड़ी में बढ़ौतरी होती और विधवा और अपंग की पैंशन में अच्छी बढ़ौतरी होती । जिस समय सारी की सारी कैबिनेट बैठती है तो कोई तो उसमें बोलने का हिम्मत रखें। जो ये 10 रूपये दिहाड़ी बढ़ायी जा रही है यह किस प्रकार का मज़ाक किया जा रहा है। जब हम विधवा पैंशन 550 रूपये से बढ़ा कर 600 रूपये कर रहे हैं, यह मज़ाक कैसा है ? लेकिन सत्ता पक्ष के भाई बोलते हैं अगर हम नहीं बढ़ा रहे है तो आपने बढ़ानी थी । ...(व्यवधान) ...यहां पर खड़े हो करके बड़े शान से बोलते हैं कि 18वां बजट है , आप दैवीय रूप हैं और आप में दैवीय शक्ति है। क्या हमारे साथ राक्षसों की शक्ति है? हमारे साथ भी भगवान हैं। यह भगवान इस बार चमत्कार करेगा और जो पाप आप कर रहे हैं, यह पाप का घड़ा भर गया है और आने वाला समय हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का होगा, यह मैं दावा करना चाहता हूं। एक 12.9.2014 को जो डिसेबल हेन्डीकेप हैं, यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह गरीबों का बजट है।

श्रीमती यू.के. द्वारा जारी...

25.03.2015/1650/यूके/1

श्री बिक्रम सिह ठाकुर--जारी----

डिसेबल्ड हैन्डीकैप्ड के बारे में 12.9.2014 को सुप्रीम कोर्ट बैंच में चीफ जस्टिस श्री आर0एम0 लोढा, एक फैसला हुआ है कि जो डिसेबल्ड हैंडीकैप्ड हैं, उनको प्रोमोशन में 3 प्रतिशत का आरक्षण मिले । बड़ी कम संख्या है । लेकिन गरीबों के मसीहा, ये सरकार, इसने भी आज तक इसको इम्पलीमैंट नहीं किया । उन्होंने कहा है कि implement this decision in Centre, State and Union Territory. सभी की बात क्या करनी, हिमाचल प्रदेश के अन्दर तो इसको अभी लागू नहीं किया है, हम चाहेंगे कि इसका लागू किया जाए ।

रिसोर्स मोबलाइजेशन के बारे में भी चर्चा हुई । कई बार कहते हैं कौल सिंह जी के बारे में कि उन्होंने रिज़ाईन कर दिया या उनसे रिज़ाईन ले लिया । ठीक किया कि रिज़ाईन कर दिया । इनकी बात कौनसी माननी थी क्योंकि इन्होंने तो कड़वी बात करनी है, ये सच्चे-पक्के आदमी है? तो अब मैडम जी, बना दिए है उसके, अब मैडम जी तो सप्लीमैंटरी क्वैश्चन का उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, ठीक ढंग से । ये रिसोर्स मोबलाइजेशन में क्या करेंगीं ? वे कहती हैं कि मैं आपकी तसल्ली करा दूंगी, आप मेरे कमरे में आओ । अब वह कमेटी क्या कर रही है? हमारी सोच से तो बाहर है । वह कमेटी क्या नहीं कर रही? वह कमेटी इस कंगाली को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रही है । कंगाली के बारे में भी बात करें तो बड़ा अच्छा है क्योकि आज मुख्य मंत्री जी नहीं है । हमें बड़ा अच्छा माहौल मिला हुआ है, नहीं तो अभी तक 10-12 बार उन्होंने खड़े हो जाना था । हमने बन्द हो जाना था, हमें पता लगना नहीं था । लेकिन आज बड़ा अच्छा चला हुआ है।

25.03.2015/1650/यूके/2

कंगाली जैसे हालात, आदरणीय रणधीर जी ने बताया था कि किस प्रकार से आप BDO ऑफिसिज़ से सारे का सारा पैसा ट्रेज़री ऑफिस में वापिस भेज रहे हैं । मैने कहा शायद रणधीर जी को इसमें शायद कोई गलतफहमी हुई है । उन्हीं का होगा शायद हमारा नहीं होगा । लेकिन जब मैने अपना पता किया 19.3.2015 को 4.77 करोड़ रुपए BDO ऑफिस से ट्रेज़री ऑफिस को भेजा गया । मैने कहा भाई, आप ठीक बताना, मैने हाऊस के अन्दर बोलना है । तो वे कहते हैं कि आप आगे की फिगर भी लो। SDP हैड 10 लाख रुपए ,एम0पी0लैड, एक बात मेरे को समझ नहीं आयी, चलो आप MLA फंड हुआ उसको आप ले जाओ, कि यह हमारी सरकार ने

दिया है लेकिन आप एम0पी0लैड को भी ट्रेज़री ले जा रहे हैं । उसका मुझे समझ नहीं आया कि क्या कारण है ? एम0पी0लैड भी चला गया । आपका विभाग है, सर । आपके विभाग से गया है, BDO ऑफिस से। रीलीफ से 10 लाख रुपए ,विकास में जन सहयोग से 10 लाख रूपए ,13वें वित्तायोग से 80 लाख रूपए ,VK &Y से 37 लाख, हमारी लोग जान खा रहे हैं कि जी आप कहते थे कि पैसे दिए हुए हैं, आपकी चिट्ठी आ गयी । हमारा तो पैसा नहीं लग रहा । यह पता मुझे अब लगा कि पैसा तो ट्रेज़री में है । 13वें वित्तायोग जिला परिषद का 10 लाख ,टोटल सेनिटरी प्रोग्राम, 10 लाख, गुरु रविदास योजना जो बन्द हो गयी है । उसका पैसा होगा वह भी ले गए 40 लाख रुपए । यह हालत है आपकी सरकार की । तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, चैयरमैनों की फौज लम्बी होती जा रही है । अच्छे और सभ्य चैयरमैन बनाओ । हमारे इलाके का भी एक चैयरमैन बनाया है । मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं और वह खड़ा हो कर बोल रहा है कि इस तरफ का विधायक गुंडा है । आप भी मेरे साथ ही रहते हो, मैने कौन

25.03.2015/1650/यूके/3

सी गंडा-गर्दी की है? किसके साथ कोई गुंडा-गर्दी की है तो बताइए । हम आपसे प्यार से बात करते हैं, आपके पांव हाथ लगाते हैं, सुजान सिंह पठानिया जी । कहते हैं कि ये गुंडा है । इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं । वह तो मूर्ख है बेचारा, जो बोल रहा है । उसको नहीं पता । उसको सभ्य भाषण नहीं आता । लेकिन जो साथ में कुर्सी में बैठे हैं, जो कहते हैं में 6 बार मुख्य मंत्री बन गया, वे भी बड़े मजे से सुन रहे हैं । बड़े दुख का विषय है । इस प्रकार की बातें और फिर हमारे जमाने में भी (घंटी) मेरे को आज भी याद है कि विपल्व ठाकुर जी विधायक थे, आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी हमारे क्षेत्र में त्रिपल में आए । उनको वहां बुलाया, बैठाया और भाषण करवाया । आपकी तो मानसिकता इतनी संकीर्ण हो गयी है कि आप हमारे क्षेत्र के अन्दर जा रहे हैं, आप पुलों का उद्घाटन कर रहे हैं जिसके लिए आपने 5 पैसे तक प्रोवाईड नहीं करवाए, सारे का सारा पैसा आदरणीय धूमल जी ने दिया है । आपका वहां का एक ऐक्सियन कटर्सी से यह भी नहीं बोलता कि विधायक जी आप हमारे इस कार्यक्रम में आइए । आपको बी0जे0पी0 वालों से इतना डर लगता है कि यदि आपके कार्यक्रम आएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे । जिस समय हमने काले झंडे दिखाने होते हैं तो हम ओपनली बोलते हैं कि हम काले झंडे दिखाएंगे ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी---

25.03.2015/1655/sls-jt-1

श्री बिक्रम सिंह...जारी

और कइयों ने मुझसे बाद में कहा कि आपके कारण साहब का जसवां का टूअर कैंसिल हो गया क्योंकि आपने काले झंडे दिखाए। मैंने कहा कि जसवां के टूअर से काले झंडों का कोई लेना-देना नहीं है। यह सैंट्रल यूनिवर्सिटी का विषय है। जब सैंट्रल यूनिवर्सिटी की बात चलेगी तो काले झंडों के साथ ही स्वागत होगा। अगर हमारे विधान सभा क्षेत्र में आते हैं तो हम स्वागत करेंगे। लेकिन आप इतने संकीण हो गए कि आप बुलाना भी उचित नहीं समझते।

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं केवल विधान सभा के अंदर बैठे कुनबे की बात नहीं कर रहा हूं।

Deputy Speaker: Please wind-up now.

श्री बिक्रम सिंह :उपाध्यक्ष महोदय, जो इनको सुपोर्ट कर रहे हैं और जो अफसर इनको गलत सुपोर्ट कर रहे हैं ,वह समय दूर नहीं है कि इसका सभी को ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा। हमें गलत काम नहीं करना चाहिए बल्कि सही तरीके से काम करना चाहिए। जो नीति के अनुसार बनता है, वह करना चाहिए। लेकिन जो यह गलत काम हो रहा है, यह ठीक नहीं है।

लिखा है कि 33737 किलोमीटर सड़कें बन गई। आज मेरे दो प्रश्न लगे थे जिनमें मैंने पूछा था कि इंटर स्टेट कनैक्टिविटी और सैंट्रल रोड फंड का कितना पैसा जसवां विधान सभा क्षेत्र के लिए है? उत्तर जीरो है। पिछले दो सालों में एक भी सड़क का फोरैस्ट केस बनकर नहीं गया। सात सड़कें ऐसी हैं जिनका काम पिछले 2-3 वर्षों से बंद है। पी.एम.जी.एस.वाई. का भी और विधायक प्राथमिकता का भी यही जवाब है कि हमने केस भेजना है। सड़कें टूट रही हैं। अभी महेश्वर सिंह जी ने बोला। वहां पर जो पैच लग रहे हैं, वह लगने के बाद 5 या 6 दिन के बाद नज़र नहीं

आते। जहां आपने ऐन्चल सर्फेसिंग करवाई है वह 15 दिन के बाद उखड़ गई है। अभी हमने एक मांग की कि बठरा से जो छुआंगता रोड जाता है ,उसकी सी.बी.आई. से

25.03.2015/1655/sls-jt-2

जांच होनी चाहिए। वहां पर करोड़ों रुपया लगा है। लेकिन विभाग सोया है। जिस समय हमारी प्लानिंग की मीटिंग हुई, उसमें प्रिंसीपल सैक्रेटरी (पी.डब्ल्यू.डी.) ने कहा कि हम 20 दिन के अंदर आपके साथ बैठेंगे और जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। उस समय तो बोल देते हैं क्योंकि वहां पर मीटिंग में खिंचाई होती है। लेकिन बाद में कोई इस काम के लिए नहीं आता। मेरा एक सुझाव है कि जो सड़कें बन रही हैं, उनमें दिहाड़ीदार मज़दूर कम हो रहे हैं। आप बाकी रिक्रूटमैंट भी कर रहे हैं। इसमें भी अगर आप दिहाड़ीदारों की संख्या बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर सड़कों का काम होगा।

यहां पर कानून-व्यवस्था के विषय में काफी चर्चा हुई। कानून-व्यवस्था कैसे ठीक होगी?

उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। आपका समय हो चुका है। आपके पूरे 28 मिनट हो चुके हैं।

श्री बिक्रम सिंहः सर, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

सारी-की-सारी पुलिस आपने श्री प्रेम कुमार धूमल जी के पीछे लगाई है। इनको कभी कहीं ढूंढ़ रहे हैं तो कभी कहीं। अनुराग ठाकुर जी के पीछे पुलिस लगाई है। आपने 5-7 केस उनके और 3-4 केस इनके बनाए हैं। आपकी पुलिस को जो काम करना चाहिए, वह उसे नहीं कर रही है। इसलिए अभी पिछले दिनों हमारे कार्यालय के ऊपर जो हमला हुआ है ,उसकी हमने इस सदन में घोर निंदा की है और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कानून-व्यवस्था पर यहां बड़ी लंबी-चौड़ी बातें हुई हैं। मैं केवल इतना कहूंगा कि जिसका जो काम है, उसको वह काम करने दीजिए। अगर आप इनको किसी और काम में लगाएंगे तो हमारी व्यवस्था बिगड़ेगी।

आपने यहां पर्यटन के बारे में भी कहा। पर्यटक आज क्यों नहीं आ रहे हैं?

Deputy Speaker: Please wind-up. It is repetition now.

25.03.2015/1655/sls-jt-3

श्री बिक्रम सिंह :ठीक है, सर।

आंकड़ों के मुताबिक आपके पर्यटक कम हुए हैं। उसके पीछे प्रमुख कारण है कि आपने आई.पी.एल. के मैच बंद करवाए हैं। रात के अंधेरे में आप लोग वहां ताले लगवाते हैं ,होटलों को बंद करवाते हैं। इस प्रकार के काम अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर चाहे पर्यटन है, हैल्थ है या कानून-व्यवस्था है, इन सभी में किसी प्रकार की स्थिति सुधरने वाली नहीं है।

आदरणीय कौल सिंह जी यहां बैठे हैं। आपने पिछली बार सदन में यह विश्वास दिया था कि आपके क्षेत्रों से हम डैपुटेशन नहीं करवाएंगे। एक डॉ० मिनाक्षी हैं, पी.एच.सी. परागपुर में हैं, उनके डैपुटेशन के ऑर्डर इसी मार्च महीने में गए हैं। मैंने सी.एम.ओ. को कहा कि आप यह काम मत करो। ...(व्यवधान)... मेरे पास चिट्ठी है, मैं रख देता हूं। उसका डैपुटेशन सिविल अस्पताल कांगड़ा में किया गया है। इस प्रकार के काम न करें। जहां पर आपकी एक्स-रे मशीन है वहां पर आपका रेड़ियोग्राफर नहीं है।

उपाध्यक्ष : प्लीज समाप्त करें अन्यथा मैं नैक्सट स्पीकर को कॉल करूंगा।

जारी..श्री गर्ग जी

25/03/2015/1700/RG/AG/1

श्री बिक्रम सिंह के पश्चात

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया अब आप बैठ जाइए। आपका समय हो गया है।

श्री बिक्रम सिंह : इन सारी बातों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो बजट भाषण यहां दिया है ,यह लंबा जरूर है ,लेकिन इसमें कुछ नहीं है। यहां पर बहुत शेर सुनाए गए, मैडम जी ने भी सुनाया था ,लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा कहते हैं। (अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार माननीय सदस्य द्वारा पंजाबी में बोला गया शेर कार्यवाही से निकाला गया।)

उपाध्यक्ष : अभी 16 माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेना है। इसलिए यदि सदन की अनुमति हो, तो सदन का समय दो घण्टे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

माननीय सदस्यगण : जी हां, समय बढ़ा दें।

उपाध्यक्ष : ठीक है ,अब इस माननीय सदन का समय शाम 7.00 बजे तक बढ़ाया जाता है। अभी श्री बिक्रम सिंह जी ने अन्त में पंजाबी में कुछ कहा था उसको इस कार्यवाही से निकाला जाए।

अब श्री राजेश धर्माणी जी ,मुख्य संसदीय सचिव चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई असंसदीय शब्द नहीं है।

Deputy Speaker: No-no, I have given my ruling. Please sit down. श्री राजेश धर्माणी जी आप बोलिए।

/-2

25/03/2015/1700/RG/AG/2

श्री राजेश धर्माणी (मुख्य संसदीय सचिव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं------ (व्यवधान)---

Deputy Speaker : Raviji, please sit down.

श्री राजेश धर्माणी (मुख्य संसदीय सचिव): कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसका मीनिंग क्या है?----(व्यवधान)---

Deputy Speaker: Please keep quiet.

श्री राजेश धर्माणी (मुख्य संसदीय सचिव) : माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट अनुमान वर्ष 2015-16 के लिए इस माननीय सदन में प्रस्तुत किए हैं इसमें आय और व्यय 28,338. 63करोड़ रुपये दर्शाया गया है। मैं इन बजट अनुमानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि यह बजट जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश के समग्र विकास को बढ़ावा देगा----(व्यवधान)---हंसेंगे,-हंसेंगे, मेरे ज्यादा हंसने से आपको निराशा होगी ,इसलिए मैं कम हंस रहा हूं। इस बजट के मुताबिक जहां हमारे पूरे प्रदेश का समग्र विकास होगा। हमारे प्रदेश का भविष्य अच्छा दिखता है वह भी बहुत सारे वर्गों के लिए। चाहें वे छात्र ,वृद्ध, महिलाएं, वृद्ध महिलाएं ,विधवा महिलाएं या फिर हमारे मजदूर भाई या कर्मचारी हैं, यह बजट सबके हित की बात करता है । इसको हम एक आशावादी बजट कह सकते हैं ,लेकिन कुछ भाइयों को जो हमारे सामने विपक्ष के भाई बैठे हैं ,यह बजट इनको निराशाजनक लगता है। यह स्वाभाविक भी है। जब हमारी सरकार कोई अच्छा काम करेगी ,जब हमारी सरकार कोई अच्छी योजना लाएगी ,अच्छा बजट पेश करेगी, उससे हमारी पार्टी को राजनैतिक लाभ मिलेगा और इनका भविष्य इससे अन्धकार में जाएगा। इसलिए इनको यह निराशाजनक बजट लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के मुताबिक यदि आप इस बजट के अच्छे पहलू को देखें ,तो हमारा जो वर्ष 2014-15 का बजट था वह माइनस 8.13 रैवेन्यु डैफिसिट था जो रैवेन्यु अब सरप्लस में है और 0.20 प्रतिशत है। वहीं फिसकल डैफिसिट जी.एस.डी.पी. का माइनस 4. 01प्रतिशत था जो अब घटकर माइनस2 . 91प्रतिशत रहेगा। जो हमारे ऊपर टोटल ऋण है वह जी.एस.डी.पी. के परसेंटेज के मुताबिक कम हुआ है। वर्ष 2014-15 के बजट में यह जी.एस.डी.पी. का 36.54 प्रतिशत था जो वर्ष 2015-16 के बजट में 33. 83प्रतिशत रहेगा। जो गारन्टीज हैं वे भी रैवेन्यु रिसीट

25/03/2015/1700/RG/AG/3

का टोटल उसकी परसेंटेज के हिसाब से वर्ष 2014-15 में 23. 30प्रतिशत थीं और अब घटकर वर्ष 2015-16 के बजट में------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

25/03/2015/1705/MS/AG/1

श्री राजेश धर्माणी (मुख्य संसदीय सचिव)जारी--------
वह भी रेवेन्यु रिसीट्स का टोटल। उसकी परसेंटेज के हिसाब से वर्ष 2014-15 में 23.30 प्रतिशत थी और अब वर्ष 2015- 16में घटकर 18. 72प्रतिशत रहेगी। हमारा जो GSDP है, वह वर्ष 2014- 15में95 ,587/-करोड़ रूपये आंका गया है और वर्ष 2015- 16में बढ़कर 1,12,934-/करोड़ रूपये हो जाएगा। ऐसा उसमें अनुमान लगाया जा रहा है। हमें इस बात का भी फक्र है कि हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से काफी ज्यादा है। जहां राष्ट्रीय स्तर की 88,538-/रूपये है वहीं पर हमारी 1,4,953-/रूपये है। अगर इन आंकड़ों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा जो बजट है, वह आशावादी है, भविष्योन्मुखी और विकासोन्मुखी है। जो हमारे वर्तमान संसाधन हैं उनके मुताबिक माननीय मुख्य मंत्री जी ने अच्छा बजट पेश किया है। हमारे यहां पर कुछ विपक्ष के साथियों ने कहा कि 13वें वित्तायोग से हिमाचल प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं? चाहे कोई भी वित्तायोग है, चाहे 13वां वित्तायोग है या 14वां वित्तायोग है। यह कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। इसमें एक्सपट्र्स बैठते हैं और फिर बाद में उसको भारत सरकार एप्रूव करती है। अगर राजनीतिक आधार पर, राजनीति को आधार मानकर हिमाचल प्रदेश की ग्रांट कम हुई है तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा और झारखण्ड में थी। इन राज्यों की एलोकेशन की परसेंटेज 12वें वित्तायोग के मुकाबले 13वें वित्तायोग में क्यों बढ़ाई गई? हिमाचल को कम क्यों मिली? (व्यवधान)इसका कारण यही था कि यहां का केस ढंग से प्लीड नहीं हुआ। कहीं-न-कहीं गलती हुई है। हालांकि आपकी तरफ से भी कोई ऐसी इन्टैंशन नहीं होगी कि हमारी रिडक्शन हो लेकिन इसमें गलती हुई है, इसको आपको मानना पड़ेगा। यहां पर 14वें वित्तायोग की बात करते

हैं। मोदी साहब हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं लेकिन वह एक ऐसे राज्य से संबंध रखते हैं जो व्यापार करना जानते हैं और व्यापारी कब अपना प्रोफिट निकाल ले, कोई पता नहीं चलता। (व्यवधान) एक तरफ जो फ्रंट में फिगर दिखती है उसके मुताबिक तो हमारी एलोकेशन बढ़ी है। स्टेट को जो टोटल पैसा जाएगा, उसके मुताबिक बढ़ी है। लेकिन यह इण्डियन एक्सप्रैस में एक खबर छपी थी। इसके मुताबिक जो सेंट्रल असिस्टैंस मिलती थी।

25/03/2015/1705/MS/AG/2

उपाध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे बीच में अपनी कमेंट्री न करें। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री राजेश धर्माणीः अच्छे विधायक बन सकते हैं जिस तरीके से व्यवहार करेंगे। सेंट्रल असिस्टैंस टू स्टेट प्लान। (व्यवधान) ये सरकार के आंकड़े हैं, कोई मेरे आंकड़े नहीं हैं। जो केन्द्र सरकार असिस्टैंस देती थी स्टेट प्लान के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वर्ष 2014-15 में कांग्रेस सरकार के समय जो वहां के बजट एस्टीमेट्स थे, जो वोट ऑन अकाउंट पेश किया था, उसमें और वर्ष 2015- 16का जो अब का बजट पेश हुआ है, उसमें कितना अंतर है ,दखिए। एक तरफ बढ़ाकर दिखता है लेकिन दूसरी तरफ कम किया गया है। मु01,34,521/-करोड़ रूपये की स्पैशल असिस्टैंस ग्रांट जो थी, वह कम की गई। हिमाचल प्रदेश को भी जो बजट भाषण माननीय मुख्य मंत्री जी का है ,3000 करोड़ रूपये का सिर्फ वर्ष2015 - 16में इसमें नुकसान होगा। आने वाले पांच सालों में 15 हजार से 20 हजार करोड़ रूपये का नुकसान होगा। अब आप अंदाजा लगा लें कि 14वें वित्तायोग से हमें क्या मिला और मोदी साहब ने हमारा भला किया या बुरा ?(व्यवधान) सामने के हाथ से दे दिया लेकिन पीछे से ले लिया। उसी तरह से यहां बजट की बात करते हैं कि केन्द्र सरकार ने यह दे दिया, वह दे दिया। कुछेक बातें यहां मुख्य मत्री जी ने भी कही। कुछ मेरे से पूर्ववक्ताओं ने भी कही है। लेकिन जो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें थी, उनको बन्द कर दिया गया।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

25.03.2015/1710/जेके/जेटी/1

श्री राजेश धर्माणी (मुख्य संसदीय सचिव)-----:जारी------
जो सैन्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्ज थी, जो फंडिंग पैट्रन सैन्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्ज थी उसमें फंडिंग पैट्रन बन्द कर दिया। श्रीमती विद्या स्टोक्स जी ने सही कहा था कि आपका जो बजट है उद्योगपतियों को लाभ देने वाला है। गरीबों की जेब में डाका डालने वाला है। आपका बजट कहां पर कम हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में कम हुआ? आपका बजट कम कहां पर कम हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में कम हुआ? आपका बजट कहां पर कम हुआ, अनुसूचित जाति एव जनजाति को जो ग्रांट जाती थी उसमें कम हुआ ? रियायतें कहां पर दी गई? लगभग 6 लाख करोड़ रूपए की रियायतें कार्पोरेट हाऊसिज को दी गई। आने वाले 4-5 साल तक वह जारी रहेगी। 5 प्रतिशत रियायत 4 साल तक जारी रहेगी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और आप सब जानते हैं कि कांग्रेस के समय में अगर 2006- 07को बेस माने उसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का मूल्य घट कर आधे से कम हो गया था।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

लेकिन अगर आप डीज़ल और पैट्रोल के रेट देखेंगे तो वह कम नहीं हुए। उसका कारण क्या है, क्योंकि एक्साईज डियूटी बढ़ा दी गई? 70हजार करोड़ रूपए की एक्साईज डियूटी मोदी साहब के प्रधान मंत्री बनने के बाद अतिरिक्त लगाई गई। अब आप यह देखें कि अच्छे दिन किसके हैं और बूरे दिन किसके आए? अच्छे दिन सिर्फ उद्योगपतियों के आए हैं। आम आदमी के अच्छे दिन नहीं आए हैं। वैट में मामूली बढ़ौत्तरी हुई है। हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष का हिस्सा है। माननीय धूमल साहब बोलते थे जब हम वहां से बोलते थे कि यह भारत सरकार की योजना है। धूमल साहब बोलते थे कि अगर हिमाचल प्रदेश को कुछ सहायता मिली है तो यह हमारा अधिकार है। हिमाचल प्रदेश कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वही तर्क आज हम देते हैं। उस वक्त आप इस बात को करते थे आज हम इस बात को कर रहे हैं। सेन्ट्रल बजट का प्रभाव प्रदेश के ऊपर पड़ता है। केन्द्रीय बजट का प्रभाव हिमाचल

25.03.2015/1710/जेके/जेटी/1

प्रदेश के ऊपर पड़ता है। आप लोग जब 12 सदस्य रह जाएंगे तब भी आपको बोलने का मौका देंगे।

Speaker: Hon'ble Members are requested not to make any commentary.

श्री राजेश धर्माणी (मुख्य संसदीय सचिव): अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि केन्द्रीय योजनाएं हिमाचल को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए मैं यह बात यहां पर कह रहा हूं। मैं आप लोगों को थोड़े शॉर्ट में बताता हूं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में बजट एलोकेशन कम हुई क्या इसका हमें प्रभाव नहीं पड़ेगा? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम और रवि जी आप तो आई.पी.एच. मिनिस्टर भी रहे हैं, इसकी एलोकेशन 8,391 करोड़ रूपए कम हुई, इसका क्या हमें प्रभाव नहीं पड़ेगा ? बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, इसमें एलोकेशन कम हुई। उसी तरीके से नार्मल सेन्ट्रल एस्सिटैंस भी कम हुई। मैं इंडियन एक्सप्रैस को कोट कर रहा हूं। उसी तरीके से मैं यहां पर किसी का नाम नहीं लेता हूं, सर्व शिक्षा अभियान पर कम हुई है, स्टील में एलोकेशन कम हुई है। आपका इन्टेग्रेटिड आई.सी.डी.एस. जो कि बच्चो से संबंधित प्रोग्राम है उसमें एलोकेशन कम हुई है। हाऊसिंग फॉर ऑल उसमें कम हुई है। नेशनल हैल्थ मिशन में एलोकेशन कम हुई है। यह तो आपकी सरकार के आंकड़ें हैं। यह मेरे आंकड़ें नहीं है। इसका फर्क हिमाचल को पड़ेगा। एक और बड़ी करागरी की गई है जो करागरी की है उसमें सर्विस टैक्स बढ़ा दिया। अगर सर्विस टैक्स बढ़ाएंगे तो बाली जी के विभाग का भी टैक्स बढ़ेगा। जो बस टिकट है उसमें भी सर्विस टैक्स लगा है। पठानिया साहब का विभाग जो बिल देता है उसमें भी सर्विस टैक्स लगेगा। टेलिफोन/मोबाईल का बिल भी बढ़ेगा। आप हवाई यात्रा या रेल यात्रा करेंगे सबके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा।

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

25.03.2015/1715/SS-AG/1

श्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय सचिव क्रमागतः

इससे महंगाई ऑवरऑल बढ़ेगी। इस तरीके से सब की जेब से पैसा निकाला जा रहा है जो न मालूम हो और पैसा भी आपकी जेब से निकल जाए। --(व्यवधान)--यह तर्क

अच्छा है। यहां पर बहुत सारे अच्छे काम इसमें दर्शाये गए हैं। मैं उनका बहुत डिटेल में वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि वे मेरे बहुत सारे साथियों ने कवर कर दिए हैं। जितना इसमें लिखा गया है अगर मैं उसको प्वाइंटवाइज पढ़ूंगा तो उसमें ही समय निकल जायेगा। यहां पर अच्छे दिनों की दुहाई देते थे लेकिन अच्छे दिन आम जन के आये नहीं हैं। सिर्फ उद्योगपतियों के आए हैं या कुछ जो बड़े कारपोरेट हाउसिज़ हैं उनके आये हैं। --(व्यवधान)--ढाई सालों का तो यहां पर वर्णन दिया है। इसको आप पढ़ो और लैपटॉप में भी डालिये। यहां पर अभी बिक्रम जी बोल रहे थे कि पंजाब और हरियाणा की तुलना में हमारे यहां दिहाड़ी कम है। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन बी0जे0पी0 के टाइम क्या थी? बी0जे0पी0 के टाइम में हमारे यहां दिहाड़ी 138 रुपये थी और पंजाब में 184 रुपये थी तथा हरियाणा में 200 रुपये थी। यह तुलना है उस समय थी और अब भी व्याप्त है। --(व्यवधान)--मैं भी चाहता हूं कि यह बढ़े लेकिन इंक्रीमैंटल इंक्रीज ज्यादा अच्छी रहती है। इसकी वजह से जितने भी कंट्रैक्ट एग्रीमैंट हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। --(व्यवधान)--ज्यादा नहीं है। हम भी चाहते थे कि बढ़े। दूसरी बात जो मैंने कही, शायद आपने नहीं सुनी। कंट्रैक्ट एग्रीमैंट पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए दिक्कत हुई है।

यहां पर केन्द्र सरकार ने माइक्रो इरिगेशन की स्कीम शुरू की थी। उसकी घोषणा की है लेकिन साथ में कट कहां लगाया? आपके ए0आई0बी0पी0 पर कट लगा दिया। जो आपके पास महकमा होता था उसमें ए0आई0बी0पी0 की इरिगेशन की स्कीमें बनती थीं उसके ऊपर कट लगा दिया। वाटरशैड योजनाओं पर कट लगा दिया। वाटरशैड की जो एलोकेशन थी उस पर कट लगा के उसकी शुरूआत की है। इस तरीके की कारीगिरी करने की कोशिश करते हैं।

यहां पर रवि जी एक बात कह रहे थे कि constituency-wise पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन जब आपकी सरकार थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय ये महसूस किया गया कि अगर इस तरीके से किसी की डिस्क्रिशन पर फंड रखेंगे तो उसका अच्छा परिणाम नहीं निकलता है। उसकी बजाय अगर हम उसको पापुलेशन के साथ, बैकवर्डनैस के साथ या जियोग्राफिकल कंडीशन के साथ जोड़ेंगे

25.03.2015/1715/SS-AG/2

तो उसके बेहतर परिणाम निकलेंगे। इसी वजह से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को जोड़ा गया और पापुलेशन का क्राइटेरिया रखा गया। इसमें एम0एल0ए0/एम0पी0 का रोल नहीं है। सिर्फ मोनिटरिंग इवैल्यूऐशन का रोल है। इसलिए आपकी पैकेज वाली बात सही नहीं है। दूसरा, जैसे मनरेगा है, अगर मनरेगा में भी पैकेज देते हैं तो उसका भी दुरूपयोग होता। इसलिए उसको पंचायतों के थ्रू और डिमांड बेस रखा है। हालांकि इसमें भी आपकी एलोकेशन कम हुई है। हमारे यहां पर 2013-14 में गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने जो लेबर बजट एप्रूव किया था ,वह 671.69 करोड़ रुपये था। उसको बाद में 551.48 करोड़ रिवाइज किया गया और एक्चुअल 477.97 करोड़ हुआ। उसी तरीके से 2014-15 में देखें तो गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने लेबर बजट 761.71 करोड़ एप्रूव किया और इसमें सैंट्रल शेयर 670.71 करोड़ बनना था। लेकिन कितना कम किया? 355.43 करोड़ कम किया। 355. 43 करोड़ पर पहुंचा दिया। आप बोलेंगे कि पंचायतों के काम नहीं हो रहे, फिर कैसे काम होंगे? --(व्यवधान)-- इसमें कम रिडक्शन हुई। मैंने इसीलिए बोला। कम्पैरीटिवली बहुत कम रिडक्शन हुई थी लेकिन आपके टाइम बहुत ज्यादा रिडक्शन हो गई।

जारी श्रीमती के0एस0

25.03.2015/1720/केएस/जेटी/1

मुख्य संसदीय सचिव, श्री राजेश धर्माणी जारी---

अध्यक्षः धर्माणी जी, वाइंड-अप करने की कोशिश करिए।

श्री राजेश धर्माणीः अध्यक्ष महोदय, यहां पर रवि जी ने कहा कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से आर्थिक स्थिति बेहतर होना शुरू हो गई है लेकिन आप उसमें और भी डिटेल में पढ़ो। हमारे देश में 70-80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। कृषि हमारा मुख्य व्यवसाय है और पूरे देश के अंदर जब से आपकी सरकार बनी है, एग्रीकल्चर ग्रोथ कम हुई है। यह ग्रोथ डेढ़ प्रतिशत से भी कम हो गई है। आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो गई है, एक्सपोर्ट ग्रोथ कम हो गई है । ये तीन इंडिकेटर है

जिससे पता चलता है कि इनकी ग्रोथ कम हुई है और ये मेरे पास भारत सरकार के डॉक्युमैंट्स हैं। 2014-15 में इन तीनों की ग्रोथ कम हुई है।

अध्यक्ष महोदय, ये मेक इन इंडिया की बात करते हैं हालांकि अच्छी बात है, मैं उसका विरोध नहीं करता लेकिन सही मायने में मेक इन इंडिया प्रोग्राम तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था । आनन्द शर्मा जी इंडस्ट्री एण्ड कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने मैनुफैक्चरिंग पॉलिसी लाई थी, उसी का नाम बदलकर मेक इन इंडिया रख दिया। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात उन्होंने की थी। कांग्रेस सरकार के समय में जब राजीव गांधी जी ने हिन्दुस्तान के अंदर कम्प्यूटर क्रान्ति की बात की थी तो उस समय आपकी पार्टी कम्प्यूटराइजेशन का विरोध करती थी । पहली मई, 1985 को भारत बन्द रखा था भारतीय मज़दूर संघ ने जो आपका मज़दूर संगठन है उसने बंद रखा था कि इससे बेरोज़गारी फैल जाएगी और आपके शीर्षक नेता भी यही कहते थे। आज की तारीख में लगभग चार

25.03.2015/1720/केएस/जेटी/2

लाख करोड़ से ज्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हमारा देश करता है जिसकी वजह से हमारी इकोनोमी चल रही है तो हमें इस बात का फख़्र है कि हमारी पॉलिसीज़ अच्छी साबित हुई है बजाय इसके कि जो आपके समय में आपकी पॉलीसी बन रही है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे इन दो सालों के अंदर अकेले पशु-पालन विभाग में, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने बोलना था लेकिन समय की कमी की वजह से इन्होने अपना नाम वापिस ले लिया। अकेले पशु-पालन विभाग के अंदर 72 वैटरिनरी डॉक्टर इन दो सालों के अंदर भर्ती हुए हैं और 90 फार्मासिस्ट भर्ती हुए और आपके समय में एक भी वैटरिनरी फार्मासिस्ट की भर्ती नहीं की गई थी।)---व्यवधान)---
श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह इतिहास है कि हिमाचल प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों में, पंचायतों में, हर जगह वैटरिनरी हॉस्पिटल खोलने का निर्णय आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने लिया था इसलिए आप अपने आंकड़े दुरुस्त कर लें।

श्री राजेश धर्माणीः पहले आप मेरी बात सुन लो, वैटरिनरी फार्मासिस्ट कोई भर्ती नहीं हुआ था।)--- व्यवधान)---

अध्यक्षः रवि जी, माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैा 1251 जो हर पंचायत में लगे वे मुख्य मंत्री आरोग्य धन पशु योजना के माध्यम से लगे थे। जो वैटरिनरी फार्मासिस्ट की बात

25.03.2015/1720/केएस/जेटी/3

धर्माणी जी कर रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि डिपार्टमैंट के अंदर कितने लगे और जो 1251 की आप बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस विभाग की सबसे बुरी हालत हुई कि बन्दर के हाथों उस्तरा दे दिया गया और एक साल की ट्रेनिंग के बाद उनको प्रैक्टिल ट्रेनिंग तक नहीं आई।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

25.3.2015/1725/jt/av/1 Semen

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी------

एक साल की ट्रेनिंग के बाद उनको प्रैक्टिकल ट्रैनिंग तक नहीं आई। मैं आज सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि (---व्यवधान---) रवि जी, आप बात सुनिए। आज आपने यह जरूर कह दिया कि हमने पंचायतों में 1251 वैटैरनरी फार्मासिस्ट लगा दिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज पंचायतों के अंदर फार्मासिस्टों को आप 5 हजार रुपये दे रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग पर दो लाख रुपये लगाये। दो लाख रुपये की ट्रेनिंग के बाद आज मात्र उनको 5 हजार रुपये मिल रहे हैं। वैटैरनरी डिपार्टमैंट में बाहर से इम्पोर्टिड सीमन लाया गया। मैंने मंत्री होने के नाते विभाग को कहा कि आप इम्पोर्टिड सीमन लगाइए। मगर जब वह आये तो बाद में कोई और ही वैरायटी निकली। वह इम्पोर्टिड सीमन आपके समय में आया था। हम ठीक बात कर रहे हैं, हम कोई नुक्ताचीनी की बात नहीं कर रहे हैं। आप सच्चाई को देखिए। मैंने विभाग से इस बारे में ठीक तरीके से बात करने का प्रयास किया है। हम इम्पोर्टिड सीमन उत्तराखंड से लाये। मैंने उत्तराखंड में सीमन के बारे में पूछा भी। हम चाहते हैं कि

हमारे पशु की नस्ल सुधरे। मगर नस्ल कहां से सुधरेगी? हम अपने यहां पर जर्सी सीमन पैदा कर सकते हैं। हमें प्रदेश के अंदर इस तरह की योजना चलानी चाहिए। आप मुख्य मंत्री आरोग्य पशु धन योजना की बात कर रहे हैं। वहां ए.आई. की सुविधा नहीं है। हमारे यहां मुख्य मंत्री आरोग्य पशु धन योजना के तहत केवल 328 डिस्पैंसरियों में ए.आई. की सुविधा है बाकियों में नहीं है। उस वक्त 28 रुपये प्रति किलोग्राम मिनरल मिक्चर आया करता था जबकि 70 रुपये प्रति किलो मिनरल मिक्चर मिलना चाहिए था। 28रुपये का मिनरल मिक्चर लेकर उस वक्त किसानों को बांटा गया। उससे पशु का दूध बढ़ने की जगह कम हुआ है। अब हमने इस पॉलिसी में परिवर्तन करने का प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि हमारे बेजुबान जानवरों को दवाई ठीक मिले, मिनरल मिक्चर ठीक मिले जिससे हमारे प्रदेश के अंदर दूध की गुणवत्ता बढ़े। हमने इसके लिए प्रयास किया है, धन्यवाद।

समाप्त

25.3.2015/1725/jt/av/2

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने खुद बोलना था, प्रोक्सी से स्पीच करवा रहे थे। जब प्रोक्सी पकड़ी गई तो खुद प्रैजैंट हो गए। इन्होंने काफी डिटेल्ज दी है। प्रदेश की हर पंचायत में पशु चिकित्सा का प्रावधान हो; यह निर्णय हमारी सरकार ने लिया था। आपने 92 फार्मासिस्ट लगाये और कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। जहां उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी वहां आपने उन पर केस बना दिए। आप कह रह हैं कि उनको 5000 रुपये वेतन के रूप में दे रहे हैं। इस बार तीसरा बजट तो आपका आ गया। आपने कितने बढ़ाये? 5हजार रुपये देना तो हमारी सरकार ने शुरु किया था। आप उनके इतने ही हितैषी है तो आपने अपने तीसरे बजट में कितने पैसे बढ़ाये? एक बजट आया, दूसरा बजट आया, तीसरा बजट आया। आर्टिफिशियल सेमिनेशन का मुख्य कारण यह है कि इम्पोर्टिड गाय आर्टिफिशियल सेमिनेशन के कारण ही ज्यादा बार बच्चा नहीं देती। फिर उसके बाद वह आवारा पशु बनकर घूमती है। हमने यह कोशिश की थी कि ट्रेडिशनल मैथड़ से बच्चे पैदा हो। आपने जो अभी डिटेल दी है उसकी सूचना मैं आर.टी.आई. से लेकर देखूंगा कि जो आप इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं इसमें चक्कर क्या है। होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको हम ऐम्बुलैंस द्वारा अस्पताल ले जा सकते हैं मगर पशु को ले जाने में दिक्कत होती है। पशु को कहां ले जायेंगे इसलिए हमने सोचा कि हर पंचायत में सुविधा हो। हमने सैंकड़ों लगा दिए और आपने अब 92 लगाये। जो व्यक्ति ट्रेनिंग दे रहा था वह गवर्नमैंट द्वारा अप्रूव्ड था जहां से ट्रेनिंग

लेकर आए। मगर आपने उसके खिलाफ केस बना दिए। आज आपको हमदर्दी हो गई कि उनको 5 हजार रुपये ही दे रहे हैं। तीसरा बजट तो आपकी सरकार का आ गया, आपने बढ़ा देने थे। कहने का भाव यह है कि पिछले साल के बजट में मैंने बात की थी मगर आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आपने कहा था कि मिल्क चीलिंग प्लांट लगायेंगे, आपने कितने लगाये? आपने कहा कि फोडर प्लांट लगायेंगे, आपने उसके बाद कितने लगाये? ----

श्री नेगी द्वारा जारी

25.03.2015/1730/negi/jt/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी.. जारी..
कितने लगाए आपने उसके बाद? जो-जो आपने वायदे किए थे। इसलिए आलोचना करना आसान है । पशु चिकित्सा के लिए हमने जो कम्पाउंडर लगाए थे उनको हमने ट्रेनिंग दी है। हमने उनको एक साल की ट्रेनिंग दी थी अगर कमी रह गई थी तो आपने उनको 6 महीने का और रिफ्रैशर कोर्स करवा देना था। आपका पी.टी.ए. ठीक है, आपका एस.एम.सी. ठीक है और आपका पैरा टीचर ठीक है। आपने जो स्कीम चलाये हैं वे सारे ठीक हैं। हमने उनको भी ट्रेनिंग देने की कोशिश की और ट्रेनिंग दी है। छुट्टियों में उनकी ट्रेनिंग होती थी । आप उसपर इम्प्रूव अपोन करते। आज उनको बोल दिया बन्दर के हाथ में उसतरा। ये शब्द मंत्री के मुंह से शोभा नहीं देते। कल को कोई आपके बारे में क्या कहेगा। आज जिला परिषद वाले आए थे आपके बारे में कहने के लिए। आपने क्या कहा। आप पी.आर.आई. का ही मतलब अभी तक नहीं समझ रहे हैं। पी.आर.आई. में आप केवल पंचायत को गिन रहे हैं। कॉन्स्टिट्युशन के आर्टिकल 243(b) में पी.आर.आई. का, तीनों का क्लीयर डेफिनेशन दी हुई है। ग्राम पंचायत इन्टरमिडिएट दैट इज बी.डी.सी. एण्ड जिला परिषद। आप कल यहां एक बात इस मान्य सदन को बताते रहे कि 14वें वित्तायोग ने कहा कि सिर्फ ग्राम पंचायत को दो। आपका ब्यान छपा है कल के आधार पर। अध्यक्ष महोदय वह इस सदन की कार्यवाही का पार्ट बन करके छपा है। उसमें लिखा है कि भ्रष्टाचार किया जिला परिषद वालों ने। जिला परिषद वाला वैसे ही सैंक्शन करता है जैसे एम.एल.ए. सैंक्शन करता है कि इस स्कीम के लिए इतना पैसा दिया जाए। जैसे मंत्री सैंक्शन करता है । मंत्री सैंक्शन कर देता है और उसके बाद एग्ज़ीक्यूट कौन करता है? That is Gram Panchayat, intermediate i.e. BDC and Zila Parishad. आप

मंत्री हो, आप पूरे प्रदेश में एक जिला परिषद मेम्बर बताओ या चेयरमेन बताओ जिसके खिलाफ आपने भ्रष्टाचार का केस बनाया हो। पंचायतों के प्रधान तो आपने सस्पेंड किए हैं, टर्मिनेट किए हैं। इस तरह की स्टेटमैन्ट देने से पहले मंत्री को अपना दायित्व समझ करके स्टेटमैन्ट देनी चाहिए मेरा यही निवेदन है।

25.03.2015/1730/negi/jt/2

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी कृपया आप संक्षेप में बोलें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय धूमल जी , मैं समझता हूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो दूसरा करता है तो ठीक है और जब खुद होता है तो उस पर गुस्सा आ जाता है। योजना अच्छी हो सकती है। हम यह नहीं कहते कि योजना बुरी है। सोच अच्छी हो सकती है । परन्तु उस सोच के साथ क्या हुआ उसका मैं जवाब दे रहा था। अब आप डिमाण्ड नम्बर-20 में देखिए जो आपके पास बजट बुक में है। डिमाण्ड नम्बर-20 में लिखा है कि 14वें वित्त आयोग से जो पैसा आया है, आप देख लीजिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप इसमें देख लीलिए। पंचायती राज इंस्टीट्युशन्ज़ की आपने डेफिनेशन ठीक दी है। परन्तु 13वें वित्त आयोग का अन्तिम साल था और 14वें वित्त आयोग के लोग जब यहां आए थे तो उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया कि जो हमारे जिला परिषद मेम्बर हैं, उन्होंने महिला मण्डल को एक लाख रूपये, युवक मण्डल को एक लाख रूपये ऐसे-ऐसे कामों के लिए देना शुरू किया जिसकी वजह से वह पैसा अन-युटिलाइज्ड़ पड़ा रहा। हालांकि आपने जिला परिषद की बात की, मैं इस मान्य सदन के अन्दर कहना चाहता हूं कि यहां पर आपने कहा गया कि यह तो 20-20 का क्रिकेट मैच है, अग्निहोत्री जी ने टेस्ट मैच की बात की। मैं समझता हूं कि आप इस तरीके से इस बात को रखना चाहते हैं। मैंने कभी राजनीति नही की है। आप भी जानते हैं। मैं राजनीति नहीं करना चाहता। जो वहां का जिला परिषद का सदस्य है वह पंचायत का प्रधान रहा है। मैं इस मान्य सदन के सामने केवल एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूं। धूमल जी, मैं वहां का विधायक हूं और भ्रष्टाचार को रोकने की बात भी कर सकता हूं । क्योंकि आपने कहा भारतीय जनता पार्टी का, वह केवल टेलरिंग का काम करता था, वह टेलर मास्टर था। वह 5 साल प्रधान रहा और 5 साल के बाद उसके पास 2 ट्रक, 2 टिप्पर, बस है। अगर इस तरीके से पंचायतों के प्रधानों के बारे में राजनीतिक मंच की बात करेंगे, तो

ठीक नही है। आपने कहा कि पंचायत प्रधानों को आपने सस्पैंड किया। उसमें मेरा चुनाव क्षेत्र का प्रधान भी है। सैरी पंचायत का प्रधान है जो कांग्रेस माइंडिड प्रधान है। अगर कोई वित्तीय अनियमितताएं पाई गई तो हमने उसको भी नहीं बक्शा है।

25.03.2015/1730/negi/jt/3

इसलिए यह बात कह देना कि हम राजनीतिक तौर पर प्रधानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ठीक नहीं है। धूमल जी जो आपने बात रखी है, हम उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। जहां 100 आदमी ट्रेनिंग कर सकते हैं वहां आपने ट्रेनिंग करने के लिए 700 आदमी भेज दिए। 700 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज भी हम वहां पर 100 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। लेकिन आपने 700 आदमियों की ट्रेनिंग करा दी। और 700 आदमियों को आपने गांव-गांव में भेज दिया और कहा कि आप जानवरों के इलाज़ कीजिए। हम कह रहे हैं कि सोच आपकी ठीक हो सकती है। मैं भाषण नहीं देना चाहता था क्योंकि समय कम था, सीधी बात है..

श्रीमती यू.के. द्वारा जारी...

25.03.2015/1735/यूके/1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज--जारी---
सीधी बात करता हूं । आपने पॉली हाऊस की स्कीम शुरु की थी । मैं अभी भी कहता हूं कि हमारे उन क्षेत्रों में पॉली हाऊसिज़ लगा दिए गए जहां बर्फ पड़ती थी, जय राम जी के क्षेत्र में भी लगे । एक बर्फ के बाद वे पॉली हाऊसिज़ खत्म हो गए । हमने यह देखना है कि प्रदेश के अन्दर जो स्कीमें बन रही हैं, वह स्कीमें किस जगह पर होनी चाहिएं और किस तरीके से स्कीमें लागू करनी चाहिए । इस पर आपने कहा, धूमल जी मैने इस बात को नहीं कहना था, लेकिन आपने कहा और रविन्द्र रवि जी ने भी इस बात को रखा कि धूमल जी ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया था, जिस मास्टर प्लान के अन्तर्गत आप इस प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से ऊपर उठाना चाहते थे । हम भी चाहते हैं कि प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हो । मैं आपको एक छोटा सा ऐग्ज़ाम्पल देना चाहता हूं । मिल्क फैडरेशन की मैने बात की है, माननीय धूमल जी आप भी आंकड़े मंगवा सकते हैं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं । 2008-09 मे आपकी सरकार थी मिल्क फैडरेशन 90 लाख रूपए घाटे में । 2009-10 में आपकी सरकार

थी, 1.02 करोड़ रुपए घाटे में । 2010-11 मे 70 लाख रुपए घाटे में ,2011-12 में 698 लाख रुपए घाटे में, 2012-13 में 402 लाख रूपए घाटे में और 2013-14 में, हमारी सरकार बनने के बाद, मैने कहा था कि मैने इसको सुधारने का प्रयास किया है , मैं बताना चाहता हूं कि 703 लाख रुपए प्रॉफिट में, 2014-15 में 8 करोड़ रूपए प्रॉफिट में । आपने 5 सालों के अन्दर मिल्क फैडरेशन 13.50 करोड़ रुपए घाटे में रही । हमने दो सालों के अन्दर 15 करोड़ रुपए इस मिल्क फैडरेशन को प्रॉफिट में लाया है । आप आंकड़े मंगवा लीजिए,

25.03.2015/1735/यूके/2

यदि मै गलत हूं तो । मैने आपके साथ भी काम किया है, पार्टी के साथ रहे हैं । मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमने आपकी 5 सरकार चलाई, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है । परन्तु जहां प्रदेश की बात आती है, यदि मेरे आंकड़ों में गलती है तो उन आंकड़ों को आप मंगवाइए । मिल्क फैडरेशन हम चाहते थे कि और आगे बढे । आपने कूलिंग यूनिट के बारे में कहा । हम कूलिंग यूनिट भी लगा रहे हैं । धूमल जी, हमारा जो मिल्क प्लांट, चक्कर है, मैने उसमें देखा कि 40-50 आदमी मैनुअली काम करते हैं तो क्यों नह हम उसको ऐटोमैटिक तरीके से करने का प्रयास करें? मैं हाऊस के अन्दर यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि 9 करोड़ रुपया उसके लिए हमने केन्द्र से आर्थिक मदद के रूप में देने को कहा है, उसके मॉर्डनाईजेशन के लिए हम ला रहे हैं । हम चाहते हैं कि मिल्क फैडरेशन में किस तरह से मैनुअल पॉवर कम हो और किस तरीके से उसको प्रॉफिट में ला सकते हैं । यह हमारा प्रयास है और मैं सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर हम प्रदेश के लिए काम करें । यदि हमसे कोई गलती हो रही है, तो विपक्ष का काम है, आपका काम है यदि सरकार गलत काम करती है तो उसको बताइए । हम उसको सुनने के लिए तैयार है । परन्तु यदि आपसे भी कोई गलती हुई है तो आप भी सनिए, हो सकता है आपसे भी कोई गलती हुई हो । उसमें कोई बड़ी बात नहीं है । ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बहुत बड़े ऐक्सपर्ट थे, आपके पास भी अधिकारी थी । मैं यह कहना चाहता हूं कि हम 14वें वित्तायोग की बात करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा इम्पार्टैंट हमारे अधिकारी थे, चीफ सेक्रेटरी

25.03.2015/1735/यूके/3

और सेक्रेटरी फाईनेंस को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने आंकड़े इस वित्तायोग के सामने रखे । इसके लिए यह ठीक है कि हम प्राईम मिनिस्टर को भी आभार प्रकट कर देंगे । परन्तु सबसे बड़ा काम यह है कि जिस तरीके से प्रोजैक्शन उन्होंने की है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए ।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

25.03.2015/1735/यूके/4

श्री प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से जवाब दिया है । लेकिन जो बात मैने कही थी, पहली बात तो यह कि "बन्दर के हाथ में उस्तरा" उस टिप्पणी पर आप चुप रहे । आपने दूसरी बात कह दी कि एक आदमी सिर्फ कपड़े ही सीता था, उसके पास ट्रक और टिप्पर हो गए । जिन्दगी में बहुत लोगों ने राईज़ किया है । आप अपने आप पर भी नज़र डालो । कहां से शुरू हुए, कहां पहुंचे । तीसरी बात आपने कही, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि हमारे समय में मिल्क फैडरेशन घाटे में थी । हमारे समय में लगातार मिल्क फैडरेशन घाटे में रही होगी लेकिन मिल्क प्रोड्यूसर मुनाफे में रहा । हर बार हमने उसको पैसा दिया है । हमारा उद्देश्य क्या था? वह अन्तर है । आपकी सोच भी बड़ी वैज्ञानिक है और बिज़नैस्समैन की है । जिस फैडरेशन के आप कर्ता-धर्ता हैं, वह फायदे मे आए । हमारी सोच यह थी कि जो गांव में पशु पालता है, जिसके कारण आप यूरिया वाला दूध पीने से बचते रहे ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

25.03.2015/1740/sls-jt-1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल...जारी
जो गोबर और गोमूत्र उठाकर गंदगी सहते हैं लेकिन आपको दूध पहुंचाते हैं, वह संपन्न हो। इसलिए हमने हर साल मिल्क का प्रोक्योरमैंट प्राईस बढ़ाया है। घाटा उस कारण से था क्योंकि लगातार राहत दी जाती रही। नई इनवैस्टमैंट्स होती रहीं। मैं

अभी जाहू के पास गया था। मैंने देखा कि हमने जो मिल्क फौडर प्लांट लगाया था, वह आज काम कर रहा है। रामपुर से आपका मिल्क फैडरेशन का दूध पहले पंजाब में जाता था। वहां से पाउडर बनकर आता था। पहले क्लैक्शन होती थी, फिर वह पंजाब के लिए ट्रांसपोर्ट होता था ,उसका पाउडर बनता था और फिर वह वापिस आता था। हमने रामपुर में ही 12.00 करोड़ रुपये का मिल्क चिलिंग प्लांट लगाया, क्योंकि आनी, कुमारसेन और रामपुर एरिया में दूध ज्यादा पैदा होता था। हमने राजनीतिक आधार पर नहीं बल्कि जहां आवश्यकता था, वहां किया। आप चक्कर वाले प्लांट को भी इंप्रूव करिए, लेकिन जो 30-40 लोगों को रोजगार मिला है कहीं अपनी इंप्रूवमैंट में उनको बेरोज़गार न कर देना और दूध की कीमत भी बढ़ाते रहना। प्रॉफिट में भी लाइए, यह अच्छी बात होगी। फैडरेशन प्रॉफिट में आनी चाहिए, तभी ठीक रहेगा। लेकिन at the same time जिसके कारण वह चलती है, कहीं यह न हो कि पशुपालक दूध पैदा करना कम कर दे और आप अपना प्रॉफिट देखते रहें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, ब्रीफली अपनी बात रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष जी, जो बात मैंने रखी है, जिसकी धूमल जी बात कर रहे हैं, अगर वह अनपार्लियामैंटरी है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। दूसरे, जो मैंने प्रधान का कहा, वह केवल सिलाई या कारपैंटरी का काम करता था। वह कपड़े सिलने वाला काम करता था। ...(व्यवधान)... धूमल जी, आप सुन लीजिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वह पंचायत प्रधान था, इसलिए नहीं कहना चाहता कि वह किस पार्टी से संबंधित है। किसी भी पार्टी से संबंध हो सकता है। परंतु एक पंचायत का प्रधान 5 सालों के अंदर भ्रष्टाचार करके कहां से कहां पहुंचता है? उसके पास और कोई काम नहीं था। ...(व्यवधान)...धूमल जी आप जो

25.03.2015/1740/sls-jt-2

यह बात कह रहे हैं, ठीक है...(व्यवधान)... अब वह सब बिक गया है। अब जब वह प्रधान पद से बाहर है तो सब बिक गया है। दूसरी बात और है, जो आपने बात रखी है। ...(व्यवधान)... कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर वह सदन के सामने रखी जाएं, तो ठीक रहेगा। तभी मैं कह रहा हूं। आपने कहा कि मिल्क प्रोड्यूसर की हम बात रखना चाहते हैं। आपने उनकी बात रखी है। आपने 2007-08 में ...(व्यवधान)...धूमल जी ने

कहा और मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। ...(व्यवधान)...मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं, आप क्यों नहीं सुनना चाहते। जब आपने कहा तो क्या मैं स्पष्टीकरण नहीं दूंगा? ...(व्यवधान)... मैं एंडलैस स्पीच नहीं कर रहा हूं। धूमल जी ने प्रश्न उठाया। आपने कहा कि प्रोड्यूसर की बात नहीं करना चाहते। मैं प्रोड्यूसर की बात कहना चाहता हूं। वर्ष 2007-08 में आपके समय में 10.80 रुपये प्रोड्यूसर को दिए जाते थे। और जैसे-जैसे आप बढ़ाते रहे, ...(व्यवधान)... सर, मैं यह बता रहा हूं कि कब से कब तक था। आप बढ़ा रहे थे तो धीरे-धीरे जो बढ़ता गया ,आज हम 20.80 रुपये का रेट प्रोड्यूसर को दे रहे हैं। क्या सबसे बड़ी बात हुई? इसमें आपने देखा कि जो कमी आई है, वर्ष 2008-09 में आपने मिल्क फैडरेशन को 9.41 करोड़ रुपया दिया। कमी कहां है? आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट के अंदर मिल्क फैडरेशन के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। ...(व्यवधान)...रविन्द्र रवि जी. .आप बैठिए। मैं आपसे ज्यादा अकाऊंट जानता हूं। ...(व्यवधान)... आप जो यह आंकड़े दे रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आपने जो ग्रांट-इन-एड मिल्क फैडरेशन को दी है वह 2010-11 में 10 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2011- 12में भी 10 करोड़ रुपये थी। आप दूध का रेट तो बढ़ाते रहे। आपने दूध का रेट बढ़ाया कि प्रोड्यूसर को जाए, लेकिन मिल्क फैडरेशन को आपने वही रेट रखा। आपने 2012-13 में 11 करोड़ रुपये दिए। जब हमारी सरकार आई तो हमने इसको 13.50 करोड़ रुपये किया। ...(व्यवधान)... हम रेट भी बढ़ाते रहे। हमने रेट कम नहीं किया। ...(व्यवधान)...आपका 17. 80पैसे रेट था जबकि आज 20.80 पैसे रेट है। ...(व्यवधान)...

जारी..श्री गर्ग जी

25/03/2015/1745/RG/AG/1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री-----क्रमागत

आप सदन को मिसगाइड न करें। मैं आज कह सकता हूं कि मिल्क फैडरेशन एक साल में आठ करोड़ रुपये प्रॉफिट में है और हम इसको और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धूमल जी, यदि राजनैतिक तौर पर ही बात करनी है ,राजनीति की बात नहीं है, मैं तो सदन में वैसे ही बहुत कम बोलता हूं। सदन में बोलने वाले बहुत से लोग होते हैं। हमने आपकी (प्रो. प्रेम कुमार धूमल) सरकार बनाई ,हमने पांच साल आपकी सरकार चलाने का वायदा किया। वह एक गठबंधन की सरकार थी, आपकी सरकार कैसे बनी, यह आप भी जानते हैं। हमने पांच सालों तक आपका समर्थन किया। एक

मिनट आप सुनिए, ---(व्यवधान)---आप तो पहली बार विधायक बने हैं। आप इस बात को सुनिए।--(व्यवधान)---

अध्यक्ष : प्लीज़, सुनिए। आप ठहरिए एक मिनट, Don't disturb?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : आप टिवैन्टी-टिवैन्टी की बात करना चाहते हैं ,हम पांच साल के टैस्ट मैच की बात करना चाहते हैं। पांच साल टैस्ट मैच का मतलब, मैं पांच साल यहां विपक्ष में था।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : आपको 6 साल के लिए राज्य सभा में भेजा था और आपकी पार्टी के सभी लोगों को हमने मंत्री बनाया था। आप इस सदन को कन्फयूज न करें।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : एक बात है कि हमने पांच साल आपकी सरकार का समर्थन किया। धूमल साहब, पांच साल तक आपकी सरकार रही। आप बैठ जाइए और सुनने की क्षमता रखिए। मैं आपको कह रहा हूं----(व्यवधान)----

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : आप इस कहानी को ज्यादा न छेड़ें। पण्डित जी ने कुछ बातों के लिए मना किया था इसलिए वे बातें मैं आज भी नहीं बताऊंगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना बता रहा हूं कि पांच साल हम विपक्ष में थे और आप रूलिंग पार्टी में थे। मुझे इस बात का बुरा लगा कि इन पांच सालों के अंदर मुझे शायद एक प्राइमरी स्कूल ही मिल जाएगा। मुझे पांच सालों तक एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं मिला। आपने कहा कि यह टिवैन्टी-टिवैन्टी का मैच है। धूमल जी, हमें पांच सालों में एक चीज भी नहीं मिली।---(व्यवधान)--हम उस समय के विपक्ष के विधायक होते हुए यह बात करना चाहते हैं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष :आप बैठ जाइए, मेरी बात सुनिए---(व्यवधान)----Please, sit down. आप बैठ जाइए। (विपक्ष के कुछ सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ बोलना चाह रहे थे।) आप लोग बैठ जाइए। एक मिनट बैठ जाइए और मेरी बात सुनिए। Why you don't want to listen to the Chair? रविन्द्र सिंह जी, क्या बात है, आप बैठ जाइए। आप मेरी बात सुनिए। एक मिनट ठहरिए। मेरी बात सुनिए, kindly sit down. मैं आपसे आग्रह करुंगा , पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर जो मर्जी करना। कृपया आप बैठ जाएं। Not to be recorded. This is wrong. आप बैठिए ,क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? You Listen to me. Please, sit down. मैं आप सभी से आग्रह करुंगा कि यह चर्चा है और सभी को समय दिया जा रहा है। यदि आपको कोई ठीक नहीं लगता---(व्यवधान)---, If you want to speak, then I will take action. This is a wrong thing. आप सबको मौका दिया जा रहा है। यदि आपको लगता है कि कोई सदस्य गलत बोल रहा है, तो अपने भाषण में उसको ठीक कीजिए। Don't generate discussion on every step, word and sentence? यदि आप हरेक प्वाइंट पर चर्चा करेंगे, तो काम कैसे खत्म होगा, चर्चा कैसे खत्म होगी? किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। जब ये बोल रहे हैं, तो आप मत बोलिए और आप बोल रहे हैं, तो ये नहीं बोलेंगे। आप अपने भाषण में उसको रैक्टीफाई कीजिए। Don't speak in between? देखिए, मैंने धूमल साहब को पूरा समय दिया है। मंत्री विभाग के मुखिया हैं ,तो वह बोल सकते हैं और धूमल साहब आपके लीडर हैं वे बोल सकते हैं, but if everybody want to generate discussion on every point then there will be no end. इनके बोलने के बाद आप बोलिए।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस समय तक तो ये अपनी बात कह देते। इस बात को सवा घण्टा हो गया है। मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया है, तो यह भी दे रहे हैं।
अध्यक्ष : मैं यही बात तो कह रहा हूं। इस बात को सवा घण्टा हो गया है-----(व्यवधान)---मंत्र जी ने जो बात उठाई है, धूमल साहब ने उसका जवाब दिया है-----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

25/03/2015/1750/MS/AG/1

अध्यक्ष जारी--------

If you want to generate discussion on every point, मैं नहीं बोलने दूंगा। जब आपकी बारी आएगी, तब बोल लेना। (व्यवधान) आपके दूसरे लोग बहुत हैं बोलने वाले। वे बोल लें। (व्यवधान) आपके दूसरे बहुत लोग हैं बोलने को, वे बोल लें, उसमें क्या है? ऐसा है कि there are about 15 Members who want to speak on the Budget. उनको कह दीजिए कि वे इस प्वाइंट को टेकअप कर लें।। will not allow. गलत बात है।

श्री जयराम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं बोल रहा हूं।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, हमने यह निर्णय लिया है कि जिन माननीय सदस्यों को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में ऑपरचुनिटी नहीं मिली थी, उनको समय दिया जाए।

अध्यक्षः मैं कह रहा हूं कि इस चर्चा में we have been fighting for the last 20 minutes. उसको ऑपरचुनिटी कहां मिलेगी ,जब आप बोलते रहेंगे ?(व्यवधान) जब आप बोलना बन्द करेंगे तब उनको ऑपरचुनिटी मिलेगी।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष जी, अभी तक तो मेरी बात समाप्त हो जाती।

अध्यक्षः बात खत्म नहीं हो रही है। मैं देख रहा हूं कि इसी प्वांइट पर बात करते हुए 20 मिनट का समय हो गया है। मेरा यह निवेदन है कि आप हर प्वांइट पर डिस्कशन जनरेट न करे। (व्यवधान)

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः इतनी देर में तो मंत्री जी ने जवाब दे देना था और इन्होंने सवाल पूछ लेना था। यह सिर्फ क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे।

अध्यक्षः यह सवाल थोड़ा न पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि (व्यवधान)

पीछे आपके देखिए कितने खड़े हैं। एक आप ही बोलें। (व्यवधान) पूछ लीजिए। Don't let everybody stand? मैं यह कह रहा हूं कि माननीय सदस्य सवाल पूछ लें लेकिन सारे खड़े हो गए हैं। फिर काम कैसे चलेगा? (व्यवधान) बाकी आपके लोग नहीं बोल पाएंगे। आप बोलिए। आप पूछिए लेकिन you let others sit there. You ask a question and then stop. मंत्री जी जवाब देंगे। अगर सब खड़े होकर बोलना चाहेंगें तो काम कैसे होगा?कोई नॉर्म्ज हैं क्या?

25/03/2015/1750/MS/AG/2

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष जी, जो यहां पर माननीय मंत्री जी ने बातें कहीं। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्लैरिफिकेशन थी या इनका भाषण था? उसके बावजूद जो बातें कहीं है, वे तथ्यों पर नहीं कही गई हैं। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 13वें वित्तायोग की अगर बात करें, पंचायती राज की अगर बात करें। मैं आपको मंत्री जी बताना चाह रहा हूं कि 13वें वित्तायोग की बड़ी क्लीयर गाइडलाइन्ज उस समय थी कि जो हमारे पंचायती राज संस्थानों में चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से इस पैसे को खर्च किया जाए। गाइडलाइन्ज स्टेट के ऊपर छोड़ दी गई थी और प्रदेश में हमने इस बात को लेकर विचार किया कि पंचायत के प्रधान को विधायक निधि भी आती है और उनके माध्यम से काम एग्जीक्यूट होता है। उनको सांसद निधि भी आती है, बैकवर्ड एरिया सब-प्लान का पैसा भी आता है और एस0डी0पी0 का पैसा भी आता है। सारी मद के माध्यम से उन तक पैसा आता है। ऐसी परिथिति में जो हमारा जिला परिषद का मैम्बर है, जो 15-16 पंचायतों का प्रतिनिधित्व करता है और ब्लॉक समिति का सदस्य जो दो-तीन पंचायतों को रिप्रेजेंट करता है, वे विकास कार्य में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में पूरे प्रदेश के सभी लोगों ने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनसे विचार करने के बाद एक कौंशियस डिसीजन लिया, ऐसे ही डिसीजन नहीं लिया। उस डिसीजन के मुताबिक हमने गाइडलाइंज में जरा सा चेंज किया। उसमें जो पहले पंचायतों को 50 प्रतिशत जाता था, उसको हमने जिला परिषद के लिए किया और जिला परिषद के साथ-साथ में ब्लॉक समिति के लिए जो पैसा जाता था, उसमें 30 प्रतिशत किया और पंचायतों को सिर्फ 13वें वित्तायोग के पैसे में थोड़ी सी कटौती हुई। इसको पूरे प्रदेश की जनता ने सराहा। पूरे प्रदेश की जनता ने कहा कि यह अच्छा निर्णय है और पंचायत के चुने हुए प्रतिनधि को जिला परिषद के वार्ड में,

जिसका बड़ा प्रतिनिधित्व रहता है, उसको एक सम्मान मिला। दूसरे, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 13वें वित्तयोग की ऐसी कोई गाइडलाइन्ज नहीं थी कि सारा पैसा पंचायत के प्रधान को देना है। पंचायत के प्रधानों का हम सम्मान करते हैं और उनके अख्तियार, अधिकार और सम्मान के लिए जो हमने काम किया है, वह आपने

25/03/2015/1750/MS/AG/3

नहीं किया । विभाग की क्या हालत है इस बात को लेकर पूरे प्रदेश का बच्चा-बच्चा जानता है। दूसरे, जो पंचायतों के प्रधानों के बारे में बातें कही है। इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पांच साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय धूमल जी के नेतृत्व में प्रदेश में रही, जो आंकड़ा पांच सालों में पंचायत के प्रधानों का सस्पैंड का हमारे समय में नहीं हुआ, उस आंकड़े को इन्होंने दो सालों में पार कर दिया। पिछले कल बताया कि 50 प्रधानों को सस्पैंड किया गया। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसे भी प्रधान जो भ्रष्टाचार के कारण सस्पैंड हुए,

जारी श्री जे0के0 द्वारा---

25.03.2015/1755/जेके/जेटी/1

श्री जय राम ठाकुरः---जारी----
एक बार नहीं, दो-दो बार सस्पैंड हुए पड़े थे उनको बहाल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, एनिमल हस्बेंडरी के बारे में माननीय धूमल जी ने आज बड़ा स्पष्ट कर दिया। मकसद हमारा बड़ा सीधा सा था, स्पष्ट था और स्पष्ट यह था कि जो प्रोड्यूसर है उसको लाभ मिले। हमने कहा कि हमने उस तक लाभ पहुंचाया है। आप लोग गांवों में जाओ और पूछो कि जो प्रोड्यूसर दूध बेचने के लिए जाता है उससे पूछो कि दूध किस प्रकार का है। मिल्क फैडरेशन की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि जो पैसा आपने ग्रांट के रूप में दिया है वही प्रोफिट के रूप में उनके खाते में गए हैं। इसके अलावा आपने मिल्क फैडरेशन का भट्टा बिठा दिया और पंचायती राज और रुरल डवैल्पमैंट डिपार्टमैंट का भट्टा बैठा हुआ है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप बैठिए। माननीय मंत्री जी आप क्लैरिफाई कीजिए।

--(व्यवधान) ----आप लोग बात सुनिए। You must know the rules that Hon. Chief Minister, Minister and Leader of Opposition can reply. So, he has to reply to your question. But you cannot contest it every time. Chief Minister, Minister and Leader of Opposition has special power. No Member can take the power of a Minister. मैं आपसे यह कह रहा हूं --(व्यवधान)----It is very simple. अगर मंत्री जी कुछ बोलेंगे तो आपको गलत लगेगा। अभी बोलने वाले कम से कम 15 माननीय सदस्य हैं। उनको कहें कि क्लैरीफाई करें। But on every point you are standing. जब आपके मेम्बर बोलेंगे तो आप उनकी बात सुनिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय सदस्य मैं बड़े आराम से बात कर रहा हूं आप मत घबराएं। मैं अपनी गलत बात को मानने के लिए भी तैयार हो जाता हूं और मैं कभी इस बात को महसूस नहीं करता। अध्यक्ष महोदय, जहां तक जयराम जी ने बात रखी वे इस विभाग के मंत्री रहे हैं , आपको मैं इसलिए कहना चाहता हूं।

25.03.2015/1755/जेके/जेटी/2

इन्होंने जिला परिषद की बात उठाई है। 13वें वित्तायोग की जो गाईडलाइन्ज है उनको मैं टेबल पर रख दूंगा। आप उन गाईडलाइन्ज को पढ़ें। उन गाईडलाइन्ज के अन्दर सीधे तौर पर कहा गया है कि 70 प्रतिशत पैसा पंचायतों को जाना चाहिए। यदि गलत है तो आप बोलिए। यह तो मैं हाऊस के अन्दर बोल रहा हूं। हाऊस के अन्दर जो भी बात रखी जाती है उसको आप वेरिफाई कर लें। यदि गलत होगा तो आप प्रिविलेज कर लें। मगर जो सच्चाई है उसको आप सुनने की क्षमता रखें। 70 प्रतिशत पैसा पंचायतों को जाना चाहिए। आप लोगों ने गाईडलाइन में चेंज कर दिया। मैंने फिर भी उनका पैसा नहीं काटा। वही पैसा रहने दिया। जैसे कि अंतिम साल है मैं क्यों इन चीजों में पड़ूं। लेकिन मैंने इस बात को जरूर रखा कि जो गाईडलाइन है, एस्टिमेट लाओ और हम उसको अप्रूव करेंगे। जहां पर पैसा बचा हुआ था और कई कहते थे कि फोरैस्ट का रोड़ है दो लाख रूपये देने की घोषणा करता हूं। परन्तु क्या आपके पास फोरैस्ट क्लीयरैंस है? वहां पर जिला परिषद के कुछ लोग और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका फैसला हमने विधान सभा के अन्दर करना है। जिला परिषद के लोग और मशीनें उनकी और पैसा अलॉटमैंट उनके

ऊपर। जिस प्रधान की बात आप करना चाहते हैं उसने 5 लाख रूपया रिपेयर करने के लिए दे दिया, जबकि मनरेगा के अन्दर रिपेयर जितना मर्जी चाहे आप कर सकते हैं। जब मैंने उनसे कहा कि 5 लाख रूपया रिपेयर के लिए जबकि कोई डंगा नहीं और केवलमात्र रिपेयर? अगर पंचायती राज को आप इस तरीके से चलाना चाहे कि पंचायत प्रधान जो चाहे वह करता रहे। मैंने इन बातों को रोकने की बात की है। मैं किसी भी द्वेष भावना के साथ काम नहीं करता हूं। आप कहते हैं प्रोड्यूसर को क्या दिया? हमने प्रोड्यूसर को बेहतर प्राईस देने का आश्वासन दिया है। दूसरी बात आपने कहा कि रेट नहीं मिल रहे हैं। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि रेट क्यों नहीं मिल रहे हैं? मैं खुद दूध उत्पादक हूं। मैंने डिपार्टमैंट के लोगों को भेजा कि आप देखें कि हमारा दूध कैसा है? इनका फैट 4.3 परसेंट है और एस.एफ.एन. पर 4.2 परसेंट है। मैंने कहा क्यों और मेरी गाय का 7.2 परसेंट है।

25.03.2015/1755/जेके/जेटी/3

इसलिए तभी रेट नहीं आया। मैंने इसके लिए प्रयास किया कि एस.एफ.एन. हमारे दूध में क्यों आती है? इसके लिए मैंने अपने डिपार्टमैंट के लोगों को भेजा।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

25.03.2015/1800/SS-JT/1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री क्रमागतः
और दो ज़िलों में हम इसके बारे में स्टडी करने की बात कर रहे हैं। Solid Not Fat, एस0एन0एफ0 जो होते हैं जो lactometer reading होती है। --(व्यवधान)--नहीं किया, उसके ऊपर क्या कमी थी? जो हम गाय को राशन या फीड देते हैं उसकी कमी की वजह से है। रविन्द्र रवि जी, मैं इस पर घंटा भी बोल सकता हूं। यह मजाक की बात नहीं है। यह प्रदेश के दूध उत्पादक की बात है। मैंने इसकी जड़ तक जाने का प्रयास किया है। उसमें अगर हम बैलेंस्ड राशन करें तो दूध का एस0एन0एफ0 बढ़ सकता है। जो हम उनको फीड दे रहे हैं उससे कम लागत की फीड देकर ज्यादा दूध पैदा कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रयास करना चाहता हूं। यह मज़ाक की बात नहीं है। धूमल जी, मैं कल भी किसी डिप्टी कमिश्नर से ऐसे ही बात कर रहा था। महाराष्ट्र में एक लड़का आया जो बाहर से था और उसने जो अंगूर पैदा करते थे

उनके साथ अंगूर मार्किटिंग का काम किया। जहां प्रोड्यूसर को 10 रुपये किलो अंगूर मिलता था, उसने वही अंगूर 40 रुपये किलो प्रोड्यूसर को देने का प्रयास किया। वहीं मार्किटिंग करके उसने 80-80 रुपये पर इम्पोर्ट किया। हम इस तरह से विधान सभा के अंदर चर्चा तो करते हैं परन्तु क्या हम प्रदेश के अंदर नौजवानों को सही रास्ते पर ले जाकर कि किस तरीके से मार्किटिंग करें प्रोत्साहित करते हैं? हमारे पास सेब है परन्तु मार्किटिंग नहीं है। क्योंकि हम जो प्लकिंग करते हैं उसमें सेब को डैमेज कर देते हैं और मार्किटिंग नहीं होती है। जितना आप चाहेंगे मैं उतना आपको जवाब दूंगा, धन्यवाद।

समाप्त

25.03.2015/1800/SS-JT/2

Speaker: Dharmani ji, would you wind up now?

श्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय सचिवः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो कहा मैं समझता हूं कि इनकी भावना यही थी कि एक तो जो पशु सहायक आपने रखे उनको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देते। उसके बाद उनको रखते। उनके लिए अच्छे आर0एंड0पी0 रूल बनाते ताकि उनका भी भविष्य खराब न होता।

दूसरा, जो किसी प्रधान की बात की, आगे कोई भी बढ़ सकता है। दर्जी का काम करने वाला भी बढ़ सकता है। चाय पिलाने वाला भी बढ़ सकता है, जब हमारे प्रधान मंत्री बन गए। उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जहां तक मैंने समझा इनके कहने का मतलब यही था कि भ्रष्टाचार गलत है। भ्रष्टाचार के तरीके से आगे बढ़ना गलत है। --(व्यवधान)--ये तो आपके सहयोगी रहे, इनको आपको एप्रीशियेट करना चाहिए। यहां इस बजट के अंदर बहुत सारी और अच्छी योजनाएं दर्शाई गई हैं। पंचायती राज विभाग से संबंधित बी0पी0एल0 के चयन की बात थी। इसमें पहले एस0डी0एम0 को सीमित अधिकार थे लेकिन अब वे सूओ-मोटो भी इंक्वायरी कर सकते हैं और जो गलत सिलैक्शन हुई होगी उसको डिलीट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इससे काफी लोगों को हम मिलकर न्याय दे पायेंगे और जो पात्र व्यक्ति है उसको उसमें शामिल कर पायेंगे। इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है। किसानों को ऊपर उठाने की बात कही गई है। क्योंकि जो अंत्योदय है, अंतिम लाइन

में व्यक्ति है अगर वह ऊपर उठेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अंत्योदय से जो सर्वोदय की बात कही गई है यह बहुत अच्छी बात है। इसलिए राजीव गांधी माइक्रो इरिगेशन स्कीम को लागू करने की बात कही गई है। लिफ्ट इरिगेशन की और बोरवैल की इंडीविजुअल और सैल्फ हैल्प ग्रुप जो फार्मर्ज़ का है उसे 50 परसैंट सबसिडी देने की बात कही गई है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक स्टैंडिंग कमेटी प्रॅपोज़ की गई है। उसमें अलग-अलग विभाग भी चैकडैम और वाटर बॉडीज़ क्रियेट करते हैं। इसमें होर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, आई0पी0एच0, रूरल डिवैल्पमैंट सारे सैक्रेटरीज़ को मेम्बर बनाया गया है। इसमें एक फॉरैस्ट छूट गया है। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें सैक्रेटरी, फॉरैस्ट को भी इंक्लूड किया जाए। क्योंकि बहुत सारे फॉरैस्ट एरियाज़ भी हैं जहां पर वाटर बॉडीज़ क्रियेट हुई हैं या कर सकते हैं। इरिगेशन के पॉटैंशियल को हम फार्मर्ज़ के हित में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहां पर स्किल

25.03.2015/1800/SS-JT/3

डिवैल्पमैंट की बात कही गई है। स्किल डिवैल्पमैंट कारपोरेशन बनाने की बात कही गई है।

जारी श्रीमती के0एस0

25.03.2015//1805केएस/जेटी/1

श्री राजेश धर्माणी जारी---
मैं ऐसा समझता हूं कि हम बेरोज़गारों को अगर स्किल्ड बनाएंगें उनके अंदर कुछ हुनर पैदा करेंगें तभी हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा और पर-केपिटा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। पर-केपिटा इन्कम तो कई कारणों से बढ़ जाती है, उसमें इंडस्ट्री भी आती है, बागवान और अन्य कारोबार की वजह से भी बढ़ जाती है लेकिन पर-केपिटा प्रोडक्टिविटी पर फोकस करने की जरूरत है। यह जो स्किल डवैल्पमैंट का इनिशिएटिव लिया गया है यह एक सराहनीय कदम है और इससे मैं समझता हूं कि हमारे समाज के अंदर एक परजीवि संस्कृति पैदा हो रही है। जो लोग बेरोज़गार रह रहे हैं या जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, एक तो बेरोज़गार है उसके अन्दर हुनर है लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है, अवसर प्रोवाइड कर रहे हैं

मगर कुछ लोगों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति भी पैदा हो गई है जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं लेकिन वे शानो-शौकत से रहना चाहते हैं। ड्रग्ज़ का धंधा कर रहे हैं, कोई दलाली कर रहे हैं। उस परजीवी संस्कृति को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम इस स्किल डवैल्पमैंट प्रोग्राम के माध्यम से जो इनिशिएटिव लिया गया है, उसके माध्यम से होगा। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इसमें सुधार करने की जरूरत है। विपक्ष के मित्रों की तरफ से भी इस सम्बन्ध में कुछ इश्यू उठाए गए हैं क्योंकि इसमें क्वालिटी के साथ कम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मंत्री जी आज यहां पर नहीं हैं लेकिन टैक्निकल ऐजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं, जितने इंस्टीच्यूट इसके लिए ऑथोराइज़ किए जाएं वे एस.सी.वी.टी. से या एन.सी.वी.टी. से रजिस्टर्ड होने चाहिए ताकि

25.03.2015//1805केएस/जेटी/2

क्वालिटी के साथ कोई कम्प्रोमाइज न हो।

मैं यहां पर अरबन डवैल्पमैंट की बात करना चाहूंगा क्योंकि इसमें एक अच्छा इनिशिएटिव लेने की बात की गई है कि 50 प्रतिशत कंट्रीब्यूट करेंगें यू.एल.बी. को पार्किंग बनाने के लिए। 50 प्रतिशत वहां से देंगें यह अच्छी बात है। इसमें मैं एक और कन्सर्न शो करना चाहूंगा क्योंकि अगर आप देखेंगें तो बहुत सारी अच्छी-अच्छी कृषि योग्य भूमि कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए उसका यूज़ किया जा रहा है। एग्रिकल्चर लैंड प्रोटैक्ट होनी चाहिए। सुन्दर नगर से नेरचौक-मण्डी के बीच में बहुत अच्छी वैली होती थी लेकिन आज की तारीख में वहां बहुत कम खेत देखने को मिलते हैं। सारी जगह घर और सड़कें बन गई है । लगातार एग्रीकल्चर लैंड का नॉन एग्रिकल्चर परपज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। यह कम हो रही है इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हमारी जो पहले की जनरेशन थी वे हाऊसिंग के लिए एक अलग से डैडिकेटिड ईयर मार्क लैंड होती थी उसका यूज़ करते थे जिसको हम आबादी में बोलते थे या लालडोरा जमीन थी उस तरीके के प्रावधान करने की आज जरूरत है ।

परिवहन से सम्बन्धित बात करना चाहूंगा। हमारे परिवहन मंत्री जी ने बहुत सारी अच्छी बसें ली गई है। JNNURM के तहत भी और उससे पहले भी बहुत सी बसें ली गई लेकिन वे बसें खड़ी हैं। लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है और लोगों को कैसे सुविधा मिलेगी, इसके बारे में मंत्री जी ने विचार करना है। इन्होंने कोशिश की

है। जिस पॉलिसी के तहत आपके समय में बस सहायक रखे गए, जब इसी पॉलिसी के तहत अब

25.03.2015//1805केएस/जेटी/3

रखने शुरू किए गए तो कुछ लोगों ने कोर्ट का सहारा ले कर स्टे ले लिया। बाद में कंडक्टर रखने की बात की गई तो वह स्टे हैं और अब जो माननीय मंत्री जी ने अप्रैटिसशिप की बात की उसमें भी पता नहीं क्या हुआ लेकिन कुल मिलाकर जब तक कंडक्टर नहीं होंगें तब तक वे बसें नहीं चलेंगी और लोगों को गांव में सुविधा नहीं मिलेगी तो मंत्री जी इसमें कुछ कीजिए। नहीं तो ये बसें बेकार में खड़ी रहेंगी। इनके ऊपर करोड़ों अरबों रुपया लगा है। इस पैसे की बर्बादी हो रही है अगर ये बसें साल-छः महीने और खड़ी रह गई तो इससे और नुकसान होगा तो लोगों को सुविधा देने की कोशिश करें। आपकी नीयत अच्छी है तभी आपने ये प्रबन्ध किया है लेकिन जब तक ये बसें गांव में नहीं जाएंगी, सड़कों पर नहीं चलेगी, लोगों को इसका लाभ नहीं होगी इसलिए इसके बारे में जरूरी कदम उठाएं ताकि लोगों को लाभ मिल सके।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, अब वाइंड-अप कीजिए।

श्री राजेश धर्माणीः सर, समाप्त करता हूं। चाहे हमारा स्वास्थ्य विभाग है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कोशिश इन्होंने भी की होगी लेकिन मैंने एक प्रश्न किया था उसके माध्यम से मुझे जो उत्तर मिला था, उस समय 79 प्राईमरी हैल्थ सैंटर ऐसे थे जिनमें एक भी डॉक्टर नहीं था। आज हमें इस बात की खुशी है कि आज की तारीख में जहां नए पी.एच.सी. हमारी सरकार ने खोले हैं, वहीं नए सी.एच.सी. भी अपग्रेड हुए हैं और पी.एच.सी. आज की डेट में ऐसा नहीं है जहां पर कोई न कोई डॉक्टर डिप्यूट नहीं किया गया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा---

25.3.2015/1810/ag/av/1

श्री राजेश धर्माणी जारी---------

अगर कहीं पर एम.बी.बी.एस. डॉक्टर नहीं है तो वहां पर आयुर्वेदिक डॉक्टर लगाया गया है। जहां कहीं कोई कमी होगी तो उसको माननीय मंत्री जी दूर करेंगे। इन्होंने स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छे कदम उठाये हैं। चाहे पैंशन बढ़ाने की बात है, उसमें भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से बहुत अच्छी बढ़ोतरी दी है। हमारे वन विभाग से सम्बंधित एक अच्छा प्रोजैक्ट जिसमें क्लाइमेट चेंज का कनसर्न भी शो किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, अंत में, ज्यादा समय न लेता हुआ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट अनुमानों का पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

समाप्त

25.3.2015/1810/ag/av/2

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा कई दिनों से चली हुई है। इस बारे में आज दिन में भी कई विधायकगण मेरे से मिले थे। उन्होंने एक ही बात कही कि बसें नहीं चल रही है। मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि यह मामला सबजूडस है। दूसरे, मैंने इसके आंकड़े लिए। इसमें लगभग 8500 के करीब केंडिडेट अप्पीयर हुए। कुछ विधायकों ने यह सोच लिया कि यह एक जॉब है। It is not a job. It is a training. बच्चों के स्किल बढ़ाने की बात है। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और इस बारे में अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। मैं तो बार-बार यह बात कहता हूं कि हमारा लक्ष्य नौजवानों को नौकरी देना है। उनको काम सिखाना है और उनको स्किल देना है। मैंने अधिकारियों को बोला कि कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जिन्होंने यह साक्षात्कार दिया है उन सबको हम स्किल की ट्रेनिंग दे सके। एक साल के अंदर पूरे स्किल की ट्रेनिंग देंगे। <u>सभी केंडिडेट; जिन्होंने साक्षात्कार दिया है उनको ट्रेनिंग व स्किल देने का पूरा प्रयास करेंगे।</u>

समाप्त

25.3.2015/1810/ag/av/3

अध्यक्ष : मैं माननीय सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि अभी 13-14 सदस्य बोलने को शेष बचते हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप संक्षिप्त में बोलें। अगर आप हर प्वाईंट पर डिसक्शन जनरेट नहीं करेंगे तो इस काम को निपटाया जा सकता है। कुछ रह जायेंगे तो कल बोल लेंगे।

अब मैं श्री पवन काजल जी को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री पवन काजल : अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा 18 मार्च, 2015 को प्रस्तुत किए गए बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस बजट में, चाहे किसान हो या बागवान हो। चाहे बच्चे, बूढ़े,जवान हो; इस बजट से हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस बजट की चर्चा मैं बाद में करुंगा। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र से बिल्कुल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहां आया हूं। हमने वहां कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ; दोनों को पछाड़ा था। कांगड़ा विधान सभा की जनता ने हमें शिमला का रास्ता दिखाया और हम इस सदन में पहुंचे। हमें ऐसा टर्निंग प्वाईंट मिला कि हमें माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का आशीर्वाद मिला। ऐसे व्यक्तित्व और ऐसी शख्सियत के साथ हमें काम करने का मौका मिला कि जिसका 52 वर्ष का राजनीतिक करियर हो और 6 बार मुख्य मंत्री रहे हों। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम जैसे जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आए थे उन्हें तवज्जो और मान-सम्मान दिया। मैं पिछले दो वर्षों के संदर्भ में कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। जैसे कि विपक्ष वाले यहां पर कह रहे थे कि दो सालों में कुछ नहीं हुआ केवल भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार बढ़ा है। मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र में जो पिछले कई वर्षों से ग्रहण लगा था उसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने गति दी----------

श्री नेगी द्वारा जारी

25.03.2015/1815/negi/ag/1

श्री पवन काजल .. जारी...
जो ग्रहण लगा था उसको गति माननीय मुख्य मंत्री जी ने दी , मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो कांगड़ा शहर के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी के आर्शीवाद से 18 करोड़ 32 लाख रूपये की योजना स्वीकृत हुई है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। 18. 32करोड़ रूपये की जो आधुनिक पेयजल योजना है इसके शुरू होने पर 24 घंटे पानी आएगा और उसका जनता को लाभ होगा। इसी तरह से कांगड़ा शहर में सीवरेज़ का कार्य जो पिछले 5 वर्षों से बन्द पड़ा था, माननीय मुख्य मंत्री जी ने आते ही इसके लिए 4.15 करोड़ रूपये का प्रावधान किया। आज उस काम को गति मिल रही है। इसी तरह माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की जब सरकार बनी तो इन्होंने कांगड़ा शहर के लिए, जहां मां बृजेश्वरी के चरणों में बसा यह शहर है और यहां पर काफी श्रद्धालु आते हैं और वहां पर पार्किन्ग की कोई सुविधा नहीं थी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पार्किंग लिए पैसों का प्रावधान किया और आज इन 2वर्षों में पार्किन्ग का काम विधिवत् पूरा हो गया है जिसका जनता को लाभ मिलेगा। इसी तरह से कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र में, मैं इसके लिए बाली साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने चंगर क्षेत्र के लिए एक आई.टी.आई. दिया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया। शिलान्यास ही नहीं बल्कि उसके 3 महीने के बाद उसकी क्लासें भी शुरू की, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। कांगडा विधान सभा क्षेत्र में कोई भी सरकारी कालेज नही था । जब मैं पहली बार जीत के आया था तो पहली प्लानिंग की मीटिंग में भी माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था और दूसरी प्लानिंग की मीटिंग में भी निवेदन किया था और विधान सभा में भी कहा था कि एक मात्र ऐसा कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र है जहां कोई भी सरकारी कालेज नही है। कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र ओ.बी.सी. बहुल्य क्षेत्र है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम गवर्नमैन्ट कॉलेज में छात्रवृत्तियां देते हैं। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया और पिछले टूअर में मुख्य मंत्री जी ने इसकी विधिवत् घोषणा की ।

उन्होंने इसकी विधिवत् घोषणा ही नहीं की बल्कि इसके लिए बजट का प्रावधान भी किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। क्योंकि हम तो नए-नए थे, पहली बार विधान सभा में पहुंचे थे, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया कि गवर्नमैन्ट हाईस्कूल समीरपुर को गवर्नमैन्ट सीनियर सकेन्डरी स्कूल किया जाए। दूसरा गवर्नमैन्ट हाईस्कूल सकोट को गर्वमैन्ट सीनियर सकेन्डरी स्कूल किया जाए। समीरपुर के बच्चे जो 5 किलोमीटर का सफर करके कांगड़ा पढ़ने आते थे इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। ठीक है विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इन दो सालों में सड़कों का बुरा हाल है। मैं इस सदन में पक्ष को भी और विपक्ष को भी बता देना चाहता हूं कि कुल्थी-बलोल के बीच बनने वाले पुल जिसकी सड़क का निर्माण आज से 20 साल पहले हो चुका है। इस सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2 करोड़ 5 लाख रूपये की स्वीकृति दी है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। इसी तरह से गालियां से खडी-बही/बडी बही के लिए 145 करोड़ रूपये की डी.पी.आर. की स्वीकृति दी है इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। लग्दा-पलेडा,बन्दला वाया हरिजन बस्ती के लिए 1.05 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। गालियां-खरट-राजल सड़क क्योंकि यह छोटी सड़क है और सीधा पहाड़ है इस सड़क की सुधारीकरण के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 4 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। इसके लिएमैं धन्यवाद करना चाहूंगा। एक और अभी-अभी 2 महीने पहले दौलतपुर से हारजलाडी वाया खजूना सड़क के लिए 5.08 करोड़ रूपये का जो डी.पी.आर. पिछले 16 वर्षों से लम्बित पड़ी थी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला भी और उनसे विचार-विमर्श भी किया और उन्होंने उसकी स्वीकृति दी। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। एक और सूंह से गालियां जाने वाला लकड़ी का पुल है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विपक्ष का पीछे जो धूमल साहब की सरकार थी तो वह कच्ची सड़क बनी थी ।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी..

25.03.2015/1820/यूके/1

श्री पवन काजल--जारी---
जो बहुत अच्छी सड़क बनी थी । जो गलियां से 32 मील को निकलती है । पर उसमें पुल का निर्माण नहीं था । तो पुल के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 11 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा । जैसा कि इस बजट में जो प्रदेश के किसान, बागवान हो, चाहे बच्चे, बूढ़े और जवान हो, मैं कह रहा था जिसके समर्थन में मैं उतरा हूं, कुछ बातें रखना चाहूंगा । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का तथा प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो विधायक निधि, जो विधायक बन कर आता है, उसका सबसे बड़ा गहना विधायक निधि होता है । उसको बढ़ा कर आपने बढ़ा कर 50 लाख से 70 लाख रूपए किये, इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा, पर इसमें कुछ जो क्वैश्चन मार्क लगाया है इसका इस्तेमाल लघु सिंचाई योजनाओं, कूहलों और तालाबों के लिए किया जाएगा । इसमें मैं थोड़ा से सुझाव देना चाहूंगा । इसमें कुछ अमेंडमैंट हो जाए क्योंकि लधु सिंचाई, कूहलों और तालाबों के लिए मनरेगा का बजट भी होता है । आपने इस बजट में भी कई कूहलों के लिए बजट दे रखा है । तो मैं यह चाहता हूं कि जो 20 लाख रुपए बढ़ाया है, उसको फ्री हैंड किया जाए । वैसे ही BPL किसानों को टोका मशीन उत्पादन के लिए मिलेगी । इससे भी BPL परिवारों को लाभ मिलेगा । एक और इस बजट में मेन विशेषता यह है कि केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों को HRTC की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा दी जायेगी । यह भी एक मेन विशेषता इस बजट में हैं ।

25.03.2015/1820/यूके/2

किसान एवं खेतिहर मजदूरों को जीवन सुरक्षा योजना शुरु की गयी यह भी अच्छी बात है । एक इस बजट में जो मेन बात है कि आम आदमी के हित में आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश लाभार्थी को इससे पहले जो पिछले बजट में 48हजार रुपए मिलता था, इसको 75 हजार रुपए किया है । इस वर्ष 10 हजार के लगभग मकान बनेंगे । मेरा एक सुझाव रहेगा कि जितने भी मकान बनेंगे इनको परसेंटेज के हिसाब से दिया जाए जैसे OBC हो या ST हो या SC हो उनको परसेंटैज के हिसाब से इसका आबंटन किया जाए । यह मेरा सुझाव रहेगा ।

किसानों तथा स्वयं सहायता समूह को 10 लाख तक की मॉडगेज डीड का स्टाम्प शुल्क में छूट दी है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा । पटवारी परीक्षार्थियों का मानदेय एक हजार रुपए से बढ़ा कर 3 हजार रुपए किया, यह भी बजट की विशेषता है । भगवान न करे कोई आपदा इस प्रदेश के अन्दर आए । आपदा राहत के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने 236 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान रखा है । प्रत्येक परिवार को 3 LED बल्ब दिए जाएंगे । LED बल्ब पर वैट को 13.75 प्रतिश से घटा कर 5 प्रतिशत किया गया है । उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ।

एक और इस बजट मे विशेषता है जो आम आदमी के हित में है । यह जो सामान को पूरी ऑन लाईन घोषणा के साथ प्रवेश करने की घोषणा की है, चाहे गुजरात से, हरियाणा से या पंजाब से ट्रक आते थे, तो जब बैरियर पर आते थे तो ड्राईवर को दो-दो या तीन-तीन दिन तक

25.03.2015/1820/यूके/13

बैरियर पर रुकना पड़ता था, लम्बी कतार में वे बैठते थे, इसके लिए भी आने वाले समय में जनता को भी लाभ मिलेगा, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ।

ढाबा, हलवाई, चाय तथा चाट व्यापारियों के लिए वैट भुगतान की छूट की सीमा को 8 लाख रुपए किया गया, इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा । एक और राजीव गांधी डिजिटल योजना के अंतर्गत 10वीं तथा 12वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

25.03.2015/1825/sls-jt-1

श्री पवन काजल...जारी

दैनिक मज़दूरों की दिहाड़ी 170 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये की गई है। कौशल विकास भत्ते के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। प्रदेश में संबंधित ट्रेड के साथ 400 छात्र क्षमता वाली 10 नई अत्याधुनिक आई.टी.आई. खोली जाएंगी। इस बजट में 7750 आशा वर्करों को प्रशिक्षण देकर उनको गावों में तैनात किया जाएगा। चिकित्सकों के 200 तथा पैरा मैडिकल कर्मियों के 500 पद भरे जाएंगे ताकि जो प्रदेश के अस्पतालों में कहीं डॉक्टर नहीं हैं, पी.एच.सी. में डॉक्टर नहीं हैं, डिसपैंसरी में डॉक्टर नहीं है, आने वाले समय में वह पद भरे जाएंगे। माननीय कौल सिंह जी बैठे हैं। एक साल के भीतर हमारे यहां लगभग सब जगह डॉक्टर हो जाएंगे। 'बेटी है अनमोल' योजना के तहत पहली से 12वीं कक्षा तक की कन्याओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में 50 प्रतिशत् की वृद्धि हुई है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि 6 वर्ष तक की आयु की सभी कन्याओं को मुफ्त चिकित्सा सुविधा की बजट में माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की है। इसमें अपंग, वृद्ध, विधवाओं की सामाजिक पैंशन में वृद्धि की गई है। जो पैंशन पहले 450 रुपये थी वह बाद में 500 रुपये की गई थी। फिर 550 रुपये की गई और इस बार 550 से 650 रुपये की गई है। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है। ऐसे 35000 लोग पात्र होंगे, जिनको इस साल से यह पैंशन मिलेगी। इससे पिछले बजट में इसके लिए इनकम सीमा 17000रुपये थी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको अब 35000 रुपया किया है। इससे पैंशन के पात्र लोगों को और गरीब जनता को लाभ हुआ है। जो इस साल 35000 केसिज लंबित पड़े हैं वह सब निकल जाएंगे। इसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। 31 मार्च, 2015 को 7 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने वाले दैनिक वेतन भोगी नियमित होंगे। 31 मार्च, 2015 को 8 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने वाले अंशकालीन कर्मी दैनिक वेतन भोगी बनेंगे। यह भी इस बजट की मुख्य विशेषता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने घोषणा-पत्र में भी कहा था कि जो अनुबंध कर्मी हैं ,उनको हमने 5 सालों में नियमित करना है। माननीय मुख्य मंत्री ने 31 मार्च, 2015 को 5 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने

25.03.2015/1825/sls-jt-2

वाले सभी अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही है। यह भी इस बजट की बड़ी विशेषता है। कुल मिलाकर यह बजट हमारे लिए समग्र कल्याण करने वाला है। यह सब मुख्य मंत्री की वित्तीय सूझबूझ एवं प्रशासनिक कुशलता का परिणाम है। इसके लिए मैं इस बजट का खुले दिल से और खुले हाथों से समर्थन करता हूं।

धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब श्री बी०के० चौहान जी चर्चा में भाग लेंगे।

जारी..गर्ग जी

25/03/2015/1830/RG/AG/1

अध्यक्ष : अब श्री बी0के0 चौहान जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बी0के0 चौहान : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। वर्ष2015 - 16के जो बजट अनुमान इस प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किए हैं ,मैं उनके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश या राष्ट्र का जब बजट बनता है, तो उसका केन्द्र बिन्दु राज्य का विकास, राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार करना होता है और इसके लिए उस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ होनी चाहिए। उसके साथ-साथ जो स्वास्थ्य सेवाएं उस प्रदेश में हैं वे भी सुदृढ़ होनी चाहिए, सबको ,हर वर्ग के लिए हर स्थान पर उपलब्ध होनी चाहिए। आखिर में जो विकास के कार्य या व्यवस्थाएं हैं चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, जो विकास की योजनाएं हैं उनका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि प्रदेश के लोगों को रोज़गार मुहैया करवाएं ,उनको अपने पैरों पर खड़ा करें ताकि बेरोज़गारों को अपनी आजीविका ढूंढने के लिए दर-दर की ठोकरें न खानी पड़ें। किसी भी सरकार का ये मुख्य उद्देश्य होता है।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में जो मैंने देखा है। सबसे पहले मैं शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जो बजट अनुमान हैं उनमें भी और राज्यपाल महोदय को इन्होंने जो अभिभाषण तैयार करके पढ़ने के लिए दिया था ,उसकी शुरूआत ही इसी से होती है कि कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सौ नए प्राथमिक स्कूल खोले हैं ,160 प्रारम्भिक पाठशालाओं और माध्यमिक पाठशालाओं को उन्नत किया है।

इसके साथ-साथ 234 माध्यमिक पाठशालाओं को उच्च तथा 225 उच्च पाठशालाओं को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत किया है ,14 नए महाविद्यालय खोले हैं और यह भी कहा गया कि वर्ष 2014-15 की अवधि में उच्च पाठशालाओं के लिए 788 पद सृजित किए जाएंगे। यह जो आंकड़ा दिया है। सरकार के आते ही इन्होंने धड़ाधड़ एक मुश्त प्राइमरी स्कूल खोलने शुरू कर दिए।

(श्रीमती आशा कुमारी, सभापति महोदया पदासीन हुई।)

सभापति महोदया, जो प्राथमिक स्कूल हैं उन्हें माध्यमिक स्कूल बना दिया , माध्यमिक स्कूलों को हाई स्कूल बना दिया और हाई स्कूलों को इन्होंने प्लस टू कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि सारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आज चरमराई हुई है। यह सब जो धड़ाधड़ बिना सोचे-समझे स्कूलों को अपग्रेड करने का सिलसिला चला ,उसमें कांग्रेस सरकार या मुख्य मंत्री महोदय ने यह नहीं देखा, जो स्वयं शिक्षा मंत्री भी हैं, कि मैं जो इन स्कूलों को अपग्रेड कर रहा हूं इनमें जो हम शिक्षक देंगे,

25/03/2015/1830/RG/AG/2

चाहे प्लस टू के लिए, हाई स्कूल या माध्यमिक स्कूलों या प्राथमिक स्कूलों के लिए उसका प्रबन्ध जब ये स्कूल अपग्रेड किए थे, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब ये स्कूल अपग्रेड हो गए, उसके बाद क्या स्थिति हुई? बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है ,स्कूल में कमरे नहीं हैं। स्कूल को अगर स्तरोन्नत कर दिया, तो उसमें कमरे बनाने के लिए भी उस स्कूल के पास अपनी भूमि नहीं है----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

25/03/2015/1835/MS/AG/1

श्री बी0के0 चौहान जारी--------
स्कूल में कमरे नहीं है। स्कूल को अगर पदोन्नत कर दिया तो उसमें कमरे खड़े करने के लिए स्कूल के पास अपनी भूमि नहीं है। इसके फलस्वरूप स्कूल की क्लासिज तो लग गई लेकिन पठन-पाठन नहीं हो सका1 क्योंकि जितने भी ये स्कूल खुले, उनका अनाउंसमैंट हुआ तो खुल गए लेकिन टीचर्स का इंतजाम आज तक भी नहीं हो पाया

है। क्योंकि जो टीचर जहां-जहां लगे हुए हैं उनको हटाना बड़ा मुश्किल है। मैं अपने चम्बा की एक तस्वीर थोड़े से आंकड़ों में पेश करना चाहूंगा। एक गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल दरदेआडू में चार विद्यार्थी हैं और वहां पर चार का ही स्टाफ है। मतलब उसमें दो जे0बी0टी0 टीचर हैं ,एक पीअन है और एक मिड-डे मील बनाने के लिए वर्कर है। उसके साथ गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल दरडाला में छः विद्यार्थी हैं। वहां भी दो जे0बी0टी0 टीचर काम कर रहे हैं और दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल औरा में आठ विद्यार्थी हैं, टीचर्स दो हैं और वर्कर भी दो हैं। गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल चलामा में आठ विद्यार्थी हैं और चार टीचर हैं। गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल खजीर में चार विद्यार्थी हैं और चार ही टीचर हैं। गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल अंगरेड में नौ विद्यार्थी हैं और चार टीचर हैं। एक सवाल मेरे साथी बिक्रम ठाकुर जी ने इसी बारे में किया था कि प्राइमरी स्कूलों में, जो ये अपग्रेड किए हैं, इनमें कितने-कितने टीचर्स कहां-कहां है। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में काफी जगहों पर एक विद्यार्थी और एक टीचर है और एक स्कूल में चार विद्यार्थी और चार टीचर्स हैं। जब मैंने इस पर मनन किया और सोचा और फोन भी किए चम्बा में, कि ऐसी व्यस्तता क्यों है? कहते हैं कि सबकी पुल और पुश है। हम यदि इनको ट्रांसफर कर भी देंगे तो ये नहीं जाएंगे। इनके अपने-अपने सिफारिशी लोग हैं। इनके पीछे कोई न कोई खड़ा है। इसलिए इनको हटाना हमारे बस का रोग नहीं है। यह तो प्राइमरी स्कूलों की बात है।

उसके बाद जो टीचर आपको हायर क्लासिज में चाहिए, उनमें हैडमास्टर चाहिए लेकिन वे नहीं हैं। उसके बाद जो आपको टी0जी0टी0 चाहिए उनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में जहां प्रिंसिपल चाहिए तो वे भी उपलब्ध नहीं हैं। कुछ लोग जो अगल-बलग के स्कूल में लैक्चरर थे, उनको ही प्रिंसिपल बनाकर भेज दिया। वे उन सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों को चला रहे

25/03/2015/1835/MS/AG/2

हैं। लैक्चरर नदारद हैं या है ही नहीं। उनका एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यु होगा, उसके बाद वे आएंगे। ऐसी व्यवस्था क्रिएट हो गई है कि शिक्षा का स्तर केवल और केवल नीचे ही नहीं जा रहा है बल्कि केओस (Chaos) पैदा गया है। लैक्चरर और टीचर्स की वैकेन्सीज भरने के लिए, मैं नहीं कहूंगा कि नया प्रयास किया गया है, ऐसा पहले भी कांग्रेस सरकारों में होता रहा है कि इंटरव्यु करना शुरू कर दिए। दो

एजैंसीज बना दी। एक SMC, जो पहले भी स्कूल मैनेजमैंट कमेटी स्कूलों की होती थीं ,वे भी भर सकते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन लेकर सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट को अधिकृत कर दिया कि सभी स्कूलों में जाकर इंटरव्यु करे और पदों को भरने का प्रयास करे।

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

25.03.2015/1840/जेके/जेटी/1

श्री बी.के. चौहान-------जारी--------
अब उसमें क्या हुआ वहां पर जो एस.एम.सी. में अपने-अपने लोग थे वे चाहे क्वालिफाई करते थे या नहीं करते थे वे रख लिये। उसमें कोई क्राईटेरिया नहीं है। उसमें जो भी उसके प्रेजिडैंट को पसन्द आया वह एस.एम.सी. का रिश्तेदार था। मैं अपने चुनाव क्षेत्र की हकीकत कह रहा हूं। विशेष करके हमारे चम्बा का यह हाल है। वह पोस्ट भर ली। उसके बाद एस.डी.एम. ने जो रखे वे सब वही रखे क्योंकि उन्होंने पहले प्रयास किया कि वे मैरिट के हिसाब से रखे। बाद में बड़ा हल्ला हुआ और जिसकी सिफारिश जितनी ज्यादा थी उसको रख लिया। जिसके नम्बर ज्यादा भी थे उसको पीछे कर दिया। एस.डी.एम. को कहा गया कि तुम ऐसे पिक एण्ड चूज क्यों कर रहे हो? हर आदमी को अपनी नौकरी प्यारी होती है। जब आदमी वहां पर साल-दो साल रह जाता है तो एक-दो साल और रहना चाहता है। उसको भी धर्म संकट था। अगर वह बात नहीं मानता है उन लोगों की जो इन्ट्रस्टिड है तो उसकी गर्दन चौपर के नीचे आ जाती है। अगर मानता है तो उसकी आत्मा उसको कचोटती है कि मैं गलत काम कर रहा हूं। फिर वह बेचारा ट्रेनिंग में चला गया। यह स्थिति शिक्षा विभाग में आज प्रिवलैंट हैं। मैं समझता हूं कि यह शायद चम्बा में ही नहीं है पूरे हिमाचल में ऐसी स्थिति होगी। शिक्षा का स्तर हिमाचल का पहले से ही इतना अच्छा नहीं है। लेकिन यह जो कार्यक्रम हुआ है और ये जो आपकी नायाब स्कीमें चली हैं इससे अब हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में और नीचे चला गया। शिक्षा का स्तर तो पहले से ही गिरा हुआ था क्योंकि हम जब भी एच.ए.एस. की परीक्षाएं या दूसरी ऑल इण्डिया परीक्षाएं देखते हैं और कम्पिटिशन को देखते हैं तो हिमाचल में एक-आध आदमी कहीं से निकल पाता है। वह भी हिमाचल में पढ़ा हुआ नहीं वह भी बाहर से उसने शिक्षा ग्रहण की हुई हो। हमारे स्कूलों से कोई अच्छा गेजेटिड ऑफिसर

निकलना बहुत मुश्किल है। यह हमारे यहां शिक्षा का स्तर है। सरकार ने इस पर इतना चिन्तन/मनन करना उचित नहीं समझा; without thinking about the constituencies, without taking into consideration the prevailing conditions in the field and the condition of education in the State. Already they have

25.03.2015/1840/जेके/जेटी/2

two-and-a-half year, ढाई सालों में आप हर चीज को इवैल्युवेट कर सकते हैं, देख सकते है कि हम इस चीज में कितने गिर रहे हैं। इस तरह से शिक्षा स्तर का तो भट्टा बैठ गया। हम सब पढ़े-लिखे लोगों को और सदन को ही सोचने का विषय नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश की जनता को भी सोचने का विषय है। हिमाचल प्रदेश में कितने लोग हैं। जो अपने बच्चों को चण्डीगढ़ में पढ़ा सकते हैं, दिल्ली में पढ़ा सकते हैं और कहीं दूसरी जगह पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि 80 per cent people depend on our Government schools. तो मुझे शिक्षा का जो भविष्य हिमाचल में है यह इस सरकार के दौरान बहुत ही दयनीय ही नहीं लगता परन्तु मैं सोचता हूं कि यह हिमाचल को 10 साल पीछे ले गए हैं।

दूसरी बात मैंने यहां पर कहीं थी हैल्थ की। हैल्थ के बारे में बहुत सारी बातें इस सदन में हो चुकी है। हैल्थ की जा दशा है और मुझे खुशी है मेरे मित्र कौल सिंह जी यहां पर बैठे हैं। ये जानते हैं कि कितनी पोस्टें विशेष करके स्पैशलिस्ट की इस राज्य में खाली पड़ी है और उससे भी ज्यादा पैरा मैडिकल की और नर्सिज की खाली हैं। क्योंकि स्पैशलिस्ट मिलना तो मुश्किल है। हमारी अपनी जो प्रोडक्शन है वह बहुत कम है तो बाहर से आजकल प्राईवेट हास्पिटल्ज का इतना उनकी सैलरी और भत्ते इतने बढ़ गए हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

श्री बी0के0 चौहान क्रमागतः

बहुत इतना बढ़ गया है कि Government job is always a second option for them. In these circumstances I feel bad for the Health Minister also that he has no planning and nothing with him to attract specialists. आप देखिये कि मेरे साथी चुराह के विधायक जी ने विषय रखा था कि एफ0आर0यू0 चम्बा में कोई काम नहीं कर रहा। चम्बा का मतलब जो हमारी पैराफरल कांस्टीचुऐंसीज़ हैं उसमें एफ0आर0यू0 कोई काम नहीं कर रहा। वे चम्बा आते हैं, चाहे चुराह के हों, चाहे भटियात के हों। भटियात वालों के लिए अच्छा है क्योंकि कम-से-कम टांडा नज़दीक है। लेकिन चाहे चुराह के हों या सलूनी के हों या चाहे डलहौजी के हों वे पहले चम्बा आयेंगे। फिर वहां से रैफर करवायेंगे तो टांडा जायेंगे या आई0जी0एम0सी0 जायेंगे या ऐम्ज़ में जायेंगे। यह जो स्थिति है यह बहुत खराब है। उसके साथ-साथ मुझे ताज्जुब होता है कि चलो स्पैशल नहीं भी मिल रहे तो ग्रैजुऐट निकलते हैं। हमारे अपने कॉलेजिज़ हैं इसमें पी0जी0 निकलते हैं। कम-से-कम उनको बाहर जाने से रोका जाए। जो अभी हमारे ग्रैजुऐट डॉक्टर्ज़ हैं उनको सरकारी खर्चे पर स्पैशलाइजेशन के लिए भेजा जाए। उससे भी बड़ा अफसोस मुझे इस बात का है कि हम नर्सों की पोस्टों को नहीं भर सकते। हम पैरा-मेडिकल और टैक्निशियन की पोस्टों को नहीं भर सकते। अब वे भी खाली पड़ी हुई हैं। यह बड़ी दयनीय स्थिति है। हैल्थ का भी काम चौपट है और शिक्षा का काम भी चौपट है। उसके साथ-साथ मैं आपको एक और मिनेस बताऊं कि ट्रांसफर्ज़ कांग्रेस पार्टी के रजीम में एक आम चीज़ गई है। जो आदमी उनके पक्ष के हैं वे प्लम पोस्ट पायेंगे। मनचाहा स्टेशन पायेंगे। लेकिन जो भी करप्ट होगा, कोई टेंटिड अधिकारी होगा या ऑफिशियल होगा या नकम्मा आदमी हो जो कहीं फिट नहीं हो सकेगा तो उनका जो हरम या स्टेशन है वह या तो चम्बा है या फिर सिरमौर है। ऑलरेडी जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, जो ऑल इंडिया बैकवर्ड लिस्ट है उसमें फॉर्थ और फिफ्थ जगह पर आते हैं। Chamba is on fifth place and I think, Sirmaur is on seventh place. वहां पर इन्होंने इसको हैवन बना रखा है। सभी निकम्मे, भ्रष्ट, गए-गुजरे जो अधिकारी/कर्मचारी हैं उनको चम्बा भेज देते हैं। यह मैं अभी से नहीं देख रहा हूं। काफी सालों से देख रहा हूं। कैसे हिमाचल का उत्थान होगा जब हमारी मानसिकता

ही ऐसी है? काहे के लिए हम यहां पर बैठने के लिए आते हैं, घंटों सिर खफाते हैं और फिर चले जाते हैं। मैंने तीन चीज़ें कही कि हम अपने हिमाचल के बच्चों को

25.03.2015/1845/SS-JT/2

अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं करवा पायेंगे, हम उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पायेंगे, अच्छे रोडस और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पायेंगे तो हमारे यहां आकर बैठने का क्या फायदा? इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि हिमाचल सरकार को कोई ऐसी कठोर नीति बनानी चाहिए जिससे हम अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकें। भविष्य का ख्याल रखें। भविष्य को उत्तम बनाने का कैसे प्रयास कर सकते हैं उस पर विचार होना चाहिए। दूसरे, ये जो बदला-बदली, यह मेरा है, यह उसका है, उसको नहीं जाने देंगे, यह उचित नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि चार बच्चों के लिए चार-चार स्टाफ क्यों है क्योंकि कहीं पर मेरा ही हाथ होगा। मेरा आदमी है, मैंने पोस्ट किया है, इसको मत भेजें। भेजेंगे तो हम यह करेंगे। वह करेंगे तो फिर दूसरे स्कूल में लेकर आ जायेंगे। यह सब नहीं होना चाहिए। हमको भी इससे बचना चाहिए और ऐसी नीतियां हमको बनानी होंगी तभी हम हिमाचल का उत्थान कर सकते हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

25.03.2015/1850/केएस/जेटी/1

श्री बी.के. चौहान जारी----
तभी हम हिमाचल का उत्थान कर सकते हैं। मैं अपने मित्र कौल सिंह जी की तरफ एक बार फिर मुखातिफ होना चाहूंगा। कौल सिंह जी हालत इतनी दयनीय हो गई है कि हमारे एक पी.एच.सी. है on the roadside. आप आते-जाते रुकते भी होंगें और देखा भी होगा। वहां पर एक पी.एच.सी. है और वहां पर एक साल पहले दो डॉक्टर पोस्ट हुए थे। I was very happy. हमने कहा कमाल कर दिया ठाकुर साहब ने दोस्ती निभाई है। परन्तु हफ्ता-दस दिन के बाद उनका चम्बा में डैपुटेशन हो गया। वहां पर दो क्लास-iv भी है मैंने कहा कि ठीक है नर्सों का काम वे भी कर लेंगी आप विश्वास नहीं करेंगें when I went last to that place, only those two class IV were there and doctors were not there. डॉक्टर नदारद थे। They had

vanished. मैंने कहा कि क्या हुआ तो मुझे बताया गया कि चम्बा को डिप्यूट हो गए। मैंने उसी वक्त सी.एम.ओ. को फोन किया कि यह क्या है और वहां पर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए कि यहां दवाइयां तो चैक करो, डॉक्टरों के अभाव में सारी दवाइयां एक्सपायर हो गई है । सारी दवाइयां अलमारी में पड़ी-पड़ी सड़ गई। जब मैंने यह कहा कि एक डॉक्टर तो यहां रख लेते दोनों को क्यों डिप्यूट कर दिया। सी.एम.ओ. कहते हैं कि यहां तो इतना रश है, मुझे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलाना ही मुश्किल हो जाएगा, लोग मुझे मार देंगें । एक तो पहले ही वहां पर स्पैशेलिस्ट नहीं है, एनेस्थिसिया का डॉक्टर नहीं है । वहां पर सर्जन भी नहीं है जिसकी बात मेरे सहयोगी कह रहे थे कि टांडा में जा कर रैफर करवाया और तब एम्ज़ में भर्ती करवाया। यह हालत है तो इन दो-तीन महत्वपूर्ण विषयों के बारे में मैं यहां पर बात करना चाहता था।

25.03.2015/1850/केएस/जेटी/2

सभापति महोदया, मैं रोड़ नैटवर्क के बारे में बात करना चाहूंगा। आप भी चम्बा हर हफ्ते जाती है। यहां से जब हम चम्बा पहुंच जाते हैं या चम्बा से यहां पहुंच जाते हैं तो कमर इतने दुखने लगती है कि इससे अच्छा तो यह टूट ही जाए और हम एक-दो महीना लेटे रहें। इतनी हालत खराब हो जाती है। जिस तरह से प्रदेश में हो रहा है. I think, I should quit. यह कूढ़न ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती । तो ऐसा है कि मैं नाम क्या गिनाऊं आपको भी पता है कि चम्बा-पठानकोट हाईवे का क्या हाल है हमको तो सारे हिमाचल की सड़कों से हो कर जाना पड़ता है, कांगड़ा और हमीरपुर की सारी सड़कों से हो कर हमें चम्बा पहुंचना पड़ता है। बुरी हालत है। The road network is totally in a dilapidated condition. आपको तो यह सब मालूम ही है। तो उस पर क्यों काम नहीं होता। बजट तो काफी रखा जाता है, पिछले बजट में भी रोड़ नैटवर्क के लिए काफी प्रावधान रखा गया था तो वह कहां गया? इस साल भी काफी प्रावधान रखा है इससे काम होगा या यह पैसा भी ऐसे ही चला जाएगा या खर्च होगा, इसको कौन सुनिश्चित करेगा? पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों की तो दशा ही खराब है। मेरे दो रोड़ज़ के सैकिण्ड फेज़ का पैसा आया पड़ा है लेकिन उसके टैंडर ही नहीं हो रहे हैं। मैंने दो-तीन बार चीफ इंजीनियर से पूछा वो कहता है कि कोई टैंडर ही नहीं डालता। तो यह तो अजीब बात है कि टैंडर वाला ही नहीं आ रहा है। रोड़ नैटवर्क को सुधारना बहुत आवश्यक है।

25.03.2015/1850/केएस/जेटी/3

सभापतिः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप कीजिए।

श्री बी.के.चौहानः सभापति महोदया ,बाली जी चले गए । बसे बन्द हो गई है । पहले जो थोड़ी-बहुत सुविधा थी स्कूल जाने की बच्चों को उनमें उन्होंने स्कूल जाना बन्द कर दिया है । रोड़ज़ की हालत बहुत खराब है और बसों की हालत बहुत खराब है।

श्रीमती अ0व0द्वारा जारी---

25.3.2015/1855/ag/av/1

श्री बी.के.चौहान जारी-------
और बसों इत्यादि की हालत बहुत खराब है। कुछ नहीं कह सकते कि इस हिमाचल प्रदेश का उत्थान और विकास कैसे हो पायेगा।

श्रीमती आशा कुमारी ,सभापतिः माननीय सदस्य, कृपया बाईंड-अप कीजिए।

श्री बी.के.चौहान : मैडम, बस एक मिनट। मैं एक बात बिजली विभाग की कहना चाहूंगा। मैडम, आपको तो पता है कि हिमाचल प्रदेश, खासकर चम्बा में कितने हाइडल प्रोजैक्ट्स लगे हैं। मैंने इस बारे में एक प्रश्न किया था जिसके चौंकाने वाले तथ्य आए थे। अभी यहां पर सुजान सिंह जी नहीं बैठे हैं। मैंने यह प्रश्न किया था कि चम्बा में कितने प्रोजैक्ट्स लगे हैं और उनसे बिजली का कितना उत्पादन होता है। उत्तर में बताया गया कि 14222 मीलियन युनिट्स का प्रति दिन उत्पादन होता है। आमदनी के बारे में बताया गया कि एक फाइनैंशियल ईयर में 16,22,15086 रुपये होती है। मैंने यह भी पूछा था कि इसमें से हमारे चम्बा जिला के विकास में कितना हिस्सा जाता है तो बताया गया कि लगभग 9 करोड़ रुपये की राशि जाती है। वहां पर इतने प्रोजैक्ट्स लगे हुए हैं और उनसे इतनी मैगावाट बिजली पैदा होती है। उनसे इनको सालाना अरबों रुपये की इनकम हो रही है और जहां ये प्रोजैक्ट्स लगे हुए हैं उनको सिर्फ 9 करोड़ रुपये की राशि जा रही है। मुझे समझ नहीं आता कि इसके लिए क्या मापदण्ड रखे हुए हैं। राज्य सरकार ने इसकी तहकीकात क्यों नहीं

की है? चम्बा बैकवर्ड रहेगा औ चम्बा में ही बिजली नहीं होगी तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। अभी पीछे विंटर में वहां दो-दो, तीन-तीन दिन तक बिजली बंद रही। चम्बा से कहां-कहां तक बिजली जाती है?

श्रीमती आशा कुमारी ,सभापतिः माननीय सदस्य, प्लीज बाईंड-अप कीजिए। अब हाउस का टाइम भी खत्म हो गया है।

25.3.2015/1855/ag/av/2

श्री बी.के.चौहान : मैडम, चलो, कम-से-कम आपने तो मेरी भावनाओं को जाना। मैं यह चाहता हूं कि आप भी जब यहां पर अपने विचार रखेंगी तो चम्बा जिला को ध्यान में रखते हुए अपनी बातें कहेंगी। बाकी पार्टी-वार्टी की बातें तो चलती रहती है। यहां पर जो मेरे मंत्रिगण दोस्त बैठे हैं उनसे मैं चाहूंगा कि चम्बा जिला की तरफ ध्यान दें। चम्बा और सिरमौर को अति बैकवर्ड बनाने का प्रयास न करें। इसको नालायकों का, भ्रष्टों का तथा अधिकारियों का डम्पिंग ग्राउंड बनाने का प्रयास न करें। इसको पनिशमैंट स्टेशन केटेगरी से हटाइए। पहले लाहौल-स्पिति और पांगी होते थे और अब चम्बा तथा भरमौर है। इसी वजह से वहां की दशा खराब हो गई है। अब पता नहीं बाकी बचे ढाई वर्षों में आप कहां-से-कहां पहुंचा देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मगर आपके बजट का घोर विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती आशा कुमारी ,सभापतिः मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहती हूं कि हाउस का जो समय बढ़ाया था वह पूरा हो चुका है। अभी 11 माननीय सदस्य शेष बचते हैं जिन्होंने चर्चा में भाग लेना है। आप सबकी इजाजत हो तो इसको एक घंटा और बढ़ा दिया जाए। (---व्यवधान---) कल नहीं है, आज ही है। आज लास्ट है। इस माननीय सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया जाता है।

(मान्य सदन का समय 8.00 बजे अपराह्न तक बढ़ाया गया।)

Health & Family Welfare Minister: Madam, Chairperson, Shri B.K. Chauhan has raised some important issues. He has specifically said that

Government is not caring for District Chamba as well as District Sirmmour. Both the districts are at

25.3.2015/1855/ag/av/3

our top priority. That is why this Government has taken a decision to open one medical college at Chamba and second medical college at Sirmour at Nahan. He has also mentioned about Dada, PHC. There were two doctors and both the doctors have been deputed by CMO to Regional Hospital, Chamba. I will direct the CMO that at least try to post one doctor whether he is MO/AMO in every Primary Health Centre. Of course, I have admitted and I still admit that there is shortage of doctors in the State and shortage of para-medical staff. Government is trying to do its best and it is because of the previous Government's wrong policy that every institution was opened but post was not created. That is why we are facing this problem and we are trying to get rid of this problem.

Concluded

Continued by BJN in Hindi

25.03.2015/1900/negi/ag/1

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के अंग्रेजी के पश्चात..

सभापतिः माननीय सदस्य, श्री बी.के. चौहान जी कुछ पूछना चाह रहे हैं।

श्री बी.के. चौहानः जो मैडिकल कॉलेज चम्बा के लिए दिया है इसका मैं धन्यवाद करता हूं, केन्द्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसके बारे में टंग ऑफ वार प्लेस के बारे में शुरू हुई कि बनौता में बनेगा, भेडू फार्म में बनेगा, यहां बनेगा और वहां बनेगा। मैडम, आपको मालूम है कि मैडिकल कॉलेज जहां बनता है वहां पर कम से कम 200-300 पेशेन्ट्स का हॉस्पिटल भी होना चाहिए और वहां स्पैशलिस्ट भी होने चाहिए। जहां ये सब हो वहीं मैडिकल कॉलेज इस्टेबलिश होता है। अब बनौता 15-20 किलोमीटर दूर है। जहां पर इन्होंने स्थल की बात की, कल भी बात कर रहे

थे कि वहां पर 100 बीघा लैंड है। वह फोरेस्ट की लैंड है और वहां पर नर्सरी कई सालों से लगी हुई है। वह जगह सुटेबल नहीं है क्योंकि वहां पर 300-400 बेडज़ का हॉस्पिटल बनाने के लिए भी जगह नही है। वह उपयुक्त नही है।

सभापति (श्रीमती आशा कुमारी) : माननीय सदस्य ,जो मैडिकल कॉलेज चम्बा में बन रहा है वह भेडू फार्म में बन रहा है न कि बनौता में ।

श्री बी.के. चौहानः भेडू फार्म की लैंड मैडम आपको मालूम होगा कि पॉलिटैक्नीक बनने के बाद जो रिमेनिरंग पोर्शन है ,यह मेरे टाईम में यह हुआ था और उसका उदघाटन भी माननीय धूमल जी ने किया था और उसके साथ वाली जो लैंड है जहां यह मैडिकल कॉलेज वाली बात है, वह ज़मीन भारत सरकार को स्थानान्तरण हो गई है। मिनिस्टरी ऑफ टैक्निकल एजुकेशन को ट्रांसफर हो गई है। वहां पर बॉयज होस्टल, गर्ल्ज होस्टल and other things are coming up. उसका पैसा सब मंजूर हो गया है और उसको पॉलिटैक्निक कॉलेज से अलग नहीं किया जा सकता है। एक और भेडू फार्म है जो चम्बा से 12-13 किलोमीटर आगे है भरमौर रोड पर, जो सबसे पहला भेडू फार्म था उसका पूरा परिसर वहां पर खाली पड़ा हुआ है। उसके सामने एन.एच.पी.सी. का ऑफिस है प्रोजक्ट-II का । वहां पर जगह बहुत है और वहां

25.03.2015/1900/negi/ag/2

हॉस्पिटल भी बन सकता है और मैडिकल कॉलेज भी बन सकता है। उसको देख लें क्योंकि और जगह चम्बा में मेरे नज़र में नहीं है।

सभापति (श्रीमती आशा कुमारी)ः माननीय सदस्य, मेरी सूचना के मुताबिक मैडिकल कॉलेज की लैंड हेल्थ डिपार्टमैन्ट को ट्रांसफर हो चुकी है।
अब माननीय सदस्य, श्री कर्ण सिंह जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

25.03.2015/1900/negi/ag/3

श्री कर्ण सिंहः धन्यवाद सभापति जी। इस वर्ष जो बजट माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस मान्य सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदया, I assure you that I will not take long and waste the valuable time of this august House. I will be precise and speak to the point only. जो सत्य है मैं वही बोलूंगा ।। won't repeat anything. मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे मेरे टीचर के बाद बोलने का मौका सभापति महोदया ने दिया। He has taught me Geography. ___(व्यवधान) ...अभी तक बुजुर्ग नही हुए हैं। Let me speak about the Budget, as I said I will speak to the point. मैं कोई मक्खन लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं।। don't believe in buttering nor I do it. जो सत्यता है वह सत्यता है। यह बजट मैं समझता हूं, आप जो भी समझे, आम आदमी की भलाई के लिए है और प्रदेश की जनता की भलाई के लिए है। It covers every field. जहां तक हमारे मुख्य मंत्री, राजा वीरभद्र सिंह जी का प्रश्न है, मैं इतना कहना चाहूंगा कि काम करने की अलग-अलग क्षमता होती है लेकिन विजन होना चाहिए। And He is a man with vision, experiment and experience. He has planning for present and future vision, especially coordination with the Ministers, Hon'ble MLAs from here and there, bureaucracy . . . .

श्री ए.जी./श्रीमती यू.के.द्वारा जारी..

25.03.2015/1905/यूके/1

श्री कर्ण सिंह-- जारी---
अधिकारी है और जो प्रदेश की जो जनता का उनके साथ प्रेम है, that is the reason कि छक्का ऐसे ही नहीं लगा । सातवां भी लगेगा । My best wishes. He started his political career at early age of 26. First MP and first Prime Minister, Pt. Jawahar Lal Nehruji, from there he started serving the people from Parliament then Himachal and still carrying on. आपने शायद पिक्चर देखी होगी, मुझे पिक्चर देखने का शौक नहीं है । एक पिक्चर आयी थी "मुन्ना भाई लगे रहो" तो मैं यह कहना चाहता हूं कि राजा साहब, आप लगे रहो, जनता आपके

साथ है और आगे भी साथ रहेगी । जिस प्रकार से आपने बजट प्रि- प्लानिंग के साथ दिशा देते हुए पेश किया है, it is a very good Budget. जहां तक मेरा प्रश्न है, । started my political life from this very House in 1990. मैं फिर कह रहा हूं कि मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूं, पहली बार आफ्टर लाँग टाईम मैने एक अच्छा बजट देखा । हर साल की बात कर रहा हूं, हर व्यक्ति का काम करने का अपना एक तरीका होता है । सभी प्रदेश की भलाई चाहते हैं, सरकारें आती हैं, जाती हैं, मुख्य मंत्री आते हैं और जाते हैं । लेकिन काम करने का उनका अलग-अलग तरीका होता है । चाहे मुख्य मंत्री हों, मंत्री हों या हम विधायक हों, अपना-अपना तरीका है । काम करते-करते गलतियां भी होती हैं । मैं क्रिकेट का शौकीन भी हूं और आजकल क्रिकेट का मौसम भी चला हुआ है । कल सबको जल्दी होगी क्योंकि कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमी-फाईनल होने जा रहा है । आप इसकी कमेंट्री भी देखते होंगे । हम इंडिया के साथ हैं क्योंकि हम

25.03.2015/1905/यूके/2

भारतीय हैं । आपने हमारे स्पिनर देखे होंगे, कई रिटायर भी हो गए हैं । भज्जी भाई, अभी तो दूसरा फैंका है, तीसरा भी फैंकेंगे इसी तरह से यहां पर भी फिर सातवीं बार भी हमारी सरकार आ जायेगी । यह सब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं सरकार में बैठा हूं, मुख्य मंत्री की मैने सिफ तारीफ ही करनी है । मक्खन लगाऊंगा, ऐसा नहीं । जो सत्यता है वह कह रहा हूं । मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई आशा ले कर बैठा हूं कि मुझे कुछ पुरुस्कार मिले । मेरा काम है जनता की सेवा करना I do not believe in pin-pointing anybody. Let me talk. I don't interrupt nor I like to be interrupted. Kindly let me speak. हाथ जोड़ कर आपसे प्रार्थना है । मैं जो कुछ कह रहा हूं this is straight from my heart and true. मैं साथ में धन्यवाद करना चाहूंगा कि जहां इतना अच्छा बजट मिला है । वहां हम केन्द्रीय सरकार को भी नहीं भूल सकते, मोदी जी को । लेकिन इसके लिए मान्यवर मुख्य मंत्री, हमारे मुख्य सचिव, फाईनैंस सेक्रेटरी तथा उनकी पूरी टीम, जिस तरीके से इन्होंने अपना पक्ष रखा और मोदी जी के लिए भी यह प्रदेश नया नहीं है । हम उनका धन्यवाद करते हैं । जिस प्रकार से जम्मू-कश्मीर के लिए उन्होंने सेवा की उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश का भी ध्यान रखा । जो सही है, वह सही है । We appreciate what is done. अच्छा होमवर्क करोगे ता प्वाइंट भी उसी हिसाब

से मिलते हैं Our CM and bureaucracy did a good homework and we got the reward for that. जैसा मैने शुरू में कहा I do not believe in counter attack. Everybody has a right

25.03.2015/1905/यूके/3

to speak their own views. जहां तक मैने देखा है मुख्य मंत्री महोदय भी पर्सनल नहीं जाते । पार्टी से परे हट कर सब की सुनते हैं । अब कभी-कभी कहासुनी हो जाती है वह अलग बात है । (घंटी) .जब कोई विधायक बनता है ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

25.03.2015/1910/sls-jt-1

श्री कर्ण सिंह...जारी
तो वह सबका विधायक है। He has to serve everybody. एम.एल.ए. बना है तो जिसने वोट दिए हैं उसके काम करने हैं और जिसने नहीं दिए हैं, उसके काम भी करने हैं। MLA is MLA. अब जो आपकी ड्यूटि है, थोड़ी-बहुत मिर्ची तो आपने लगानी ही है that is part of your game. So, I don't think about it.

मैं ज्यादा समय न लेता हुआ, अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ बातें कहना चाहता हूं। । don't repeat anything. जैसे चम्बा की बात कर लें ,चौहार की बात कर लें, आनी की कर लें, सिराज की बात कर लें; ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। जो डीलिमिटेशन हुई, उससे कुल्लू जिला ज्यादा प्रभावित हुआ जैसे और जिले भी हुए हैं। जो आनी की तीन कोठी है ,सांबयाली थी और गाड़ा गशैणी का क्षेत्र जो जय राम जी का था ,वह मेरे साथ बंजार में आ गया। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि डीलिमिटेशन के कारण पहला तोहफा हमें कॉलेज मिला, 3 प्लस टू स्कूल मिले, 3 हाई स्कूल, 3 मिडल स्कूल और एक प्राईमरी स्कूल मिला। वैटरिनरी डिसपैंसरीज की आपके समय में शुरुआत हुई थी। हर पंचायत में डिसपैंसरीज खुलनी हैं। लारजी में हमने सब्जी मण्डी खोली थी लेकिन वह वर्षों बंद रही। हमारी सरकार ने आते ही सब्जी मण्डी को चालू कर दिया। सड़क की बुरी हालत थी। सैंज से लारजी तक की

सड़क की ऐसी हालत थी कि मण्डी जल्दी पहुंच जाते थे ,यह फैक्ट है लेकिन औट पहुंचने में ज्यादा समय लगता था। अब सड़क बढ़िया बन गई है। बंजार के बाई पास और सबसे बड़ी बात टनल की है। उसके साथ नेशनल हाईवे बंजार होकर आएगा। सयान आनी से होता हुआ, सोजा से होता हुआ औट तक आएगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं; हम सब धार्मिक लोग हैं लकिन हमारे यहां देवताओं के प्रति हमारे विशेष नियम हैं। जो पुरानी सड़क औट से लेकर लारजी तक थी, ...(व्यवधान)... जो पुरानी सड़क थी, टनल नहीं है It is a death trap, rejected by the Army also. पता नहीं किसकी ऐसी सोच थी जो वह बनाया गया। (Bell) I will just take ten

25.03.2015/1910/sls-jt-2

minutes. पिछली बार, क्योंकि देवी तक तो दशहरा में जाते ही थे इसलिए टनल के बीच में से नहीं जाते थे बल्कि पानी के बीच में से जाते थे। हमने अनुरोध किया और मुख्य मंत्री जी ने तुरंत आदेश दिए। उस सड़क को मोटरेबल बनाया गया है और अब उसको ऊंचा किया जाएगा ताकि बाई पास से, उधर से ही जाएं। सैंज में जो आर . आर. प्लॉन की बात हुई, वहां सैटलमैंट की बात थी। पहली बार हुआ कि 18 लोगों को रैगुलर नौकरी मिली तथा और 68 लोगों को मिलने जा रही है। जो कमी रह गई है, एस.डी.एम. और डी.सी. मिल कर कर रहे हैं। उनको आदेश दिए गए हैं कि आगे दो महीनों के अंदर सारे केसिज को रिवियु किया जाए और आर. आर. प्लान के तहत जो भी है ,उनका नुकसान पूरा किया जाए।

फॉयर स्टेशन एक बड़ी अचीवमैंट है। पीछे जब मैं दस साल छुट्टी से पहले एम.एल.ए. रहा, मेरी तमन्ना थी कि बंजार में अग्निशमन केंद्र खुले। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आदेश दे दिए हैं और अश्योंरैंस दी है कि अब बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। हम सरकार को और वन विभाग को बधाई भी देना चाहेंगे। भरमौरी जी यहां पर हैं नहीं। हमारे सैंज एरिया में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है which is now world heritage. बहुत बड़ी लंबी जगह है और प्राचीन जगह है। वहां तीन गांव पड़ते हैं - सुगाड़, साकती और मरौड़। डैम बनने से वहां पहले 24 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। अब फिर भी 14 किलोमीटर चलना पड़ता है। All over the world ऐसे पार्क, जहां पर ज्वाय इवैंट्स होती हैं,

जीप में राईड देते है, एलीफैंट्स पर राईड होती हैं, टूरिस्ट जो जाता है वह वहां खुद जानवर देखता है। मैं 1990 से जा रहा हूं ...(व्यवधान)...

सभापति : माननीय सदस्य, please wind-up.

श्री कर्ण सिंह : मैंने तो अभी शुरू ही किया है जबकि बाकी को आधा-आधा घंटा दिया गया है। मैंने तो अभी शुरू ही किया है।...(व्यवधान)...

सभापतिः माननीय सदस्य, आपको मालूम है...(व्यवधान)...

25.03.2015/1910/sls-jt-3

श्री कर्ण सिंह : मैंने तो अभी शुरू ही किया है? I will not speak less.

Chairman: No, please wind-up otherwise I will have to call the next Speaker.

Shri Karan Singh: If you want I will sit down.

Chairman: Please wind-up your speech.

Shri Karan Singh: At least give me five minutes.

Chairman: I have no objection provided the House. . . . .

जारी... गर्ग जी

जारी..गर्ग जी

जो दूसरे बोलने वाले वक्ता हैं यदि वे अपना समय आपको दे दें, तो ठीक है।

Shri Karan Singh: Members have spoken for half an hour.

Chairman: No, no. There are ten more people to speak and there are only 50 minutes. So, it for you to decide. They won't speak. So, it is not for me to decide.

Shri Karan Singh: Why it is only for me. पता नहीं मेरे साथ ही क्यों अन्याय होता है? हर ओर से मेरे साथ ही अन्याय होता है। Why? मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं, इससे तो अच्छा मैं लिखकर ही दे देता। मेरे यहां कुछ मिडिल स्कूल हैं ,कुछ प्राथमिक स्कूल और हाई स्कूल हैं ,पी.एच.सी. हैं, सब-सैन्टर्ज भी बना दिए हैं। मैं यह सब लिखकर दे दूंगा। There is no point. I will give the names. लेकिन सभापति महोदया, मैं अन्त में पर्यटन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हम पर्यटन की बात करते हैं, बहुत कुछ है पर्यटन में। ट्रॉउट फिशिंग, नगरी में फिश फार्म बने हुए 10 साल से ज्यादा हो गया। It is not functioning. It is a tourist spot for angling. और लारजी में ,सबसे बड़ी बात हुई है, लेकिन कह रहे हैं कि अब समय नहीं है। वहां इतनी अच्छी झील है। It is most safe. वहां लारजी रैस्ट हॉऊस है ,वहां बोट हॉऊस बन सकता है ,वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं और उसमें फिशिंग हो सकती है तभी तो वहां पर्यटक आएंगे, हमें प्रकृति ने सब कुछ दिया है। कुल्लू-मनाली कहते हैं ,अच्छी बात है। वहां सब कुछ है। आप जानते हैं कि वहां विकास हुआ है। लेकिन उसके अलावा शोजा है, शांगन है और इस प्रकार के बहुत से इलाके हैं जहां पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। अब स्कूल कॉलेज के नाम की बात है यदि मैं न पढ़ू ,तो ठीक नहीं, जनता सुनना चाहती है ,अब मैं लिखकर दूं, तो क्या ठीक है?वैसे तो मैंने अभी बोला ही कुछ नहीं है।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त करें, otherwise I will have to call the next speaker.

Shri Karan Singh: Just one minute.

Chairperson: Half a second.

25/03/2015/1915/RG/JT2

श्री कर्ण सिंह : यदि मैं शिक्षा की बात करूं ,तो सैंज में कॉलेज ,शांगल, दियोरी, पलाईच, मंगलौर और मिडिल स्कूल नाजन, शिल, नाही ,टिन्दा, पजोही, नरैश, शीण ,मिडिल स्कूल भूपन, कलैहली, प्रोहाधा ,पेरचा ,पधरनी, कटौणा ,नरवाली, शटौगी ,न्यू प्राइमरी स्कूल ओटम, बछूट, टील ,छैछर ,बजौरा पी.एच.सी. , सी.एच.सी. सैंज में डॉक्टर की कमी, ये सब-सैन्टर्ज दियोठा ,बथोड़, बहु, लारजी न्यू सब-सैन्टर्ज दलाशनी ,दिम्रचारी, टिन्डर, रोपा, पलाईच। न्यू आयुर्वेदा उरसु में स्टाफ इत्यादि की कमी है। That is all. इससे शॉर्ट हो नहीं सकता था। जो आपने मुझे टाईम दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : धन्यवाद। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि सदन का समय हमने आठ बजे तक बढ़ाया है अर्थात हमारे पास 45 मिनट और हैं और अभी 10 सदस्य बोलने को हैं। अगर हम 10 सदस्यों से डिवाइड करें, तो हरेक तो साढ़ चार मिनट मिलते हैं। बाकी सदन की इच्छा है, यदि आप कहेंगे, तो मैं सदन को रात के 12.00 बजे तक भी ऐक्सटैंड कर दूंगी।

अब माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगबे।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : सभापति महोदया, इस प्रदेश का वर्ष 2015-16 का बजट इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। सभापति महोदया, इस बजट को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि 18साल में 18वीं बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है ,लेकिन इस बजट में किसी भी प्रकार की सूझबूझ या प्रदेश को कोई दिशा ,कोई नीति ऐसी कोई भी बात कहीं भी नजर नहीं आती। हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए यह बजट दिशाहीन है और कोई सोच प्रदान नहीं करने वाला और प्रदेश के हर वर्ग को चुभने वाला ऐसा बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में रखा है। एक बात पर विशेष चर्चा यहां पर रही कि माननीय मुख्य मंत्री

जी ने कहा कि पहले योजना आयोग के द्वारा फण्डिंग होती थी और अब यह नीति आयोग बना है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग का सदस्य तो मैं भी हूं। लेकिन अभी तक मुझे भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि नीति आयोग क्या है? दुर्भाग्य इस बात का है कि नीति आयोग का एक जनवरी, 2015 को इस देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने गठन किया।-----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

25/03/2015/1920/MS/AG/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जारी--------

दुर्भाग्य इस बात का है कि नीति आयोग का एक जनवरी, 2015 को इस देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने गठन किया है। लगभग पिछले 60 सालों से योजना आयोग चल रहा था। यह योजना आयोग एक सफेद हाथी के रूप में काम कर रहा था और देश के लिए एक आवश्यकता यह थी कि कुछ परिवर्तन हो, कुछ नयापन आए, कुछ तेज गति से हम आगे बढ़े। इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने नेशनल इंन्स्टीच्यूशन फॉर ट्रांसफोर्मिंग इंडिया, यह कहा कि नीति आयोग बनेगा। जिसके चैयरमैन प्रधानमंत्री होंगे और प्रदेशों के मुख्य मंत्री उसके सदस्य रहेंगे। पहले योजना आयोग जो निश्चित करता था, वही प्रदेशों को मानना पड़ता था। आज प्रातः मुख्य मंत्री जी ने स्वयं यहां खड़े होकर कहा कि नीति आयोग की मीटिंग में जाकरके मुझे भी प्रदेश के संबंध में बोलने का मौका मिला। ऐसा मौका योजना आयोग के समय में नहीं मिलता था ,जैसा प्रधानमंत्री जी ने मौका दिया है। जब एन0डी0ए0 की सरकार थी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जमाना था तो वह हिमाचल प्रदेश में आते रहते थे। वह छः वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहे। देश का इतिहास गवाह है कि कभी कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं रहे जिन्होंने छः वर्षों में एक साल में कम से कम 10 दिनों तक प्रधानमंत्री कार्यालय मनाली के प्रीणी से चलाया हो। यह हिमाचल के लोगों के लिए गौरव की बात है। वह जब भी हिमाचल आते थे तो आते हुए कहते थे कि 100 करोड़ दे दिया, 200 करोड़ दे दिया या 500 करोड़ दे दिया लेकिन जाते-जाते फिर से कहते थे कि जाते हुए तुम्हें क्या चाहिए। एक समय जब प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो इनकी झोली वह भरकर जाते थे। यहां तक कि वीरभद्र सिंह जी जब प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो यह भी पूरी

केबिनेट के साथ मनाली के प्रीणी में गए थे और इनको भी उन्होंने खाली हाथ नहीं लौटाया बल्कि पैकेज के साथ झोली भरकर लौटाया। यह अटल जी का हिमाचल के प्रति प्रेम था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वर्तमान वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान देने के लिए जो उनके नाम पर हिमाचल में योजनाएं चलाई थीं, उनके ही नाम हटाने शुरू कर दिए। लेकिन तब भी

25/03/2015/1920/MS/AG/2

देश और दुनिया का इतिहास गवाह है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न प्राप्त हुआ है। भारत रत्न 27 तारीख को देश के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी श्रद्धेय अटल जी के घर पर जाकर उनको देने वाले हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी वजह से भारत का शीश दुनिया के सामने गौरव से खड़ा हुआ है। अमरीका में रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया गया है। क्या नेपाल, क्या भूटान बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतें चीन और जापान को यह बता दिया कि भारत माता कहीं पर झुकने वाली नहीं है। हमारा माथा सबसे उन्नत है। यह गौरव अगर किसी ने बढ़ाया है तो श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बढ़ाया है। मित्रों ,मैं एक बात कहूंगा कि-

राज तो हमारा हर जगह पर है,
पसन्द करने वालों के दिल में ,
और न पसन्द करने वालों के दिमाग में भी है।
कुछ भी सोचो लेकिन है जमाना ,
नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का ।

आज हम जिस 13वें वित्तायोग की बात करते हैं। केन्द्र में यू0पी0ए0 की सरकार थी। यू0पी0ए0 सरकार के अनदेखेपन के कारण से हिमाचल प्रदेश का पक्ष नहीं सुना, जिसके परिणाम-स्वरूप पांच वर्षों में मु010, 725करोड़ रूपये का नुकसान हमें झेलना पड़ा है। जो आपका बजट डॉक्यूमैंट यहां पर आया है, इसमें स्वयं प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा है कि अध्यक्ष महोदय, हमने 14वें वित्तायोग के समक्ष अपने राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत किया,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

25.03.2015/1925/जेके/जेटी/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः-----जारी-------

अध्यक्ष महोदय, हमने 14वें वित्तायोग के समक्ष अपने राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत किया। हमें प्रसन्नता है कि हमारी चिन्ताओं और कठिनाइयों को ध्यान में रखा और हमें राजस्व घाटा अनुदान में समुचित वृद्धि दी। लेकिन उन्होंने कहा कि यह वृद्धि हम दे रहे हैं और हजारों करोड़ों रूपए से आपकी झोली भर रहे हैं लेकिन प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ठीक करना, प्रदेश में फिजूलखर्जी को रोकना यह काम प्रदेश का है। वित्तायोग ने बड़े जबरदस्त तरीके से झोली भर दी। ऐसे सारे वातावरण में और सभापति महोदय प्रदेश को जिस बात की उम्मीद थी वह आप लोग कर नहीं पाए। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पटर्यटन, ऊर्जा, उद्योग और इन हर क्षेत्र में विफलता से आपके कदम छू रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के अन्दर देखा जाए तो सड़कों की हालत इतनी खराब है कि जहां से भी जाओ, अब पर्यटन सीज़न प्रारम्भ होने वाला है, सेब सीजन प्रारम्भ होने वाला है। आप स्वारघाट नेशनल हाई वे-21 पर कदम रखो कदम रखते ही पर्यटक मनाली, रोहतांग तक क्या महसूस करेंगे इस सड़क की दुर्दशा आपने करके रख दी है? आज प्रदेश के अन्दर सिंचाई की योजनाएं, पीने के पानी की दशा और बिजली की समस्याएं जस की तस है। सभापति महोदय, कुल्लू जिला के साथ लगता लाहौल-स्पिति, पांगी, भरमौर इस सारे जिले के लिए केन्द्र की सरकार से हम बात करेंगे लेकिन प्रदेश की सरकार भी इस बात को करने के लिए तैयार हो। कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी कुल्लू जिला के लिए कोई बड़ा पैकेज नहीं दिया। श्रद्धेय प्रेम कुमार धूमल जी ने हमें पोलिटैक्निक कॉलेज भी दिया, टूरिज्म मैगा प्रोजैक्ट भी दिया, नवोदय भी दिया। लेकिन अब हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि कुल्लू जिला, लाहौल-स्पिति, पांगी और भरमौर के लिए हमें कुल्लू जिला में मेडिकल कॉलेज चाहिए। उस मेडिकल कॉलेज के साथ एक इंजीनियरिंग कॉलेज की भी आवश्यकता हमें है। कुल्लू-मनाली की जो लैफ्ट बेचिंज की जो सड़क है लगभी 45 किलोमीटर

25.03.2015/1925/जेके/जेटी/2

रामशीला से मनाली तक इस सड़क की डी.पी.आर. बनाने का काम सिर्फ धूमल जी के जमाने में प्रारम्भ हुआ था। इस सड़क की डी.पी.आर. तैयार हो और इसको सेन्ट्रल रिजर्व फंड के अन्तर्गत डाला जाए। सभापति महोदय, एक बात आज और दुर्भाग्य की है कि अभी कहा गया कि ये सरकार तिब्बती समुदाय के अवैध कब्जों को नियमित कर रही है। लेकिन जो लोग पर्यटन की दृष्टि से अनेक वर्षों से काम कर रहे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। मेरी मांग इस माननीय सदन के माध्यम से यह है कि उन सब गरीब लोगों के लिए भी सरकार पुनर्वास नीति लेकर आए। जहां तक रोप वे की बात है और एक रोप वे की बात यहां पर फिर से कही गई है। क्या वशिष्ट से रोहतांग तक रोप वे बनाएंगे । मुख्य मंत्री जी भूल गए होंगे पिछले साल इसी सदन में मुख्य मंत्री जी को मैंने प्रश्न किया था और उन्होंने यह कहा था कि वशिष्ट से रोहतांग का रोप वे नहीं बनेगा। कारण यह है कि उससे हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमने कहा वशिष्ट से रोहतांग रोप वे बनाने के बजाए पहले वशिष्ट से भृगु तक रोप वे बनें। कुल्लू से बिजली महादेव रोप वे बनें और अन्य डैस्टिनेशन को तैयार किया जाए। हम इस रोप वे का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं। जहां तक टूरिज्म की दृष्टि से जो मैगा प्रोजैक्ट स्वीकृत हुआ था और पर्यटन विभाग की नालायकी यहां तक है कि जो 33 करोड़ मैगा प्रोजैक्ट के लिए था उसमें जितने भी विकास कार्य थे उसमें किसी भी कार्य की डी.पी.आर. तैयार नहीं की है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि समय की कमी के कारण से इस बजट का मैं विरोध करता हूं। इसके विरोध में मैंने अपनी बात कही है लेकिन एक बात यह है कि जो हम यहां पर विधायक बैठे हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

25.03.2015/1930/SS-JT/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर क्रमागतः

विधायक निधि 50 लाख से 70 लाख रुपये की उसके लिए धन्यवाद। लेकिन यह निधि आज के समयानुसार जनहित में कम-से-कम एक करोड़ रुपये होनी चाहिए

थी। अगला निवेदन यह है कि जो हमारी डिस्क्रिशनरी ग्रांट है यह दो लाख से कम-से-कम 5 लाख रुपये होनी चाहिए।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त मैं एक और निवेदन आपके माध्यम से सरकार से करूंगा कि यह जो विधायिका यहां पर बैठी है अगर इस विधायिका को और अच्छी प्रकार से लोकतंत्र में काम करना है तो मुझे लगता है कि यहां की समिति के माध्यम से जो सरकार को प्रेषित किया जायेगा उन सुविधाओं को निश्चित रूप से विधायकों को प्रदान करना चाहिए। उसके लिए एक सराहनीय कदम सरकार को उठाना चाहिए। केन्द्र की सरकार ने हमारे प्रदेश का जो हिस्सा है वह 32 परसैंट से 42 परसैंट तक बढ़ाया और हर प्रकार से हमारी झोली को भरा है।

सभापति महोदया, यह मेरी अंतिम बात है। मैं छोटी-सी लाइनें पढ़कर अपनी बात समाप्त करूंगा और इस बजट का विरोध करूंगा।

"छोटी-सी ज़िन्दगी है हर बात में खुश रहो,
छोटी-सी ज़िन्दगी है हर बात में खुश रहो,
जो चेहरा पास नहीं है, उसकी आवाज़ में खुश रहो,
कोई रूठा हो तुमसे, उसके इस अंदाज में भी खुश रहो,
कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो,
खुशियों का इंतजार किसलिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो,
क्यों तड़फते हो हर पल किसी के लिए, कभी तो अपने आप में खुश रहो,
छोटी-सी तो ज़िन्दगी है हर हाल में खुश रहो।"

सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

25.03.2015/1930/SS-JT/2

सभापतिः अब माननीय सदस्य, श्री इंद्र दत्त लखनपाल जी चर्चा में भाग लेंगे।
श्री इंद्र दत्त लखनपाल ,मुख्य संसदीय सचिव :सभापति महोदया, 18 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री, वीरभद्र सिंह जी ने लगातार तीन घंटे तक जो प्रदेश के लिए

यहां पर बजट प्रस्तुत किया, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले तीन दिनों से लगातार बजट के ऊपर यहां पर चर्चा हो रही है। आरोप-प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष की जो मानसिकता है वह केवलमात्र विरोध करने की है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने तीन घंटे दस मिनट के अंदर इस प्रदेश के हर वर्ग को जो लाभ देने की कोशिश की है उसमें विपक्ष ने मात्र आलोचना के सिवाय और कुछ नहीं कहा। इस बजट में एक झलक जो हमारा युवा आज के समय में भटक गया है उसको वापिस खेतों की ओर लाने के लिए जो इस बजट में प्रावधान किये गये हैं उसका इनको धन्यवाद करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया। आज पूरा देश जहां कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसी के चलते माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी इस प्रदेश के युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनकी आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए जो कृषि क्षेत्र में घोषणाएं की हैं ,वे लाजवाब हैं। उससे मैं निश्चित तौर पर समझता हूं कि प्रदेश के युवाओं को खेतों में काम करने का मौका मिलेगा और उनका जीवन-स्तर ऊंचा उठेगा। ऐसा मेरा मानना है। सबसे बड़ी बात जो प्रदेश में हमारी महिलाएं हैं उनको स्वावलम्बी बनाने के लिए उनके जन्म से लेकर मरण तक जो योजनाएं इस बजट के अंदर हैं उसका भी धन्यवाद किया जाना चाहिए था। 6वर्ष की आयु की कन्याओं के लिए सभी चिकित्सालयों में मुफ्त स्वास्थ्य लाभ देने की घोषणा की है। एक कन्या के बाद 35 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। दो कन्याओं के बाद 25 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की बात की है। हमारी महिलाओं और कन्याओं के लिए जो अनमोल बेटी की बात करते हैं वह एक बहुत बड़ी बात है। इसका धन्यवाद होना चाहिए था।

स्वरोजगार के लिए महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता ढाई हज़ार रुपये से बढ़ाकर पांच हज़ार रुपये की।

जारी श्रीमती के0एस0

25.03.2015/1935/केएस/एजी/1

मुख्य संसदीय सचिव, श्री इंद्र दत्त लखनपाल जारी---
स्वरोज़गार के लिए महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता ढाई हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये की और इसी के साथ जो बाल गृह में हमारी बच्चियां शिक्षा पूरी करती है, उनको इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में सभी सरकारी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा सरकार देगी इसका प्रावधान किया जाना चाहिए था । समाजिक पैंशन

जो हमारे बुजुर्गवान जो आज अपने आप को गांव में असहाय समझते हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार ने एक हजार से ग्यारह सौ रुपये का प्रावधान रखा सामाजिक सुरक्षा पैंशन में, उसका धन्यवाद किया जाना चाहिए था। महिलाओं के लिए जो सिलाई की मशीन खरीदने के लिए 1200 से बढ़ाकर 1800 रुपये किया उसका धन्यवाद किया जाना चाहिए था और जो हमारे छोटे कारोबारी लोग है, जो असंगठित हैं, उनको 8 लाख रुपये तक के उनके कारोबार में टैक्स में छूट देने की घोषणा की है।

सभापति महोदय, आज यहां पर अटल योजना के बारे में बात हुई जिसका नाम बदलने की बात विपक्ष ने की। शायद ये भूल गए कि अटल योजना का नाम भी आप लोगों ने ही रखा था। केन्द्र सरकार ने कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं की थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपैयी जी का नाम न हो हम भी उनका सम्मान करते हैं, वे हमारे प्रधान मंत्री रहे हैं। योजना केन्द्र सरकार की और यहां पर धर्माणी जी ने बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की कि सैंटर गवर्नमैंट का जो बजट होता है उसका प्रभाव प्रदेश सरकार पर पड़ता है, प्रदेश के बजट पर पड़ता है और हमारा पहाड़ी प्रदेश होने के नाते जो 90 प्रतिशत अनुदान हमें मिलता है और नीति आयोग की यहां

25.03.2015/1935/केएस/एजी/2

पर बात की गई, 40 हजार करोड़ रुपये, 14वें वित्तायोग की बात की गई, ठीक है वह हमें मिला लेकिन जो हमें और मिलना चाहिए था, उसमें जो कटौती की गई है, उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए थी। यदि वे देंगें तो हम धन्यवाद जरूर करेंगें क्योंकि आज भी इस प्रदेश का जोअस्तित्व है, हमें डॉ0 वाई.एस. परमार जी का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने इस प्रदेश की संरचना की। धन्यवाद करना चाहिए स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जिन्होंने इस प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। उस समय तो आप लोग स्टेट हुड मारो ठुड का नारा दिया करते थे और आज कहते हैं कि प्रदेश का सम्पूर्ण विकास हमने ही किया है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आज ये जन-धन योजना की बात करते हैं किसने अधिकार दिया? पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की देन है इस प्रदेश के अंदर जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया उसकी वजह से आज जन-धन योजना की बात की जा रही है। इसी प्रकार से आज विपक्ष के साथ कह रहे थे कि प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी

जी ने पूरे विश्व के अंदर हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है। ऐसा नहीं है। जितने भी इस देश में प्रधानमंत्री रहें, उनको विदेश जाने का मौका मिला और उन्होंने अपनी बात इस देश के लिए जोरदार ढंग से रखी और इस देश ने अगर तरक्की की है तो उसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है।

सभापति महोदय, मनरेगा के बारे में जब प्रधान मंत्री जी ने बयान दिया था, देश की संसद को सम्बोधित करते हुए कि मनरेगा के जो गड्ढे कांग्रेस सरकार ने खोदे हैं उनको मैं समृति चिन्ह बनाकर रखूंगा उन्हें

25.03.2015/1935/केएस/एजी/3

मैं बन्द नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री महोदय यह वह मनरेगा है जिससे देश के अंदर महिलाओं को स्वावलम्बी बनने का मौका मिला, उनके हाथों में पैसा गया है। वे इसको बन्द कर ही नहीं सकते। उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वे मनरेगा की स्कीम को बन्द करें क्योंकि इससे आम जनता जुड़ी हुई है, आम महिलाएं जुड़ी हुई है, गांव का गरीब किसान इससे जुड़ा हुआ है , बेरोज़गार जुड़ा हुआ है । एक मात्र शब्दों के जाल में कि 15 लाख रुपये आपके खाते में आ जाएंगें ,कुछ नहीं आया। आपके अमित शाह जी जो आपके अध्यक्ष हैं, दिल्ली के चुनाव थे, उन्होंने बयान दिया कि यह तो चुनावी जुमला था। वह सब जुमले बन गए। उधार के एम.पी. आपने ले लिए लेकिन आज जो देश के अंदर परिस्थितियां है, मंहगाई वहीं की वहीं खड़ी है, बेरोज़गारी वहीं की वहीं खड़ी है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा--

25.3.2015/1940/ag/av/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जारी ----------
महंगाई वैसी-की-वैसी खड़ी है। बेरोजगारी वहीं-की-वहीं खड़ी है। भाषण में बड़े जोर-शोर से कहा था कि नौकरियां देंगे। नौकरियां एक साल के बंद, अगले साल भी नहीं खुल पायेगी। व्यापारी घरानों को जो लाभ देने की चेष्टा की गई है वह आप सबके सामने है। गरीबों के लिए कोई योजना नहीं है। भूमि अधिग्रहण बिल से साफ जाहिर होता है कि केवल व्यापारी तबके को लाभ देने की कोशिश की गई है। आधार

कार्ड लिंकिंग के लिए विपक्ष ने पूरे देश के अंदर जो हो-हल्ला मचाया था वह सबको ज्ञात है। आज वे उस आधार कार्ड को हर जगह लिंक करने की बात करते हैं। यह दो तरह का चरित्र ठीक नहीं है। एफ.डी.आई. का विरोध सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, आज एफ. डी.आई. के माध्यम से क्या हो रहा है, यह आप सबके सामने है। सारी-की-सारी स्कीमें जो यू.पी.ए. सरकार ने इस देश की तरक्की के लिए लाई थी आज वही स्कीमें केंद्र सरकार चला रही है। पंचायती राज में संशोधन किसने किए थे? इस देश में आई.टी.यू. कौन लाया था, सबको मालूम है। इस देश के अंदर हरितक्रान्ति कौन लाया था, यह भी सबको मालूम है। आज यदि इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो जितना भी विकास इस देश या प्रदेश में हुआ है, वह कांग्रेस पार्टी की देन है।

इस बजट के अंदर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने चाहे वह किसान है या बागवान है, युवा है, महिलाएं हैं; उन्होंने हर तबके को कुछ-न-कुछ देने की कोशिश की है और दिया भी है। 5 हजार शिक्षकों को जो अनुबंध के आधार पर अपना कार्यभार सम्भाले हुए थे उनको नियमित करने का मौका दिया। जो अंशकालीन जलवाहक थे उनको डेलीवेजिज में बदलने की घोषणा की गई। हमारी जो 5 हजार के करीब फंक्शनल पोस्टें हैं उनको भरने की कोशिश की है। आपने पिछले वर्ष भी देखा है। चाहे पुलिस का विभाग हो, होम गार्ड का विभाग हो, चाहे इलैक्ट्रिसिटी में फंक्शनल पोस्टों को भरने की बात हो; हर क्षेत्र में पदोन्नतियां दी गई। इन दो वर्षों के अंदर क्या-क्या नहीं हुआ? आपने पिछले 5 वर्षों में जो किया है उससे

25.3.2015/1940/ag/av/2

दोगुना-तीन गुना हमारी सरकार ने इन दो वर्षों में कर दिया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सबसे बड़ी बात यह की है कि इन्होंने प्रदेश में ऊपर-नीचे की खाई को तोड़ा। मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रदेश में दौरा करके हर क्षेत्र में कुछ-न-कुछ दिया है। चाहे वह स्कूलों की बात हो, अस्पतालों की बात हो, सब डिविजन की बात हो, आई.पी.एच. विभाग की बात हो या लोक निर्माण विभाग की बात हो; हर क्षेत्र में करोड़ों रुपये की सौगातें दी हैं। इन सब बातों से साफ जाहिर होता है कि वीरभद्र

सिंह जी ने अनथक प्रयास करके इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। पहले भी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे।

माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया,आपका धन्यवाद और मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं।

समाप्त

25.3.2015/1940/ag/av/3

श्री नरेन्द्र ठाकुर : सभापति महोदया जी, आपने मुझे यहां बजट पर हो रही चर्चा के संदर्भ में बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

18 मार्च को माननीय वीरभद्र सिंह जी ने यहां पर बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने लगभग 3 घंटे 15 मिनट का समय लिया। उन्होंने यहां पर बड़े दमदार और एनर्जैटिक तरीके से बजट पेश किया। सौभाग्य से मुझे यह पहला बजट सैशन अटैंड करने का मौका मिला था। मैंने सोचा जिस ढंग से उन्होंने बजट प्रस्तुत किया उतना ही दमदार हमारा इस बार का बजट होगा और इस बार हिमाचल प्रदेश जरूर स्विटजरलैंड बनेगा। मगर जब मैंने इसका माइन्युटली निरीक्षण किया तो मुझे दुख भी हुआ। मैंने इस बजट में अपने प्रदेश की जो फाइनैंशियल और इकोनॉमिक सिचुएशन देखी तो इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं लगा।-----

श्री नेगी द्वारा जारी

25.03.2015/1945/negi/ag/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर.. जारी..
जो इकोनोमिक सिचुएशन देखी तो इस बजट में ऐसा कुछ भी नही है। यहां पर 2-3 दिन से चर्चा हो रही है। चर्चा जो बजट पर होनी चाहिए। हमारे प्रदेश की इकोनोमिक पोजिशन क्या है इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए । सत्ता पक्ष की बात तो मैंने मान ली। लेकिन यह कौन सा पक्ष है बीच में, यह इनसे भी बढ़ गया है। यहां बजट के ऊपर चर्चा न हो कर सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के ऊपर चर्चा हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री ऐसे है, इतने दूरदर्शी हैं। इतने ऊपर के दूरदर्शी है और इतने नीचे के दर्शी हैं। दैवीय

शक्ति है, पूजनीय है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। यह बजट सेशन है और यहां पर बजट के ऊपर बहस होनी चाहिए न कि व्यक्ति विशेष के ऊपर बहस होना चाहिए। मैं तो पहली बार यह देख रहा हूं। ...(व्यवधान) ...मैंने बोल ही दिया है कि यह मेरा पहला बजट है। अगर आपको बोलने का ज्यादा शौक है तो खड़े हो करके बोलिए।

सभापति (श्रीमती आशा कुमारी): माननीय सदस्य, please don't disturb the Member. यह पहली बार बोल रहे हैं और यह इनकी मेडन स्पीच है। Kindly don't disturb the Member. यह इनकी मेडन स्पीच है, kindly don't disturb the Member.

श्री नरेन्द्र ठाकुर: थैक्यू मैडम. जहां तक इस प्रदेश की फाइनैंशियल पोजिशन है , जो इकोनोमिक सर्वे रिपोर्ट आई वह मैंने देखी है। इस प्रदेश का अपना जो सोर्सिज़ है, टोटल बजट में कितना परसेन्ट हम अपने सोर्सिज़ से जेनरेट करते हैं-सिर्फ 33 परसेन्ट । और 67 परसेन्ट हमें या तो केन्द्र से सहायता लेनी पड़ती है या लोन ले करके गुजारा करना पड़ता है। इस बार के बजट में क्या है ? 50 परसेन्ट केन्द्र की ग्रांट आएगी और 17 परसेन्ट लोन इस बार भी हमें लेना पड़ेगा। और यह 17 परसेन्ट लोन भी बहुत बड़ी चीज हैं। आप किस बजट की बात कर रहे हैं? मैं आपको क्या कहूं? इस बजट को देख करके लग रहा है कि यहां सभी भिखारी हैं and beggars can't be the choosers. आप कौन सा बजट पेश कर रहे हैं? आपके पास अपना

25.03.2015/1945/negi/ag/2

है क्या ? माननीय सभापति महोदया जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि टोटल बजट का 40 परसेन्ट इस प्रदेश में डिवलपमैन्ट के लिए लगेगा और 60 परसेन्ट बजट इस प्रदेश की देनदारियों में चला जाता है। 40 परसेन्ट बजट जो हमारा बचता है वह फील्ड में कितना लगता है, यह सबको पता है। उसमें हमने जितने चेयरमेन बनाया है उनका खर्चा भी शामिल है। जितने आप यहां बैठे हैं, मंत्री बैठें हैं उनका खर्चा भी शामिल है। आपके जितने सलाहकार बैठे हैं इसमें उनका खर्चा भी शामिल है। जितने रिटायर्ड आदमियों को आपने सलाहकार बनाया हुआ है उनका भी इसमें खर्चा शामिल है। ब्यूरोक्रैट्स, टैक्नोक्रैट्स और नीचे का जो स्टाफ है

वह किस ढ़ंग से काम करता है, प्रदेश की क्या पोजिशन है, किस ढंग से प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है वो खर्चा भी इसमें शामिल है। सही मायने में 10 परसेन्ट बजट डिवलपमैन्ट के ऊपर नहीं लगता है। इस स्टेट की प्रेजेन्ट जो इकोनोमिक पोजिशन है वह यह है। मैं ज्यादा लम्बा-चौड़ा भाषण नही दूंगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि यहां बड़ी जोर-शोर से चर्चा हो रही थी, अभी माननीय लखनपाल जी ने एग्रीकल्चर के ऊपर यहां पर बोला कि इस बार एग्रीकल्चर के लिए बहुत कुछ है। माननीय सभापति जी, हिमाचल प्रदेश हमारे देश का पहला राज्य है जिसका 90 परसेन्ट पापुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेन्ट करती है। कामगार लोग जो हमारे इस प्रदेश में काम करते हैं, 70 परसेन्ट कामगारों को रोजगार एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। स्टेट की जो टोटल इन्कम है उसमें इसका शेयर आता है 14 परसेन्ट। जो पहले सर्वे हुआ था उसमें इसका हिस्सा था 57 परसेन्ट।...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

25.03.2015/1950/यूके/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर--जारी---

उसका हिस्सा 57% था । 1967-68 में 55% ,1990-91 में 26% ,1913-14 में 14% । अब आप कह रहे हैं कि कृषि की दुदर्शा है कि जो 1950 में 57% इनकम का सोर्स इससे प्राप्त होता था। आज हमारी पोजीशन यह है कि हम 14% के ऊपर आ गए हैं। Who is responsible for that? आज हमारी स्टेट का दिवालिया हो गया है, who is responsible for that? मैं कहता हूं कि आप लोग, जिन्होंने सन् 1971 में जब हमारा प्रदेश अस्तित्व में आया था, 1971 के बाद आज तक 45 साल हो गए हैं, जब हमारा प्रदेश ऐग्जिस्टेंस मे आया तब लोन नहीं लेता था । ये लोन लेना किसने शुरू किया ? आपकी सरकार ने । चिंता तो इसके ऊपर करनी चाहिए थी कि हमारी स्टेट सैल्फ इंडिपैंडेंट हो । सोर्सिज़ जनरेट करने चाहिए थे । लेकिन आप सोर्सिज़ जनरेट करने की बजाय मौज-मस्ती करते रहे और इस प्रदेश को भ्रष्टाचार के मामलों में पूरा डुबो दिया । आज यह सिचुएशन आ गयी है कि अगर केन्द्र से ग्रांट आपको न आए, अगर आप लोन न लें तो जो आपका सोर्स है उसमें आप सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन देने के अलावा और कुछ नहीं कर पायेंगे । आज हमारे प्रदेश की यह हालत है । ऐग्रीकल्चर के बारे में मैने आपको बता दिया । किसी ने इसके बारे

में कोई चर्चा नहीं की । डे-बाय-डे हमारा ऐग्रीकल्चर का और कल्टीवेटिड एरिया कम हो रहा है । यह भी आपको पता है । प्रोडक्शन कम हो रही है । इसकी क्या वजह है? आप बताइए किसी ने इसके बारे में डिसकशन की? क्या वजह है, यह क्यों कम हो रही है ? आप तो कह रहे हैं कि हमने इतना करोड़ रुपए का बजट रख दिया । हम ये कर रहे हैं,

25.03.2015/1950/यूके/2

हमारा हॉर्टिकल्चर बढ़ गया है । पर डे-बाय-डे कम हो रहा है जो कि यह बढ़ना चाहिए था । क्या वजह है, इसमें? बाकी तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन जो हमारे 7-8 जिले हैं, कांगड़ा, चम्बा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर भी बीच में आ जाता है । क्या वजह है कि वहां एक भी खेत बन्दरों, आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से सुरक्षित नहीं है । सिर्फ आपकी जिन क्रॉप का बंदर और जंगली जानवर नुकसान कम करते हैं, इसके अलावा न तो आप सब्जी पैदा कर सकेंगे । व्हीट की क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचता । बाकी आप कोई फसल ले लो । इस वक्त यह पोजीशन आ गयी है कि आप तैयार नहीं कर सकते हैं । धूमल जी ने कहा था कि हमारे पास अब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा हुआ है । जो आपने यह नसबन्दी वगैरहा भी चलाई है, यह लाँग प्रोस्सेस है, तब तक तो सारे खेत खाली हो जाएंगे, आपका ऐग्रीकल्चर जीरो हो जायेगा । इसमें कोई दो राय नहीं है । हमारे पास सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव है, वह है किलिंग और कोई इसका मैथर्ड आपको निकालना पड़ेगा । अगर इनसे निज़ात नहीं पायी गयी तो हमारा ऐग्रीकल्चर, खास कर के जो जिले मैने अभी बताए यहां पर कृषि बिल्कुल खत्म हो जायेगी । कोई भी किसान खेत नहीं बीजेगा । (घंटी.) .इसके बारे में हाऊस को चिंता करनी चाहिए थी । लेकिन सत्ता पक्ष से किसी ने इसके बारे में चर्चा नहीं की । वे केवल आंकड़े पढ़ते रहे । आंकड़े तो हमने भी पढ़ ही लिए हैं कि इस बार बजट में दिहाड़ी बढ़ा दी है या सामाजिक सुरक्षा पेंशन 50 रुपए बढ़ा दी है । यह तो हमने भी पढ़ लिया है । लेकिन जो बेसिक चिंता हाऊस को करनी चाहिए

25.03.2015/1950/यूके/3

थी, उसके बारे में सत्ता पक्ष बिल्कुल साइलैंट बैठा हुआ है । क्या कहते हैं कि भई, जीव को भी जीने का हक है । हम भी कहते हैं कि यदि कोई जानवर है या किसी जीव को कोई लाईफ मिली है तो उसको जीने का हक है । चाहे लैपर्ड और टाईगर हैं इनको भी जीने का हक है । जब वे मैन-ईटर बन जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उनको शूट-आऊट करके मार दिया जाता है । अब बन्दरों ने यह पोजीशन कर दी है ,वह मैन-ईटर तो 5-10 खायेगा लेकिन ये पूरे प्रदेश को खा रहे हैं । इसलिए इनका सफाया करना बहुत जरुरी है । इसलिए मेरा हाऊस से यह निवेदन है कि यदि आपने ऐग्रीकल्चर को बचाना है तो

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः आप बजरंग दल वालों को पूछें इसके बारे में ।
श्री नरेन्द्र ठाकुरः सर, इसके लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा यह बड़ा चिंता का विषय है । मैडम, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा टाईम और लूंगा और टूरिज़म के बारे में बोलना चाहूंगा । टूरिज़म एक ऐसा डिपार्टमैंट है, हिमाचल प्रदेश इससे इनकम जनरेट कर सकता है । आज हमारी स्टेट की टोटल इनकम में इसका 7.5% हिस्सा है । लेकिन टूरिज़म की क्या हालत है? पीछे एक किस्म का सर्वे हुआ । जो यहां पर टूरिस्ट आता है, उनसे पूछा जाता है कि क्या आप हिमाचल में दोबारा आएंगे ?

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

25.03.2015/1955/sls-jt-1

श्री नरेन्द्र ठाकुर...जारी
उससे पूछा जाता है कि क्या आप दोबारा हिमाचल आएंगे? क्या इस बार पूरी सुविधा मिली? सर्वे में ज्यादातर पर्यटकों ने कहा कि हम बंगलादेश या पाकिस्तान चले जाएंगे लेकिन हिमाचल में दोबारा नहीं आएंगे।

हमारी सड़कों का बुरा हाल है और पर्यटकों के रहने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है। दुर्घटना होने पर हम उनको बचा नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य सुविधा हमारे पास नहीं है। मेरा आपसे निवदेन है कि पर्यटन को अगर बढ़ाना है तो सड़कों के ऊपर,

स्वास्थ्य के ऊपर, रहने का सही प्रबंध हो, सिक्योरिटी हो, इसके ऊपर ध्यान देने से ही पर्यटन बढ़ पाएगा। यह एक चिंता का विषय है। कहने को कुछ भी कह लें लेकिन बेसिक चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको प्रदेश की इकोनोमी के बारे में सोचना पड़ेगा।

मैं ज्यादा न कहता हुआ, अगर आगे समय मिलेगा तो मैं सभी विभागों के बारे में बोलूंगा।

जो यह बजट है यह एक किसम का छलावा है। हमारे पास कुछ भी नहीं है; we are the beggars. हम क्या बजट बनाएंगे? क्या बैगर का बजट होता है? और हम बैगर भी कौन हैं? कर्जदार बैगर हैं। ऐसा बैगर जिनके ऊपर कर्जा भी है और वह बैगिंग भी कर रहा है।

इस बजट में कुछ नहीं है। यह सिर्फ़ एक धोखा है। जो पिछले वर्ष आपने बजट पेश किया था ,मैं उसकी थोड़ी-सी झलक दिखाना चाहूंगा। आपने कहा था कि दसवीं और प्लस टू के मैरिट में आने वाले 7500 बच्चों को हम लैपटौप देंगे, कोई नहीं दिया गया। 13 नए बस अड्डे खोलेंगे, कोई नहीं खुला। 490 किलोमीटर नए रोड बनाएंगे, एक किलोमीटर भी नया रोड नहीं बना। 30 नए पुल बनाएंगे, एक भी नहीं बना। 555 किलोमीटर पक्का रोड बनाएंगे, एक किलोमीटर भी नहीं बना। 2000

25.03.2015/1955/sls-jt-2

किलोमीटर की मेंटेनैंस होने की बात की थी, एक किलोमीटर नहीं हुई। 6000 किलोमीटर आपने रोड्ज में पानी की निकासी का प्रबंध करना था जो नहीं हुआ। यह सारी घोषणा की घोषणा रह गईं। इस बार के बजट में जो घोषणा की है, अगले साल जब हम देखेंगे तो वह भी वैसी की वैसी ही होंगी।

इसलिए इस बजट का समर्थन न करते हुए मैं इसको आऊटराइटली रिजैक्ट करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

सभापति : धन्यवाद।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि अभी 8 और सदस्य बोलने वाले हैं। जो समयावधि बढ़ाई थी वह पूर्ण हो चुकी है। अगर हाऊस की इजाजत हो तो बैठक आधा घंटा आज बढ़ा लें और बाकी लोग कल बोल लेंगे। अब इस सदन की बैठक 8.30 बजे तक बढ़ाई जाती है। माननीय सदस्य मनोहर धीमान जी चर्चा में हिस्सा लेंगे।

25.03.2015/1955/sls-jt-3

श्री मनोहर धीमान : माननीय सभापति महोदया, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 2015- 16का बजट सदन में प्रस्तुत किया है ,मैं उस पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसमें संदेह नहीं है कि 15 अप्रैल, 1948 को अनेकों पहाड़ी रियासतों के विलय से बना हिमाचल 25जनवरी ,1971 को अपने पूर्ण अस्तित्व में आया। हिमालय की गोद में बसा भौगोलिक एवं बहुरंगी सांस्कृतिक विविधता से भरपूर यह पहाड़ी राज्य आज अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए एक उदाहरण है। इसका सर्वाधिक श्रेय मैं माननीय मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी को देना चाहता हूं जो छठी बार प्रदेश के मुख्य मंत्री पद पर सुशोभित है। 18 तारीख को जो बजट प्रस्तुत किया, वह उनका 18वां बजट था। उनकी राजनीतिक दूर दृष्टि, राजनीतिक परिपक्वता एवं कर्मठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश के मेहनतकश प्रदेशवासियों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप ही आज हिमाचल प्रदेश इस मुकाम पर पहुंचने में सफल हुआ है। माननीय सभापति जी, हर बार की तरह माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट प्रस्तावों में समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ..

जारी..गर्ग जी

25/03/2015/2000/RG/JT/1

श्री मनोहर धीमान-------क्रमागत
माननीय सभापति महोदया, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की विकास की गति को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया है। मेहनतकश किसान तथा बागवान इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी हैं। इस वर्ग

के लिए कई योजनाओं की घोषणा बजट में की गई है। जैसे निजी सिंचाई योजनाओं के लिए 50 प्रतिशत उपदान देना ,एक लाख किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना ,केंचुआ खाद इकाइयों को पचास प्रतिशत उपदान देना जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा विपणन मण्डियों का सृजन करना ,उत्तर चारा उपदान योजना ,मौसम आधारित फसल बीमा योजना और इसके अलावा दस लाख रुपये तक के कृषि ऋणों पर स्टाम्प डियुटी की छूट आदि-आदि, ऐसे बजट में कई प्रावधान किए गए हैं जो सीधे-सीधे किसान और बागवानों के हितों को सुरक्षित तथा सुनिश्चित करते हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से नम्र आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रकार की योजनाओं का सीमांत तथा लघु किसानों को अधिक-से-अधिक लाभ मिले। इसे सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार युवा वर्ग को भी अन्य सुविधाओं के साथ-साथ साढ़े सात लाख रुपये के शिक्षा ऋणों पर स्टाम्प डियुटी की छूट दी गई है जो बहुत ही सराहनीय कदम है। मेरा मानना है कि कोई भी मेधावी छात्र पैसे के अभाव के कारण शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रह पाए।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का इन्दौरा में कांगड़ा जिले के कन्द्रोणी में 107करोड़ रुपये के औद्योगिक क्षेत्र स्वीकृत करने के लिए विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही माननीय उद्योग मंत्री जी का भी इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। गत वर्ष भी ऐसी ही एक योजना छाँछ खड्ड के तटीयकरण को भी स्वीकृति प्रदान की गई थी। उसके लिए मैं आभारी हूं। इससे युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

माननीय सभापति महोदया, इस सबके साथ-साथ माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने विधान सभा सदस्यों की विधायक क्षेत्र विकास निधि को पचास लाख से बढ़ाकर सत्तर लाख रुपये किया है। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

25/03/2015/2000/RG/JT/2

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं। अभी हाल ही में भारी या बेमौसमी बरसात के कारण फसलों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि जैसे पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने किसानों के ऋण माफ किए हैं और फसलों का मुआवजा देने की बात कही है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध रहेगा कि पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर यहां के किसानों को भी इसका लाभ दिया जाए। भारी बरसात के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र की अधिकांश सड़कें टूट चुकी हैं ,मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इनकी मरम्मत के लिए राशि उपलब्ध करवाई जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 15 खड्डे ऐसी हैं जिनको नदी-नाले बोलते हैं वे बरसात के दिनों में उपजाऊ भूमि को बहा देती हैं। सारा साल किसान उस भूमि को बनाने में लगा देता है और एक ही बरसात में वह भूमि बह जाती है। मैं चाहता हूं कि इन खड्डों का तटीयकरण भी छॉछ खड्ड की तर्ज पर किया जाए----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

25/03/2015/2005/MS/AG/1

श्री मनोहर धीमान जारी--------

मैं चाहता हूं कि इन सभी खड्डों का तटीयकरण छौंछ खड्ड की तर्ज पर किया जाए। प्रदेश में जो उद्योग लगे हैं और अन्य भी लगने वाले हैं, उनमें एक ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई है। वहां रोजगार के लिए चाहे मजदूर भी हो, यदि वह वहां सीधा जाता है तो एक ठेकेदार के माध्यम से वहां उसकी एंट्री होती है। जो कमीशन ठेकेदार को जाती है, मेरा सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और उद्योग मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि वे विभाग को ऐसी हिदायत दें कि सीधी भर्ती हो। मेरा इंदौरा विधान सभा क्षेत्र जो पंजाब की सीमा के साथ सटा हुआ है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि इसकी डिमार्केशन करवाई जाए ताकि वहां सीमा की हद का पता चल जाए। इसमें खनन के अलावा आजकल नशे का कारोबार भी बहुत बढ़ चुका है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाए। हमारे क्षेत्र के बच्चे और नौजवान इसकी गिरफ्त में हैं। मैं एक बात इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी भी

विभाग की कोई गुप्त टीम जब छापा मारने या रेड करने यहां से निकलती है तो कौन सा तंत्र है कि जब टीम शिमला से सोलन के लिए चलेगी तो कलप्रिट्स को पता होता है? जब धर्मशाला से कोई टीम जाती है कि बॉर्डर एरिया में रेड करना है तो उन लोगों को पहले पता होता है।

सभापति महोदया, अगर आपकी अनुमति हो तो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हमारे पठानकोट के एरिये में डीडा नाम का एक गांव था। वहां कच्ची शराब निकलती थी और वह शराब किसी अंग्रेज को किसी ने पिलाई। वह शराब इंग्लैण्ड तक मशहूर हो गई। वहां अंग्रेज घूमते रहते थे कि डीडा गांव कहां है तो वहां से वे कच्ची शराब लेकर जाते थे। उनका नैटवर्क देखो, वैसे आजकल तो मोबाइल से सब मुमकिन है। उन्होंने मेन रोड से जो उस गांव को सड़क जाती थी, वहां एक चाय वाले की दुकान के साथ तालमेल किया हुआ था। उस दुकान वाले को लाउड स्पीकर लेकर दिया हुआ था। उस लाउड स्पीकर को एक बड़े से पेड़ में टांगा हुआ था। जब कभी पुलिस उस तरफ को जाती थी तो उसके लिए उन्होंने कोड वर्ड रखा हुआ था। वह गाना गा देता था। "वतन की आबरू खतरे में है, सम्भल जाओ।" तो वे गांव वाले समझ जाते थे कि अब कुछ खतरा आने वाला है और वे अपना इंतजाम कर लेते थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह कौन सा तंत्र है कि जब सरकार के

25/03/2015/2005/MS/AG/2

अधिकारी/कर्मचारी यहां से छापे के लिए निकलते हैं तो वहां उनको पहले पता चल जाता है? इस पर गौर करने की जरूरत है।

एक बात और मैं कहना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में शाह नहर प्रोजैक्ट है। वह लगभग 90 प्रतिशत बनकर तैयार हो गया है। मेरा निवेदन रहेगा कि अधिकांश जो प्रोजैक्ट हैं वे मेरे इंदौरा विधान सभा क्षेत्र और फतेहपुर में आते हैं। लेकिन वहां जो XEN बैठते हैं ,वहां एक ही डिवीजन है और वे टैरिस पर बैठते हैं। अब किसानों को कहीं कोई शिकायत लेकर जाना हो तो 70 किलोमीटर का सफर तय करके वे XEN के पास पहुंचते हैं। मेरा निवेदन रहेगा, मैंने पिछली बार भी यह प्रश्न किया था कि बड़ूखर में इसका सैंटर बनता है और वहां बनने से किसानों का आधा सफर कम हो जाएगा। इसलिए तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात और, मेरे क्षेत्र में इंदौरा, नुरपूर और फतेहपुर क्षेत्र में किन्नू, संतरा और आम की भरपूर फसल होती है,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

25.03.2015/2010/जेके/जेटी/1

श्री मनोहर धीमान-जारी---------
किन्नू, संतरा और आम की भरपूर फसल होती है। किसी समय इस एरिया को मिनी नागपुर के नाम से जाना जाता था। इतना ज्यादा वहां पर संतरा होता है लेकिन धीरे किसान पीछे हट रहे हैं कि वहां पर मार्किटिंग नहीं है। अब तो सब्जियां भी वहां पर बहुत सारी होनी शुरू हो गई है। मैं चाहता हूं कि सरकार वहां पर कोई उद्योग ऐसा लगाए यानि फ्रूट प्रोसैसिंग का प्लांट लगे ताकि जो किसान दर-दर ठोकरें खाता है वह न खाएं। एक दर्दनाक सीन है उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के लोग 20 मार्च को जो अभी कठुआ में हादसा हुआ है वहां के तीन जमींदार अपना किन्नू बेच कर आ रहे थे। उनकी गाड़ी को अगवा किया गया। वर्दीधारी उग्रवादियों ने उनको अगवा किया। पीठ पर पिस्तौल रख कर पुलिस स्टेशन के अन्दर उनको अटैक करना था। उनको एक साजिश के तौर पर ले कर गए और उन्होंने बोला कि गेट खोलो हम उग्रवादी लेकर आए हैं। इनको हमने आपके पास अन्दर करवाना है। जैसे ही उन्होंने पुलिस थाने का गेट खोला और सबसे पहले उन्होंने एक सन्तरी को गोली मारी। उसके बाद धड़ाधड़ हमारे तीनों नौज़वान किसानों को गोलियां चला दी। वे अपना ही सन्तरा बेचने वहां पर गए हुए थे। एक की तो स्पॉट में ही डैथ हो गई, एक भाग निकला और एक अभी भी कठुआ अस्पताल में दाखिल है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार उसको मुआवज़ा दें क्योंकि उसके छोटे-छोटे बच्चे पीछे रह गए हैं। मैं तो यह कहता हूं कि जो शहीद हुआ है उसको कोई ईनाम दिया जाए। उसका पहले भी एक भाई फौज में था। वह भी कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गया था। उसके जो छोटे-छोटे बच्चे पीछे रह गए हैं और एक जो अस्पताल में एडमिट है उनको आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिले। हमारी सरकार जम्मू-कश्मीर सरकार से बातचीत करके वहां से उसको मुआवज़ा दिलाने का प्रयास करें। ऐसा मेरा सदन से अनुग्रह रहेगा।

25.03.2015/2010/जेके/जेटी/2

माननीय सभापति जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हर सीजन में 5-7-10 घटनाएं आग लगने की होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां पर एक फायर स्टेशन अति आवश्यक खुलना चाहिए क्योंकि अगर आग लग जाए तो हमें या तो पंजाब से या 40-45 किलो मीटर नूरपुर पड़ता है वहां से सहायता लेनी पड़ती है। जब तक फायर बिग्रेड की गाड़ी वहां पर आती है तब तक काम तमाम हो जाता है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि इसकी व्यवस्था की जाए। आदरणीय महेश्वर सिंह जी ने जो सड़कों की बात कही वह बिल्कुल ठीक है और ये 15 एम.एम. की बात कर रहे थे । अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी तीसरे दिन ही तारकोल उखड़ गई। मैं चाहता हूं कि यह चाहे ठेकेदार की गलती है, चाहे अधिकारी की गलती है लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। मैंने तो उन ठेकेदारों की पेमैंट रोक रखी है। जब तक वह दोबारा से काम नहीं करेंगे उनकी पेमैंट नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से हो जाए और आगे से कम से कम ऐसी गलती न करें। माननीय सभापति जी, कुल मिला कर यह बजट अत्यन्त संतुलित और हर वर्ग को राहत देने वाला है। इसका मैं स्वागत करता हूं और भरपूर समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत आभार। जय हिन्द, जय हिमाचल।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

25.03.2015/2015/SS-AG/1

सभापतिः अब माननीय सदस्य, श्री राम कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राम कुमार :सभापति महोदया, धन्यवाद। मैं बजट अनुमान 2015-16 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सीमित साधनों को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत कड़ी मेहनत करके बजट बनाया है। हमारे अधिकारीगण यहां बैठे हैं जैसे इसको 3 घंटे उनको पढ़ने में लग गए इससे पता चलता है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कितनी मेहनत हमारे अधिकारियों के साथ बैठ करके इस बजट को बनाने में की होगी। इसके लिए मैं इस बजट का स्वागत और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। यह ऐसा संतुलित बजट है जिसमें सब वर्गों को तरज़ीह दी

गई है। खासकर गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग के लिए और आम आदमी के उत्थान के प्रबंध इसमें किये हैं। विभिन्न विकास की योजनाओं को इसमें दर्शाया गया है। किसानों, मजदूरों, बागवानों और पैंशनरों, बुजुर्गों, अपंगों, कर्मचारियों का खास ध्यान इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है। पिछले दो दिन से इस पर चर्चा चल रही है। आज तीसरा दिन इस चर्चा का है। विपक्ष बड़ी तेज़ी से प्रहार करके हर बार यह कहता है कि गरीबों के लिए इसमें क्या किया गया। मैं इसके कुछ अंश जो गरीबों के लिए इस बजट में दर्शाये गए हैं ब्रीफ में कहना चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है। 15 मिनट बाकी हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 4.48 लाख लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड जारी किये जायेंगे। राजीव गांधी अन्न योजना के तहत 37 लाख लोगों को लाया जायेगा।

सभापतिः माननीय सदस्य, कृपया आपस में बात न करें। माननीय सदस्य कुछ बोल रहे हैं, कृपया सब सुनें।

श्री राम कुमारः पैंशनरों के पैंशन भत्ते में बढ़ोत्तरी की गई। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी बढ़ाई गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के अतिरिक्त मानदेय में 50 प्रतिशत की एक रिकॉर्ड वृद्धि के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने योजना बनाई। अंशकालीन जलवाहकों के मासिक मानदेय में 200 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई। बेरोजगारों को कौशल भत्ता दिया जा रहा है। जिसमें अभी तक लगभग 64 हजार हमारे नौजवान साथियों को कौशल विकास भत्ता दिया जा रहा है। राजीव गांधी सूक्ष्म योजना के तहत 85 हजार हैक्टेयर भूमि पर फुव्वारे से 14 हजार किसानों को लाभ होगा। किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए सॉयल हैल्थ सर्विसिज़ के तहत सॉयल टैस्टिंग लैबोरेटरी की स्थापना इस बजट के तहत की गई है जोकि मैं

25.03.2015/2015/SS-AG/2

समझता हूं कि एक अहम कदम है। उससे हमारे किसानों की पैदावार की बढ़ोत्तरी होगी। डॉ0 वाई0एस0 परमार किसान स्व-रोजगार योजना के तहत बेरोजगार व्यक्तियों के लिए हाईटैक पॉलीहाउस निर्माण योजना बनाई गई। उत्तम चारा योजना के तहत 25 हजार हैक्टेयर भूमि चारा उत्पादन क्षेत्र के तहत लाई जायेगी। मुख्य मंत्री किसान एवं खेती मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत मृत्यु व अपंग

होने पर डेढ़ लाख व 50 हजार मुआवजे का प्रावधान माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट में किया है। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी हुई है। एच0आर0टी0सी0 के माध्यम से हमारे जो दूर-दराज के क्षेत्र हैं उनमें बसों की सुविधा देने के लिए 800 बसों का बेड़ा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत माननीय मुख्य मंत्री और माननीय बाली जी ने किया है। अंशकालीन को डेली बेजिज़ और सात वर्षीय दैनिक भोगियों को पक्का करना, 6 वर्षीय कर्मियों को परमानेंट नियमित करना, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रावधान किया है। जिसमें विपक्ष की तरफ से मैं नाम नहीं लूंगा कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है कि इसमें कांग्रेस के लोगों को पक्का किया जा रहा है। मैं सामने वाले अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि वे आदमी बी0जे0पी0 के हैं या कांग्रेस के हैं। जो भी उसमें आयेंगे वे सब पक्के होंगे। इसमें समय-सीमा तय कर दी गई है। उसके लिए इनको धन्यवाद करना चाहिए। विधायक निधि जो सबसे अहम है, हम विधायकों के लिए जीने का जरिया है, लोगों में जाने का जरिया है वह 50 लाख से 70 लाख की गई। मैं पूरे सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे साथ लगते जो पड़ोसी राज्य हैं चाहे वह पंजाब या हरियाणा है, पिछले दिनों मोहाली (पंजाब) के विधायक से मुझे मिलने का मौका मिला। वे कहते हैं कि हमारे पास एक रुपया, एक फूटी कोड़ी एनाऊंसमैंट के लिए नहीं होती। हम गांव में नहीं जा सकते। उलटा जो सत्ता पक्ष है उनके जो हारे हुए एम0एल0ए0 हैं ....

जारी श्रीमती के0एस0

25.03.2015/2020/केएस/एजी/1

श्री राम कुमार जारी---
उलटा जो सत्ता पक्ष है, उनके जो हारे हुए विधायक हैं जैसे ये बात कर रहे हैं, बोर्ड और निगमों के चेयरमैन्ज़ की कि वो लोग वहां जाकर सरकार की योजनाओं की घोषणा करते हैं इसलिए विपक्ष को धन्यवाद करना चाहिए कि यह हमें जीने का जरिया सरकार ने दिया है माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे विधायकों की जो एक मीटिंग धर्मशाला में हुई थी, हमने संजय रतन जी के माध्यम से यह मांग रखी थी तो उसमें उन्होंने यह आश्वासन दिया था। हमने एक करोड़ रुपये की मांग रखी थी लेकिन उन्होंने इस बजट में इसको 70 लाख किया है इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का विशेषतौर पर आभार।

सभापति महोदय, बी.पी.एल. परिवारों के लिए 75 करोड़ रु0 की लागत से 10 हजार आवासों का निर्माण करने की प्रस्तावना की गई है। स्वच्छता मिशन के अंतर्गत राज्य की 470 पंचायतों में ठोस कचरा प्रबन्धन का कार्य किया जाएगा। सभी विभागों में जो रिक्त पदों की बात होती है हम भी इस बात से चिन्तित है । मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो विभिन्न विभागों में पदों का सृजन किया है, समय कम है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। सिविल सेवाओं में हिमाचलियों की कमी को देखते हुए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रारम्भिक परीक्षा उतीर्ण करने वाले को 30 हजार रुपये देने का प्रावधान किया है। बद्दी और कुल्लू में शिमला की तर्ज पर महिला थाने खोले जाएंगें इसके लिए भी मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

25.03.2015/2020/केएस/एजी/2

सभापति महोदया, इसके अलावा मेरे हलके में जो विकासात्मक कार्य माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से चल रहे हैं, उनकी थोड़ी सी चर्चा इस माननीय सदन में करना चाहूंगा। सी. टीवी प्लांट प्रोजैक्ट 60 करोड़ की लागत से बद्दी में माननीय आनन्द शर्मा जी ने उसका नींव का पत्थर रखा था वह बन कर तैयार हो गया है। बद्दी-बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते वहां का ग्राऊंड वाटर खराब हो गया था। इस बात को बार-बार माननीय मेरे पूज्य पिताजी, पूर्व विधायक श्री लज्जा राम जी ने कई बार उठाया और उस पानी को साफ करने के लिए जो ट्रीटमैंट प्लांट लगा उससे एक तो हमारी जो पुरानी सिंचाई योजनाएं हैं, वे जीवित होंगी और पानी का जो डिस्चार्ज है वह तीन गुना बढ़ जाएगा। हमें स्वच्छ पानी मिलेगा इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा। दूसरे, इन्होंने सैंटर में मिनिस्टर रहते हुए स्किल डवैल्पमैंट सैंटर साढ़े नौ करोड़ रुपये की लागत से बद्दी में दिया जिसमें 134 लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा, जब कांग्रेस की सरकार थी बी.बी.एन.डी.ए. का गठन हमारे बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के लिए किया इसके गठन के समय 25 करोड़ रु0 के बजट का प्रावधान माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया था लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो केवल 5 करोड़ रुपये ही ये लोग दे पाए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बी.बी.एन.डी.ए. को 20 करोड़ के बजट का प्रावधान अगले वर्ष के लिए किया है। इससे पहले पंचायत को इस निधि से कोई पैसा नहीं मिलता था। मैंने एक प्रश्न के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जिसमें 79 प्रतिशत पैसा

25.03.2015/2020/केएस/एजी/3

पंचायत एरिया में खर्च किया जा रहा है और बाकी 11 प्रतिशत पैसा उद्योगों में खर्च किया जा रहा है लेकिन भाजपा के समय में जब मैं चेयरमैन, जिला परिषद सोलन था हमने 2 लाख रुपये की ग्रांट बी.बी.एन. के तहत जो पंचायतें आती हैं, उनको देने की मांग की थी। 2 लाख रुपये की घोषणा की गई थी उसके बाद भाजपा के जो हमारे ब्लॉक नालागढ़ के प्रधान थे उन्होंने उसका विरोध किया और वह ग्रांट बन्द हो गई। इनके समय में एक भी रुपया हमारे रूरल एरिया में नहीं लगा तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और उद्योग मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके प्रयासों से 79 प्रतिशत पैसा हमारी पंचायतों में खर्च हो रहा है।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में चार बड़े पुल लगभग साढ़े 17 करोड़ रुपये की लागत से माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकृत किए हैं। इनका नींव पत्थर मुख्य मंत्री जी 4 अप्रैल को रखने वाले थे लेकिन अब इन्होंने इसके लिए 13 तारीख का समय दिया है इसके लिए भी इनका धन्यवाद। मेरे क्षेत्र में दो आई.टी.आई. दी गई है जिनमें क्लासिज़ शुरू हो गई है, इसके लिए भी बाली जी और मा0 मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद। दो लेबर हॉस्टल्ज़ माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमें दिए हैं और इंडस्ट्रियल डिपार्टमैंट के माध्यम से नालागढ़ और दून क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से दो पार्कों का निर्माण उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। पंचायतों को जो कम्प्यूट्रीकृत किया गया ,वह पिछले समय में जो कांग्रेस की सरकार थी उसके समय में शुरू हुआ। स्वर्गीय सत्त महाजन जी हमारे पंचायत

25.03.2015/2020/केएस/एजी/4

मंत्री होते थे, मैं अध्यक्ष होता था उस समय कम्प्यूटर का कार्य हमारी पंचायतों में किया।

श्रीमती अ0व0द्वारा---

श्री राम कुमार------जारी
उस समय हमारी पंचायतों में कम्प्यूटर का कार्य किया गया जिससे हमारी पंचायतें आज ठीक कार्य कर रही हैं। बजट में पंचायतों के लिए 195 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि 195 करोड़ रुपये के बजट में से जो हमारे द्वारा दी गई निधि में से पंचायतों में रोड्ज बनती है उन पंचायतों के रख-रखाव के लिए इस राशि में से प्रावधान किया जाए ताकि बरसात के समय बंद होने वाली रोड्ज को खोला जा सके।

आई.पी.एच. डिपार्टमैंट के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक 33 करोड़ रुपये की सीवरेज की स्कीम है। उसके अलावा अन्य सभी स्कीमों को जोड़कर 8034 लाख रुपये की स्कीमें सैंक्शन है। पिछले वर्ष 606 लाख रुपये आई.पी.एच. स्कीमों के तहत खर्च किए जा चुके है जो पेयजल की स्कीमें तैयार है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पीछे एक 23 करोड़ रुपये की स्कीम दी है जिससे हमारे चंडी क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध होगा। यह बहुत बड़ी स्कीम है जिसके तहत दो पंचायतें अर्की की और 13 पंचायतें मेरे विधान सभा क्षेत्र की लाभान्वित होंगी। इसमें 6 डीप ट्यूबवैल प्लेन क्षेत्र में लगाकर आगे पहाड़ी क्षेत्र में पानी दिया जायेगा। एक 778लाख रुपये की अपरनी-गोयला पेयजल स्कीम बनकर लगभग तैयार हो गई है। मैं उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

अब मैं थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर बोलना चाहूंगा। भारत सरकार की तरफ से शायद स्वस्थता की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि जब मैं अध्यक्ष था तो उस समय टोटल सेनेटरी का कार्य शुरु हुआ था। सोलन जिला में ही 15पंचायतों को निर्मल पंचायत पुरस्कार भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिया जा चुका है। केंद्र सरकार स्कीमों के नाम चेंज करके वाह-वाही लूट रही है। जिस नीति आयोग का गठन किया गया है उसकी न कोई नीति है और न ही कोई नीयत है। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि माननीय

25.3.2015/2025/ag/av/2

मोदी जी प्रधान मंत्री बने तो टी.वी. पर दिखाया गया कि गंगा के किनारे इस तरह के शहर बसेंगे। मगर वे सारे कार्य टी.वी. पर ही रह गये और प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ।

मैं ज्यादा न कहता हुआ, क्योंकि समय की कमी है। मैं इस संतुलित बजट का स्वागत करता हूं और आपका समय देने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं विपक्ष से यह आग्रह करुंगा कि सैंटर ने जो हमारे कट लगाये हैं आप उनमें वहां से पैसा लाने में सहयोग करें। धन्यवाद, जयहिन्द, जय भारत।

समाप्त

25.3.2015/2025/ag/av/3

श्रीमती आशा कुमार, सभापति :अब इस मान्य सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 26 मार्च, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **श्री सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः25.3.2015 **सचिव।**